173

टी. अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसायटी एवं अन्य इत्यादि

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

26 अप्रैल, 1974

[न्यायमूर्तिगण ए. एन. राय सी. जे., डी. जी. पालेकर, पी. गगनमोहन रेड्डी, एच. आर. खन्ना, के. के. मैथ्यू, एम. एच. बेग, एस. एन. द्विवेदी, वाई. वी. चंद्रचूड़ और ए. अलगिरिस्वामी]

भारत का संविधान 1950 कला। 29 और 30-क्या पारस्परिक रूप से अनन्य

का दायरा

गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949-एस. 5 , 33 ए (1) (ए), 33 ए (1) (बी), एस। 39 , एस. 40 (1)

और (2), एस। 41 (1) , एस. 51 ए (1) और 52 ए-संवैधानिकता।

पहला याचिकाकर्ता एक धार्मिक संप्रदाय है, जिसने उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक कॉलेज का गठन किया ईसाई और अन्य छात्रों को शिक्षा। याचिकाकर्ता के कॉलेज को एस के तहत संबद्धता प्रदान की गई थी। 33 गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 1972 में संशोधित किया गया।

विश्वविद्यालय की सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया कि सभी निर्देश, पढ़ाते हैं अध्ययन के उन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण और प्रशिक्षण, जिनके संबंध में विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने में सक्षम है, विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि इसके भीतर स्थित कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं है।

विश्वविद्यालय, राज्य सरकार की मंजूरी के अलावा, किसी भी अन्य विश्वविद्यालय के किसी भी विशेषाधिकार के साथ किसी भी तरह से संबद्ध होगा या प्रवेश लेगा।

कानून द्वारा स्थापित। अधिनियम की धारा 33 ए (1) (ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक कॉलेज सरकार द्वारा बनाए गए सरकारी कॉलेज या कॉलेज के अलावा,

एक शासी निकाय के प्रबंधन के अधीन होगा जिसमें शामिल हैं -

कुलपति द्वारा नामित। धारा 33 ए (1) (बी) (आई) में प्रावधान है कि प्रधानाचार्य की भर्ती के मामले में, एक चयन समिति की आवश्यकता होती है

अन्य लोगों के अलावा, विश्वविद्यालय के नामित प्रतिनिधि से मिलकर गठित

कुलपतिया आरो (ii) सोद्रोमा सायख 'नायनि बेलायाव महाविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों की एक चयन समिति जिसमें प्राचार्य शामिल होते हैं

और कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि। उप. धारा की धारा (3) में कहा गया है कि उप-धारा (1) के प्रावधान एस. 33 ए को निर्दिष्ट प्रत्येक कॉलेज की संबद्धता की शर्त माना जाएगा। उस उप-खंड में। धारा 39 में यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालय के भीतर इस क्षेत्र में सभी स्नातकोत्तर शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय या ऐसे संबद्ध महाविद्यालय या संस्थान द्वारा और ऐसे में कानून द्वारा निर्धारित विषय। धारा 40 (1) अधिनियमित करती है कि

' विश्वविद्यालय का न्यायालय यह निर्धारित कर सकता है कि सभी निर्देश, शिक्षण और अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण जिसके संबंध में विश्वविद्यालय सक्षम है परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा और प्रदान किया जाएगा विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा। एस की उप-धारा (2)। 40 कहते हैं कि राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी जिसमें घोषणा की जाएगी कि एस के प्रावधान। 41 करेंगे।

अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से लागू होता है। अनुभाग 41 (1) अधिनियम में कहा गया है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर सभी कॉलेज जो हैं एस के तहत विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में भर्ती। 5 (3) और भीतर के सभी कॉलेज उक्त क्षेत्र जो इसके बाद विश्वविद्यालय से संबद्ध हो सकता है, प्रतिकूल होगा।

विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित महाविद्यालय। उप-धारा (4) में कहा गया है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर घटक महाविद्यालय और अन्य संस्थानउस संबंध में बनाए जाने वाले कानूनों द्वारा शासित किया जाएगा।

धारा 51 ए (1) (बी) यह अधिनियमित करती है कि शिक्षण का कोई भी सदस्य अन्य शैक्षणिक और किसी संबद्ध महाविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बर्खास्त या हटा दिया जाएगा या प्रक्रिया के अनुसार पूछताछ के बाद को छोड़कर रैंक में कमी

सी. एल. में निर्धारित। (क) और उस पर लगाए जाने वाले दंड को अनुमोदित किया जाता है कुलपति या विश्वविद्यालय का कोई अन्य अधिकारी जो कुलपति द्वारा अधिकृत हो।

इस ओर से कुलाधिपति। इसी तरह सी. एल. (ख) उप-धारा (2) के लिए अपेक्षित है कि ऐसी समाप्ति को कुलपति या किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस संबंध में कुलपति द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय। धारा 52 क (1)

अधिनियमित करता है कि शासी निकाय और चाय के किसी भी सदस्य के बीच कोई भी विवाद चिंग और अन्य कर्मचारी, शासी निकाय या सदस्य के अनुरोध पर संबंधित को एक सदस्य वाले मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा जाएमहाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा नामित, एक सदस्य द्वारा नामित संबंधित सदस्य और कुलपति द्वारा नियुक्त एक अंपायर।

संविधान के अनुच्छेद 29 (1) में कहा गया है कि नागरिकों का कोई भी वर्ग भारत के क्षेत्र में या उसके किसी भाग में रहने वाली, जिसकी कोई विशिष्ट भाषा हो। अपनी लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। लेख 30 (1) यह अधिनियमित करता है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है।

शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने में खंड (2) के तहत राज्य को आदेश दिया गया है किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव न करना कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के तहत, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।

परिच्छेद 32 के तहत एक याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार था और साथ ही संबद्धता का भी अधिकार था। द पेटी

याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी।

दूसरी ओर प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 29 और 30 हैं पारस्परिक रूप से अनन्य, कि संबद्धता का कोई मौलिक अधिकार नहीं था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मांग या मान्यता। कि ए संबद्धता या मान्यता को मान्यता के लिए निर्धारित शर्तों के अनुरूप होना चाहिए कि जब तक कोई कानून या विनियमन पूरी तरह से विनाशकारी नहीं है अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों का अधिकार प्रभावित होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

और अंत में यह कि न्यायालय को विवादित प्रावधानों को निरस्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उन धाराओं के अनुसरण में क़ानून या अध्यादेश बनाए जाने तक इंतजार करना चाहिए। पकड़ना:

द्विवेदी, जे. : अनुच्छेद 29 (1) के तहत अधिकार की सामग्री की सामग्री से अलग है, अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार

पूर्ण न्यायालय द्वारा संबद्धता का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन स्थापित करने के अधिकार के सार्थक प्रयोग के लिए मान्यता या संबद्धता आवश्यक है और शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करना।

बहुमत से: (रे, सी. जे., पालेकर, जगमचन रेड्डी, खन्ना, मैथ्यू, चैनद्रचूड़ और अलगिरिस्वामी जे. जे.) धारा 35 ए अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं हो सकती है।

भीख माँगें। जे: धारा 33 ए अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगी। ' द्विवेदी, जे. : धारा 33 ए (1) (ए) अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन है।

बहुमत से: (रे सी. जे., पालेकर, जगनमोहन रेड्डी, खन्ना, मैथ्यू, चैन

द्रचूड़ और अलगिरिस्वामी। जे. जे) धारा 40 और 41 अनिवार्य नहीं हो सकती है। अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए आवेदन। बेग, जे। : धारा 40 और 41 का उल्लंघन होगा।

संस्थान जब तक कि वे संबद्धता का विकल्प नहीं चुनते। द्विवेदी, जे. : धारा 40 और 41 पर कोई वैध आपत्ति नहीं ली जा सकती थी।

बहुमत से (रे सी. जे., पालेकर, जगनमोहन रेड्डी, खन्ना, मैथ्यू, चंद्रचूड़ और अलगिरिस्वामी, जे. जे.) धारा 51 (ए) (1) और (2) और धारा 52 ए अल्पसंख्यक संस्थानों में लागू नहीं हो सकता है।

जे. बेग ने अपने विचार पर विचार करना वास्तव में आवश्यक नहीं समझा।

अधिनियम की धारा 51 ए (1) और (2) और धारा 52 (ए) की वैधता, लेकिन यह मानने के बाद कि ऐसा करना आवश्यक था, इन प्रावधानों को एस. टी., एक्स. ए. वी. ई. आर. एस. कॉलेज v. गुजरात।

द्विवेदी, जे. : धारा 51 ए और 52 ए संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन नहीं करते हैं। संविधान। रे सी. जे. और पालेकर, जे।

आर्ट पढ़ना गलत होगा। 30 (1) अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सीमित करने के रूप में केवल मामलों के लिए अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन जहाँ ऐसे संस्थान भाषा, लिपि या संस्कृति से संबंधित हैं। अल्पसंख्यक। अगर कला का दायरा। 30 (1) शिक्षा की स्थापना और प्रशासन करना है

अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थान, यह प्रदान करेगा कला. 30 अनावश्यक। यदि कला के तहत अधिकार। 29 (1) और 30 (1) तब समान हैं

परिणाम यह होगा कि नागरिकों का कोई भी वर्ग, जरूरी नहीं कि भाषाई हो या धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा अपनी पसंद की संस्थाएं। कला का दायरा। 30 भाषाई या धार्मिक पर निर्भर करता है अल्पसंख्यकों और भारत के नागरिकों के किसी अन्य वर्ग को ऐसा अधिकार नहीं है। अगर कला का दायरा। 30 (1) अनुच्छेद 29 (1) के तहत अधिकार का विस्तार किया गया है धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार उनकी धार्मिक शिक्षाओं या सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान करने के लिए, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार उनकी पसंद को छीन लिया जाएगा। [191CG]

केरल शिक्षा विधेयक 1957 [1959] एस. सी. आर. 995 और रेव. फादर प्रोस्ट वी. बिहार राज्य [1969] 2 एस. सी. आर. 73 संदर्भित।

(2) इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि कोई मौलिक नहीं है। अल्पसंख्यक संस्थान का संबद्धता का अधिकार। ए. एफ. आई. के लिए नियामक उपाय शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकरूपता, दक्षता और उत्कृष्टता के लिए अनुबंध हैं और

अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करें। 30 . [193 सी; 194 डी]

(3) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रशासकों को दिया गया अधिकार अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान एक पूर्ण अधिकार नहीं हैं। यह अधिकार विनियमन से मुक्त नहीं है। जिस तरह मुख्य के लिए नियामक उपाय आवश्यक हैं इसी तरह अल्पसंख्यक संस्थानों के शैक्षिक चरित्र और विषय-वस्तु को कम करना।

सुव्यवस्थित, कुशल और सुदृढ़ विज्ञापन सुनिश्चित करने के लिए नियामक उपाय आवश्यक हैं। मंत्रालय। [194 जी-एच]केरल शिक्षा विधेयक 1957 [1959] एस. सी. आर. 995 का उल्लेख किया गया है।

(4) एस के प्रावधान। 33 ए (1) (ए) अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं हो सकता है।

इस धारा के प्रावधानों का प्रबंधन को विस्थापित करने का प्रभाव पड़ता है और इसे एक अलग एजेंसी पर भरोसा करना। प्रशासन का अधिकार आचरण का अधिकार है और संस्था के मामलों का प्रबंधन करना। इस अधिकार का प्रयोग एक निकाय के माध्यम से किया जाता है। जिन व्यक्तियों में संस्था के संस्थापकों को विश्वास और विश्वास है और

जिनके पास उस क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता है। प्रशासन का अधिकार इसके अधीन है - अनुमेय नियामक उपाय। अगर प्रशासन में सुधार करना है तो एजेंसी या मौजूदा प्रबंधन के माध्यम से

किया जाना चाहिए इसे विस्थापित करके नहीं। प्रशासन के अधिकार पर प्रतिबंध केवल आम जनता के हित में प्रस्तुत किया गया है न कि और के हित में

संबंधित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लाभ के लिए प्रभावित होगा प्रशासन में स्वायत्तता। [198 जी; 198 एच-199 ए; 199 डी-ई]

(5) एस में निहित प्रावधान। 33 ए (1) (बी) अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं हो सकता है संस्थाएं। [199 एचजे

(6) अधिनियम की धारा 40 का अल्पसंख्यकों पर कोई अनिवार्य अनुप्रयोग नहीं हो सकता है संस्थान क्योंकि यह प्रशासन करने के उनके मौलिक अधिकार को छीन लेगा अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान। जैसे ही अदालत, जो एक है विश्वविद्यालय के अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि शिक्षण और प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाए, एस के प्रावधान। 41 अधिनियम लागू होता है। यह सच है कि विश्वविद्यालय की अदालत द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है

एस के तहत। 40 ; लेकिन शक्ति का उपयोग अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में किया जा सकता है। एक बार ऐसा करने पर अल्पसंख्यक संस्थान तुरंत घटक बन जाएंगे।पैर। एस का वास्तविक निहितार्थ। 40 अधिनियम का यह है कि शिक्षण और प्रशिक्षण

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा। [197 सी-ई; जी]आई.

(7) चूँकि धारा 40 और 41 एक साथ लटकती हैं, अधिनियम की धारा 41 में कोई नहीं हो सकता है अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अनिवार्य अनुप्रयोग। अधिनियम की धारा 41 है - एस के लिए उपसंहार। 40 अधिनियम से। चूंकि एक संबद्ध कॉलेज एक घटक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर. बन जाता है।

एस के अर्थ के भीतर कॉलेज। 41 अधिनियम के अनुसार, यह विश्वविद्यालय में एकीकृत हो जाता है। एक घटक महाविद्यालय अपने पूर्व व्यक्तिगत चरित्र को बरकरार नहीं रखता है। अब और इसका अल्पसंख्यक चरित्र खो जाता है। [198 ई]

(8) अधिनियम की धारा 51 ए अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं हो सकती है। उपकुलपति की मंजूरी का उद्देश्य प्रशासन पर रोक लगाना हो सकता है। एस में निहित प्रावधान। 51 ए (बी) को परमिस नहीं कहा जा सकता है।

व्यापक नियामक उपाय क्योंकि यह उपाध्यक्ष को एक विरोधाभासी शक्ति प्रदान करता है

कुलाधिपति अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन के अधिकार को छीन लेंगे।

[200 सी]

(9) एस में निहित प्रावधान। 52 ए अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं हो सकता है। मध्यस्थता का संदर्भ शैक्षणिक संस्थानों के भीतर मुकदमेबाजी के विवाद का एक क्षेत्र पेश करेगा। शासी निकाय का अपना घरेलू अधिकार क्षेत्र होता है जिसे विस्थापित किया जाएगा और प्रशासन में एक नया अधिकार क्षेत्र बनाया जाएगा।

[200 डी-ई]

जगनमोहन रेड्डी और अलगिरिस्वामी, जे. जे.

(1) कला के तहत अधिकार। 30 वैक्यू में अभ्यास नहीं किया जा सकता है। न ही ऐसा होगा।

द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों के रूप में संबद्धता या मान्यता को संदर्भित करने का अधिकार

कला के तहत अधिकार का सार्थक अभ्यास। 30 (1) इसमें अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की मान्यता शामिल होगी और अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिसके बिना अधिकार केवल एक भूसी होगा। इस न्यायालय ने लगातार प्रहार किया है

समतुल्य शर्तों पर संबद्धता या मान्यता बनाने के सभी प्रयासों को कम करें

कला के तहत अपने अधिकारों का समर्पण। 30 (1) उन अधिकारों को कम करना या छीनना।

पुनः, जैसा कि संबद्धता के बिना अधिकार का कोई सार्थक प्रयोग नहीं हो सकता है कला के तहत। 30 (1) दी जाने वाली संबद्धता उस अधिकार के अनुरूप होनी चाहिए।

न ही यह अप्रत्यक्ष रूप से वह हासिल करने की कोशिश कर सकता है जो वह सीधे नहीं कर सकता है। [211 ई-जी]

री. केरल एजुकेशन ब्ल! 1957 [1959] एससीआर 995। केरल राज्य बनाम। बहुत रेव. मदर प्रोविंशियल आदि [1971] 1 एस. सी. आर. 734 और डी. ए. वी. कॉलेज आदि।

वी. पंजाब राज्य और अन्य। [1971] सप. इसके बाद एस. सी. आर. 688 आया।

(2) एकमात्र उद्देश्य जो कला के तहत मौलिक अधिकार है। 30 (1) यह काम करेगा कि अल्पसंख्यक अपने संस्थानों की स्थापना कर सकें, अपना पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकें, अपनी पसंद के विषयों में निर्देश प्रदान कर सकें, परीक्षा राष्ट्रों का संचालन कर सकें और डिग्री या डिप्लोमा प्रदान कर सकें। ऐसे संस्थानों को अपनी डिग्री और डिप्लोमा के लिए मान्यता प्राप्त

करने और सहायता मांगने का अधिकार है, जहां उनके द्वारा प्राप्त उत्कृष्टता के आधार पर समान शिक्षा देने वाले अन्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता दी जाती है। राज्य उनकी योग्यताओं और संस्थानों को मान्यता देने के लिए बाध्य है और डिग्री की मान्यता के रूप में उनके शैक्षिक मानकों में उत्कृष्टता की कमी के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

या शैक्षिक योग्यता का संबंध है और कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है

जहाँ तक सहायता की बात है। [212 ई-एफ]

खन्ना, जे.

कला। 30 इसमें सी. एल. से आयातित किसी भी सीमा को पढ़कर। (1) कला की। 29. अनुच्छेद 29 (1) नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखने का अधिकार देता है। इस खंड को लागू करने के लिए यह नहीं है यह आवश्यक है कि नागरिकों का वर्ग अल्पसंख्यक होना चाहिए। इसके विपरीत

वह, कला द्वारा प्रदत्त अधिकार। 30 (1) केवल उन अल्पसंख्यकों पर है जो या तो धर्म या भाषा पर आधारित हैं। कला का खंड (1)। 30 इसमें "उनकी पसंद के" शब्द शामिल हैं। ये शब्द जो "शैक्षणिक संस्थानों" को योग्य बनाते हैं, वे उस विशाल विवेक और विकल्प को दर्शाते हैं जो अल्पसंख्यकों के पास उन संस्थानों के प्रकार का चयन करने में है जिन्हें वे स्थापित करना चाहते हैं। यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की जाती है, तो ऐसी संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दोनों कला के अंतर्गत आता है। 29 (1) साथ ही कला के तहत भी। 30 (1) . ऐसी संस्था की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की गारंटी कला द्वारा दी जाती है। 30 (1) और यह तथ्य कि ऐसी संस्था अल्पसंख्यक समुदाय की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण नहीं करती है, इसे कला के दायरे से बाहर नहीं ले जाएगी। 30 (1) . [238 डी-एच]

(2) अनुच्छेद 25 से 30 का उद्देश्य धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करना, उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखना और उन्हें राजनीतिक विवाद के उतार-चढ़ाव से दूर करना था। इन प्रावधानों में एक उपयुक्त एसटी को शामिल किया गया था।

देश के संविधान में अल्पसंख्यकों को शपथ, जिनके सबसे बड़े बेटे ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। . जब तक संविधान आज है, तब तक उन अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ऐसा करने का कोई भी प्रयास केवल आस्था के हनन का कार्य नहीं होगा, यह होगा।

संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य और द्वारा निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी अदालतें।

यद्यपि संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्दों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि हमारे संविधान निर्माता ऐसे राज्य की स्थापना चाहते थे। संविधान के प्रावधानों को तदनुसार तैयार किया गया था। वहाँ है।

राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र में कोई रहस्यवाद नहीं है। धर्मनिरपेक्षता न तो विरोधी है

राज्य के मामलों से भगवान को हटा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नहीं होगा धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, [224 ए-सी]

अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार देने का विचार दयालु होना नहीं है। आबादी के एक विशेषाधिकार प्राप्त या लाड़ले वर्ग का लेकिन अल्पसंख्यकों को देने के लिए

सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास की भावना। तब से भारत के महान नेता

अनादिकाल से सहिष्णुता और कैथोलिक दर्शन के सिद्धांत का प्रचार किया गया था। वे महान विचार संविधान में निहित थे। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों को असमानता पैदा करने के लिए नहीं बनाया गया था। इनका वास्तविक प्रभाव अल्पसंख्यक संस्थाओं के संरक्षण को सुनिश्चित करके समानता लाना था।

प्रशासन के मामले में अल्पसंख्यकों को स्वायत्तता की गारंटी देना उन संस्थाओं से। अल्पसंख्यकों को देकर उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार

विशेष अधिकारों का उद्देश्य एक संतुलन लाना है, ताकि समानता के आदर्श को केवल एक अमूर्त विचार तक सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह एक जीवित वास्तविकता बन जानी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप न केवल सिद्धांत में, बल्कि सिद्धांत में भी सच्ची, वास्तविक समानता, एक समानता हो। तथ्य। वयस्क मताधिकार की प्रणाली में बहुमत को शायद ही किसी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह अपनी देखभाल कर सकता है और अपने हितों की रक्षा कर सकता है। माजो द्वारा वांछित कोई भी उपाय

रियायत को बिना किसी कठिनाई के क़ानून की किताब में लाया जा सकता है क्योंकि माजो

निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस तरह का जनादेश देकर ऐसा किया जा सकता है। केवल अल्पसंख्यकों को ही सुरक्षा की आवश्यकता है, और कुछ अन्य के अलावा अनुच्छेद 30

लेख, उस सुरक्षा को वहन करने और गारंटी देने के लिए है। [224 एफ-एच]

(3) राज्य के लिए उचित विनियम निर्धारित करने और बनाने की अनुमति है

यह एक अल्पसंख्यक संस्थान की मान्यता या संबद्धता के अनुसार एक पूर्ववर्ती शर्त है। हालाँकि, मान्यता या संबद्धता के लिए ऐसी शर्तें निर्धारित करने की अनुमति नहीं है जो

अल्पसंख्यक या उनके शैक्षणिक संस्थानों को आशीर्वाद देने और प्रशासित करने के अधिकार को बाधित करती हैं। कला में संबद्धता और मान्यता का उल्लेख नहीं है। 30 (1) . स्थिति यह बनी हुई है कि जब तक अल्पसंख्यक उन संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार का समर्पण नहीं करते हैं, तब तक अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता देने या उनसे संबद्ध करने से इनकार करने से कला द्वारा बताए गए अधिकार को प्रदान करने का प्रभाव पड़ेगा। 30 (1) पूरी तरह से भ्रमपूर्ण और वास्तव में एक चिढ़ाने वाला भ्रम होना। एक शैक्षणिक संस्थान शायद ही किसी उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है या किसी भी व्यावहारिक उपयोगिता को तब तक लागू कर सकता है जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध न हो या अन्य शैक्षणिक संस्थानों की तरह मान्यता प्राप्त न हो। कला द्वारा प्रदत्त अधिकार। 30 यह एक वास्तविक और सार्थक अधिकार है। अनुच्छेद 30 (1) का उद्देश्य वास्तविक महत्व रखना था और इसका इस तरह से अर्थ लगाना अनुज्ञेय नहीं है जिससे इसका महत्व कम हो जाए। [240 ए-सी]

री. केरल शिक्षा विधेयक 1957, [1959] एस. सी. आर. 995 का उल्लेख किया गया है।

(4) यह तर्क कि जब तक कानून पूरी तरह से मिनोरी के अधिकार का विनाशकारी नहीं है

कला के तहत संबंध। 30 (1) यह अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो असमर्थनीय है और कला की साधारण भाषा के विपरीत है। 13 . वह कानून जो किसी शासी निकाय या प्रबंधन परिषद के अल्पसंख्यक सदस्यों के चयन में हस्तक्षेप करता है, कला द्वारा गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन होगा। 30 (1) . [241 बी-सी] री. केरल शिक्षा विधेयक, 1957, [1959] एस. सी. आर. 995, सिद्धजभाई साराभाई बनाम। बॉम्बे राज्य [1963] 3 एस. सी. आर. 837; आर टी। रेव बिशप एस. के. पात्रो और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य। [1970] 1 एस. सी. आर 172; केरल राज्य बनाम। बहुत रेव. मदर प्रोविंस सियाल [1971] 1 एस. सी. आर. 734; डी. ए. वी. कॉलेज बनाम पंजाब राज्य [1971] सप. इसके बाद एस. सी. आर. 688 आया।

(5) धारा 33 ए जो प्रबंधन के लिए एक नए शासी निकाय का प्रावधान करती है

जहाँ तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का संबंध है, कॉलेज और चयन समितियों के साथ-साथ उनके गठन को भी कला के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया जाना चाहिए। 30 (1) . [242 ए-बी]

(6) वह कानून जो अल्पसंख्यक समुदाय के योग्य शिक्षकों की पसंद में हस्तक्षेप करता है या

शिक्षकों और संस्थान के कर्मचारियों के अन्य सदस्यों पर इसका अनुशासनात्मक नियंत्रण कला का उल्लंघन करने के रूप में शून्य है। 30 (1) . [242 जी]

13 - एल 131 सुप सी. आई./75 इरा

178

रेव. सिद्धजभाई भाई और अन्य। वी. बॉम्बे राज्य और ए. एन. आर. [1963] 3 एससीआर

और आर. रेव. बिशप एस. के. पात्रो और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य। [1970] 1 एससीआर 172 .

(7) राज्य और उसके शैक्षणिक प्राधिकरणों के लिए यह निर्धारित करने की अनुमति है

शिक्षकों की योग्यताएँ, लेकिन एक बार जब अपेक्षित योग्यता रखने वाले शिक्षकों का चयन अल्पसंख्यकों द्वारा उनके शैक्षणिक संस्थानों के लिए किया जाता है, तो राज्य को उन शिक्षकों के चयन पर वीटो करने का कोई अधिकार नहीं होगा। एक शैक्षणिक संस्थान के लिए शिक्षकों का चयन और नियुक्ति एक शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन के अधिकार के आवश्यक तत्वों में से एक है और अल्पसंख्यकों को कला का उल्लंघन किए बिना चयन और नियुक्तियों के इस तरह के अधिकार से स्पष्ट रूप से वंचित नहीं किया जा सकता है। 30 (1) . [242 जी-एच]

(8) यद्यपि अल्पसंख्यक शिक्षाविदों के शिक्षकों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण

संस्थान शासी परिषद के पास होगा, शिक्षकों की सेवा की उचित शर्तों को ठीक करने और शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में निष्पक्ष समर्थन प्राप्त करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। ऐसे प्रावधान जिनकी गणना शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए की जाती है, उनके परिणामस्वरूप कार्यकाल की सुरक्षा होगी और इस प्रकार अनिवार्य रूप से शिक्षकों के पदों के लिए सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए बनाए गए विनियमों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के हित में माना जाना चाहिए और इस तरह वे कला का उल्लंघन नहीं करेंगे। 30 (1) . [243 ई-एफ]

(9) एस की उप-धारा (1) और (2) का खंड (ए)। 51 अधिनियम का ए जो बनाता है

किसी शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारी के सदस्य पर प्रस्तावित दंड के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर देने का प्रावधान वैध है। [243 जी]

(10) एस के प्रत्येक उपखंड का खंड (बी)। 51 ए होना चाहिए

जहां तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का संबंध है, 30 (1) कला का उल्लंघन है। [244 सी]

उन उप-धाराओं का खंड (ख) जो कुलपति को शक्ति प्रदान करता है।

और कर्मचारी के किसी सदस्य को दंड देने में किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन निकाय की कार्रवाई को वीटो करने के लिए उसके द्वारा अधिकृत विश्वविद्यालय का अधिकारी अपने शिक्षकों पर प्रबंधन निकाय के अनुशासनात्मक नियंत्रण में हस्तक्षेप करता है। इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्ति एक व्यापक शक्ति है। उस शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं और यह प्रावधान नहीं है कि प्रोवल को केवल बर्खास्तगी, हटाने, रैंक में कमी या सेवा की समाप्ति के मामले में दुर्भावनापूर्ण या उत्पीड़न या अन्य समान कारण से रोका जाना है। किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन निकाय की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कुलपति या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को ऐसी व्यापक शक्ति प्रदान करने से किसी शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने के प्रबंधन निकाय के अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। [244 ए-बी]

(11) धारा 52 ए को कला का उल्लंघन करने वाला माना जाना चाहिए। 30 (1) जहाँ तक

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान चिंतित हैं। धारा 52 ए व्यापक रूप से लिखी गई है और जैसा कि यह है, यह किसी शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारी की सेवा की शर्तों से जुड़े हर विवाद को इसके दायरे में लाएगी, चाहे वह कितना भी तुच्छ या महत्वहीन क्यों न हो। इस धारा का प्रभाव यह होगा कि किसी शैक्षणिक संस्थान की प्रबंध समिति अपने चालकों द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही की एक श्रृंखला में उलझी होगी। इस खंड के प्रावधान एक शैक्षणिक संस्थान के प्रभावी प्रशासन के चक्र में एक वक्ता के रूप में कार्य करेंगे। इस धारा में जो आपत्तिजनक है वह है कुलपति को अंपायर को नामित करने की शक्ति देना। इससे संस्थान के प्रशासन के लिए शासी निकाय के अधिकार में बाधा आएगी। [244 ई-एफ]

(12) घटक महाविद्यालयों की अवधारणा जिसकी एस. एस. में कल्पना की गई है। 40 और 41

अधिनियम में यह विचार किया गया है कि अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर पर शिक्षण केवल विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाएगा। अल्पसंख्यक महाविद्यालय अपने स्वयं के शिक्षकों के माध्यम से अध्ययन के दौरान शिक्षा प्रदान करने के हकदार नहीं होंगे। [246 जी]

(13) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के संबंध में धारा 40 और 41 अमान्य हैं।

[245 ई]

एक प्रावधान जो यह अनिवार्य बनाता है कि स्नातक पाठ्यक्रमों में शिक्षण

इसे केवल विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जा सकता है और इसे केवल विश्वविद्यालय के चाय विक्रेताओं द्वारा प्रदान किया जा सकता है जो अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। इस तरह के प्रावधान के परिणामस्वरूप उन्हें एस. टी. होना चाहिए।

XAVIERS कॉलेज वी. गुजरात

179

अल्पसंख्यक संस्थानों के परिणामस्वरूप कला का उल्लंघन होना चाहिए। 30 (1) . एक बार एस। 40 जहाँ तक अल्पसंख्यकों का संबंध है, इसे असंवैधानिक माना जाता है, वही बुराई 8 को पीड़ित करेगी। 41 क्योंकि एस। 41 केवल तभी काम कर सकता है जब एस। 40 हमले में वह बच जाता है और उसे कला का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाता है। 30 (1) . [245 सी-ई]

(14) अल्पसंख्यकों के स्थापना और प्रशासन के अधिकार को कम करना

विवादित प्रावधानों के बावजूद उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान बड़े हैं। यह तथ्य कि विवादित प्रावधानों के अनुसरण में कोई कानून या अध्यादेश नहीं बनाए गए हैं, विवादित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को रोकने में शायद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जब तक कला के तहत अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानून नहीं बनाए जाते, तब तक इंतजार करना सही तरीका नहीं होगा। 30 (1) . [247 ईजे

ओटावा बनाम के लिए रोमन कैथोलिक अलग स्कूलों के न्यासी। ओटावा कॉर्पोरा

टियन और ओआरएस। [1917] ए. सी. 76 का उल्लेख किया गया।

मैथ्यू और चंद्रचूड़, जे. जे.

(1) केवल कला पर एक नज़र। 29 (1) और 30 (1) यह दिखाने के लिए पर्याप्त होगा कि

कला। 29 (1) कला की चौड़ाई को सीमित नहीं कर सकते। 30 (1) . किसी धार्मिक व्यक्ति को अधिकार की गारंटी

या कला के तहत भाषाई अल्पसंख्यक। 30 (1) अपनी पसंद के किसी भी शिक्षा को स्थापित करने का अधिकार है। जबकि कला। 29 (1) यह न केवल एक अल्पसंख्यक को अधिकार प्रदान करता है जैसा कि इसके तकनीकी अर्थों में समझा जाता है, बल्कि शहर के एक वर्ग को भी अधिकार प्रदान करता है।

भारत के क्षेत्र में रहने वाले ज़ेंस, जो अपनी तकनीकी स्थिति में अल्पसंख्यक नहीं हो सकते हैं

अर्थ, कला के तहत अधिकार का लाभार्थी। 30 अल्पसंख्यक है, या तो धार्मिक या

भाषाई। दूसरा, जबकि कला। 29 शिक्षा को कला के रूप में नहीं देखा जाता है। 30

केवल शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन से संबंधित है।

यह हो सकता है कि किसी दिए गए मामले में दोनों ओवरलैप हो सकते हैं। जब एक भाषाई अल्पसंख्यक

अपनी भाषा के संरक्षण के लिए एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करता है, भाषाई मिनो

रिटी दोनों वस्तुओं के संरक्षण का आह्वान कर सकता है। जब कला। 30 (1) कहते हैं कि ए भाषाई अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं।

विकल्प, इसका मतलब है कि यह किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन कर सकता है। यदि एक भाषाई अल्पसंख्यक अपने संरक्षण के लिए केवल एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है

भाषा तब कला में उनकी पसंद की अभिव्यक्ति, 30 (1) व्यावहारिक रूप से लूटी जाती है।

इसका अर्थ है। [251 सी-ई; 250 एफ; 251 ए-बी] पुनः में - केरल शिक्षा विधेयक, 1957 [1959] एस. सी. आर. 995,1053; रेव. फादर डब्ल्यू.

प्रोस्ट और अन्य वी। बिहार राज्य और अन्य। [1969] 2 एस. सी. आर. 73; रेव. सिद्धजभाई

भाई और अन्य बनाम। बॉम्बे राज्य [1963] 3 एस. सी. आर. 837; आर टी। रेव. बिशप एस. के. पात्रो और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य [1970] 1 एस. सी. आर. 172 और

डी. ए. वी. कॉलेज आदि। पंजाब राज्य और अन्य। [1971] सप. एस. सी. आर. 683 निर्दिष्ट

को।

दीपेंद्र नाथ बनाम। बिहार राज्य ए. आई. आर. 1962 पटना, 101 अनुमोदित,

(2) (क) वर्षों से इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मान्यता या मान्यता के बिना

स्थापित करने के अधिकार का कोई वास्तविक सार्थक प्रयोग नहीं हो सकता है और

कला के तहत शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करना। 30 (1) . [256 एच]

पुनः में - केरल शिक्षा विधेयक 1957, [1959] एस. सी. आर. 995,1053; रेव. सिद्धजभाई

सभाई और अन्य बनाम। बॉम्बे राज्य [1963] 3 एस. सी. आर. 837,856 और डी. ए. वी. महाविद्यालय, आदि। पंजाब राज्य और अन्य। [1971] सप. एस. सी. आर. 688,709 निर्दिष्ट

को।

(ख) केरल में शिक्षा: बिल इस अदालत ने इंगित किया कि "कोई शैक्षिक नहीं

संस्थान को वास्तविक व्यवहार में राज्य की सहायता के बिना चलाया जा सकता है और

यदि उन्हें यह तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे अपने अधिकारों का समर्पण नहीं करते हैं, तो वे सामूहिक रूप से करेंगे।

वित्तीय आवश्यकताओं के कारण, कला के तहत अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए।

30 (1) . " जिस शर्त में समर्पण शामिल है वह उतना ही प्रभावी है जितना कि एक निवारक

कला के तहत अधिकार का प्रयोग। 30 (1) प्रत्यक्ष निषेध के रूप में इस प्रकार होगा

माना जाता है कि यह स्पष्ट है कि धार्मिक अल्पसंख्यक स्वेच्छा से छूट नहीं देते हैं

इसका अधिकार-इसे विशेषाधिकार के बुनियादी महत्व के कारण मजबूर किया गया है शामिल, अर्थात्, संबद्धता। [261 एच; 262 ए-बी]

(ई) यह संदेहपूर्ण है कि क्या कला के तहत मौलिक अधिकार है। 30 (1) हो सकता है

किसी स्वैच्छिक कार्य द्वारा विनिमय या समर्पण या इसे माफ किया जा सकता है।

इसका कारण यह है कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों की बहुलता में एक इकाई के रूप में निहित है, अर्थात व्यक्तियों के समुदाय में आवश्यक रूप से उतार-चढ़ाव होता है। क्या अल्पसंख्यक समुदाय के पूर्व भेजे गए सदस्य वस्तु विनिमय कर सकते हैं या अनुच्छेद के तहत अधिकार का समर्पण कर सकते हैं ताकि अपने भावी सदस्यों को एक इकाई के रूप में बांध सकें? मौलिक अधिकार जीवित पीढ़ी के लिए है। एक धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित एक शैक्षणिक संस्थान की संबद्धता के स्वैच्छिक कार्य द्वारा समुदाय के पूर्व सदस्य उस समुदाय के भावी सदस्यों के अधिकार को आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं। समुदाय के भावी सदस्य कला के तहत अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। 30 (1) उत्तराधिकार या विरासत द्वारा। [262 सी-डी]

(घ) वास्तव में हर किसी को एक ही पैकेज की पेशकश नहीं की जा रही है।

यह केवल उन लोगों की गतिविधियों पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है जिनके पास है

कला द्वारा गारंटीकृत प्रकृति का मौलिक अधिकार। 30 (1) , अर्थात्, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जो विशेषाधिकार की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में माफ किए जाने के लिए आवश्यक अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। संवैधानिक अधिकार की बात करना और फिर भी उस अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के साथ भेदभाव करना विरोधाभासी है। [264 बी-सी]

(ई) मान्यता या संबद्धता को पूरी तरह से रोकने की शक्ति नहीं है।

अपने साथ ऐसी शर्तें लागू करने की असीमित शक्ति रखें जो मौलिक अधिकारों के प्रयोग को रोकने का प्रभाव डालती हैं। मान्यता या मान्यता जैसे विशेषाधिकार प्राप्त करने की सामान्य इच्छा, जिसके बिना अल्पसंख्यकों द्वारा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित शैक्षणिक संस्थान प्रभावी रूप से उस उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे, जिसके लिए उनकी स्थापना की गई थी, को गारंटीकृत अधिकार के दमन का एक अनुदेश नहीं बनाया जा सकता है। एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन फिर भी उल्लंघन है क्योंकि एक विशेषाधिकार की शर्त के माध्यम से पूरा किया जाता है। यदि कोई विधायिका किसी सार्वजनिक लाभ या विशेषाधिकार से एक अतिरिक्त राशि जोड़ती है, जो किसी भी तर्कसंगत तरीके से लाभ की योजना के उद्देश्यों को आगे नहीं बढ़ाती है, लेकिन मौलिक अधिकार के प्रयोग को रोकती है, तो प्रतिबंध को लाभ या विशेषाधिकार से जोड़े जाने

से कोई भी संवैधानिक ताकत नहीं मिल सकती है, लेकिन इसे इस तरह मापा जाना चाहिए जैसे कि यह पूरी तरह से अलग अधिनियम था। [264 एफ-इन]

(च) लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि सामान्य कानूनों जैसे कि टैक्स के कानून द्वारा

कानून जो इसके संक्षिप्त होने के बराबर नहीं होंगे। [265 बी-सी] हडसन कंट्री वाटर कंपनी v. मैककार्टर, 209 यू. एस. 349,355,357 और ऑस्ट्रेलिया की सामान्य संपत्ति बनाम। बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स, [1950] ए. सी. 235,310 संदर्भित

(छ) ऐसे उपाय जो गतिविधियों के अन्य रूपों पर निर्देशित होते हैं लेकिन जिनके पास हैं

अधिकार पर द्वितीयक या अप्रत्यक्ष या आकस्मिक प्रभाव आम तौर पर अधिकार को कम नहीं करता है जब तक कि अधिकार की सामग्री को विनियमित नहीं किया जाता है। [265 जी]

(ज) यह विरोधाभासी लगता है कि एक ऐसा अधिकार जो संविधान निर्माता चाहते थे

निरपेक्ष होने के लिए नियमों के अधीन किया जा सकता है जो केवल राज्य की आवश्यकता के अस्पष्ट और लोचदार परीक्षण को पूरा करने की आवश्यकता है। संविधान के भाग III में इस अधिकार को अन्य मौलिक अधिकारों के विपरीत पूर्ण रूप से शामिल करने का उद्देश्य इसे राजधर्म की पहुंच से वापस लेना था। आज के अधिकार को राज्य की आवश्यकता की प्रोटियन अवधारणा द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन करना, जैसा कि बहुमत द्वारा कल्पना की गई थी, उस शुद्ध मुद्रा को नष्ट करना होगा जिसके लिए अधिकार दिया गया था। [266 ई-एफ]

(i) मान्यता या संबद्धता एक ऐसी सुविधा है जिसे विश्वविद्यालय किसी को प्रदान करता है।

छात्रों को बैठने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थान

अ.

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विषयों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री प्राप्त करने के लिए और इसलिए, यह अभिनिर्धारित करना तर्कसंगत है कि कोई भी विनियमन जो उद्देश्य से असंबंधित है, लागू नहीं किया जा सकता है। यदि मान्यता या संबद्धता के अलावा किसी धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा संचालित किसी शैक्षणिक संस्थान को सहायता प्रदान की जाती है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे दिया जाता है, आगे के नियमों की अनुमति होगी। इस मामले का सार यह है कि किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित कोई भी शैक्षणिक संस्थान विधायिका या विश्वविद्यालय द्वारा नियमों से पूर्ण प्रतिरक्षा का दावा

नहीं कर सकता है यदि वह संबद्धता या मान्यता चाहता है; लेकिन अनुमेय नियमों का चरित्र उनके उद्देश्य पर निर्भर करना चाहिए। [267 बी-डी] एसटी।

XAVIERS कॉलेज वी. गुजरात

181

(3) हर मामले में जब किसी विनियमन की तर्कसंगतता सामने आती है

न्यायालय के समक्ष विचार करने के लिए, यह प्रश्न पूछा और उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या विनियमन की गणना अल्पसंख्यक समुदाय की सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए एक वाहन के रूप में संस्थान की मान्यता या संबद्धता के उद्देश्य को कम करने के लिए की गई है या प्रभावी रूप से कम करेगा और

को

अन्य व्यक्ति जो इसका सहारा लेते हैं। यह प्रश्न कि क्या कोई विनियमन जनता के सामान्य हित में है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, यदि यह उत्कृष्टता को आगे नहीं बढ़ाता है

पूर्व परिकल्पना के रूप में सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए एक वाहन के रूप में संस्थान

केवल अनुमेय नियम वे हैं जो नियम की प्रभावशीलता को सुरक्षित करते हैं। सुविधा की स्थिति अर्थात् शैक्षणिक संस्थानों की उत्कृष्टता

उनके शैक्षिक मानकों का सम्मान करना। [267 ई-एफ]

सिद्धजभाई बनाम। बॉम्बे राज्य, [1963] 3 एस. सी. आर. 837,856-857; पुनः में - केरल

शिक्षा विधेयक 1957 [1959] एस. सी. आर. 995,1953 और केरल राज्य बनाम। माँ।

प्रांतीय [19711 1 एस. सी. आर. 734 संदर्भित।

(4) एस की उप-धारा 1 (ए) और 1 (बी) के प्रावधान। 33 ए एब्रिज दाएँ

धार्मिक अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करना और इसलिए उनकी पसंद। आवश्यकता है कि महाविद्यालय में एक शासी निकाय होना चाहिए

शासी निकाय का गठन करने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों सहित

यीशु के समाज का प्रभाव उस शरीर को उसके अनन्य अधिकार से वंचित करने का है

शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन करें। मलाड को रोकने की आड़ में

विश्वविद्यालय द्वारा गठित महाविद्यालय के शासी निकाय का अधिकार

संस्था के प्रशासन के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों को हटाया नहीं जा सकता है। द.

►

प्रावधान का प्रभाव यह है कि धार्मिक अल्पसंख्यक वस्तुतः अपना अधिकार खो देते हैं

इसने जिस संस्थान की स्थापना की है उसका प्रशासन करें। [269 जी-एच; 270 बी] केरल बनाम, मदर प्रोविंशियल [1971] 1 एस. सी. आर. 734 740 पर, डब्ल्यू. प्रोस्ट बनाम। बिहार (1969) 2. एस. सी. आर. 73 77-78 और रेव. बिशप एस. के. पात्रो बनाम। बिहार [1970) 1 एस. सी. आर. 172.

(5) यह एक कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों पर निर्भर करता है कि एक शैक्षणिक संस्थान का लहज़ा और स्वभाव क्या है। उन पर इसकी प्रतिष्ठा, अनुशासन का रखरखाव और शिक्षण में इसकी दक्षता निर्भर करेगी। प्रधानाचार्य चुनने और उनके दृष्टिकोण और दर्शन के समग्र मूल्यांकन के बाद प्रबंधन द्वारा नियुक्त शिक्षकों द्वारा शिक्षण का संचालन करने का अधिकार शायद एक शैक्षणिक संस्थान को प्रशासित करने के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि प्राचार्य की भर्ती के लिए या विभाग के प्रमुख के आग्रह के लिए चयन समिति में होना चाहिए, इसके अलावा विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि शिक्षण कर्मचारियों के सदस्यों की भर्ती के लिए चयन समिति में होना चाहिए। जब तक चुने गए व्यक्तियों के पास विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यताएँ हैं, तब तक चुनाव प्रबंधन पर छोड़ दिया जाना चाहिए। [270 जी-एच]

(6) एस के सादे शब्दों पर। 40 यह स्पष्ट है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का शासी निकाय सबसे महत्वपूर्ण कार्य से वंचित रहेगा।

महाविद्यालय के प्रशासन के अपने अधिकार के लिए, अर्थात् अध्ययन के पाठ्यक्रम में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुदेश जिसके संबंध में विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम है। अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को प्रशासित करने के अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों द्वारा इस प्रकार स्थापित संस्थानों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अध्ययन के पाठ्यक्रमों में निर्देश देने का प्राथमिक अधिकार शामिल है। यदि प्रशासन के अधिकार के इस मूल घटक को अल्पसंख्यकों से छीन लिया जाता है और विश्वविद्यालय में निहित किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कला के

तहत गारंटीकृत शैक्षणिक संस्थान को प्रशासित करने का अधिकार है। 30 (1) ले जाया जाता है। [271 जी-एच]

(7) यदि एस। 40 यह अति अधिकार कला है। 30 (1) एस. 41 जो, विधान की वर्तमान योजना में एस पर निर्भर है। 40 जीवित नहीं रह सकते। [272 डी]

(8) एस के उपखंड (1) (बी) और (2) (बी) में निहित प्रावधान। 51 ए कला के तहत अधिकार का उल्लंघन है। 30. प्रबंधक और एक शिक्षक के बीच का संबंध एक नियोक्ता और कर्मचारी का होता है और यह किसी से भी आगे निकल जाता है।

यह समझते हुए कि प्रबंधन एक शिक्षक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर. की सेवाओं को समाप्त नहीं कर सकता है।

182

रोजगार अनुबंध के आधार पर। समाप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता है

जाँच के बाद एक शिक्षक की सेवाएँ प्रबंधन द्वारा आयोजित की गई हैं।

कुलपति या किसी बाहरी एजेंसी की मंजूरी होनी चाहिए।

उसका नामांकित व्यक्ति शिक्षा का प्रशासन करने के उसके अधिकार का संक्षिप्तकरण होगा। संस्था। उप-धारा 1 (बी) और 2 (बी) के तहत कोई बाध्यता नहीं है कि

कुलपति या उनके मनोनीत व्यक्ति को अस्वीकृति का कोई भी कारण बताना चाहिए। ए.

प्रबंधकों की कार्रवाई को अस्वीकार करने के लिए बिना किसी दिशानिर्देश के कंबल शक्ति यह निश्चित रूप से प्रबंधन के बर्खास्त करने के अधिकार का अतिक्रमण करेगा या

पूछताछ के बाद एक शिक्षक की सेवाओं को समाप्त कर दें। [273 एफ; 273 सी-ई]

(9) धारा 52 ए अल्पसंख्यकों पर लागू होने में गलत है। प्रावधान कोन

इस खंड में कोई प्रस्ताव नहीं है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह होगा संस्थान के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना। प्रत्येक

शिक्षक या गैर-शिक्षक कर्मचारी के सदस्य द्वारा उठाया गया छोटा विवाद

यदि यह सेवा शर्तों को छूता प्रतीत होता है तो मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

मध्यस्थता, शिक्षा प्रदान करना नहीं, शिक्षा का व्यवसाय बन जाएगा।

राष्ट्रीय संस्थान। [274 - बी]

बी. ई. जी., जे. (1) यद्यपि अनुच्छेद 29 और 30 एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं

अल्पसंख्यकों के कुछ अधिकारों का अभी भी संबंध है, संविधान का अनुच्छेद 29

किसी भी तरह से लागू नहीं करता है। शिक्षा के प्रकार या चरित्र की एक सीमा जिसे कोई अल्पसंख्यक अपने बच्चों को अपनी संस्था के माध्यम से प्रदान करने का विकल्प चुन सकता है।

अपने सदस्यों या अन्य लोगों के लिए जो अपने बच्चों को इसके स्कूलों में भेजने का विकल्प चुन सकते हैं।

[274 ई-एफ]

(2) भले ही संविधान के अनुच्छेद 30 (1) को निरपेक्ष और

अल्पसंख्यक संस्थानों पर प्रबंधन के निरंकुश अधिकार, केवल इसके अधीन

स्वास्थ्य और कानून के हित में बिल्कुल न्यूनतम और नकारात्मक नियंत्रण और आदेश, यह विनियमन की एक बड़ी डिग्री को बाहर करने के लिए नहीं किया जा सकता है और

नियंत्रण जब एक अल्पसंख्यक संस्थान सामान्य धर्मनिरपेक्षता के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करता है

और गैर-सांप्रदायिक शिक्षा, बड़े पैमाने पर ऐसे शिक्षकों को नियुक्त करती है जो नहीं हैं

उन लोगों द्वारा भुगतान किए गए शुल्क से इसकी आय जो विशेष के सदस्य नहीं हैं विचाराधीन अल्पसंख्यक। नियंत्रण की इस तरह की अधिक डिग्री को उचित ठहराया जा सकता है

प्रबंधन से प्रभावित लोगों के हितों को सुरक्षित करने की आवश्यकता

अल्पसंख्यक संस्थान और यह जो शिक्षा प्रदान करता है लेकिन जो सदस्य नहीं हैं

प्रबंधन में अल्पसंख्यक। . जहाँ एक अल्पसंख्यक संस्थान ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से, एक क़ानून की शर्तों के तहत संबद्धता का विकल्प चुना है, वहाँ यह माना जाना चाहिए कि

त्याग करने के लिए चुना गया, संबद्धता के परिणामस्वरूप होने वाले लाभों की कीमत के रूप में,

कुछ अधिकारों का प्रयोग जो एक अन्य संदर्भ में अनुचित प्रतीत हो सकते हैं

अपने मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुँचाया। यदि किसी अधिनियम का उद्देश्य

एक अल्पसंख्यक संस्थान को, यहां तक कि अप्रत्यक्ष रूप से भी, इसके अभ्यास को छोड़ने के लिए मजबूर करना है। मौलिक अधिकार जिन प्रावधानों का यह प्रभाव है, वे अमान्य या अमान्य होंगे। एक अल्पसंख्यक संस्थान के खिलाफ सक्रिय। संबद्धता की कीमत एक नहीं हो सकती है

अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का पूर्ण परित्याग संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त। [291 एच; 275 डी-ई]

(3) संबद्धता केवल एक वैधानिक है और मिनो का मौलिक अधिकार नहीं है

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत इस अनुच्छेद के तहत अधिकार नहीं हो सकता है।

जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि कॉलेज का आवेदन का उल्लंघन किया गया है

क्योंकि स्वायत्तता को अस्वीकार किया गया है या किया जाना तय है। कॉलेज को मजबूर करना

विश्वविद्यालय का एक घटक हिस्सा बनना इसके हिस्से को छीनने के बराबर है

कानून के बल द्वारा अलग पहचान। लेकिन अगर कॉलेज ने वास्तव में हासिल किया है संगठन और उत्कृष्टता के ऐसे मानक जो उसने करने का दावा किया है, वह कर सकता है

(4) एस के रूप में जितना। 5 याचिका दायर करने वाले कॉलेज को कानून से पूरी तरह से बाहर रखने के विकल्प से इनकार करने से अधिनियम का एक सम्मोहक प्रभाव पड़ता है, धारा इसके खिलाफ निष्क्रिय होगा। धारा 5 (1) में बाध्य करने का प्रभाव है

गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता के लिए एक मूल्य के रूप में संविधान क्योंकि यह है की मंजूरी के बिना किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध होने की अनुमति नहीं

सरकार। [277 ए; 276 जी]

(5) एकमात्र प्रावधान जो इसके खिलाफ बाध्यकारी प्रभाव डाल सकते हैं

याचिका दायर करने वाला कॉलेज एस हो सकता है। 5 और फिर धारा 40 और 41 जो स्वचालित रूप से संबद्ध कॉलेजों को विश्वविद्यालय, अनुसूचित जनजाति के घटक कॉलेजों में परिवर्तित कर देगी।

XAVIERS कॉलेज v. गुजरात

183

एक विकल्प के अंतर्वेशन के बिना, और इसलिए, याचिका दायर करने वाले कॉलेज को एक स्वायत्त सह-कॉलेज बनने के अवसर से वंचित करने के लिए कहा जा सकता है। एस के प्रावधान। 40 और धारा के शेष प्रावधान। 41 अधिनियम के सभी भाग एक ही बाध्यकारी योजना या तंत्र के भाग हैं जो अनुच्छेद 30 (1) द्वारा लागू किया गया है। धारा 41 (1) याचिका दायर करने वाले कॉलेज पर और भी अधिक प्रत्यक्ष रूप से काम करती है, जिसे एस के तहत "विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में भर्ती" किया गया था। 5 (3) नफरत से। इस प्रावधान का मजबूर करने वाला प्रभाव होगा कि यह स्वतः विश्वविद्यालय की एक घटक इकाई बन जाएगी, और इसलिए, याचिका दायर करने वाले कॉलेज के खिलाफ निष्क्रिय माना जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है। [278 डी-ई; 277 बी]

(6) अधिनियम की धारा 41, जैसा कि यह है, नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

एस द्वारा प्रदत्त अधिकार। 38 अधिनियम के बी ने यांत्रिक रूप से और कानून के संचालन द्वारा संबद्ध कॉलेजों को घटक कॉलेजों में परिवर्तित कर दिया ताकि उसके बाद स्वायत्तता का कोई सवाल व्यावहारिक रूप से उत्पन्न न हो सके। (278 ई]

(7) याचिका दायर करने वाले कॉलेज द्वारा किए गए दावों पर यह बहुत संभव प्रतीत होता है

कि महाविद्यालय को एस का लाभ मिलेगा। 38 अधिनियम का बी और इसलिए विवादित धाराओं में पाए जाने वाले संबद्धता के परिणामों से बच जाएगा। यह सच है कि अधिनियम की धारा 38 बी कुछ शर्तें लगाती है जिन्हें पूरा करने में कॉलेज को कोई कठिनाई नहीं होगी। किसी भी मामले में जब तक इसका आवेदन नहीं हो जाता

स्वायत्त स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया जाता है, यह उचित रूप से शिकायत नहीं कर सकता है कि अन्य

धारा 5,40 और 41 के अलावा अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग इसके खिलाफ किया जाएगा।

यह। [288 डी-ई]

(8) संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार का सार

दान के साथ-साथ उनके शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन का। दोनों इन्हें मिलाकर किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रकार या चरित्र का निर्धारण किया जाता है।

जिसे अल्पसंख्यक को चुनने का अधिकार है। ये प्रतिरूप कहाँ हैं स्वयं एक अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया, पालन करने की आवश्यकता

ये प्रतिरूप अनुच्छेद 30 (1) द्वारा संरक्षित अधिकारों का वास्तविक उल्लंघन नहीं होंगे।

एक ऐसे मामले में जिसमें एक अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा स्वेच्छा से पैटर्न स्वीकार किया जाता है

किसी कानून द्वारा प्रदत्त लाभों का लाभ उठाने की दृष्टि से

प्रशासन के अधिकार के पूरी तरह से स्वतंत्र प्रयोग पर जोर नहीं दे सकते।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 30 (1) द्वारा संरक्षित अधिकार "निरपेक्ष" में निर्धारित किए गए हैं।

अनुच्छेद 19,25 और 26 में पाए गए व्यक्त प्रतिबंधों के बिना शब्द संविधान से। लेकिन, अगर किसी अल्पसंख्यक संस्थान के पास विकल्प खुला है

वैधानिक प्रतिबंधों से पूरी तरह से बचने के लिए, यदि यह इसके साथ छोड़ देता है, तो लाभ एक सांविधिक अधिकार की, इसके तहत अधिकार की निरपेक्षता का कोई कारण नहीं है

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) को हटा दिया गया है या संक्षिप्त कर दिया गया है। [280 बी-एफ]

(9) यह केवल तभी होता है जब क़ानून की शर्तें अनिवार्य रूप से अल्पसंख्यक को मजबूर करती हैं।

अनुच्छेद 30 (1) के तहत अपने अधिकारों के मूल को छोड़ने के लिए संस्था जो वह कर सकती है

माध्य के भीतर किसी मौलिक अधिकार को छीनने या संक्षिप्त करने के लिए राशि

संविधान का अनुच्छेद 13 (2)। [280 - एच]

(10) कुलपतियों के प्रतिनिधियों की मात्र उपस्थिति

शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सदस्यों और कॉलेज के छात्रों को आवश्यक एस द्वारा। 33 ए, प्रशासन के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं करेगा। इस तरह का "छिड़काव"

लिंग "से उस प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की अधिक संभावना है और

इससे प्रभावित सभी लोगों के लिए स्वीकार्य। एक अल्पसंख्यक संस्थान के पास अभी भी हो सकता है

शासी निकाय में बहुमत। [281 डी-ई}

(11) एस के प्रावधान। 51 ए एक अनुचित अतिक्रमण नहीं है

कला द्वारा संरक्षित अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकारों के सार पर विचार करना। 30 (1)

संविधान जिसमें चयन की स्वतंत्रता शामिल है। धारा 52 ए में ऐसा नहीं है

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत विशेष अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन

संविधान। [281 - एच]

री. केरल शिक्षा विधेयक, 1957, [1959] एस. सी. आर. 995; रेव. सिद्धराजभाई भाई और

ओआरएस। वी. बॉम्बे राज्य और ए. एन. आर. , [1963] 3 एस. सी. आर. 837 रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट

& ओआरएस। वी. बिहार राज्य और अन्य, [1969] 2 एस. सी. आर. 73; आर टी। रेव. बिशप

एस. के. पात्रो और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य।

[1970] 1 एस. सी. आर. 172 और सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर.

18 4

केरल आदि v. बहुत रेव. मदर प्रांतीय आदि, [1971] 1° एस. सी. आर. 734 संदर्भित

को द्विवेदी जे. (1) कला के तहत अधिकार की सामग्री। 29 (1) कला के तहत अधिकार की सामग्री से अलग है। 30 (1) . अनुच्छेद 29 (1) अलग लिपि, भाषा या संस्कृति रखने वाले नागरिकों के एक वर्ग के अधिकार को सुरक्षित करता है, दूसरी ओर अनुच्छेद 30 (1) किसी धार्मिक या धार्मिक व्यक्ति के अधिकार की गारंटी देता है।

एक ही।

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए। अनुच्छेद 29 (1) ब्याज को सुरक्षा प्रदान करता है: अनुच्छेद 30 (1) किसी गतिविधि को सुरक्षा प्रदान करता है।

(2) अनुच्छेद 30 (1) स्पष्ट या निहित शब्दों में, अल्पसंख्यकों के किसी विशेष प्रकार के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के अधिकार को सीमित नहीं करता है। द. एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का अधिकार निहित रूप से दो प्रकार प्रदान करता है -

विकल्प चुनें। अल्पसंख्यकों को किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने या न करने का अधिकार है। यह नकारात्मक विकल्प है। अल्पसंख्यक, किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। यह सकारात्मक विकल्प है। चुनाव हर स्वतंत्रता में निहित है। बिना विकल्प के स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं है।

इसलिए "उनकी पसंद के" शब्द केवल पेटेंट बनाते हैं जो कला में अव्यक्त है, 30 (1)। उन शब्दों का उद्देश्य पहले से निहित पसंद के क्षेत्र को बढ़ाना नहीं है।

कला द्वारा प्रदत्त अधिकार। 30 (1) . [293 एच, 294 ए-बी]

(3) संबद्धता का अधिकार: कला में आत्मीयता के अधिकार का कोई स्पष्ट अनुदान नहीं है। 30 (1) . यह जरूरी नहीं कि कला में भी निहित हो। 30 (1) . यदि संविधान निर्माताओं का इरादा संबद्धता के अधिकार को ऊपर उठाने का है

एक मौलिक अधिकार जो वे आसानी से स्पष्ट रूप से अपने इरादे व्यक्त कर सकते थे

कला में शब्द। 30. चूंकि हमारा राज्य चरित्र में धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह एक संस्थान से संबद्ध है

धार्मिक शिक्षा प्रदान करना या केवल किसी विशेष धर्मशास्त्र का शिक्षण देना।

धर्मनिरपेक्ष सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान को वह अधिकार प्रदान करें। द. कला के तहत अधिकार की सामग्री। 30 (1) दोनों प्रकार की संस्थाओं के लिए समान होना चाहिए। [294 ई-एच]

री में। केरल शिक्षा विधेयक [1959] एस. सी. आर. 995 पीपी. 1076-1077 .

(4) संबद्ध विश्वविद्यालयः कला के बाद से। 30 (1) यह संबद्धता का अधिकार प्रदान नहीं करता है कि राज्य एक संबद्धता विश्वविद्यालय रखने के लिए बाध्य नहीं है।

यह केवल एक शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक राज्य के लिए खुला है। [296Â]

(5) संविधान के भाग III के संदर्भ और योजना पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि संविधान निर्माताओं का इरादा किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को शिक्षा की स्थापना और प्रशासन के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान करने का नहीं था

संस्थाएं। यह सच है कि अनुच्छेद 30 (1) को विशाल और अयोग्य भाषा में व्यक्त किया गया है। कला भी ऐसी ही है। 14. हालाँकि, इस न्यायालय ने इस सीमा को पढ़ा है

कला की सामान्य और अप्रतिबंधित भाषा में वर्गीकरण। 14. संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान और स्वतंत्रता के प्रथम संशोधन में मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता

एस में व्यक्त व्यापार, वाणिज्य और संभोग। 92 ऑस्ट्रेलियाई संविधान, जो दोनों पूर्ण शब्दों में व्यक्त किए गए हैं, को विनियमन के अधीन माना जाता है। इन उदाहरणों के तर्क को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए पूर्ण या निकट-कला के पूर्ण शब्दों से एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा एक शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का पूर्ण अधिकार। 30 (1) . शब्दों की व्यापकता के लिए निरपेक्ष शब्द निरपेक्ष अधिकार प्रदान नहीं करते हैं।

हो सकता है कि कानून या संविधान के संदर्भ और योजना के अनुसार कटौती की गई हो, [298 ई; 296 डी; 298 सी]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। अनवर अली सरकार [1952] एस. सी. आर. 284 पी. 295, चरणजीत लाल बनाम। भारत संघ [1950] एस. सी. आर. 869 पी. 890 , कैथी रनिंग

रावत बनाम। सौराष्ट्र राज्य [1952] एस. सी. आर. 435 पी. 442 , कैंटवेल वी। कोनेक टिकट (310) यू. एस. 296 पीपी पर। 303-304 , 95 लॉ एडन, 1137 पी। 1160 , डब्ल्यू. एस. ए. वेन्स विधायी। ऑस्ट्रेलिया में कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ, दूसरा संस्करणः पी। 339 और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल और अन्य बनाम। बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स और अन्य [1950] अपील मामले 235।

(6) अनुच्छेद 29 (2), 15 (4) और 28 (3) कला में अधिकार पर कुछ स्पष्ट सीमाएँ रखते हैं। 30 (1) . इस अधिकार पर कुछ निहित सीमाएँ भी हैं। अधिकार को उन निहित सीमाओं के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। [299 सी] 18 5

£ टी. XAVIERS कॉलेज वी. गुजरात

(7) संविधान का भाग III व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है -

समूहों और कुछ अल्पसंख्यक समूहों पर। वे अधिकार हमारे संविधान में स्वतंत्रता की एक एकल, भारतीय दृश्य और संतुलन प्रणाली का गठन करते हैं। यह प्रणाली प्रत्येक मामले की आवश्यकताओं के अनुसार हमारी स्वतंत्रता का गठन करने वाले विभिन्न अधिकारों के बीच व्यवस्था और सद्भाव का तात्पर्य है। जाहिर है, संविधान निर्माताओं का कभी भी एक दूसरे के साथ टकराव का इरादा नहीं हो सकता था। एकॉर्ड 'य, कला में अधिकार। 30 (1) इसका प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि किसी नागरिक के कानूनी या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो। सभ्य व्यक्ति की स्वतंत्रता असंभव है।

समुदाय को पूर्ण अधिकार प्राप्त हों। समाज के प्रत्येक सदस्य द्वारा अपने अधिकारों का उचित आनंद लेने के लिए अधिकारों का कुछ विनियमन आवश्यक है। [299D; 300 B; DE]

(8) विनियामक शक्ति का विस्तार: विनियामक शक्ति की सीमा

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के अनुसार राज्य अलग-अलग होते हैं। यह एक वर्ग से दूसरे वर्ग के साथ-साथ एक वर्ग के भीतर भी भिन्न हो सकता है। किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को बहुसंख्यक शैक्षणिक संस्थान से अलग व्यवहार के लिए नहीं चुना जा सकता है। इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार को पूरा करने वाला एक विनियमन कला के लिए अप्रिय होगा। 30 (1) . [301 एच; 302 डी]

(9) एक वैध विनियमन का परीक्षण इसकी आवश्यकता है। कोई भी नियम जो

समाज के हितों (जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं) की रक्षा के लिए जो आवश्यक है, उससे आगे नहीं जाता है या समाज के व्यक्तिगत सदस्यों के अधिकार संवैधानिक रूप से मान्य होने चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह का विनियमन कला द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन लेता है या कम कर देता है। 30 (1) . [302 ई-एफ]

(10) आवश्यकता क्या है, यह निर्धारित करने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

सरी। प्रश्न की जांच विवादित प्रावधानों और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में की जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि विवादित कानून को विनियमित अधिकार और

सामाजिक हित या संरक्षित व्यक्तिगत अधिकार के बीच एक उचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। न्यायालय को विनियमित अधिकार के मूल्य और संरक्षित सामाजिक हित या व्यक्तिगत अधिकार के मूल्य को संतुलित करना चाहिए। इन प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करते हुए, न्यायालय को विधायी निर्णयों को उचित महत्व देना चाहिए। न्यायालय की तरह, विधानमंडल ने भी संविधान को बनाए रखने का रास्ता अपनाया है। यह लोगों की स्वतंत्रता और कल्याण का उतना ही रक्षक है जितना कि न्यायालय। यह सरकार की तात्कालिक आवश्यकताओं और समुदाय की आवश्यकताओं के बारे में न्यायालय की तुलना में अधिक सूचित है। [302 इन-एच]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। अनवर अली सरकार [1952] एस. सी. आर. 284 पी. 303 प्रति

दास I

(11) इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि एक विनियमन, होने के लिए

संवैधानिक, हमेशा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की उत्कृष्टता में सुधार के लिए गणना की जानी चाहिए। राज्य पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम को शिक्षा की उत्कृष्टता के दृष्टिकोण से उतना ही निर्धारित करता है जितना कि शिक्षा का एक समान मानक होने के दृष्टिकोण से, [303 बी-सी]

(12) न ही नियामक शक्ति को ऐसी अवधारणाओं से बाधित किया जाना चाहिए जैसे कि

" अधिकार के वास्तविक और प्रभावी प्रयोग को विनियमन द्वारा प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए या यह विनियमन कला द्वारा प्रदत्त अधिकार पर "प्रत्यक्ष रूप से और तुरंत" हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 30 (1) . अधिकार का वास्तविक और प्रभावी प्रयोग क्या है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी भी प्रतिस्पर्धी सामाजिक हित या किसी व्यक्ति के किसी भी प्रतिस्पर्धी संवैधानिक या कानूनी अधिकार की रक्षा के लिए समय, स्थान और परिस्थितियों के संदर्भ में विवादित विनियमन कितना आवश्यक है। [303) जी-एच]

रेव. सुथलभाई भाई और अन्य बनाम। बॉम्बे राज्य [1963] 3 एस. सी. आर. 837

पी पर। 850 संदर्भित किया गया।

(13) कला के तहत अधिकार। 30 (1) एक जटिल और परस्पर निर्भरता का हिस्सा है

विभिन्न सामाजिक हितों का समूह। एक स्थायी, निश्चित विज्ञापन नहीं हो सकता है।

अधिकार और उन सामाजिक हितों का न्याय। उन्हें समय-समय पर और अलग-अलग परिस्थितियों में समायोजन और पुनः समायोजन की आवश्यकता होगी। [305 एच}

धारा 33 ए (1) (ए) कला के लिए अप्रिय है। 30 (1) .

[307 ई] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर.

186

(14) चूँकि संबद्धता का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है जिसकी गारंटी

कला। 30 (1) विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में शिक्षण को संभालने में कोई कठिनाई नहीं है। किसी भी वैध आपत्ति को उप-धाराओं में नहीं लिया जा सकता है। (1) 9 से। 41. केवल यह परिस्थिति कि एक संबद्ध कॉलेज को एक घटक बनाया जाता है विश्वविद्यालय का महाविद्यालय आवश्यक रूप से कला का अपमान नहीं करेगा, 30 (1)। 'घटक महाविद्यालय' अभिव्यक्ति की परिभाषा अपने आप में हानिरहित है। एक घटक महाविद्यालय की अवधारणा तरल है। यह एक अल्पसंख्यक कॉलेज के प्रशासन पर बाहरी नियंत्रण की डिग्री है न कि इसका वैधानिक नाम जो कला के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है। 30 (1) . [308 ए-सी]

(15) एस की उप-धारा (3)। 41 इसका विरोध भी नहीं किया जा सकता है। यह अनुमति देता है

संबद्ध कॉलेज जो राज्य और गुजरात विश्वविद्यालय की अनुमति से किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के लिए एक घटक कॉलेज नहीं बनना चाहता है। [308 ई]

(16) यहां तक कि तर्क के लिए यह मानते हुए कि खंड (ii) से (vi)

उप-एस, एस के 4। 41 कला का उल्लंघन करते हैं। 30 (1) याचिकाकर्ताओं को कुछ भी हासिल नहीं होगा क्योंकि इसके पहले भाग के खिलाफ कोई वैध आपत्ति नहीं की जा सकती है।

उप-धारा (4)। जब तक कानून वास्तव में नहीं बनाए जाते हैं, तब तक संवैधानिक हमला समय से पहले होता है। [309 ए]

(17) उप-धाराओं के पहले भाग पर कोई वैध आपत्ति नहीं ली जा सकती है।

(1) और (2) एस। 51 ए. चूंकि अनुमोदन की शक्ति जाँच करने तक ही सीमित है कर्मचारियों को बर्खास्त करने के अधिकार का दुरुपयोग, यह कला का अपमान नहीं करता है। 30 (1) . शक्ति।

शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा। सेवा की सुरक्षा आवश्यक है। दक्षता और कर्तव्य के ईमानदार निर्वहन को बढ़ावा देने के लिए। इसकी गणना की जाती है कि

दीर्घावधि में संस्थान में सुधार करें। धारा 51 ए सस्ती और सस्ती व्यवस्था प्रदान करती है। कर्मचारियों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए त्वरित उपचार। [310 एफजे

(18) एस के लिए किसी भी वैध आपत्ति का पता लगाना मुश्किल है। 52 उस पर ए

कला का आधार, 30 (1)। इस प्रावधान का उद्देश्य शक्ति के दुरुपयोग की जाँच करना है प्रबंध निकाय द्वारा प्रशासन और सस्ती और त्वरित व्यवस्था प्रदान करना।

छोटे अनुचर शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए उपाय। यह आवश्यक है। सेवा की सुरक्षा के हित में। [311 सी]

याचिकाकर्ताओं के लिए तर्क:

(1) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का कानून रहा है

भारत के गणराज्य बनने के बाद से। अल्पसंख्यक और शैक्षणिक संस्थान इस प्रकार घोषित कानून के आधार पर खुद को अनुकूलित किया है। विभिन्न प्रकार के

भारत में उच्च न्यायालयों ने भी इसी आधार पर कानून निर्धारित किया है। द.

अल्पसंख्यक अधिकारों का सवाल बहुत संवेदनशील और नाजुक है।

कोई सम्मोहक या जबरदस्त विचार नहीं हैं जो इसे उचित ठहराएँ

अदालत ने अपने पिछले फैसलों पर फैसला सुनाया और मामले की सामग्री को कम किया

अल्पसंख्यकों को दिया गया अधिकार।

(2) उद्देश्यों में घटक द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव

सभा में यह घोषणा की गई कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाने चाहिए

के लिए

राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं और अपने धर्म को मानने और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संतुष्ट होते हैं। उनकी पसंद से। इसलिए अनुच्छेद 26,29 और 30 को मूर्त रूप दिया गया था।

अल्पसंख्यकों को इन अधिकारों की गारंटी देने के लिए संविधान। (केरल शिक्षा विधेयक 1959 एस. सी. आर. 995)। ऐतिहासिक उत्पत्ति और संवैधानिक पृष्ठभूमि

अनुच्छेद 30 के अर्थ में इसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। (3) संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अलग और विशिष्ट प्रदान करते हैं। (1) निवासी नागरिकों के किसी भी वर्ग का अधिकारों के संरक्षण का अधिकार (2) सभी का अधिकार

अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति [अनुच्छेद 29 (1)], और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षिक धार्मिक अधिकार स्थापित करने और प्रशासित करने के लिए उनकी पसंद की संस्थाएं [अनुच्छेद 30 (1)]; (3) राज्य सहायता के मामले में संस्था के अल्पसंख्यक या भाषाई न होने पर भेदभाव किया गया।

इस आधार पर कि यह एक धार्मिक (2) के प्रबंधन के तहत है; और (4) नागरिक का अधिकार है कि उसे प्रवेश से वंचित नहीं किया जाए [अनुच्छेद 30 एसटी।

XAVIERS कॉलेज वी. गुजरात

18 7

धर्म, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर किसी भी राज्य-अनुरक्षित या राज्य-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश [अनुच्छेद 29 (2)]।

अनुच्छेद 30 (1) को इसके साथ पढ़कर कम नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 29 (1)। अनुच्छेद 30 (1) और 29 (1) के बीच अंतर गलत नहीं हैं जबकि अनुच्छेद 29 "नागरिकों के किसी भी वर्ग" को मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें बहुसंख्यक वर्ग शामिल होगा। अनुच्छेद 30 (1) केवल अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है। जबकि अनुच्छेद 29 (1) "भाषा, लिपि या संस्कृति" से संबंधित है, अनुच्छेद 30 (1) "धर्म या भाषा" के आधार पर राष्ट्र के विभाजन से संबंधित है; जबकि अनुच्छेद 29 (1) भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों की अपनी पसंद के "शैक्षणिक संस्थानों" की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित है। "प्रशासन" शब्द बहुत व्यापक महत्व का शब्द है। अन्य प्रमुख शब्द उनकी पसंद के हैं। अल्पसंख्यकों के प्रशासन

के अधिकार में अनिवार्य रूप से (i) अपने प्रबंधन या शासी निकाय को चुनने का अधिकार; (ii) छात्रों को प्रवेश से इनकार करने के लिए मजबूर नहीं होने का अधिकार; (iii) अपने शिक्षकों को चुनने का अधिकार; और (4) अपनी संपत्ति और संपत्ति का उपयोग अपने स्वयं के संस्थान के लाभ के लिए करने का अधिकार शामिल होना चाहिए।

हालांकि अल्पसंख्यक संस्थान अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण का दावा कर सकते हैं।

कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जिन्हें संभवतः शैक्षिक नहीं माना जा सकता है, उदाहरण के लिए पॉकेट का एक स्कूल या जहां विध्वंसक या आपराधिक गतिविधियों को पढ़ाया जाता है। ऐसे संस्थान अनुच्छेद 30 के संरक्षण का आह्वान नहीं कर सकते क्योंकि वे बिल्कुल भी शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं। हालांकि अनुच्छेद 30 के तहत स्वतंत्रता शर्तों के संदर्भ में अयोग्य है, लेकिन यह विनियमों से मुक्त नहीं है। कानून द्वारा शासित समुदाय में कोई निरपेक्ष नहीं हो सकता है। तदनुसार, एक शैक्षणिक संस्थान को भवनों के निर्माण और रखरखाव, श्रम कानूनों, कर कानूनों आदि के संबंध में नगरपालिका कानूनों जैसे कानूनों का पालन करना चाहिए। अनुच्छेद 30 के तहत अनुमेय नियामक उपाय वे हैं जो इसे सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासन के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करते हैं और संस्थान के लाभ के लिए और शैक्षणिक राष्ट्रीय संस्थानों के प्रबंधन के साधन के माध्यम से अधिकार का बेहतर और अधिक प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करते हैं, लेकिन प्रबंधन को विस्थापित किए बिना। यदि प्रशासन में सुधार करना है तो यह मौजूदा प्रबंधन की एजेंसी या साधन के माध्यम से होना चाहिए न कि इसे विस्थापित करके। प्रशासन के अधिकार पर प्रतिबंध केवल आम जनता के हित में लगाए गए हैं, न कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के हित में और उनके लाभ के लिए।

के अधिकार पर प्रतिबंध के बीच एक मौलिक अंतर है

प्रशासन और प्रशासन के तरीके को निर्धारित करने वाला एक विनियमन। प्रशासन के अधिकार का अर्थ है प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने का अधिकार और संस्थाओं के कार्यों का संचालन करना। यह प्रशासन में स्वायत्तता का प्रतिपादन करता है। प्रशासन के अधिकार का अर्थ है कार्य संचालन और प्रबंधन का अधिकार।

एक समिति या व्यक्तियों के निकाय के माध्यम से संस्था की, जिन्हें प्रबंधन में विश्वास और विश्वास है और जिन्हें उसमें पूर्ण स्वायत्तता है।

अनुमेय विनियामक उपायों के अधीन, आदर्शों के साथ उनकी अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का अधिकार

और संस्थान के उद्देश्य, आकांक्षाएं और परंपराएं। शैक्षिक संस्थान ऐसा शिक्षक नहीं चाहते हैं जो भले ही प्रतिभाशाली हो लेकिन

घृणित या झगड़ालू या जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के पंथ और मान्यताओं और प्रथाओं के प्रति विरोधी है। अधिकार में स्वीकार करने का अधिकार शामिल है।

अपनी पसंद के छात्र शैक्षणिक योग्यता के बारे में उचित नियमों के अधीन हैं। अपने स्वयं के शिक्षकों और राजकुमारों को चुनने और नियुक्त करने का अधिकार, नियंत्रण और पर्यवेक्षण का प्रयोग करके अनुशासन को लागू करने का अधिकार

शिक्षकों को। कोई भी कार्य या उपाय जो रोकता है

प्रभावी

और

किसी मौलिक अधिकार का वास्तविक प्रयोग उस अधिकार का उल्लंघन है, इसलिए उन नियमों और शर्तों पर संबद्धता के अधिकार पर जोर देना जो इसे प्रतिबंधित करते हैं।

(4) अनुच्छेद 29 (1) और 30 (1) के शब्द इस धारणा का समर्थन नहीं करते हैं कि बाद वाला अनुच्छेद केवल स्थापित शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा। एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अपनी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर. के संरक्षण के एकमात्र उद्देश्य के लिए।

188

विशिष्ट भाषा या लिपि या संस्कृति। अनुच्छेद 29 (1) में उपयोग किए गए शब्द "नागरिकों का कोई भी वर्ग है जिसकी अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है"। अनुच्छेद 30 (1) में उपयोग किए गए शब्द "अल्पसंख्यक हैं, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों।" अनुच्छेद 29 (1) में धर्म का कोई उल्लेख नहीं है; अनुच्छेद 30 (1) में केवल धर्म और भाषा का उल्लेख है और संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। जहाँ तक भारत में ईसाइयों का संबंध है, वे अपनी संस्कृति होने का दावा नहीं करते हैं। उनकी संस्कृति भारत की संस्कृति है। लेकिन वे धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं जिन पर अनुच्छेद 30 (1) लागू होगा। इस बात पर जोर देना कि अल्पसंख्यकों को राज्य से मान्यता या सहायता प्राप्त करने के लिए एक शर्त के रूप में अपने मानसिक अधिकार का समर्पण करना चाहिए, इस अधिकार को अवास्तविक और भ्रामक बनाना है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्थाओं को मान्यता और सहायता देना और उन्हें इस आधार पर अल्पसंख्यकों को देने से इनकार करना कि वे संविधान के तहत अपने मौलिक अधिकार को सौंपने से इनकार करते हैं, वास्तव में अनुच्छेद 30 (2) के अर्थ के भीतर भेदभाव है। संविधान के तहत

केवल अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार दिया गया है। बहुसंख्यक समुदाय को अधिकार नहीं मिला है।

यह शक्ति का निर्माण है जो आपत्ति के अधीन है न कि इसका प्रयोग।

कानूनों के प्रशासन का उचित तरीका विचार करने में अप्रासंगिक है।

इसकी संवैधानिकता।

संशोधन अधिनियम की धारा 41 और 42 का प्रभाव यह है कि शिक्षण

और महाविद्यालयों में प्रशिक्षण विश्वविद्यालय और निजी संस्थानों द्वारा आयोजित किया जाएगा।

महाविद्यालय विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय बन जाएंगे जिसका अर्थ है कि

अल्पसंख्यक महाविद्यालय अपने अल्पसंख्यक चरित्र को पूरी तरह से खो देंगे। द.

घटक महाविद्यालयों के संबंध बनाए गए कानूनों द्वारा शासित होंगे।

विश्वविद्यालय द्वारा। प्रशासन के अधिकार का अर्थ है प्रभावी ढंग से कार्य करने का अधिकार

संस्थान के कार्यों का प्रबंधन और संचालन करना। यह स्वायत्तता का प्रतिपादन करता है

प्रशासन।

संशोधन अधिनियम की धारा 51 और 52 का विनाश करने का प्रभाव है।

शिक्षण और गैर पर शैक्षिक एजेंसियों का अनुशासनात्मक नियंत्रण

महाविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी। कोई सजा नहीं दी जा सकती

कर्मचारी के किसी सदस्य पर प्रबंधन जब तक कि उसे उपाध्यक्ष की मंजूरी न मिल जाए

कुलाधिपति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। अनिवार्य के लिए प्रावधान

विवादों के मध्यस्थता से प्रबंधन के लिए यह मुश्किल हो जाएगा कि

कर्मचारियों पर प्रभावी अनुशासनात्मक नियंत्रण। [डी. ए. वी. कॉलेज बनाम पंजाब राज्य

ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 737.] के अधिकार बनाने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती

कर्मचारियों के सदस्य न्यायसंगत हैं लेकिन यह अधिकार का उल्लंघन होगा

प्रशासन का यदि किसी बाहरी निकाय को निर्धारण के लिए अंतिम प्राधिकरण बनाया जाता है

कर्मचारियों के सदस्यों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण से संबंधित सभी प्रश्न।

उत्तरदाताओं के लिए तर्क: अनुच्छेद 30 (1) की व्याख्या अलग-अलग नहीं बल्कि इसके संदर्भ में की जानी चाहिए -

संविधान, विशेष रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का इसका आदर्श और इसका उद्देश्य देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें और मजबूत करें। आज़ादी,

के हित में एक व्यवस्थित समाज में नियामक उपायों के साथ दृढ़ समाज। संबद्धता चाहने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान के मामले में

विश्वविद्यालय, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के हित में नियामक उपाय

यह अनिवार्य रूप से प्रबंधन से संबंधित होना चाहिए क्योंकि इस तरह की शिक्षा पूरी तरह से होती है।

राष्ट्रीय संस्था, अर्थात शासन का चरित्र और संरचना

निकाय, शिक्षण कर्मचारियों की गुणवत्ता, उनके कार्यकाल और अनुशासन की सुरक्षा शैक्षणिक संस्थान में। नियामक उपायों को अनिवार्य रूप से होना चाहिए

सभी शैक्षणिक संस्थानों पर समान रूप से लागू और भेदभाव नहीं किया जा सकता है टोरी "। अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने का अधिकार

अनुच्छेद 30 (1) जिसमें सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने का अधिकार शामिल है।

इसलिए, विनियामक उपायों द्वारा सीमित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 30 (1) नहीं हो सकता है

जहाँ दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष और सामान्य या विशेष हो, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है।

चरित्र। यह अनुच्छेद किसी भी भाषाई या धार्मिक बहुसंख्यक को प्राप्त होने वाले अधिकार से अधिक या उससे अधिक कोई अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है। अनुच्छेद एसटी।

XAVIERS कॉलेज v. गुजरात

189

30 (1) इसे अन्य संज्ञानात्मक प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। , अनुच्छेद 30 (2), 25,26 और। 29 और विशेष रूप से अनुच्छेद 30 (2) और 25 (2) (ए)। अल्पसंख्यक संस्थानों को किसी के द्वारा संबद्धता पर जोर देने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है

विश्वविद्यालय। एक अल्पसंख्यक संस्थान भाषा या धर्म के आधार पर किसी अन्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक संस्थान के रूप में संबद्धता से संबंधित सामान्य कानून से बंधा होता है। धारा 33ए, 40,41,51ए और 52ए के प्रावधानों के साथ-साथ विवादित अध्यादेश भी याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक अधिकार के लिए विनाशकारी नहीं हैं। वे केवल नियामक प्रकृति के होते हैं और केवल ऐसे प्रतिबंध लगाते हैं जो ऊपर बताए गए हैं। वे वैध और प्रभावी हैं।

कोई भी मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है और किसी एक अधिकार पर आधारित दावा नहीं है।

अन्य के आधार पर दावों के अनुसार योग्यता के अधीन हो सकता है

अधिकार।

लेखों में निहित निदेशक सिद्धांतों का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए।

41 , 45 , 46 और 38 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौन सी शिक्षा एक आवश्यक और शक्तिशाली है यंत्र। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन का अधिकार

था।

देश के सामान्य कानून के अनुसार। प्रशासकों का उद्देश्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का अनुपात दो गुना है: (1) संरक्षण

धर्म, भाषा और लिपि सहित संस्कृति (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी बच्चे सामान्य शिक्षा भी प्राप्त करते हैं ताकि वे शिक्षा में प्रवेश कर सकें।

एक के लिए आवश्यक योग्यताओं के साथ अच्छी तरह से और पर्याप्त रूप से सुसज्जित दुनिया

जो इन जुड़वां वस्तुओं में से किसी की उपलब्धि में बाधा डालेगा अल्पमत अनुच्छेद 30 (1) के उल्लंघन के रूप में अमान्य होगा। इन बातों के अधीन

योग्यता प्रशासन के अनुसार किया जा सकता है कानून। गुजरात अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य सुधार करना था

सामान्य शिक्षा के साथ-साथ शिक्षकों के कार्यकाल की सुरक्षा की गारंटी भी।

सेवा की सुरक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षकों की सुरक्षा करना नहीं है।

शोषण लेकिन इसका उद्देश्य अकादमिक स्वतंत्रता, प्रबंधन सुनिश्चित करना है-शिक्षक

संबंधों को केवल नियोक्ता के बजाय उचित प्रचार में समझना होगा।

कर्मचारी संबंध।

मौलिक न्यायनिर्णय: 1973 की रिट याचिका संख्या 232 और 233।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाएं।)

एन. ए. पालखीवाला, आई. एम. नानावती, सुधीर नानावती, ए. नटराई,

जे. बी. दादाचंजी, पी. सी. भर्तारी, ओ. सी. माथुर और रविंदर नारायण याचिकाकर्ताओं के लिए।

एफ. एस. नरीमन, ऐड! , सोल। भारत के जनरल आर. एच. ढेबर और

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए एस. पी. नायर।

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए एस. टी. देसाई, एस. एन. शेलट और एस. आर. अग्रवाल।

एन. ए. पालखीवाला, जे. बी. दादाचंजी, ए. जी. मेनेसेस, पी. सी. भर्तारी,

इंटरवेनर नंबर के लिए एस. स्वरूप, ओ. सी. माथुर और रविंदर नारायण। 1 , 9 , और 10.

सोली जे. सोराबजी, जे. बी. दादाचंजी, पी. सी. भर्तारी, एस. स्वरूप, ओ.

इंटरवेनर नंबर के लिए सी. माथुर और रविंदर नारायण। 2 , 6 , 7-8 .

1. एम. नानावती, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. माथुर और रविंदर

इंटरवेनर नंबर के लिए नारायण और पी. सी. भर्तारी। 3 और 5.

फ्रैंक एंथनी, जे. बी. दादाचंजी, पी. सी. भर्तारी, एस. स्वरूप, ओ. सी.

इंटरवेनर नंबर 4 के लिए माथुर और रविंदर नारायण।

निरेन डे, भारत के लिए महान्यायवादी, एस. पी. नायर मध्यस्थ के लिए

सं. 11 (डब्ल्यूपी सं. 232/73 में)।

डॉ. वी. ए. सैय्यद मोहम्मद और के. एम. के. नायर

हस्तक्षेपकर्ता

संख्या 12 (डब्ल्यू. पी. 232/73 में)।

[

1975] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

190

ओ. एन. टिक्कू, जम्मू-कश्मीर राज्य के महाधिवक्ता और विनीत

कुमार इंटरवेनर नंबर 13 के लिए।

सीतलवाड़, के. सी. अग्रवाल, ए. टी. एम. संपत, एम. एम. एल.

श्रीवास्तव, ई. सी. अग्रवाल, इंटरवेनर नंबर 14 के लिए।

इंटरवेनर नंबर 15 के लिए हरदेव सिंह और आर. एस. सोधी।

जोसेफ विथायथिल और ई. सी. अग्रवाल इंटरवेनर नंबर 16 के लिए।

नौनीत लाल और सुश्री ललिता कोहली को इंटरवेनर नंबर 17 (डब्ल्यू. पी. में) के लिए चुना गया।

232/73) और मध्यस्थ संख्या 5 (डब्ल्यू. पी. में। 233/73)।

इंटरवेनर नंबर 18,20 के लिए ई. सी. अग्रवाल और डेनियल ए. लतीफी,

43 और 50-52 तक।

श्रीमती शेहराजादे आलम, एम. कमरुद्दीन और ई. सी. अग्रवाल

हस्तक्षेपकर्ता संख्या 19.

इंटरवेनर नंबर 44 के लिए हारू भाई और जे. राममूर्ति।

इंटरवेनर के लिए एम. के. राममूर्ति, हारू भाई और जे. राममूर्ति

नंबर 45।

इंटरवेनर के लिए बी. पी. माहेश्वरी, सी. एल. जोसेफ और सुरेश सेठी

नं. 46।

हस्तक्षेपकर्ता संख्या 47 के लिए डी. गोबर्धन।

टी

एफ. एस. नरीमन एडिशनल। सोल। भारत के जनरल (मध्यस्थ संख्या 48 के लिए)

और इंटरवेनर नंबर के लिए एम. एन. श्रॉफ। 48-49 (डब्ल्यूपी में। 1973 का सं. 233)।

वी. एम. तारकुंडे, जोसेफ विथायथिल, के. सी. अग्रवाल, ए. टी. एम.

संपत, पी. सी. चंडी, एम. एम. एल. श्रीवास्तव और ई. सी. अग्रवाल

हस्तक्षेपकर्ता संख्या 53 (डब्ल्यू. पी. में। 233/73)।

निम्नलिखित निर्णय दिए गए थे

राय, सी. जे. विचार के लिए सवाल यह है कि क्या अल्पसंख्यक

धर्म या भाषा के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 30 के अर्थ के भीतर सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है।

अल्पसंख्यक संस्थान जो सच्चाई और वास्तविकता में शैक्षिक हैं

संस्थान जहाँ शिक्षा अपने विभिन्न पहलुओं में प्रदान की जाती है, वे अनुच्छेद 30 के संरक्षण का दावा करते हैं।

इससे यह सवाल उठता है कि क्या अनुच्छेद 30 (1)

और संविधान के 29 (1) परस्पर अनन्य हैं।

संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 को शीर्ष के तहत समूहीकृत किया गया है।

"सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार"। अनुच्छेद 29 (1) भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग के अपने लिंग युग, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 30 (1) में प्रावधान है कि सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 29 (2) शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

उसमें केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 30 (2) राज्यों को इस आधार पर सहायता देने में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ किसी भी भेदभावपूर्ण राष्ट्र को बनाने से रोकता है कि इसका प्रबंधन किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा किया जाता है।

एसटी. एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (रे, सी. जे.)

191

अनुच्छेद 29 और 30 चार अलग-अलग अधिकार प्रदान करते हैं। पहला अधिकार है

निवासी नागरिकों का कोई भी वर्ग अनुच्छेद 29 (1) में उल्लिखित अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण करेगा। दूसरा सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का अनुच्छेद 30 (1) में उल्लिखित अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। तीसरा, किसी भी शैक्षणिक संस्थान का भेदभाव न करने का अधिकार है।

राज्य सहायता के मामले में इस आधार पर कि यह इसके अधीन है

अनुच्छेद में उल्लिखित धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का प्रबंधन 30 (2) . चौथा नागरिक का यह अधिकार है कि उसे प्रवेश से वंचित नहीं किया जाए

अनुच्छेद में उल्लिखित धर्म, जाति, नस्ल या भाषा का आधार 29 (2) .

अनुच्छेद 30 (1) को अधिकार को सीमित करने के रूप में पढ़ना गलत होगा।

अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना

केवल उन मामलों के लिए विकल्प जहां ऐसे संस्थान समस्या से संबंधित हैं

अल्पसंख्यकों की आयु, लिपि या संस्कृति। इसके कारण ये हैं। सबसे पहले,

अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

जिसमें बहुमत खंड शामिल होगा जबकि अनुच्छेद 30 (1) प्रदान करता है

सभी अल्पसंख्यकों का अधिकार। दूसरा, अनुच्छेद 29 (1) से संबंधित है - भाषा, लिपि या संस्कृति, जबकि अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों से संबंधित है

धर्म या भाषा पर आधारित राष्ट्र। तीसरा, अनुच्छेद 29 (1) है

भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के अधिकार से संबंधित, जहाँ

अनुच्छेद 30 (1) शिक्षा की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित है।

अल्पसंख्यकों की अपनी पसंद की राष्ट्रीय संस्थाएं। चौथा, कॉन अनुच्छेद 29 (1) के तहत भाषा, लिपि या संस्कृति की सेवा

एक नाबालिग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन अनुच्छेद 30 (1) के तहत किसी भी उद्देश्य से असंबद्ध हो सकता है

भाषा, लिपि या संस्कृति की सेवा करें। एक अल्पसंख्यक एक संस्थान का प्रशासन कर सकता है

धार्मिक शिक्षा के लिए शिक्षा जो किसी भी शिक्षा से पूरी तरह से असंबद्ध है

किसी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का प्रश्न।

यदि अनुच्छेद 30 (1) का दायरा शिक्षा की स्थापना और प्रशासन करना है।

अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान, यह अनुच्छेद 30 को निरर्थक बना देगा। यदि अनुच्छेद 29 (1) के तहत अधिकार और

30 (1) समान हैं तो परिणाम यह होगा कि किसी भी धारा का

आवश्यक रूप से भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होने वाले नागरिकों को यह अधिकार होगा अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना। द.

अनुच्छेद 30 का दायरा भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों पर है और नहीं

भारत के नागरिकों के अन्य वर्ग को ऐसा अधिकार है।

उनके शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को विकल्प दिया गया है ताकि

बहुसंख्यक जो उचित कानून बनाकर हमेशा अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं अल्पसंख्यकों को स्थापित करने के लिए निषेध करने वाला कानून पारित न करें और

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करें। यदि इसका दायरा अनुच्छेद 30 (1) को अनुच्छेद 29 (1) के तहत अधिकार का विस्तार बनाया गया है।

शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के रूप में

धार्मिक शिक्षा देना या अपने धर्म में शिक्षा प्रदान करना। शिक्षाएँ या सिद्धांत अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार को स्थापित करते हैं और

उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन छीन लिया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर.

192

जनता के हर वर्ग, बहुसंख्यक के साथ-साथ अल्पसंख्यक भी

अनुच्छेद 25 और 26 में उल्लिखित धर्म के संबंध में अधिकार और अनुच्छेद में उल्लिखित भाषा, लिपि, संस्कृति के संबंध में अधिकार

29. अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करने का पूरा उद्देश्य

30 यह सुनिश्चित करना है कि बहुमत और के बीच समानता होगी

अल्पसंख्यक। यदि अल्पसंख्यकों को ऐसी विशेष सुरक्षा नहीं है तो वे

समानता से वंचित किया जाएगा।

रे में। केरल शिक्षा विधेयक 1957 [1959] एस. सी. आर. 995

अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 30 (1) में सामान्य सुरक्षा प्रदान करने वाले संस्थान शामिल हैं।

लार शिक्षा। अनुच्छेद 30 का उद्देश्य मिनो के बच्चों को सक्षम बनाना है।

पूरी तरह से सुसज्जित दुनिया में बाहर जाने का अधिकार। सभी व्यक्तियों में चाहे अनुच्छेद 25 के तहत बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक को स्वतंत्र रूप से अधिकार है -

धर्म का प्रचार, पालन और प्रचार करें। नागरिकों का कोई भी वर्ग जो इसमें अनुच्छेद के तहत बहुमत के साथ-साथ अल्पसंख्यक भी शामिल हैं।

29 उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। कि यही कारण है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा के संबंध में एक विशिष्ट अधिकार दिया जाता है।

अनुच्छेद 30 के तहत संस्थान। अनुच्छेद 30 (1) भाषा का अधिकार देता है।

अल्पसंख्यकों के साथ-साथ जहाँ धर्म का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह है, वहाँ

इसके अलावा, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को अनुच्छेद 30 से बाहर करना बिल्कुल भी संभव नहीं है।

1959 में केरल शिक्षा विधेयक मामले (ऊपर) के बाद से इस न्यायालय ने

लगातार यह माना जाता है कि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आती है।

इस न्यायालय ने रेव. फादर प्रोस्ट बनाम. बिहार राज्य [1969] 2

एस. सी. आर. 73 ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या सुरक्षा की गारंटी है। अनुच्छेद 30 (1) के तहत अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत अधिकार का परिणाम है।

29 (1) . एक तर्क दिया गया था कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा अनुच्छेद 2961) केवल एक विशिष्ट भाषा, लिपि के संरक्षण का अधिकार था।

या अपनी संस्कृति, और इसलिए, शैक्षणिक संस्थान जो

प्रदत्त सामान्य शिक्षा अनुच्छेद 30 के संरक्षण के लिए योग्य नहीं थी।

इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 30 की चौड़ाई में कटौती नहीं की जा सकती है

ऐसा कोई भी विचार प्रस्तुत करना जिस पर अनुच्छेद 29 (1) आधारित हो। लेख

29 (1) नागरिकों के वर्गों को संरक्षण के लिए दी जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा है

उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति। अनुच्छेद 30 मिनो का विशेष अधिकार है।

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। यह न्यायालय

उन्होंने कहा कि दोनों अनुच्छेद दो अलग-अलग अधिकार पैदा करते हैं, हालांकि यह संभव है

कि अधिकार किसी दिए गए मामले में मिल सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में सन्निहित वास्तविक कारण है -

राष्ट्र की अंतरात्मा कि अल्पसंख्यक, धार्मिक के साथ-साथ

उन्हें देने के उद्देश्य से उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान बच्चों को पूर्ण पुरुष बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सामान्य शिक्षा और

देश की महिलाएँ। अल्पसंख्यकों को यह सुरक्षा दी जाती है अनुच्छेद 30 अखंडता और एकता को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए

देश से। सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के क्षेत्र का उद्देश्य है

हमारे देश के लड़कों और लड़कियों की समानता का विकास करना। यह

माध्यम के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सच्ची भावना में है

शिक्षा से। यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण नहीं दिया जाता है

अनुच्छेद 30 के तहत शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन

अपनी पसंद की स्थितियों में, वे अलग-थलग और अलग महसूस करेंगे। जनरल

धर्मनिरपेक्ष शिक्षा धारणा के द्वार खोलेगी और प्राकृतिक रूप से कार्य करेगी।

हमारे देशवासियों के लिए समग्र रूप से जीने के लिए मन का प्रकाश।

एसटी. XAVIERS कॉलेज v. गुजरात (रे, Ça.)

- 193

दूसरा सवाल जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या रिली

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जिन्हें स्थापित करने का अधिकार है और

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करते हैं, एक मौलिक है

संबद्धता का अधिकार। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार उनके बिना होगा।

यदि संबद्धता से इनकार किया जाता है तो कोई भी अर्थ। उत्तरदाता सवाल उठाते हैं

एक सांविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध होना: प्रबंधन की शर्तें अन्य संबद्ध कॉलेजों पर लागू होने वाले कॉलेजों से अलग,

इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि कोई फंड नहीं है।

अल्पसंख्यक संस्थान का संबद्धता का मानसिक अधिकार। एक स्पष्टीकरण

कानून के उस कथन पर रखा गया है। यह है कि संबद्धता होनी चाहिए

इस मामले में अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एक वास्तविक और सार्थक अभ्यास

सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करना। कोई भी कानून जो प्रदान करता है

उन शर्तों पर संबद्धता जिसमें अधिकार का संक्षिप्तकरण शामिल होगा

भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा का प्रशासन और स्थापना करना।

अपनी पसंद की संस्थाएं अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन करेंगी। शिक्षाविद् लड़कों के लिए अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्थानों से उनकी उपयोगिता छीन ली जाएगी

और लड़कियों को विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए ऐसे संस्थानों में प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यक अपने बच्चों को तैयार करने का अपना अधिकार लगभग खो देंगे।

सामान्य करियर यदि संबद्धता कार्यकालों पर हो जो उन्हें बना देगा

समर्पण करें और शिक्षा की स्थापना और प्रशासन के अपने अधिकार खो दें

अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद की संस्थाएं। का प्राथमिक उद्देश्य

संबद्धता यह है कि अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र

एक उपयोगी कैरियर के लिए आवश्यक डिग्री के रूप में योग्यताएँ हों

प्रभावी लेकिन अवास्तविक भी जब तक कि ऐसा संस्थान किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध न हो। छात्रों को डिग्री प्रदान करने के उद्देश्य से।

विश्वविद्यालय से संबद्धता के वास्तव में दो भाग होते हैं। एक भाग

टियोन। दूसरे भाग में संबंधित नियम और शर्तें शामिल हैं। संस्थानों का प्रबंधन। यह शैक्षिक प्रशासन से संबंधित है।

:

संस्थाएं।

संबद्धता के संबंध में एक अल्पसंख्यक संस्थान को इसका पालन करना चाहिए

शैक्षिक मानकों और दक्षता को विनियमित करने वाले वैधानिक उपाय,

अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम, निर्देश के पाठ्यक्रम और सिद्धांत

शिक्षकों की योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के संबंध में शैक्षणिक संस्थानों आदि में छात्रों का प्रवेश।

जब कोई अल्पसंख्यक संस्थान किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के लिए आवेदन करता है,

यह सामान्य शिक्षा प्रणाली में भाग लेने के लिए अपनी पसंद व्यक्त करता है

और उस विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निर्देश के पाठ्यक्रम। संबद्धता है सह के उद्देश्य के लिए संस्थानों में शिक्षा के पाठ्यक्रमों को विनियमित करना

शिक्षा के मानकों का समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना। इस संबंध में

विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों से संबद्धता

शिक्षा के स्वरूप और मानकों में सहमत होना चाहिए। विनियामक

संबद्धता के उपाय अल्पसंख्यक संस्थानों को समान रूप से साझा करने में सक्षम बनाते हैं

–131 एस. पी. सी. आई./75 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर.

19 4

गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ शिक्षा के पाठ्यक्रम और समान डिग्री।

केरल राज्य बनाम में यह न्यायालय। बहुत रेव. मदर प्रोविंशियल, आदि [1971] 1 एस. सी. आर. 734 ने देश और लोगों के हित में प्रणाली और शिक्षा के मानक के रेग्यू लेटोरी उपायों की आवश्यकता और महत्व को समझाया। जब कोई अल्पसंख्यक संस्थान संबद्धता के लिए आवेदन करता है, तो वह अध्ययन के समान पाठ्यक्रमों का पालन करने के लिए सहमत होता है। संबद्धता अल्पसंख्यक संस्थानों के शैक्षिक चरित्र और विषय-वस्तु को विनियमित कर रही है। ये विनियम न केवल सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के हित में उचित हैं, बल्कि अल्पसंख्यक संस्थानों के कद और ताकत में सुधार के लिए भी हैं। सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के सभी संस्थानों, चाहे वे अल्पसंख्यकों या गैर-अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित हों, को छात्रों को न केवल उनकी बौद्धिक प्राप्ति के लिए बल्कि करियर की खोज के लिए भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थानों की संबद्धता का उद्देश्य शैक्षणिक क्षेत्र में उनके बच्चों और अन्य छात्रों का विकास और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है। संबद्धता मुख्य रूप से संस्थान के शैक्षणिक और शैक्षिक चरित्र से संबंधित है। इसलिए, ऐसे उपाय जो अध्ययन के पाठ्यक्रमों, शिक्षकों की योग्यता और नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति की शर्तों, छात्रों के स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं के लिए सुविधाओं को विनियमित करेंगे, सभी अल्पसंख्यक संस्थानों की संबद्धता के मामलों में शामिल हैं। इन नियामक उपायों के लिए

संबद्धता शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में एकरूपता, दक्षता और उत्कृष्टता के लिए है और अल्पसंख्यकों के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।

अनुच्छेद 30 के तहत संस्थान। पूरा विवाद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार की सीमा के आसपास केंद्रित है। कहा जाता है कि प्रशासन के अधिकार में चार प्रमुख मामले शामिल हैं। सबसे पहले अपने प्रबंधन या शासी निकाय को चुनने का अधिकार है। ऐसा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक संस्थान के संस्थापकों को अपनी समिति या निकाय में विश्वास और विश्वास होता है जिसमें उनके द्वारा चुने गए व्यक्ति शामिल होते हैं। दूसरा अपने शिक्षकों को चुनने का अधिकार है। ऐसा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक संस्थान चाहते हैं कि शिक्षक संस्थान के आदर्शों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हों। तीसरा यह अधिकार है कि छात्रों को प्रवेश से इनकार करने के लिए मजबूर न किया जाए। दूसरे शब्दों में, अल्पसंख्यक संस्थान शैक्षणिक योग्यता के बारे में उचित नियमों के अधीन अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार चाहते हैं। चौथा, अपनी संपत्तियों और परिसंपत्तियों का उपयोग अपने लाभ के लिए करने का अधिकार है।

संस्था।

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार पूर्ण अधिकार में नहीं है। यह अधिकार विनियमन से मुक्त नहीं है। बस नियामक के रूप में अल्पसंख्यक संस्थानों के शैक्षिक चरित्र और विषय-वस्तु को बनाए रखने के

लिए उपाय आवश्यक हैं, इसी तरह व्यवस्थित, कुशल और सुदृढ़ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए नियामक उपायों की आवश्यकता है। दास, सी. जे. ने केरल शिक्षा विधेयक मामले (उपरोक्त) में प्रशासन के अधिकार के सही अर्थ को एक संदर्भ में संक्षेप में यह कहते हुए व्यक्त किया कि

प्रशासन का अधिकार कुशासन का अधिकार नहीं है।

एसटी. जेवियर कॉलेज वी. गुजरात '(रे, सी. जे.)

195

याचिकाकर्ताओं की ओर से, यह कहा जाता है कि प्रशासन का अधिकार

इसका अर्थ है प्रशासन में स्वायत्तता। संस्थान को जैसा वह उचित समझता है, उसे ढालने के लिए मिनो रीति के दावे पर जोर दिया जाता है। यह कहा जाता है कि विनियामक उपायों को प्रशासन के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्पसंख्यक संस्थान के प्रबंधन के साधन के माध्यम से इसे सुविधाजनक बनाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक संस्थान के प्रबंधन को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रशासन के अधिकार का उल्लंघन होगा।

केरल शिक्षा विधेयक मामले (ऊपर) ने कुछ नियामकों को बरकरार रखा

अल्पसंख्यक संस्थान के प्रशासन के बारे में प्रावधान प्रशासन के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक की नियुक्ति ऐसे अधिकारी के अनुमोदन के अधीन की जानी थी जिसे सरकार अधिकृत करे। सरकार ने शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित की। लोक सेवा आयोग ने शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन किया। सरकारी स्कूलों की तरह ही सेवा की शर्तें होनी चाहिए थीं। इस संबंध में सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी शिक्षक को पद से हटाया, हटाया या हटाया या निलंबित नहीं किया जाना था।

केरल शिक्षा विधेयक मामले (ऊपर) ने इसे बरकरार नहीं रखा

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 में खंड 14 और 15 की वैधता। इन खंडों ने सरकार को कुछ परिस्थितियों में किसी भी सहायता प्राप्त स्कूल को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अधिकृत किया। इस न्यायालय ने पाया कि वे खंड विद्यालयों को ज़ब्त करने के बराबर हैं। स्कूलों को इस

शर्त पर मान्यता दी गई थी कि वे उन खंडों को प्रस्तुत करें। इस तरह का समर्पण अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार का समर्पण है।

इस न्यायालय ने रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट मामले (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया कि

बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 48-ए, जो 1 मार्च, 1962 से लागू हुई, ने रांची के जेसुइट्स द्वारा स्थापित सेंट जेवियर्स कॉलेज के शासी निकाय की स्वायत्तता को पूरी तरह से छीन लिया। उक्त अधिनियम की धारा 48-ए में अन्य बातों के साथ नियुक्तियों का प्रावधान किया गया है। कॉलेज के शासी निकाय द्वारा बर्खास्तगी, निष्कासन, सेवा की समाप्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोग की सिफारिश पर और विश्वविद्यालय के अनुमोदन के अधीन की जानी थी। उस धारा में अन्य प्रावधान थे। , कि आयोग वरीयता के क्रम में व्यक्तियों के नामों की शासी निकाय से सिफारिश करेगा और किसी भी मामले में शासी निकाय किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता जिसकी सिफारिश विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने नहीं की थी।

आर टी में। रेव. बिशप एस. के. पात्रो बनाम बिहार राज्य [1970] 1 एस. सी. आर.

172 , बिहार राज्य ने राज्य के आदेश के अनुसार चर्च मिशनरी सोसाइटी स्कूल, भागलपुर से स्कूल की एक प्रबंधन समिति का गठन करने का अनुरोध किया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य अधिकारी अपने आदेश के अनुसार विद्यालय से एक प्रबंध समिति का गठन करने की अपेक्षा नहीं कर सकते।

डी. ए. वी. कॉलेज बनाम पंजाब राज्य [1971] पूरक। एस. सी. आर 688

उस मामले में विवादित क़ानून का खंड 17, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि शुरू में नियुक्त कर्मचारियों को कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और बाद के परिवर्तनों की सूचना विश्वविद्यालय को कुलपति के अनुमोदन के लिए दी जाएगी, प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप करते हुए पाया गया मन में।

केरल राज्य बनाम में यह न्यायालय। बहुत रेव. माँ प्रांतीय

मामला (ऊपर) केरल विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 48 और 49 पाया गया

1969 का अनुच्छेद 30 का उल्लंघन होना। उन खंडों को पाया गया था

कॉलेज और इसे एक अलग कॉर्पोरेट निकाय को देना जो किसी भी तरह से नहीं था संस्था के प्रति जवाबदेह। अल्पसंख्यक समुदाय को पाया गया

अपने द्वारा स्थापित संस्थान को प्रशासित करने का अधिकार खो दें। उन अनुभागों में विचारित शासी निकाय में कॉलेजों का प्रशासन करना था

अधिनियम, कानूनों, अध्यादेशों, विनियमों के प्रावधानों के अनुसार

राज्य, उप-कानून और उनके तहत बनाए गए आदेश। शासी निकाय की शक्तियाँ और कार्य, सदस्यों को हटाना और उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सभी कानूनों द्वारा निर्धारित की जानी थी। इन प्रावधानों के तहत संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन निकायों के हाथों में सौंप दिया गया था।

विश्वविद्यालय।

इस न्यायालय के ये निर्णय इंगित करते हैं कि कैसे और कब लिया जा रहा है

अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन के अधिकार को दूर करना या कम करना।

शासी निकाय के चयन, शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशासन के अधिकार के संबंध में।

रेव. सिद्धजभाई भाई बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। की स्थिति

बॉम्बे [1963] 3 एस. सी. आर. 837 यह दर्शाता है कि कैसे राज्य के आदेश द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, जिसमें आदेश का पालन न करने के लिए सहायता अनुदान को रोकने की धमकी पर सरकार के आदेश के तहत अल्पसंख्यक संस्थान को 80 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता होती है। केरल शिक्षा विधेयक मामले में इस अदालत ने कहा कि राज्य अप्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकता जो वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता है। रोक-थाम

उन शर्तों पर सहायता जो संस्था को प्रशासित करने के लिए अल्पसंख्यक के अधिकार के समर्पण की मांग करती हैं, अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार का उल्लंघन है।

शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के मंदिर हैं। के गुण

मानव बुद्धि शिक्षा द्वारा निपुण और सामंजस्यपूर्ण होती है। जहाँ शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले के बीच पूर्ण सामंजस्य होता है, जहाँ शिक्षक पढ़ाता है और छात्र प्राप्त करता है, जहाँ शिक्षक

और पढ़ाए जाने वाले का सीखने में पूर्ण समर्पण होता है, जहाँ शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले के बीच अनुशासन होता है, जहाँ दोनों सीखने की पूजा होती है, वहाँ कोई कलह या चुनौती पैदा नहीं होगी। एक शैक्षणिक संस्थान सुचारू रूप से चलता है जब शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले ज्ञान की खोज के सामान्य आदर्श में लगे होते हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि शिक्षकों की नियुक्ति शैक्षणिक संस्थानों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षकों की योग्यता और चरित्र इस प्रकार हैं -

वास्तव में महत्वपूर्ण। अल्पसंख्यक संस्थानों को संस्थानों के प्रशासन का अधिकार है। इस अधिकार का तात्पर्य छात्रों को सर्वोत्तम प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों के दायित्व और कर्तव्य से है। प्रशासन के अधिकार में, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए नियामक उपायों के रूप में नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता होती है। प्रशासन के अधिकार को सुचारू प्रशासन की सुविधा के लिए नियामक उपायों के साथ संयमित किया जाना है। सबसे अच्छा प्रशासन अल्पसंख्यक का कोई निशान या रंग प्रकट नहीं करेगा। एक अल्पसंख्यक संस्थान को संस्थान के प्रशासन में अनुकरणीय उदारता के साथ चमकना चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थान को सबसे अच्छी प्रशंसा यह दी जा सकती है कि वह अपने अल्पसंख्यक चरित्र पर निर्भर या घोषित नहीं करता है।

एसटी. XAVIERS कॉलेज v. गुजरात (रे, सी. जे.)

19 7

नियम जो छात्रों के हितों की पूर्ति करेंगे, नियम

जो शिक्षकों के हितों की पूर्ति करेंगे, वे अच्छे प्रशासन में सर्वोपरि हैं। शिक्षकों की दक्षता, अनुशासन और प्रशासन में निष्पक्षता के हित में विनियमन संबद्ध संस्थानों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

सत्यनिष्ठा के विकास में शिक्षा एक महान सामंजस्यपूर्ण शक्ति होनी चाहिए।

राष्ट्र से। शिक्षा राष्ट्र के लोकाचार का विकास करती है। इसलिए, यह देखने के लिए नियम आवश्यक हैं कि प्रशासन में कोई विभाजनकारी या विघटनकारी ताकतें न हों।

अनुच्छेद 33 के उल्लंघन के रूप में नियमों के तीन सेटों पर महाभियोग चलाया जाता है।

पहले समूह में गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 की धारा 40 और 41 शामिल हैं, जैसा कि अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है। दूसरे समूह में धारा 33 ए (1) (ए) शामिल है। तीसरे समूह में धारा 51 ए और 52 ए शामिल हैं।

अधिनियम की धारा 40 में कहा गया है कि शिक्षण और प्रशिक्षण

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से निर्देश देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति या मान्यता दी जा सकती है। जैसे ही न्यायालय, जो विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में से एक है, यह निर्धारित करता है कि शिक्षण और प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा, अधिनियम की धारा 41 के प्रावधान लागू हो जाते हैं।

अधिनियम की धारा 41 में चार उप-धाराएँ हैं। पहला उप

अनुभाग में कहा गया है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर सभी कॉलेज जो हैं

अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश प्राप्त और सभी कॉलेज जो इसके बाद विश्वविद्यालय से संबद्ध हो सकते हैं, विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज होंगे। यह सच है कि विश्वविद्यालय की अदालत द्वारा अधिनियम की धारा 40 के तहत अभी तक कोई निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन शक्ति मौजूद है। शक्ति का उपयोग अल्पसंख्यक संस्थान के संबंध में किया जा सकता है। एक बार ऐसा करने के बाद अल्पसंख्यक संस्थान तुरंत घटक महाविद्यालय बन जाएंगे। द.

अधिनियम की धारा 40 का वास्तविक निहितार्थ यह है कि शिक्षण और प्रशिक्षण

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा। "आचरण" शब्द। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विश्वविद्यालय एक शिक्षण विश्वविद्यालय है। धारा 40 के तहत

अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय स्नातक कक्षाओं के शिक्षण का कार्य अपने हाथ में लेता है।

अधिनियम की धारा 41 अधिनियम की धारा 40 का एक परिणाम है। सेक.

अधिनियम की धारा 41 धारा 40 से स्वतंत्र नहीं है।

एक्ट करें। एक बार जब कोई संबद्ध कॉलेज एक घोषणा के अनुसार अधिनियम की धारा 41 के अर्थ के भीतर एक घटक कॉलेज बन जाता है।

अधिनियम की धारा 40 इसे विश्वविद्यालय में एकीकृत कर देती है। एक कॉन स्थायी महाविद्यालय अब अपने पूर्व व्यक्तिगत चरित्र को बरकरार नहीं रखता है।

कॉलेज का अल्पसंख्यक चरित्र खो गया है: अल्पसंख्यक संस्थान

विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग बनें। परिणाम यह है कि धारा 40

अधिनियम का अल्पसंख्यक संस्थानों पर कोई अनिवार्य अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। राज्य क्योंकि यह उनके प्रशासन के मौलिक अधिकार को छीन लेगा

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान।

अधिनियम की धारा 41 में चार उप-धाराएँ हैं। पहला उप

खंड में मोटे तौर पर कहा गया है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर सभी महाविद्यालय

विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय हों। दूसरा उप-खंड

यह बताता है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर सभी संस्थान संघ होंगे

विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित संस्थान।

तीसरे उप-खंड में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर.

198

विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर स्थित कोई भी शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय की सहमति और राज्य सरकार की मंजूरी के अलावा, किसी भी तरह से कानून द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय के किसी भी विशेषाधिकार के साथ संबद्ध नहीं होगा या प्रवेश नहीं लेगा। चौथी उप-धारा में कहा गया है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर घटक कॉलेजों और घटक, मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्थानों के संबंध उस संबंध में बनाए जाने वाले कानूनों द्वारा शासित होंगे और ऐसे क़ानून विशेष रूप से विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यास के लिए प्रदान करेंगे।

घटक डिग्री महाविद्यालयों और घटक मान्यता प्राप्त संस्थानों के संबंध में उसमें उल्लिखित शक्तियाँ।

अधिनियम की धारा 41 (4) (ii) विश्वविद्यालय को शक्ति प्रदान करती है -

महाविद्यालयों द्वारा की गई शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी देना। अधिनियम की धारा 41 (4) (iii) में कॉलेजों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों का योगदान करने की आवश्यकता है।

शिक्षण और अनुसंधान के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और अन्य उपकरण। धारा 41 (4) (v) विश्वविद्यालय को छात्रों के नामांकन को सीमित करने के लिए आवश्यक होने पर महाविद्यालय संस्थानों की आवश्यकता के लिए शक्ति प्रदान करती है और कुछ

विषयों में। धारा 41 (4) (vi) विश्वविद्यालय को महाविद्यालयों और संस्थानों से योगदान लेने और अनुदान देने की शक्ति प्रदान करती है।

उनके लिए।

हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम की धारा 40 और 41 लटकती हैं

एक साथ और अधिनियम की धारा 40 का अल्पसंख्यक संस्थानों पर कोई अनिवार्य अनुप्रयोग नहीं हो सकता है, यह इस प्रकार है कि अधिनियम की धारा 41 का अल्पसंख्यक संस्थानों पर समान रूप से कोई अनिवार्य अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। अधिनियम की धारा 41 में निहित प्रावधानों पर कोई राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है कि क्या ऐसे प्रावधान किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू किए जा सकते हैं, भले ही संबद्ध कॉलेजों को घटक कॉलेजों में परिवर्तित किया गया हो।

अधिनियम की धारा 33 ए (1) (ए) में निहित प्रावधान बताते हैं कि

प्रत्येक महाविद्यालय एक शासी निकाय के प्रबंधन के अधीन होगा जिसमें इसके सदस्यों में कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि और शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और महाविद्यालय के छात्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह प्रशासन के मौलिक अधिकार पर आक्रमण है। ऐसा कहा जाता है कि महाविद्यालय का शासी निकाय इसके प्रशासन का एक हिस्सा है और इसलिए प्रशासन को छुआ नहीं जाना चाहिए। प्रशासन का अधिकार संस्था के कार्यों के संचालन और प्रबंधन का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग उन व्यक्तियों के निकाय के माध्यम से किया जाता है जिनमें संस्थान के संस्थापकों को विश्वास और विश्वास होता है और जिन्हें उस क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होती है। प्रशासन का अधिकार अनुमेय नियामक उपायों के अधीन है। अनुमेय विनियामक उपाय वे हैं जो प्रशासन के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करते हैं, बल्कि इसे सुविधाजनक बनाते हैं और संस्थान के लाभ के लिए अधिकार का बेहतर और अधिक प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करते हैं और शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन की तात्कालिकता के माध्यम से और प्रबंधन को विस्थापित किए बिना। यदि प्रशासन में सुधार करना है तो यह मौजूदा प्रबंधन की एजेंसी या साधन के माध्यम से किया जाना चाहिए न कि इसे विस्थापित करके।

एसटी, एक्सएवीयर्स कॉलेज वी. गुजरात (रे, सी. जे.) के अधिकार पर प्रतिबंध

केवल आम जनता के हित में थोपा गया प्रशासन, न कि संबंधित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के हित में और उनके लाभ के लिए, प्रशासन में स्वायत्तता को प्रभावित करेगा।

प्रशासन में स्वायत्तता का अर्थ है प्रभावी ढंग से प्रशासन करने का अधिकार।

और संस्थानों के कार्यों का प्रबंधन और संचालन करना। यह अंतर प्रशासन के अधिकार पर प्रतिबंध और प्रशासन के तरीके को निर्धारित करने वाले विनियमन के बीच है। प्रशासन का अधिकार दिन-प्रतिदिन का प्रशासन है। प्रबंधन के कर्मियों में चयन प्रशासन का एक हिस्सा है। विश्वविद्यालय को हमेशा यह देखने का अधिकार होगा कि कोई कुशासन न हो। अगर ऐसा है तो

प्रशासन, विश्वविद्यालय इसे ठीक करने के लिए कदम उठाएगा।

पता लगाने के लिए प्रशासन पर नियंत्रण और जाँच हो सकती है क्या अल्पसंख्यक संस्थान ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो

अल्पसंख्यकों के हित या उनकी आवश्यकताओं के लिए अनुकूल नहीं शिक्षक और छात्र। केरदा राज्य बनाम। बहुत रेव. माँ

प्रांतीय आदि (ऊपर) इस न्यायालय ने कहा कि यदि प्रशासन

चयन में एक निकाय के पास जाता है जिसके बारे में संस्थापकों का कोई कहना नहीं है,

प्रशासन विस्थापित हो जाएगा। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि परिस्थितियाँ उनकी कल्पना तब की जा सकती है जब उनकी एक प्रभावशाली आवाज हो। कि

अधिनियम की धारा 33 ए (1) (ए) में निहित विस्थापन का प्रभाव है प्रबंधन और इसे एक अलग एजेंसी को सौंपना। स्वायत्तता

प्रशासन में खो जाता है। प्रतिनिधियों के रूप में नए तत्व विभिन्न प्रकार के लाए जाते हैं। एक संस्थान का शांत जल

यह न केवल परेशान करेगा बल्कि मिश्रित भी होगा। धारा में ये प्रावधान

33 अतः ए (1) (ए) अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं हो सकता है।

अधिनियम की धारा 33 ए (1) (बी) में निहित प्रावधान थे -

याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई। हस्तक्षेप करने वालों ने उन्हें चुनौती दी

प्रावधान। इस न्यायालय की स्थापित प्रथा यह है कि एक हस्तक्षेपकर्ता है

याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह नहीं की गई दलीलें नहीं उठाना। में। इस तथ्य का दृष्टिकोण कि अल्पसंख्यक संस्थानों को नोटिस दिए गए थे

33 अधिनियम का ए (1) (बी)। धारा 33 ए (1) (बी) में निहित प्रावधान अधिनियम के अनुसार प्राचार्य और सदस्यों की भर्ती के लिए

एक कॉलेज के शिक्षण कर्मचारियों की एक चयन समिति होती है

महाविद्यालय जिसमें प्राचार्य की भर्ती के मामले में,

कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि का

और, के शिक्षण कर्मचारियों के सदस्य की भर्ती के मामले में

महाविद्यालय, द्वारा नामित विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि का

कुलाधिपति और विभाग प्रमुख, यदि कोई हो, विषयों के लिए

ऐसे लोगों द्वारा सिखाया गया। इस संबंध में हस्तक्षेप करने वालों का विवाद

इन प्रावधानों में कोई संकेत और मार्गदर्शन नहीं है किस प्रकार के व्यक्तियों को प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जा सकता है, इस बारे में कार्य करें।

आप। यह सुझाव दिया गया कि ऐसे मामलों को असीमित नहीं छोड़ा जाना चाहिए

चयन की शक्ति। धारा 33 ए (1) (बी) में निहित प्रावधान

इसलिए यह अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं हो सकता है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा अभिशंसन किए गए प्रावधानों के तीसरे सेट में शामिल हैं -

धारा 51 क आ 52 क। धारा 51 ए में कहा गया है कि कोई भी सदस्य

किसी संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षण, अन्य शैक्षणिक और गैर-शिक्षण कर्मचारी [1975] 1 एस. सी. आर.

जाँच के बाद को छोड़कर उन्हें बर्खास्त या हटा दिया जाएगा या पद से हटा दिया जाएगा

जिसमें उसे आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और एक उचित आदेश दिया गया है। सुनवाई का अवसर और जब तक (ए) उसे एक उचित अवसर नहीं दिया जाता है

प्रस्तावित किसी भी ऐसे दंड पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर

उस पर अधिरोपित किया जाए; और (ख) उस पर अधिरोपित दंड है -

कुलपति या विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित

इस संबंध में कुलपति द्वारा प्राधिकृत। आपत्ति ली जाती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा कुलपति द्वारा जुर्माने की मंजूरी के लिए या

उसके द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय का कोई अन्य अधिकारी। सबसे पहले कहा जाता है कि

कि कुलाधिपति को बिना किसी निर्देश के एक पूर्ण शक्ति दी जाती है

और भी। दूसरा, यह कहा जाता है कि शब्द "किसी भी अन्य अधिकारी का

उनके द्वारा अधिकृत विश्वविद्यालय "कुलपतियों को भी शक्ति प्रदान करता है।

किसी को भी अधिकृत करने के लिए और वहाँ कोई दिशानिर्देश नहीं पाए जाते हैं। संक्षेप में, कुलपति को असीमित और अनिर्धारित शक्ति प्रदान की जाती है।

कुलपति द्वारा अनुमोदन एक चेक होने का इरादा हो सकता है। प्रशासन में। धारा 51 ए, खंड में निहित प्रावधान

(ख) अधिनियम को अनुमेय नियामक उपाय नहीं कहा जा सकता है।

चूंकि यह कुलपति को लेने की मनमानी शक्ति प्रदान करता है अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन के अधिकार को समाप्त करना। अनुभाग

51 इसलिए अधिनियम का ए अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं हो सकता है।

अधिनियम की धारा 52 ए में निहित प्रावधानों पर विचार किया गया है।

किसी संबद्ध संस्थान के शिक्षण, अन्य शैक्षणिक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का कॉलेज जो इस तरह के ज्ञापन की सेवा की शर्तों से जुड़ा है

एक नामित सदस्य से मिलकर बना मध्यस्थता न्यायाधिकरण

महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा नामित एक सदस्य

संबंधित सदस्य और कुलपति द्वारा नियुक्त एक अंपायर।

मध्यस्थता के इन संदर्भों से मुकदमेबाजी का एक क्षेत्र सामने आएगा।

शैक्षणिक संस्थान के अंदर अतिक्रमण। का वातावरण

इसका अपना अनुशासनात्मक अधिकार है। शासी निकाय के अपने गुंबद हैं। टिक अधिकार क्षेत्र। यह अधिकार क्षेत्र विस्थापित हो जाएगा। नया अधिकार क्षेत्र

प्रशासन में बनाया जाएगा। धारा में निहित प्रावधान

52 इसलिए अधिनियम का ए अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं हो सकता है।

इन कारणों से धारा 40,41 में निहित प्रावधान,

33 ए (1) (ए), 33 ए (1) (बी), 51 ए और 52 ए अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं किया जा सकता है। संस्थाएं। ये प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं

अल्पसंख्यक संस्थान।

√एक अल्पसंख्यक संस्थान का अंतिम लक्षय भी सामान्य शिक्षा प्रदान करना है

ध्यानपूर्वक अभिनिर्धारित किया कि यह न केवल अनुमेय है बल्कि विनियमित करने के लिए भी वांछनीय है उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए शैक्षिक और शैक्षणिक मामलों में सब कुछ

और शिक्षा के मानकों में एकरूपता।

प्रशासन के क्षेत्र में यह दावा करना उचित नहीं है कि

अल्पसंख्यक संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता होगी। इस पर जाँच करें

प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि प्रशासन कुशल और सुदृढ़ हो और संस्थान की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अपने शैक्षणिक संस्थान को प्रशासित करने के लिए एक अल्पसंख्यक के अधिकार में, इसके हिस्से के रूप में, अच्छे प्रशासन का एक सहसंबंधी कर्तव्य शामिल है।

एसटी. जेवियर कॉलेज वी. गुजरात (रे, सी. जे.)।

शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले अपनी एक अलग दुनिया बनाते हैं जहाँ

हर कोई सीखने का समर्थक है। उन्हें किसी भी भेद के बारे में नहीं बताया जाना चाहिए। उनका सामंजस्य सीखने के लिए समर्पित और अनुशासित प्रयास पर आधारित है। अल्पसंख्यकों के प्रशासन के क्षेत्रों को समायोजित किया जाना चाहिए ताकि सीखने को सबसे उत्कृष्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यह तभी संभव है जब सभी संस्थान इस आदर्श वाक्य का पालन करें कि संस्थान राष्ट्र किसी भी संप्रदाय और भेद की परवाह किए बिना छात्रों और शिक्षकों द्वारा एक साथ सीखने की पूजा के स्थान हैं।

गगनमोहन रेड्डी, जे. इस बड़ी पीठ का गठन किया गया है

कला के तहत मौलिक अधिकारों के दायरे पर विचार करें। 30 (1) , उन अधिकारों का कला के तहत अधिकारों के साथ अंतर संबंध। 29 (1) , अनुच्छेद के तहत अधिकारों की तुलना में राज्य की नियामक शक्तियों का दायरा। 30 (1) , और उपरोक्त कई पहलुओं पर लिए गए दृष्टिकोण के आलोक में संशोधित अधिनियम के कुछ विवादित प्रावधानों की वैधता पर विचार करें।

गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949-जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है। कला के दायरे और दायरे पर हमारे सामने विवाद उठाए गए। 29 (1) और 30 (1) नए नहीं हैं, लेकिन इस न्यायालय द्वारा पहले आग्रह किया गया है और निर्णय लिया गया है। गुजरात राज्य की ओर से एक बार फिर उन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का प्रयास किया गया है जो अल्पसंख्यकों को अपने दम पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकारों की जड़ तक जाते हैं और क्या राज्य बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के साथ समान व्यवहार कर सकता है, एक ऐसा मुद्दा जिस पर इस न्यायालय ने पहले के अवसरों पर बिना किसी अनिश्चित शब्दों में फैसला सुनाया है।

हम माननीय मुख्य न्यायाधीश के फैसले से सहमत हैं

घोषित और अपने निष्कर्षों के साथ कि एसएस। 40 , 41 , 33 अधिनियम के ए (1) (ए), 33 ए (1) (बी), 5.1 ए और 52 ए अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और इसलिए, उनके द्वारा स्थापित संस्थानों और प्रशासकों पर लागू नहीं हो सकते हैं। हम आम तौर पर एक अलग राय लिखना आवश्यक नहीं पाते जब वही बात कही जानी है जैसा कि उनके द्वारा इतनी संक्षिप्त रूप से कहा गया है, लेकिन जो पहले ही कहा जा चुका है उसे फिर से बताने की कोशिश में, कभी-कभी यह धारणा बनाई जाती है कि कुछ नया कहा जा रहा है या पहले से ही संकलित सिद्धांतों से कुछ विचलन है इस तरह के किसी भी विवाद को गुंजाइश देने से बचने के लिए, हम अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए पहले से ही कुछ प्रावधानों का उल्लेख करेंगे। 30 (1) जो विवादित प्रावधानों

के समान हैं, जो इस न्यायालय द्वारा पहले ही लिए जा चुके हैं, उन्हें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में उनके आवेदन में उल्लंघनकारी माना जा सकता है। हालाँकि, इस अलग राय का कारण उन प्रावधानों की अयोग्यता को इंगित करना नहीं है जिन्हें माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होने के लिए माना है, बल्कि इस सवाल की जांच करना है कि अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया अधिकार किस हद तक है: 30 (1) इसमें अल्पसंख्यकों का उनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों के लिए संबद्धता या मान्यता का दावा करने का अधिकार शामिल होगा।

भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों का शिक्षा का प्रशासन करने का अधिकार

इस न्यायालय ने अपनी पसंद के राष्ट्रीय संस्थानों को, हालांकि पूर्ण रूप से स्थापित, विनियामक उपायों के अधीन माना है, जिन्हें राज्य शिक्षा के मानकों की उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए लागू कर सकता है। कैशन। कला के तहत अधिकारों का दायरा और दायरा। 29 (1) और इस न्यायालय द्वारा अपनी सलाह देते समय 30 (1) पर पहले विचार और विश्लेषण किया गया था।

कला के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ पर। 143 संविधान में रे।

(2)

[1944] एफ. सी. आर. 317

(1) [1959] एससीआर 995।

{ [1975

] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

202

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (1)। उस संदर्भ में राष्ट्रपति को दी गई रिपोर्ट, यह सच है, इस न्यायालय के लिए किसी भी बाद के मामले में बाध्यकारी नहीं है, जिसमें किसी भी समान प्रावधान के तहत अधिकारों के उल्लंघन के ठोस मामले पर सवाल उठाया जा सकता है, हालांकि यह बहुत महत्वपूर्ण होने का हकदार है। कला के तहत। 143 यह न्यायालय अपनी राय व्यक्त करता है यदि वह ऐसा चाहता है और कुछ मामलों में वह अपनी राय व्यक्त करने से भी इनकार

कर सकता है। एस्टेट शुल्क का शुल्क (2) दास, सी. जे. द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत। केरल शिक्षा विधेयक, 1957। कुछ मामलों में राय कुछ कथित आकस्मिकताओं या कुछ कल्पित या काल्पनिक स्थितियों पर आधारित हो सकती है, जबकि एक ठोस मामले में कला के तहत अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष आती है। 133 , या कला के तहत विशेष छुट्टी द्वारा। 136 या कला के तहत एक याचिका द्वारा। 32 , कला के आधार पर उसके द्वारा घोषित कानून। 143 भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। फिर भी कला के तहत अधिकारों के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या। 29 (1) और कला। 30 (1) दास, सी. जे. द्वारा, बहुमत के लिए बोलते हुए, अत्यंत स्पष्टता के साथ, महान स्पष्टता और विवेक वह पाठ रहा है जिससे इस न्यायालय ने अपने बाद के निर्णयों में अपना समर्थन प्राप्त किया है। जिस हद तक इस न्यायालय ने इन सिद्धांतों को ठोस मामलों में लागू किया है, दास, सी. जे. द्वारा जो टिप्पणी की गई है, उसके साथ कोई टकराव होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। इस मामले में चुनौती दिए गए समान प्रावधानों पर दिए गए निर्णय प्रथम दृष्टया इन मामलों को नियंत्रित करेंगे, जब तक कि यह बड़ी पीठ उनसे अलग न हो।

केरल शिक्षा विधेयक के कुछ प्रावधानों के संबंध में, अर्थात् -

खंड 9,11 (2) और 12 (4), दास, सी. जे. ने कहाः

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये विज्ञापन के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण हैं।

मंत्रालय और उस अधिकार का उल्लंघन करने के करीब खतरनाक रूप से दिखाई देता है।

लेकिन यह देखते हुए कि वे प्रावधान सभी शिक्षा पर लागू होते हैं राष्ट्रीय संस्थान और सी. एल. एस. के विवादित भाग। 9 , 11

और 12 बीमारों को सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं।

वेतनभोगी शिक्षक जो सेवा प्रदान करने में लगे हुए हैं

राष्ट्र और पिछड़े वर्गों की रक्षा के लिए हम तैयार हैं

वर्तमान में इन खंडों 9,11 (2) और 12 (4) पर विचार करने की सलाह दी जाती है।

अनुमेय विनियमों के रूप में जो राज्य लागू कर सकता है

अल्पसंख्यकों को उनकी शिक्षा के लिए सहायता देने की शर्त के रूप में संस्थाएं "।

इसमें यह भी देखा गया कि सी. एल. एस. 7 , 10 , 11 (1) , 12 (1) , (2) , (3) और (5) को आसानी से उचित विनियमों या शर्तों के रूप में माना जा सकता है

सहायता का अनुदान। लेकिन कुछ प्रावधान सी. एल. एस. के अनुरूप हैं। 11 , 12 (1) , (2) , (3) और (5) को इस न्यायालय द्वारा अमान्य ठहराया गया है जब उन्हें अल्पसंख्यक संस्थानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी गई थी।

केरल राज्य में बनाम. बहुत रेव. मदर प्रोविंशियल (1) सब-एसएस। (1) (2) और केरल विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969 की धारा 53 के (9) को अमान्य माना गया। ये प्रावधान संदर्भ और प्रभाव में सी. एल. के समान हैं। 11 केरल शिक्षा विधेयक, 1957। इसी तरह, एस की उप-धाराएँ (2) और (4)। 56 केरल विश्वविद्यालय अधिनियम का संदर्भ और प्रभाव में समान होना

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के खंड 12 के उपखंड (1), (2) और (3), जिन्हें उचित और उपखंड (4) का उपखंड माना गया था।

(2) [1971] सप. एस. सी. आर 688

(1) [1971] 1 एस. सी. आर. 734

एसटी. एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (रे, सी. जे.)

203

वह खंड जिसे उस मामले में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए खतरनाक रूप से निकट माना गया था, अमान्य माना गया क्योंकि वे केरल शिक्षा अधिनियम की धारा 48 और 49 के साथ आते हैं। गुरु नानक विश्वविद्यालय अधिनियम के क़ानूनों में एक समान समर्थक दृष्टि, अर्थात्,

उपखंडों के समान प्रावधान करने वाला संविधि 17। (1) , (2) और केरल शिक्षा विधेयक के खंड 12 के (3) को डी. ए. वी. में अमान्य ठहराया गया था।

महाविद्यालय आदि। पंजाब राज्य और अन्य (2)। उप-धाराएँ (4) और (6)। 63 केरल विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969, जो समान प्रावधान करता है

आकस्मिकताएँ जो एस में प्रदान की गई हैं। 52 अल्पसंख्यक संस्थानों के शासी निकाय और शिक्षण कर्मचारियों के किसी भी सदस्य या अन्य शैक्षणिक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच विवादों से निपटने वाले अधिनियम के विवादित प्रावधानों में से ए को मदर प्रोविंशियल मामले में अमान्य माना गया था। अधिनियम की विवादित धारा 33 ए (1) और (बी) और 51 ए के प्रावधान प्रकृति में एस. एस. के प्रावधानों के समान हैं। 53 , 56 48 और केरल विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 49। गुरु नानक विश्वविद्यालय अधिनियम की संविधि 2 (1) (ए) भी एस. एस. के अनुरूप है। 48 और केरल विश्वविद्यालय अधिनियम के 49 और प्रकृति में एस के समान है। 33 अधिनियम का ए। डी. ए. वी. कॉलेज मामले में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में उनके आवेदन को अमान्य माना गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जहां तक ये निर्णय केरल शिक्षा विधेयक पर राय से थोड़ा अलग या इसके विपरीत सिद्धांत निर्धारित करते हैं, वे इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून हैं।

आक्षेपित प्रावधान, अर्थात् एस. एस.। 40 , 41 , 33 ए (1) (ए), 33 ए (1)

(ख), 51 ए और 52 ए पहले ही माननीय के निर्णय में दिए जा चुके हैं।

मुख्य न्यायाधीश। इनकी तुलना केरल शिक्षा विधेयक, केरल विश्वविद्यालय अधिनियम और गुरु नानक विश्वविद्यालय अधिनियम के क़ानूनों के प्रावधानों से की जा सकती है, जिन्हें उन प्रावधानों की प्रकृति की आसान समझ के लिए जोड़ा गया है जिन्हें ऊपर उल्लिखित मामलों द्वारा अमान्य ठहराया गया है:

गुरु नानक विश्वविद्यालय

के कानून

केरल विश्वविद्यालय अधिनियम

धारा 53

निजी कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति

पैर

:

(1) निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के पद

चयन के पद होंगे।

(2) राजकुमार के पद पर नियुक्ति

एक निजी कॉलेज में दोस्त बनाया जाएगा

शासी निकाय या प्रबंध परिषद द्वारा

सिल, जैसा भी मामला हो, के बीच से

महाविद्यालय के या सभी के शिक्षक

ऐसे महाविद्यालय में कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है या महाविद्यालय, अन्य व्यक्तियों से।

(9) कोई भी शिक्षक, एक से व्यथित

उप-धारा (7) के तहत नियुक्ति

तारीख से साठ दिनों के भीतर नियुक्ति, सिंडिकेट को अपील, और

उस पर सिंडिकेट का निर्णय होगा

अंतिम होना, धारा 56-शिक्षक संविधि की सेवा की शर्तें 17 स्वीकृत होंगी-प्रारंभ में कुलपति द्वारा नियुक्त कर्मचारी। डी.

निजी महाविद्यालयों का

.....बाद के सभी परिवर्तनों की सूचना दी जाएगी।

कुलपतियों के लिए विश्वविद्यालय

(1) शिक्षकों की सेवा की शर्तें

मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण संस्थान के मामले में

शर्तों सहित निजी महाविद्यालयों का

शिक्षक, छात्र अनुपात नहीं होगा

वेतन, पेंशन, भविष्य निधि से संबंधित,

1 से कम होना: 12 . गैर-

सरकारी

उपदान, बीमा और सेवानिवृत्ति की आयु

महाविद्यालय आवश्यकता

का पालन करेंगे

करेगा: जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है

अध्यादेश शासन में

निर्धारित किए गए विचार

क़ानूनों।

ई में शिक्षकों की सेवा और

आचरण

गैर-सरकारी कॉलेज जो भी

हों

1. (2) निजी महाविद्यालय का कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं करेगा

किया जाए, खारिज किया जाए, हटाया जाए या कम किया जाए

विश्वविद्यालय द्वारा

निर्मित।

:

शासी निकाय या प्रबंधन द्वारा पद

पूर्व मंजूरी के बिना परिषद

कुलपति या निलंबित कर दिया गया

-शासी निकाय द्वारा पेंशन • या

निरंतर अवधि के लिए प्रबंध परिषद:

ऐसे पूर्व के बिना पंद्रह दिनों से अधिक

!

विवेकपूर्ण सजा।

(4) एक शिक्षक जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई

कार्रवाई करने का अधिकार होगा

सिंडिकेट और सिंडिकेट को अपील करें

पुनर्स्थापना का आदेश देने की शक्ति होगी

गलत तरीके से हटाने के मामले में शिक्षक

या बर्खास्तगी और ऐसे अन्य आदेश का आदेश देना

उपचारात्मक उपाय जो वह उचित समझता है, और

शासी निकाय या प्रबंध परिषद के रूप में

मामला हो सकता है, इसका पालन करेगा

आदेश दें।

(2)

(3)

क़ानून 2 (1) (ए)

प्रवेश के लिए आवेदन करने वाला कॉलेज

विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार भेजे जाएँगे

पंजीयक को आवेदन पत्र

और सीनेट को संतुष्ट करेगा:

(क) कि महाविद्यालय में एक नियम होगा।

जार्ली द्वारा गठित शासी निकाय में शामिल हैं

20 से अधिक व्यक्तियों को मंजूरी नहीं

सीनेट द्वारा और अन्य सहित।

2 विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि और

महाविद्यालय के पदेन प्राचार्य,

बशर्ते कि उक्त शर्त सरकार द्वारा अधिकृत कॉलेज के मामले में लागू नहीं होगी, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य (पदेन) और विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधियों से बनी एक सलाहकार समिति होगी।

:

: .

(5) यह सरकार का कर्तव्य होगा।

निजी महाविद्यालय के प्रशासन के लिए निकाय

इन प्रावधानों के अनुसार

अधिनियम और कानून। अध्यादेश, विनियमन

राज्य, नियम, उप-कानून। और आदेश दिए गए

इसके नीचे।

(6) की शक्तियाँ और कार्य

सदस्यगण

शासी निकाय, का निष्कासन

पीछा किया।

इसकी प्रक्रिया और

इसके द्वारा, अपनी शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित, क़ानूनों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(7) कुछ भी शामिल होने के बावजूद

उप-धारा (6) में, सरकार के निर्णय

बैठकों में अर्निंग बॉडी ली जाएगी

साधारण बहुमत के आधार पर

सदस्य उपस्थित होते हैं और मतदान करते हैं।

धारा 49

निजी महाविद्यालयों के लिए प्रबंध परिषद निगमित प्रबंधन के तहत

(a) ऐसे में बारी-बारी से एक मूलधन

जिस तरह से निर्धारित किया जाए

कानून;

(ख) निजी महाविद्यालय का प्रबंधक:

´ (ग) विश्वविद्यालय द्वारा नामित व्यक्ति

में प्रावधानों के अनुसार

वह पक्ष जो क़ानूनों में निहित है;

((घ) सरकार द्वारा नामित व्यक्ति

• मन में;

(ङ) तदनुसार चुने गए दो व्यक्ति

ऐसी प्रक्रिया के साथ जो निर्धारित की जाए

आपस में कानूनों द्वारा

सभी प्रायमरी के स्थायी शिक्षकों द्वारा

वेटे कॉलेज; और (2)

(3) `

(च) पंद्रह से अधिक व्यक्ति नामित नहीं

शैक्षिक एजेंसी द्वारा स्थापित।

(2) प्रबंध परिषद एक होगी।

स्थायी उत्तराधिकार रखने वाला निगमित निकाय

और एक आम मुहर।

(3) निजी महाविद्यालयों के प्रबंधक

प्रबंध के अध्यक्ष होंगे

परिषद।

(4) प्रबंध परिषद के सदस्य

चार की अवधि के लिए पद धारण करेगा

संविधान की तारीख से वर्षों,

(5) यह प्रबंधन का कर्तव्य होगा। सभी निजी निकायों का प्रशासन करने के लिए परिषद

निगमित प्रबंधन के तहत महाविद्यालय इसके प्रावधानों के अनुसार

अधिनियम और कानून, अध्यादेश, विनियमन

दान, अलविदा-वहां बनाए गए कानून और आदेश

नीचे।

(6) की शक्तियाँ और-कार्य

परिषद का प्रबंधन, सदस्यों को हटाना

उसका और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

इसके द्वारा, इसके प्रतिनिधिमंडल सहित शक्तियाँ, क़ानून द्वारा निर्धारित की जाएंगी

टेस।

(7) कुछ भी शामिल होने के बावजूद

उप-धारा (6) में,

प्रबंध परिषद की बैठक में लिया जाएगा

"

सदस्य उपस्थित होते हैं और मतदान करते हैं। धारा 63-प्रबंधन को विनियमित करने की शक्ति

निजी महाविद्यालयों का संचालन

(4) यदि शासी निकाय या प्रबंधन

परिषद, जैसा भी मामला हो, अस्वीकार करती है 3

(2) .

(1) .

ई.

15

विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय

-

थो के प्रबंधन के साथ संबंध

एल.

निजी महाविद्यालयों को मामले भेजे जाएंगे।

131

शासी निकाय या प्रबंध
परिषद द्वारा
सिल, जैसा भी मामला हो, सरकार को

सुप.

तिथि के एक महीने के भीतर।
उप-धारा के तहत रिपोर्ट की प्राप्ति

/ 75

(3) इसके बाद ऐसा आदेश
कौन पारित करेगा?

जिस पर वे उचित समझते हैं
और संवाद करते हैं

शासी निकाय के लिए समान
या

प्रबंध परिषद और
विश्वविद्यालय को भी

सिटी।

(6) उप के तहत नियुक्त
प्रबंधक

धारा 50 की धारा (1) बाध्य
होगी।
के निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए

विश्वविद्यालय और यदि
किसी भी समय, यह प्रकट होता है

विश्वविद्यालय के लिए कि
प्रबंधक नहीं है
अपने निर्णयों को पूरा करने के लिए, वह कर सकता है

लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारण और प्रबंधक को मौका देने के बाद

कार्यालय से और किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करें परामर्श के बाद प्रबंधक बनना

शैक्षिक संस्था,

.

लगातार और स्पष्ट निर्णयों के बावजूद जो हुए हैं

कुछ राज्यों के विश्वविद्यालय अधिनियमों के कुछ प्रावधानों को अवैध करार देते हुए कहा गया है कि वे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के अधिकार में निहित स्थितियों में अल्पसंख्यकों के प्रबंधन के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं।

कला के तहत उनकी पसंद। 30 (1) , गुजरात राज्य ने उन समान प्रावधानों को शामिल किया है जिन्हें इस न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन मल में

उस अधिकार का मौलिक अधिकार का कोई भी उल्लंघन जिसकी गारंटी है

अल्पसंख्यकों का प्रभाव उस राज्य की सीमाओं से परे होगा और

देश के बाकी हिस्सों में अल्पसंख्यक अपने बारे में आशंकित महसूस करेंगे

अन्य राज्यों द्वारा इसी तरह से अधिकारों पर आक्रमण किया जा रहा है। एक प्रकार से राजनीतिक निकाय में स्थिरता एक राज्य की कार्रवाई से पैदा होगी जो

के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए एक जानबूझकर प्रयास के रूप में माना जाएगा

अल्पसंख्यक जहाँ पहले के समान प्रयासों को सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी

और उल्लंघनकारी प्रावधान अमान्य ठहराए गए।

जिस केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया था, वह संभवतः वास्तविक है

इस मुद्दे की संवेदनशील प्रकृति के कारण कोई विवाद सामने नहीं आया

उन लोगों के विपरीत जिन पर पहले से ही विचार किया गया है और इस द्वारा निर्णय लिया गया है

अदालत, हालांकि हमें एटर के व्यक्तिगत विचारों का लाभ था

नी-उन अधिकारों के कुछ पहलुओं पर सामान्य। व्यवहार की समानता

खनन। स्थायी न्यायालय की सलाहकार राय के अनुसार अल्बानिया में अल्पसंख्यक स्कूलों पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय (6 अप्रैल 1935),

न्यायालय के प्रकाशन, श्रृंखला ए/बी संख्या 64, पी। 19 :

" जबकि वास्तव में समानता की आवश्यकता शामिल हो सकती है

एक परिणाम प्राप्त करने के लिए अंतर उपचार जो स्थापित करता है

विभिन्न स्थितियों के बीच एक संतुलन की कामना करता है।

. ऐसे मामलों की कल्पना करना आसान है जिनमें समानता हो।

बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार, जिनकी स्थिति

राष्ट्र और आवश्यकताएँ अलग हैं, जिसके परिणामस्वरूप असमानता होगी।

.....बहुसंख्यक सदस्यों के बीच समानता और

.....

अल्पसंख्यकों के लिए प्रभावी, वास्तविक समानता होनी चाहिए। . . . .

हमारी राय है कि यह दृष्टिकोण एक ध्वनि है और विवाद विज्ञापन है वैधता के समर्थन में कुछ उत्तरदाताओं की ओर से

विवादित प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

जहाँ तक संबद्धता या मान्यता के अधिकार का संबंध है, नहीं।

संदेह, दास, सी. जे. की टिप्पणियाँ, रे में। केरल शिक्षा विधेयक

मामला (1) कला के तहत ऐसे किसी भी अधिकार को नकारात्मक प्रतीत होता है। 30 (1) . उन्होंने कहा कि

पी। 1067 :

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौलिक अधिकार जैसी कोई चीज नहीं है

राज्य द्वारा मान्यता लेकिन शिक्षा को मान्यता देने से इनकार करना

शिक्षा के प्रशासन के उनके संवैधानिक अधिकार उनकी पसंद की राष्ट्रीय संस्थाएं सच्चाई में हैं और प्रभावी रूप से

उन्हें कला के तहत उनके अधिकारों से सम्मानित करें। 30 (1) . ” .

ये अवलोकन हमें सी. ई. आर. से कुछ भिन्न प्रतीत होते हैं। अन्य टिप्पणियों पर ध्यान दें। लेकिन अगर इन टिप्पणियों की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है

(1) [1959] एससीआर 995।

एसटी. XAVIERS कॉलेज v. गुजरात (जगमोहन रेड्डी, जे.) 211।

शून्य में, उनका मिलान और सामंजस्य किया जा सकता है। दास, सी. जे. ने पहले पीपी में अवलोकन किया था। 1066-1067 वह:

" अल्पसंख्यक, काफी स्पष्ट रूप से, इसे आवश्यक मानते हैं

कि उनके बच्चों की शिक्षा उनके अनुसार होनी चाहिए।

उनके धर्म की शिक्षाओं के साथ और वे धारण करते हैं, काफी सम्मान

जनता के सभी सदस्यों के लिए डिज़ाइन किए गए स्कूल लेकिन केवल कर सकते हैं प्रभाव और गुइ के तहत संचालित स्कूलों में सुरक्षित किया जाए

अपने धर्म के सिद्धांतों में पारंगत लोगों का नृत्य और

उनकी संस्कृति की परंपराओं में.. वे भी चाहते हैं

कि उनके शैक्षणिक संस्थानों के विद्वानों को बाहर जाना चाहिए दुनिया योग्यताओं के साथ अच्छी तरह से और पर्याप्त रूप से सुसज्जित है

जीवन में एक उपयोगी कैरियर के लिए आवश्यक। लेकिन शिक्षा के अनुसार

कैशन कोड अब संचालन में है जिसके लिए यह अनुमति है

आक्षेपित प्रावधानों के प्रभाव का पता लगाने के लिए

उच्च के लिए अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं है विश्वविद्यालय में उसकी शिक्षा और प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं

लोक सेवाएँ। मान्यता के बिना, इसलिए,

द्वारा स्थापित या स्थापित किए जाने वाले शैक्षणिक संस्थान

अल्पसंख्यक समुदाय अपने वास्तविक उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं।

चयन और कला के तहत अधिकार। 30 (1) प्रभावी नहीं हो सकता है व्यायाम किया। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार

इसलिए उनकी पसंद का मतलब वास्तविक रूप से स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए।

समुदाय और वे विद्वान जो अपने शैक्षणिक संस्थान का सहारा लेते हैं। शब्द "।

कला के तहत अधिकार। 30 वैक्यू में अभ्यास नहीं किया जा सकता है। न ही संबद्धता या मान्यता को राज्य द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों के रूप में संदर्भित करना सही होगा। अपने नागरिकों की शिक्षा और ज्ञान पर जोर देने वाली सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसे तत्व होने चाहिए जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। कला के तहत अधिकार का सार्थक अभ्यास। 30 (1) अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा दी जाने वाली धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की मान्यता को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए और जिसके बिना अधिकार मात्र होगा। भूसा। इस न्यायालय ने अब तक समतुल्य शर्तों पर संबद्धता या मान्यता देने के सभी प्रयासों को लगातार खारिज कर दिया है। कला के तहत अपने अधिकारों का समर्पण करना। 30 (1) उन अधिकारों को कम करने या छीनने के रूप में। फिर से संबद्धता के बिना कोई सार्थक नहीं हो सकता है

कला के तहत अधिकार का प्रयोग। 30 (1) , दी जाने वाली संबद्धता उस अधिकार के अनुरूप होनी चाहिए, और न ही यह अप्रत्यक्ष रूप से वह हासिल करने का प्रयास कर सकता है जो वह सीधे नहीं कर सकता है। केरल शिक्षा विधेयक मामला (1) रेव. सिद्धजभाई भाई और

अन्य बनाम देखें। बॉम्बे राज्य और एक अन्य (2) और डी. ए. वी. कॉलेज मामला (3) पी. 709 .

यदि मान्यता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका तार्किक परिणाम होगा।

इस अभिधारणा का यह होगा कि राज्य को सभी संस्थानों के लिए सामान्य शर्तों को छोड़कर मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी राज्य द्वारा मान्यता अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में सीमित है, तो इसके तहत

(1) [1959] एस. सी. आर. 995, पृ. 1059 , 1060 , 1067 & 1068. (2) [1963] 3 एस. सी. आर. 837 856 पर।

(3) [1971] सप. 709 पर एस. सी. आर. 688।

[1975] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

212

इस शक्ति का प्रयोग करने की आड़ में, राज्य शर्तें निर्धारित नहीं कर सकता है

एक निष्कर्ष जो संभवतः उपरोक्त टिप्पणियों से प्राप्त किया जा सकता है दास, सी. जे. का दूसरा निष्कर्ष जो संभव है वह यह है कि

सेवाएँ कानून के प्रावधानों तक ही सीमित रखनी होंगी

जिसकी वैधता के लिए न्यायालय की राय मांगी गई थी। उस मामले में,

विधेयक में स्कूल तैयार करने के लिए स्कूलों को मान्यता देने का प्रावधान किया गया था

बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए डेंट, और इस तरह प्रदान करने में

इसने ऐसी शर्तें लगाई थीं जिन्हें न्यायालय ने समान माना था -

अल्पसंख्यक संस्थानों को आत्मसमर्पण करने या उन्हें अस्वीकार करने की आवश्यकता होती है

कला के तहत अधिकार। 30 (1) . न्यायालय का संबंध किसी कानून से नहीं था

जो संबद्धता या मान्यता के सवाल से बिल्कुल भी नहीं निपटता था या जहाँ शिक्षण केवल राज्य द्वारा प्रबंधित और मुख्य शिक्षा तक ही सीमित था।

जर्जर स्कूल। इसलिए दास, सी. जे. की टिप्पणियाँ, कड़ाई से बोलते हुए, इस तथ्य स्थिति पर लागू नहीं हो सकती हैं। जब इसे पढ़ा जाता है, तो वे ऐसा नहीं कर सकते।

यह अभिनिर्धारित किया जाए कि राज्य को पुनरावृत्ति देने के लिए प्रावधान करना चाहिए

कम से कम अल्पसंख्यक संस्थानों को या मान्यता विषय को मान्यता देना।

ऐसी शर्तों के लिए जो सच्चाई में और प्रभावी रूप से एक के बराबर नहीं होगी

कला के तहत उनके अधिकार का उल्लंघन। 30 (1) . दूसरे शब्दों में, जहाँ

कानून किसी भी शिक्षा संस्थान को मान्यता या संबद्धता देने का प्रावधान नहीं करता है, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक।

संस्था, क्या अल्पसंख्यक संस्था जमीनी स्तर पर मान्यता का दावा कर सकती है

कि मान्यता या संबद्धता के बिना शैक्षणिक संस्थान स्थापित करता है

उनके द्वारा लुभाया गया अपनी पसंद के वास्तविक उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता है और छोटे लोग कला के तहत अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 30 (1) ? अगर

टिप्पणियों से बहने वाला तार्किक उत्तर यह है कि यह नहीं कर सकता है, तो

सवाल यह उठेगा कि अनुच्छेद (1) का उद्देश्य क्या है। 30 सेवा करता है? एकमात्र उद्देश्य जो कला के तहत मौलिक अधिकार है। 30

(1) उस मामले में यह काम करेगा कि अल्पसंख्यक स्थापित कर सकते हैं

उनके संस्थान, अपने पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, निर्देश प्रदान करते हैं

उनकी पसंद के विषय, परीक्षा आयोजित करते हैं और डिग्री या डिप लोमा प्रदान करते हैं। ऐसे संस्थानों को अपने सम्मान और डिप्लोमा को मान्यता प्राप्त करने और सहायता मांगने का अधिकार है, जहां उत्कृष्टता के आधार पर समान शिक्षा देने वाले अन्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता दी जाती है।

उनके द्वारा प्राप्त लेंस। राज्य उन्हें मान्यता देने के लिए बाध्य है

योग्यता और संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

अपनी शैक्षिक स्थिति में उत्कृष्टता की कमी के आधार को छोड़कर

जहाँ तक डिग्री या शैक्षिक योग्यता की मान्यता है

जहाँ तक सहायता का संबंध है, संबंधित और कुशल प्रबंधन की कमी।

डी. ए. वी. कॉलेज मामले में (1) मिनो की अनिवार्य संबद्धता

पूरे भारत में भाषाई राज्यों के गठन को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय के उन शैक्षणिक संस्थानों को, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से अल्पसंख्यकों की भाषा के अलावा अन्य निर्देशों का एक माध्यम निर्धारित किया था, सुझाव दिया गया था कि किसी भी अनिवार्य संबद्धता पर जोर नहीं दिया जा सकता है

जिस पर कला के तहत गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन होता है। 29 (1) और 30 (1)। यदि, जैसा कि माना गया था, अनिवार्य संबद्धता खराब है, तो यह उन्हें उस भाषाई राज्य में एक विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के लिए स्वतंत्र कर देगा जो अल्पसंख्यकों की भाषा और लिपि के लिए सुविधा प्रदान करता है। यह पूर्व-मान लेता है कि

(1) [1971] सप. 709 पर एस. सी. आर. 688।

एसटी. एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (खन्ना, जे.)

213

भारत में जहां अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करना संभव है, वहां मान्यता या संबद्धता प्राप्त करने का अधिकार है।

हम इस संबंध में पार्लिया के सर्वसम्मत प्रस्ताव का उल्लेख कर सकते हैं।

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपायों पर 19 सितंबर, 1956 को राज्य पुनर्गठन रिपोर्ट के भाग IV में यह सिफारिश की गई थी कि संबंधित राज्यों को अपने विश्वविद्यालय के कानूनों में संशोधन करके अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। संसद द्वारा अनुमोदित ज्ञापन के पांचवें पैराग्राफ में कहा गया है:

" 5. अल्पसंख्यक लेन का उपयोग करने वाले स्कूलों और कॉलेजों की संबद्धता

अनुमान लगाएँ। - पूर्व में निहित प्रस्तावों के साथ जुड़ा हुआ

अनुच्छेदों का त्याग करना शिक्षा की संबद्धता का प्रश्न है।

नए या पुनर्गठित राज्यों में स्थित राष्ट्रीय संस्थान

उपयुक्त विश्वविद्यालय या शिक्षा बोर्ड। यह है

पाठ्यक्रम वांछनीय है कि विकसित होने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए

ऐसी व्यवस्थाएँ जिनके द्वारा विद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थान और

महाविद्यालय संबद्ध हो सकते हैं, अध्ययन के पाठ्यक्रमों के संबंध में

मातृभाषा, विश्वविद्यालयों और अन्य प्राधिकरणों के लिए जो हैं

एक ही राज्य में स्थित है। हालाँकि, यह हमेशा नहीं हो सकता है

इस तरह की व्यवस्था करना संभव है; और

इस तरह के संस्थानों की संख्या, यह कभी-कभी कोन हो सकती है

स्वयं संस्थाओं को, कि उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए बाहर स्थित उपयुक्त निकायों से संबद्धता प्राप्त करने के लिए

राज्य। इसे वास्तव में एक आवश्यक परिणाम माना जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 30 में निहित प्रावधानों के लिए,

जो अल्पसंख्यकों को स्थापना और विज्ञापन का अधिकार देता है

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों के मंत्री "।

ऐसी मान्यता या संबद्धता प्राप्त करना असुविधाजनक या असंभव है। जिस राज्य में वे स्थापित हैं, उसके बाहर भी? इस तरह के दायरे में

विश्वविद्यालय शिक्षा सहित शिक्षा राज्य का विषय है और राज्य की विधायी शक्ति भी कला के अधीन है। 29 (1)

और कला। 30 (1) , एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने में सक्षम अल्पसंख्यक

मान्यता पर जोर दे सकते हैं, जहां संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है

उनके द्वारा प्रदत्त शैक्षिक योग्यताओं के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम,

चाहे डिग्री, डिप्लोमा या अन्य प्रमाण पत्र, जो इसके अनुरूप हों

राज्य द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित शैक्षिक मानक ऐसी उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य प्रमाण पत्र।

खन्ना, जे. के अधिकारों का दायरा और दायरा क्या है?

खंड (1) के तहत अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करना। संविधान के अनुच्छेद 30 का वह प्रश्न है जो उत्पन्न होता है

अहमदाबाद सेंट जेवियर्स द्वारा दायर इस रिट याचिका पर विचार

कॉलेज सोसायटी और दूसरा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

याचिका में शामिल प्रतिवादी गुजरात राज्य हैं। और गुजरात विश्वविद्यालय।

पहला याचिकाकर्ता (इसके बाद याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित) है

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर.) के तहत पंजीकृत सोसायटी।

214

21 1860 का) और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम 29) के तहत एक ट्रस्ट। याचिकाकर्ता अहमदाबाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स चला रहा है। उक्त महाविद्यालय की स्थापना जून 1955 में एक धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई थी जिसे सोसाइटी ऑफ जीसस के नाम से जाना जाता है, जो कैथोलिक पादरियों और भाइयों का एक धार्मिक आदेश है। पेट्टीशनर सोसायटी का गठन उपरोक्त पुरुषों के कॉलेज को अपने नियंत्रण में लेने के उद्देश्य से किया गया था।

वर्ग और पंथ बशर्ते वे योग्यता शैक्षणिक मानकों को प्राप्त करते हैं, उन्हें सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है। पूर्ववर्ती बॉम्बे राज्य के महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य में विभाजन से पहले, बॉम्बे राज्य विधानमंडल

गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 पारित किया (इसके बाद प्रमुख अधिनियम के रूप में संदर्भित)। अधिनियम का उद्देश्य एक शिक्षण और संबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना और उसे निगमित करना था। सेंट जेवियर्स कॉलेज को जून 1955 को या उसके आसपास प्रधान

अधिनियम की धारा 33 के तहत संबद्धता प्रदान की गई थी। मूल अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाएँ थीं। हम प्रासंगिक परिभाषाएँ निर्धारित कर सकते हैं:

" (1) ' 'सम्बद्ध महाविद्यालय' से संबद्ध महाविद्यालय अभिप्रेत है।

धारा 5 या 33 के तहत।

(2) ' कॉलेज 'का अर्थ है डिग्री कॉलेज या इंटरमीडिएट।

महाविद्यालय।

(2(क) 'संविधान महाविद्यालय' से विश्वविद्यालय महाविद्यालय अभिप्रेत है।

या धारा 41 के तहत संबद्ध कॉलेज को घटक बनाया गया है।

(3) ' 'डिग्री कॉलेज' का अर्थ है एक संबद्ध कॉलेज जो अपने छात्रों को परीक्षा क्वाली में जमा करने के लिए अधिकृत है।

विश्वविद्यालय की किसी भी डिग्री के लिए आवेदन करना।

(8) ' मान्यता प्राप्त संस्थान का अर्थ है किसी संबद्ध महाविद्यालय के अलावा अनुसंधान या विशेष अध्ययन के लिए एक संस्थान।

और विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त।

(12) ' शिक्षक का अर्थ है प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और ऐसे अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रदान करते हैं। शहर, एक संबद्ध कॉलेज या एक मान्यता प्राप्त संस्थान जो हो सकता है

कानून द्वारा शिक्षक घोषित किया जाए।

(13) ' विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अर्थ है शिक्षक एपी।

प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इंगित या मान्यता प्राप्त

उसकी ओर से निर्देश।

(15(क) 'विश्वविद्यालय महाविद्यालय' से ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो

-

विश्वविद्यालय इस अधिनियम के तहत स्थापित या रखरखाव कर सकता है या महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया और इसके द्वारा इसका रखरखाव किया गया।

(16) ' विश्वविद्यालय विभाग 'का अर्थ है कोई महाविद्यालय, स्नातकोत्तर या अनुसंधान संस्थान या विभाग जिसका रखरखाव किया जाता है।

विश्वविद्यालय द्वारा "।एसटी.

एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (खन्ना, जे.)

215

प्रधान अधिनियम की धारा 39 में प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर, सभी स्नातकोत्तर निर्देश, शिक्षण और प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा या ऐसे संबद्ध कॉलेजों या संस्थानों द्वारा और ऐसे विषयों में आयोजित किया जाएगा जो क़ानून द्वारा निर्धारित किए जाएं। अधिनियम की धारा 40 के अनुसार, उस तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर जिस दिन धारा 3 (जो विश्वविद्यालय के निगमन से संबंधित है) लागू होती है, सीनेट यह निर्धारित करेगी कि इंटरमीडिएट परीक्षाओं के चरण से परे सभी शिक्षण और प्रशिक्षण निर्देश, अहमदाबाद शहर के क्षेत्र के भीतर और ऐसे अन्य सन्निहित क्षेत्र जो सीनेट निर्धारित करे, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाएंगे और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। सीनेट तब राज्य सरकार को अपने निर्णय से अवगत कराएगी जो सरकार, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि धारा 41 के प्रावधान उस तारीख को लागू होंगे जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए। धारा 40 को 1954 के बॉम्बे अधिनियम 30 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप "तीन वर्ष" शब्दों को "सात वर्ष" शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया था। उस संशोधन का प्रभाव यह था कि सीनेट अधिनियम की धारा 40 के तहत उस तारीख से सात साल के भीतर अपना निर्णय ले सकती थी जिस दिन धारा 3 लागू हुई थी। प्रधान अधिनियम की धारा 41 घटक महाविद्यालयों और संस्थानों से संबंधित थी। इसके प्रावधान

अहमदाबाद क्षेत्र के भीतर के राज्य घटक संस्थान होंगे। विश्वविद्यालय से। इसके भीतर कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है।

अहमदाबाद क्षेत्र, यह निर्दिष्ट किया गया था, की सहमति से बचत होगी विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की मंजूरी,

किसी भी तरह से किसी के साथ संबद्ध, या किसी भी विशेषाधिकार में प्रवेश चाहते हैं

कानून द्वारा स्थापित अन्य विश्वविद्यालय। धारा 41 की उप-धारा (4)

घटक महाविद्यालयों और घटक के संबंधों से निपटा गया

अहमदाबाद क्षेत्र के भीतर संस्थान और यह प्रदान करते हुए कि

इस संबंध में बनाए जाने वाले कानूनों द्वारा शासित होगा। द.

जिन विषयों के संबंध में क़ानूनों में प्रावधान किए जाने थे

विशेष रूप से घटक महाविद्यालयों के संबंधों के संबंध में और

मान्यता प्राप्त संस्थानों को भी निर्दिष्ट किया गया था।

गुजरात विश्वविद्यालय की सीनेट ने कोई निर्णय नहीं लिया

सात वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर धारा 40 में उल्लिखित। द.

उक्त अवधि 22 नवंबर, 1957 को समाप्त हो गई। संबद्ध महाविद्यालय

तदनुसार गुजरात विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय बने रहे।

उस तारीख को बदल दें। 28 सितंबर, 1971 को सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया।

कि सभी निर्देश, शिक्षण और प्रशिक्षण के स्तर से परे अहमदाबाद शहर में इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित की जाएगी।

विश्वविद्यालय द्वारा और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता है। द.

विश्वविद्यालय के कुलसचिव को निर्णय से अवगत कराने का निर्देश दिया गया था

सीनेट से राज्य सरकार तक। याचिकाकर्ताओं और कुछ

इसके बाद अन्य लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कि सीनेट की शक्तियाँ और

मूल अधिनियम की धारा 40 के तहत राज्य सरकार ने

22 नवंबर, 1957 को समाप्त हो गया जब सात साल की अवधि

मूल अधिनियम के प्रारंभ से ही इसकी अवधि समाप्त हो गई थी।

में

[1975] 1. एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

216

वैकल्पिक रूप से, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह कहा गया था कि धारा 40 और 41 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14,19,26,29 और 30 का उल्लंघन करते हैं। इन याचिकाओं के लंबित होने को देखते हुए, राज्य सरकार ने 28 सितंबर, 1971 को सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की।

गुजरात विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 (का अधिनियम संख्या 6)

1973) (इसके बाद संशोधन अधिनियम के रूप में संदर्भित) को गुजरात विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था। संशोधन अधिनियम 12 मार्च, 1973 को लागू हुआ। इसने "सीनेट" शब्द के स्थान पर "अदालत" शब्द और "सिंडिकेट" शब्द के स्थान पर "कार्यकारी परिषद" शब्द रखा। सुविधा के लिए संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम को संशोधित अधिनियम के रूप में वर्णित किया जा सकता है। संशोधित अधिनियम की धारा 33 ए, 39,40,41,51 ए और 52 ए निम्नानुसार है:

" 33 ए. (1) प्रत्येक महाविद्यालय (सरकार को छोड़कर)

सरकार द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय या महाविद्यालय) गुजरात विश्वविद्यालय के आरंभ होने से पहले

(संशोधन) अधिनियम, 1972 (इसके बाद इस धारा में देखें

लाल से 'इस तरह की शुरुआत')

(क) एक शासी निकाय के प्रबंधन के अधीन होगा।

कुलपति और तीन प्रतिनिधियों द्वारा महाविद्यालय के शिक्षक और प्रत्येक में कम से कम एक प्रतिनिधि

गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सदस्य और छात्र

ऐसे महाविद्यालयों में से क्रमशः चुने जाने के लिए

शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सदस्य और छात्र;

और

(ख) प्राचार्य और सदस्यों की भर्ती के लिए

एक कॉलेज के शिक्षण कर्मचारियों में से एक चयन कॉम है महाविद्यालय की समिति जिसमें शामिल होंगे -

(1) प्रधानाचार्य की भर्ती के मामले में,

उपाध्यक्ष द्वारा नामित विश्वविद्यालय की प्रस्तुति

कुलाधिपति और

(2) सदस्य की भर्ती के मामले में

महाविद्यालय के शिक्षण कर्मचारी, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि

कुलाधिपति और कुलाधिपति द्वारा मनोनीत

पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित विभाग, यदि कोई हो

ऐसे सदस्य से।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक महाविद्यालय, -

(क) इस तरह की शुरुआत के बाद छह महीने की अवधि के भीतर

इसके शासी निकाय का गठन या पुनर्गठन

उप-धारा (1) के साथ औपचारिकता, और

((ख) इस प्रकार के काम के बाद पहली बार कब और कब अवसर आता है।

एस. टी. के प्राचार्य और शिक्षकों की भर्ती के लिए।

एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (खन्ना, जे.)

महाविद्यालय अपनी चयन समिति का गठन या पुनर्गठन करता है ताकि वह उप-धारा (1) के अनुरूप हो।

(3) उप-धारा (1) के प्रावधान माने जाएंगे।

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक महाविद्यालय की संबद्धता की शर्त होना।

39. विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर, सभी स्नातकोत्तर

विश्वविद्यालय या ऐसे संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थानों द्वारा और ऐसे विषयों में जो क़ानून द्वारा निर्धारित किए जाएं, निर्देश, शिक्षण और प्रशिक्षण का संचालन किया जाएगा।

40. (1) न्यायालय यह निर्धारित कर सकता है कि सभी निर्देश,

अध्ययन के उन पाठ्यक्रमों में शिक्षण और प्रशिक्षण, जिनके संबंध में विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम है, विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा संहिताबद्ध किया जाएगा और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

विश्वविद्यालय और न्यायालय अपने निर्णय को सूचित करेंगे -

राज्य सरकार।

(2) उप-धारा के तहत संचार की प्राप्ति पर

(1) , राज्य सरकार ऐसी जाँच करने के बाद

जैसा कि वह उचित समझता है, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा करता है

कि धारा 41 के प्रावधान लागू होंगे।

ऐसी तिथि पर जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए।

41. (1) विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर सभी महाविद्यालय जो

उप के तहत विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में भर्ती हैं धारा 5 की धारा (3) और उक्त क्षेत्र के भीतर सभी महाविद्यालय

जो इसके बाद विश्वविद्यालय से संबद्ध हो सकता है

विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय।

(2) विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर सभी संस्थान

धारा 35 और 63 के तहत मान्यता प्राप्त या इसके तहत अनुमोदित धारा 35क एकर घटक संस्था होयत।

विश्वविद्यालय।

(3) इसके भीतर कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है।

विश्वविद्यालय क्षेत्र विश्वविद्यालय की सहमति से बचेगा।

और राज्य सरकार की मंजूरी, सहयोगी हो

किसी भी तरह से, के किसी भी विशेषाधिकार के साथ, या प्रवेश की मांग करते हुए,

कानून द्वारा स्थापित कोई अन्य विश्वविद्यालय।

(4) घटक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के संबंध

विविधता। क्षेत्र में बनाए जाने वाले क़ानूनों द्वारा शासित किया जाएगा उस ओर से, और ऐसे क़ानून विशेष रूप से प्रदान करेंगे

विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग

घटक डिग्री महाविद्यालयों और घटक का सम्मान

मान्यता प्राप्त संस्थान

((i) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना।

शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को नियुक्त किया गया ऐसे महाविद्यालयों और संस्थानों और उनकी शर्तों द्वारा

सेवा; सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर.

8

((ii) शिक्षकों की नियुक्तियों को मंजूरी देना।

ऐसे महाविद्यालयों और संस्थानों द्वारा;

((ग) ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय और संस्थान से -

किसी भी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त शिक्षकों के निर्धारित कोटे का योगदान करें।

विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षण के लिए विषय;

((iv) प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का समन्वय और विनियमन करना।

और ऐसे महाविद्यालयों और संस्थानों द्वारा किया गया व्यय पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और अन्य उपकरणों के संबंध में

शिक्षण और अनुसंधान के लिए;

(v) 'ऐसे महाविद्यालयों और संस्थानों की आवश्यकता के लिए, जब

आवश्यक, छात्रों के नामांकन को कुछ निश्चित तक सीमित करने के लिए

विषय;

((vi) ऐसे महाविद्यालयों से अंशदान वसूल करना और

संस्थान बनाना और उन्हें अनुदान देना; तथा

(vii) शिक्षण के लिए संतोषजनक व्यवस्था की आवश्यकता

और ऐसे महाविद्यालयों और संस्थानों में इसी तरह के अन्य कार्य और समय-समय पर ऐसी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना;

बशर्ते कि एक घटक डिग्री कॉलेज या एक संस्थान

टचूएंट मान्यता प्राप्त संस्थान इस तरह के शिक्षण का पूरक होगा।

शिक्षण या अन्य निर्देश शिक्षण या प्रशिक्षण द्वारा द्वारा बनाए जाने वाले विनियम द्वारा निर्धारित किया जाने वाला तरीका

अकादमिक परिषद।

(5) विधानों के प्रावधानों के अधीन बोर्ड

विश्वविद्यालय शिक्षण और अनुसंधान विभाग का आयोजन और अपने भीतर निर्देश, शिक्षण और प्रशिक्षण का समन्वय करें।

विश्वविद्यालय क्षेत्र।

51 ए (1) शिक्षण का कोई सदस्य नहीं, अन्य शैक्षणिक

और किसी मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारी

एक जांच के बाद के अलावा रैंक में कमी जिसमें वह है उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया और एक

उनके संबंध में सुनवाई का उचित अवसर

शुल्क और तब तक

(a) उसे एक उचित अवसर दिया गया है

प्रस्तावित किसी भी ऐसे दंड पर प्रतिनिधित्व करना

उस पर हमला किया, और

(ख) उस पर लगाए जाने वाले दंड को मंजूरी दी जाती है -

कुलपति या विश्वविद्यालय का कोई अन्य अधिकारी

इस संबंध में कुलपति द्वारा प्राधिकृत।

(2) ऐसे सदस्य की सेवा की कोई समाप्ति नहीं

उप के अंतर्गत आने वाली उसकी बर्खास्तगी या निष्कासन की राशि धारा (1) तब तक वैध होगी जब तक कि

(a) उसे एक उचित अवसर दिया गया है

प्रस्तावित समाप्ति और एसटी के खिलाफ कारण दिखाना।

(ख) ऐसी समाप्ति को कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

या उप द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी

इस संबंध में कुलाधिपतिः

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी लागू नहीं होगा

कोई भी व्यक्ति जिसे केवल अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

52 ए. (1) शासी निकाय के बीच कोई भी विवाद और

शिक्षण का कोई भी सदस्य, अन्य अकादमिक और

नहीं।

किसी संबद्ध कॉलेज या मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त कॉलेज के शिक्षण कर्मचारी अनुमोदित संस्थान जो शर्तों से जुड़ा हुआ है

ऐसे सदस्य की सेवा के लिए, के अनुरोध पर

शासी निकाय, या संबंधित सदस्य को संदर्भित किया जाए

द्वारा नामित एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए

महाविद्यालय का शासी निकाय या, जैसा भी मामला हो, मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्थान का सदस्य, एक

संबंधित सदस्य द्वारा नामित सदस्य और

अ.

कुलपति द्वारा नियुक्त अंपायर।

(2) धारा 52 के प्रावधान, तदनुसार,

उत्परिवर्तन इस तरह के अनुरोध और निर्णय पर लागू होते हैं।

जो ऐसे न्यायाधिकरण द्वारा दिया जा सकता है।

विश्वविद्यालय सीनेट की एक बैठक 27 मार्च को बुलाई गई थी।

28 और 29,1973 जिसमें प्रस्तावों को आइटम संख्या के रूप में पेश करने का प्रस्ताव किया गया था। 144 और कार्यक्रम के 145 में कहा गया है कि अध्ययन के उन पाठ्यक्रमों में सभी निर्देश, शिक्षण और प्रशिक्षण, जिनके संबंध में विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने के लिए

सक्षम था, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाएँ और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रदान किए जाएँ। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सेंट जेवियर्स कॉलेज अहिनेदा बैड एक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान है और संशोधित अधिनियम की धारा 40 और 41 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14,19,26,29,30 और 31 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने पारित करने के लिए गुजरात विधानमंडल की क्षमता पर भी सवाल उठाया है। संशोधन अधिनियम। याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई तीन मुख्य राहतें। ये हैं:

" (1) गुजरात विश्वविद्यालय की धारा 40 और 41

अधिनियम, 1949 (बॉम्बे अधिनियम सं। 1949 का एल) द्वारा यथासंशोधित

गुजरात विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 (गुजरात)

1973 का अधिनियम सं. 6) इन विधायी शक्तियों से परे है -

राज्य विधानमंडल और/या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहे हैं,

19 (1) (संविधान के क), (च) और (छ), 26,29,30 और 31

भारत की स्थिति;

(2) वह धारा 51 ए और 52 ए जैसा कि गुज में अंत:स्थापित किया गया है

रैट विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 (बॉम्बे अधिनियम सं। 1949 का एल) के रूप में

गुजरात विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा संशोधित

(1973 का गुजरात अधिनियम सं. 6) अनुच्छेद 14,19 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। (1) (क) (च) और (छ) के संविधान के 26,29 और 30

भारत, और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर. के अध्यादेश 120 डी, 120 ई, 120 एफ और 120 जी।

220

गुजा के तहत गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए अध्यादेश

रैट विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 और की उप-धारा (4) द्वारा संरक्षित गुजरात विश्वविद्यालय की धारा 55 (संशोधन अधिनियम,

1972 अनुच्छेद 14,19 (1) (च) और (छ), 26,29 अधिकार से बाहर हैं।

और भारत के संविधान का 30;

(3) वह धारा 33 ए गुजरात विश्वविद्यालय में डाली गई थी।

अधिनियम 1949 (बॉम्बे अधिनियम सं। 1949 का एल) के रूप में संशोधित

गुजरात विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 (गुजरात अधिनियम)

1973 का सं. 6) धारा 20 (खंड XXXIX) के साथ पढ़ा गया

गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 में शामिल किया गया

विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 1972 अनुच्छेद 14,

19 (1) (च) और (छ) के संविधान के 26,29 और 30

भारत "।

याचिकाकर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय को मद संख्या पर विचार करने या प्रस्तावों को पारित करने से रोकने के लिए भी प्रार्थना की गई थी। 144 और 27,28 और 29 मार्च, 1973 को होने वाली बैठक में एजेंडा का 145 प्रस्तावित किया गया। जब याचिका 27 मार्च, 1973 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए आई तो इस कोर्ट ने एक आदेश दिया कि विश्वविद्यालय 27,28 और 29 मार्च, 1973 को विचाराधीन प्रस्ताव पारित कर सकता है, लेकिन इसे लागू नहीं करना चाहिए। 27 और 28 मार्च, 1973 को आयोजित बैठक में सीनेट द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया था।

" एतद्द्वारा यह संकल्प लिया जाता है कि सभी निर्देश, शिक्षण और

अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण जिसके संबंध में विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय के भीतर परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम है

विविधीकरण क्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा और इसका संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विभाजित "।

इस न्यायालय के स्थगन आदेश को देखते हुए उपरोक्त प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया है।

याचिका का दो प्रतिवादियों द्वारा विरोध किया गया है, और गुजरात सरकार के अवर सचिव और विश्वविद्यालय के कुलसचिव के हलफनामे के विरोध में दायर किए गए हैं याचिका।

जब याचिका 12 नवंबर, 1973 को सुनवाई के लिए आई, तो अदालत ने याचिका को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। यह निर्देश दिया गया कि

इस मामले की सूचना राज्यों के महाधिवक्तों को जारी की जाए,

भारत के साथ-साथ भारत संघ के महान्यायवादी। सार्वजनिक

अल्पसंख्यक संस्थानों को भी नोटिस जारी किया गया था कि यदि उन्हें सलाह दी जाती है तो वे उपस्थित हों। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ भी था

मामले में सुनवाई की अनुमति दी गई। इसके बाद याचिकाकर्ताओं, प्रतिवादियों के साथ-साथ अन्य लोगों की ओर से लंबी दलीलों को संबोधित किया गया है जिन्हें हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई है। हालाँकि, तर्क दिए गए हैं

इस सवाल पर जुर्माना लगाया गया कि क्या विवादित प्रावधानों का उल्लंघन होता है संविधान का अनुच्छेद 30। इस मुद्दे पर कोई तर्क नहीं सुना गया

कि क्या विवादित प्रावधान निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं

अन्य कारणों से।

एसटी. एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (खन्ना, जे.)

221

अब हम संविधान के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं।

ट्यूशन जिसका संदर्भ दिया गया है। अनुच्छेद 25 के खंड (1) के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन, सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को (ए) धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार देता है।

(ख) धार्मिक मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करना; (ग) चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना; और (घ) कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करना। अनुच्छेद 28,29 और 30 शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रावधानों को कम करते हैं और निम्नानुसार पढ़े जाते हैं:

" 28. (1) कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।

पूरी तरह से राज्य से बाहर रखा गया कोई भी शैक्षणिक संस्थान

कोष।

(2) खंड (1) की कोई बात किसी शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगी।

संस्थान जो राज्य द्वारा प्रशासित है लेकिन

किसी भी बंदोबस्ती या न्यास के तहत स्थापित जिसके लिए आवश्यक है कि

ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी।

(3) किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जाने वाला कोई भी व्यक्ति

राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करना

किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेना आवश्यक होगा। जो ऐसी संस्था में प्रदान किया जा सकता है या किसी में भाग लेने के लिए

धार्मिक पूजा जो ऐसी संस्था में की जा सकती है

उससे संलग्न किसी भी परिसर में, जब तक कि ऐसा व्यक्ति या, यदि

ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, उसके अभिभावक ने अपनी सहमति दे दी है

वहाँ तक।

29. (1) भूभाग में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग

भारत का राज्य या उसका कोई भाग जिसकी कोई विशिष्ट भाषा हो, अपनी लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा।

एक ही।

(2) किसी भी नागरिक को किसी भी शिक्षा में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

राज्य द्वारा अनुरक्षित या सहायता प्राप्त करने वाली राष्ट्रीय संस्था राज्य का धन केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा के आधार पर

उम्र या उनमें से कोई भी।

30. (1) सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या

भाषा को स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार होगा

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान।

(2) राज्य शिक्षा के लिए सहायता प्रदान नहीं करेगा।

संस्थान, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव करते हैं

इस आधार पर कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन में है,

चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।

अनुच्छेद 28 खंड (2) में निहित अपवाद के अधीन, मना करता है।

किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देश देना। पूरी तरह से राज्य निधि से बाहर रखा गया। लेख में प्रो भी शामिल है

एक शैक्षणिक संस्थान [1975] 1 एस. सी. आर. में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए मजबूरी के खिलाफ दृष्टि।

राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए

किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लें जो इस तरह से दी जा सकती है

संस्था या किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए जो आयोजित की जा सकती है

ऐसी संस्था में या उससे जुड़े किसी परिसर में।

यद्यपि अनुच्छेद 29 के सीमांत नोट में संरक्षण का उल्लेख है -

अल्पसंख्यक अधिकार, वास्तव में उस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार नहीं हैं

केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित। उस के खंड (1) के अनुसार अनुच्छेद, भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग

इसके किसी भी हिस्से की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है।

उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। आह्वान करने के लिए इस खंड का लाभ, जो कुछ भी आवश्यक है वह यह है कि सिटी का एक खंड

सी. एफ. भारत या उसके किसी भाग के क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रों के पास होना चाहिए

अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति। एक बार जब यह प्रदान किया जाता है

उन नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि को संरक्षित करने का अधिकार होगा या

इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे माजो के सदस्य हैं या नहीं

धार्मिक समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय। अनुच्छेद 29 का खंड (2)

किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नागरिकों को प्रवेश देने से मना करना

राज्य द्वारा अनुरक्षित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करना

केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर।

अनुच्छेद 30 का खंड (1) सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी आधार पर हों।

धर्म या भाषा पर, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन

उनकी पसंद के उपाय। उस खंड का विश्लेषण करते हुए यह होगा कि

जो अधिकार खंड द्वारा प्रदत्त किया गया है, वह दो प्रकार के लघु अधिकारों पर है।

बंधन। वे अल्पसंख्यक या तो धर्म या भाषा पर आधारित हो सकते हैं।

उक्त अल्पसंख्यकों को स्थापित करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है।

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों के मंत्री। शब्द "स्थापित करें"

लिश "अस्तित्व में लाने के अधिकार को इंगित करता है, जबकि अधिकार

किसी संस्थान के प्रशासन का अर्थ है प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने का अधिकार और संस्था के मामलों का संचालन करना। प्रशासन का अर्थ

संस्थान के मामलों का प्रबंधन। प्रबंधन को करना चाहिए

नियंत्रण से मुक्त रहें ताकि संस्थापक या उनके नामांकित व्यक्ति ढाले जा सकें

संस्थान जैसा वे उचित समझते हैं और उनके विचारों के अनुसार

सामान्य रूप से समुदाय और संस्था का हित किस प्रकार है

विशेष रूप से सबसे अच्छा परोसा जाएगा। उनकी पसंद के शब्द "योग्य" हैं।

शैक्षणिक संस्थान और दिखाएँ कि शैक्षणिक संस्थान

अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित कुछ होने की आवश्यकता नहीं है

विशेष वर्ग; अल्पसंख्यकों को स्थापित करने का अधिकार और स्वतंत्रता है

और ऐसे शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करें जो वे चुनते हैं। खंड

(2) अनुच्छेद 30 राज्य को भेदभाव करने से रोकता है

जमीनी स्तर पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सहायता प्रदान करने का मामला

कि संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है या नहीं

धर्म या भाषा के आधार पर।

इससे पहले कि हम और हमारे सामने आगे बढ़े विवाद से निपटें

संविधान के अनुच्छेद 30 के दायरे और दायरे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करना उचित हो सकता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इस विशाल भूमि में

रहने वाले लोग विभिन्न धर्मों को मानते हैं और विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं। इसके बावजूद धर्म और भाषा की विविधता, राष्ट्र के ताने-बाने के माध्यम से एक बुनियादी जन्मजात एकता का सुनहरा धागा चलती है। यह विभिन्न धर्मों की भाषाओं और संस्कृतियों का मिश्रण है। उनमें से प्रत्येक ने एक एसटी बनाया है।

XAVIERS कॉलेज V: गुजरात (खन्ना, जे.)

223

भारतीय राजनीति पर निशान और भारत आज उन सभी के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों में सांप्रदायिक दंगे और मतभेद हुए। अविश्वास की भावना भी थी और

मुसलमानों के एक संप्रदाय द्वारा एक अलग गृह भूमि की मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप अंततः देश का विभाजन हुआ। जिन लोगों ने भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया, उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द और समझौते पर बहुत जोर दिया। वे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना चाहते थे जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों में समानता और गैर-भेदभाव की भावना होनी चाहिए। विभाजन से पहले अल्पसंख्यकों के वर्गों द्वारा सीटों के आरक्षण और अलग निर्वाचक मंडल की भी मांग की गई थी। जनसंख्या के विभिन्न वर्गों का पूर्ण एकीकरण और एकीकरण लाने के लिए, संविधान निर्माताओं ने अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली शुरू की, ताकि चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को सभी के समर्थन के लिए ताला लगाना पड़े।

नागरिकों के वर्ग। विशेष सुरक्षा उपायों की गारंटी दी गई थी

अल्पसंख्यकों और उन्हें मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया गया था अल्पसंख्यकों में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करना।

वे प्रावधान अल्पसंख्यकों के लिए एक तरह के अधिकारों के चार्टर थे।

ताकि किसी को भी यह महसूस न हो कि जनसंख्या का कोई भी वर्ग

इसमें प्रथम श्रेणी के नागरिक और अन्य द्वितीय श्रेणी के नागरिक शामिल थे।

परिणाम यह हुआ कि अल्पसंख्यकों ने आरक्षण के लिए अपने दावों को छोड़ दिया सीटें। · सरदार पटेल, जो सलाहकार आयोग के अध्यक्ष थे

अल्पसंख्यकों के सवाल से निपटने वाली समिति ने कहा कि

27 फरवरी, 1947 को दिया गया उनका भाषण:

" यह समिति सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है

संविधान सभा और सबसे कठिन कार्यों में से एक

जो हमें करना है, वह इस समिति का काम है।

अक्सर आपने ब्रिटिश में विभिन्न बहसों में सुना होगा।

इससे पहले कि जब अंग्रेजों की ओर से इसका दावा किया गया हो सरकार कि उनकी एक विशेष जिम्मेदारी है-एक विशेष

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दायित्व। वे दावा करते हैं कि वे हमसे अधिक विशेष रुचि रखते हैं। यह है।

हमारे लिए यह साबित करने के लिए कि यह एक झूठा दावा है, एक झूठा दावा है, और कि

प्रो में भारत में हमसे ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं ले सकता है।

हमारे अल्पविकसितों की शिक्षा। हमारा मिशन हर किसी को संतुष्ट करना है।

सभी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना और उनकी संतुष्टि "। (भारत के संविधान की रचना B.

शिव राव दस्तावेज़ चुनें। खण्ड. II पी। 66) .

यह उस पृष्ठभूमि के संदर्भ में है कि हमें प्रोवी को देखना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 में निहित हैं। वस्तु।

अनुच्छेद 25 से 30 का उद्देश्य धर्म और भाषा के अधिकारों को संरक्षित करना था।

टिक अल्पसंख्यकों, उन्हें एक सुरक्षित आसन पर रखने और उन्हें वापस लेने के लिए

राजनीतिक विवादों के उतार-चढ़ाव से। इन प्रावधानों में

के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए एक उपयुक्त प्रतिज्ञा की गई

जिस देश के सबसे बड़े बेटे ने सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, अल्पसंख्यकों को। जब तक संविधान आज है, तब तक नहीं

उन अधिकारों के साथ छेड़छाड़ को स्वीकार किया जा सकता है। कोई भी प्रयास करें

इसलिए यह न केवल आस्था भंग करने का कार्य होगा, बल्कि यह संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर. होगा।

224

राष्ट्रीय रूप से अस्वीकार्य और अदालतों द्वारा निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी। यद्यपि संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्दों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि हमारे संविधान निर्माता ऐसे राज्य की स्थापना चाहते थे। संविधान के प्रावधानों को तदनुसार तैयार किया गया था। राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र में कोई रहस्यवाद नहीं है। धर्मनिरपेक्षता न तो ईश्वर विरोधी है और न ही ईश्वर समर्थक; यह भक्त, अज्ञेयवादी और नास्तिक के साथ समान व्यवहार करता है। यह राज्य के मामलों से भगवान को हटा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही संविधान स्पष्ट रूप से विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। संविधान निर्माता हमारे देश की विशाल जनता का धर्म के प्रति गहरा लगाव, उनके दिमाग पर इसका प्रभाव और उनके जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के संरक्षक थे। धर्म के मामलों में विधायिका और कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप की सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए, अनुच्छेद 25 से 30 में उल्लिखित अधिकारों को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया गया और उन अनुच्छेदों में निहित धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी संविधान द्वारा दी गई थी।

जैसा कि धर्म के मामले में होता है, भाषा के मामले में भी इस मामले का महत्व और इस मुद्दे पर लोगों की संवेदनशीलता को लिया गया था

संविधान निर्माताओं द्वारा नोट। भाषा का संस्कृति के साथ घनिष्ठ संबंध है। द्विभाषावाद पर शाही आयोग के अनुसार

और द्विसंस्कृतिवाद (1965), भाषा की जीवंतता एक संस्कृति के संरक्षण के लिए एक आवश्यक शर्त है और सांस्कृतिक समानता प्रदान करने का प्रयास मुख्य रूप से इसके लिए प्रावधान करने का प्रयास है। भाषाई समानता (कनाडाई संविधान के पृष्ठ 590 पर उद्धृत)

जे. नोएल लाइका और रोनाल्ड जी. ई. द्वारा आधुनिक परिप्रेक्षय में कानून एटीके)।

अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार देने का विचार आबादी के एक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त या लाड़ले वर्ग को रखने के लिए नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की भावना और विश्वास की भावना देना है। भारत के महान नेताओं ने अनादिकाल से उपदेश दिया था

सहिष्णुता और दृष्टिकोण की कैथोलिकता का सिद्धांत। वे महान विचार

संविधान में निहित थे। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों को असमानता पैदा करने के लिए नहीं बनाया गया था। इनका वास्तविक प्रभाव अल्पसंख्यक संस्थानों के संरक्षण को सुनिश्चित करके और इन संस्थानों के प्रशासन के मामले में अल्पसंख्यकों को स्वायत्तता की गारंटी देकर समानता लाना था। अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देकर उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का उद्देश्य एक संतुलन लाना है, ताकि समानता के आदर्श को केवल एक अमूर्त विचार तक सीमित नहीं किया जा सके, बल्कि यह एक जीवित वास्तविकता बन जाए और इसका परिणाम सच हो।

वास्तविक समानता, न केवल सिद्धांत रूप में बल्कि वास्तव में भी एक समानता। वयस्क मताधिकार की प्रणाली में बहुमत को शायद ही किसी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह अपनी देखभाल कर सकता है और अपने हितों की रक्षा कर सकता है। बहुमत द्वारा वांछित किसी भी उपाय को बिना किसी कठिनाई के क़ानून की पुस्तक में लाया जा सकता है क्योंकि बहुमत निर्वाचित प्रतिनिधियों को ऐसा जनादेश देकर ऐसा कर सकता है। केवल अल्पसंख्यकों को ही सुरक्षा की आवश्यकता है और कुछ अन्य अनुच्छेदों के अलावा अनुच्छेद 30 का उद्देश्य उस सुरक्षा की गारंटी देना है। यह इस संदर्भ में एस. टी. के लिए उपयुक्त हो सकता है।

एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (खन्ना, जे.)

225

लाथम सी. जे. द्वारा एडिलेड कंपनी ऑफ जेहोवा विट्नेस इंक. वी. में की गई टिप्पणियों का संदर्भ लें। राष्ट्रमंडल (1) ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल (संविधान) अधिनियम की धारा 116 पर विचार करते हुए जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रमंडल किसी भी धर्म के स्वतंत्र अभ्यास को प्रतिबंधित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाएगा। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहाः ..... यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुसंख्यक धर्म के संरक्षण के लिए धारा 116 जैसे प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश लोगों का धर्म अपनी देखभाल कर सकता है। धारा 116 अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से अलोकप्रिय अल्पसंख्यकों के धर्म (या धर्म की अनुपस्थिति) की रक्षा के लिए आवश्यक है।

उपरोक्त संदर्भ में ओ. बी. का उल्लेख करना भी उचित होगा।

अल्बानिया में अल्पसंख्यक स्कूलों से संबंधित मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के बहुमत की सेवाएँ। 2 अक्टूबर, 1921 को अल्बानिया, लीग में उनके प्रवेश के बाद

राष्ट्रों ने अल्पसंख्यकों की स्थिति से संबंधित एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए अल्बानिया में। उस घोषणा के अनुच्छेद 4 का पहला पैराग्राफ चला

इस प्रकार है: " सभी अल्बेनियाई नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे, और

बिना किसी भेदभाव के समान नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेंगे जाति, भाषा या धर्म "। घोषणा का अनुच्छेद 5 था -

निम्नलिखित शब्द:

" अल्बानियाई नागरिक जो नस्लीय, धार्मिक या राजवंशीय हैं

अल्पसंख्यकों को कानून में समान व्यवहार और सुरक्षा का आनंद मिलेगा और वास्तव में

अन्य अल्बानियाई नागरिकों के रूप में। विशेष रूप से उनके पास एक बराबर होगा

अपने खर्च पर बनाए रखने, प्रबंधन और नियंत्रण करने या स्थापित करने का अधिकार भविष्य में हानि, धर्मार्थ, धार्मिक और सामाजिक संस्थान, स्कूल

और अन्य शैक्षणिक प्रतिष्ठान, जिनका अपना उपयोग करने का अधिकार है

भाषा और। उसमें स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करें। , 1933 में

अल्बेनियाई राष्ट्रीय सभा ने संविधान के अनुच्छेद 206 और 207 को संशोधित किया।

अल्बेनियाई संविधान जिसने निजी की स्थापना की अनुमति दी

अल्बेनियाई विषयों की शिक्षा राज्य के लिए आरक्षित है और यह सरकारी स्कूलों में दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है।

अल्बेनियाई नागरिक और उन्हें नि:शुल्क दिया जाएगा। निजी स्कूल

वर्तमान में संचालित सभी श्रेणियों को बंद कर दिया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेदों में उपरोक्त परिवर्तन के बाद

लीग की परिषद को कई याचिकाएं प्रस्तुत की गईं

यह कहते हुए कि संविधान के नए प्रावधान इसके विपरीत थे

घोषणा पत्र। जनवरी 1935 में लीग की परिषद ने अपनाया

अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय से अनुरोध करने वाला एक प्रस्ताव

इस प्रश्न पर राय देने के लिए कि क्या, इस संबंध में विचार किया जा रहा है

ऊपर-2 अक्टूबर, 1921 की समग्र घोषणा,

अल्बानियाई सरकार अपनी दलील में उचित है कि, के उन्मूलन के रूप में

अल्बानिया में निजी स्कूल एक सामान्य उपाय है जो लागू होता है बहुमत के साथ-साथ अल्पसंख्यक के लिए, यह इसके अनुरूप है

पत्र और शर्त की भावना "। यह 3 के मुकाबले 8 मतों से हुआ था।

कि अल्बेनियाई सरकार की दलील है कि, पिर के उन्मूलन के रूप में अल्बानिया में वेट स्कूल एक सामान्य उपाय है जो लागू होता है

(1) [1943] 67 कॉम. एल. आर. 116

16 - एल 131 सुपर।

CI./75-[1975]

1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26

ओरिटी के साथ-साथ अल्पसंख्यक के लिए, यह ले के अनुरूप है

अनुच्छेद 5, पहले पैराग्राफ में निर्धारित शर्तों की भावना

2 अक्टूबर, 1921 की घोषणा अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। एबीटी में

पाठ न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 1. अल्पसंख्यक संधियों का उद्देश्य। विचार के तहत

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संधियों को झूठ बोलना सुरक्षित करना है

किसी राज्य में शामिल कुछ तत्वों के लिए, जनसंख्या जिनमें से जाति, भाषा या धर्म में उनसे अलग है,

उस आबादी के साथ शांति से रहने की संभावना और

इसके साथ सौहार्दपूर्ण रूप से सह-संचालन, जबकि एक ही समय में संरक्षित

विशेषताएँ जो उन्हें माजो से अलग करती हैं

न्याय, और सुनिश्चित करने वाली विशेष जरूरतों को पूरा करना।

उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, दो चीजों पर विचार किया गया था

विशेष रूप से आवश्यक, और प्रो के विषय का गठन किया है

इन संधियों में दर्शन।

पहला यह सुनिश्चित करना है कि जातीय रूप से संबंधित नागरिक,

धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को हर स्थान पर रखा जाएगा।

अन्य नागरिकों के साथ पूर्ण समानता के आधार पर काम करना

राज्य से। दूसरा है अल्पसंख्यकों के लिए मतदान सुनिश्चित करना।

उनके नस्लीय संरक्षण के लिए उपयुक्त साधन

विशिष्टताएँ, उनकी परंपराएँ और उनकी राष्ट्रीय विशेषताएँ।

ये दोनों आवश्यकताएँ वास्तव में हैं। एक दूसरे से घिरा हुआ,

क्योंकि बहुमत और एक के बीच कोई वास्तविक समानता नहीं होगी

अल्पसंख्यक यदि बाद वाले अपने स्वयं के संस्थानों से वंचित थे

और परिणामस्वरूप त्याग करने के लिए मजबूर थे जो

यह अल्पसंख्यक होने का सार है "।

आगे देखा गया:

" वास्तव में समानता के साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से कानूनी भी होना चाहिए

में भेदभाव की अनुपस्थिति के अर्थ में समानता

कानून के शब्द। कानून में समानता भेदभाव को रोकती है

किसी भी प्रकार की; जबकि वास्तव में समानता में आवश्यकता शामिल हो सकती है

एक परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपचार जो स्थापित करता है

विभिन्न स्थितियों के बीच एक संतुलन की कामना करता है।

ऐसे मामलों की कल्पना करना आसान है जिनमें उपचार की समानता हो।

बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, जिनकी स्थिति और

आवश्यकताएँ। अलग हैं, वास्तव में असमानता में परिणाम होगा; इस विवरण का उपचार पहले के विपरीत होगा

अनुच्छेद 5 के अनुच्छेद 1 का वाक्य। के बीच समानता

बहुसंख्यक और अल्पमत के सदस्यों को एक होना चाहिए प्रभावी, वास्तविक समानता; यही इस प्रो का अर्थ है।

दृष्टि "।

न्यायालय ने घोषणा के अनुच्छेद 5 का उल्लेख किया और कहा कि

" पैराग्राफ के इस वाक्य को पहले से जोड़ा जा रहा है

'विशेष रूप से' शब्दों से यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि यह एसटी है।

XAVIERS कॉलेज v. गुजरात (खन्ना, जे.)

227

एपली के एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण चित्रण की परिकल्पना की गई है कानून में समान व्यवहार के सिद्धांत का समर्थन और

तथ्य जो अनुच्छेद के पहले वाक्य में निर्धारित किया गया है।

दूसरे वाक्य में उल्लिखित संस्थानों के लिए हैं -

अल्पसंख्यकों को समान व्यवहार का आनंद लेने में सक्षम बनाने के लिए अपरिहार्य

बहुमत के रूप में माना जाता है, न केवल कानून में बल्कि वास्तव में भी। द. इन संस्थानों का उन्मूलन, जो अकेले संतुष्ट कर सकते हैं

अल्पसंख्यक समूहों की विशेष आवश्यकताएँ, और उनकी आवश्यकताएँ

सरकारी संस्थानों द्वारा नियुक्ति, इसे नष्ट कर देगी

उपचार की समानता, इसके प्रभाव के लिए वंचित करना होगा

अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त संस्थानों का अल्पांश, जबकि

बहुमत ने उन्हें आपूर्ति करना जारी रखा होगा

राज्य द्वारा बनाए गए संस्थान।

इस स्तर पर उन मामलों को संदर्भित करना उचित होगा जिनमें

इस न्यायालय ने अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों पर अनुच्छेद 30 के प्रभाव पर विचार किया है। पहला मामला (1) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत केरल शिक्षा विधेयक के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता से संबंधित कुछ प्रश्नों पर इस न्यायालय की राय का पालन करने के लिए किया गया था, जिसे केरल विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा गया था।

दाँत। चार प्रश्न न्यायालय को भेजे गए थे, जिनमें से हम वर्तमान में प्रश्न संख्या 2 से संबंधित हैं जो निम्नानुसार था:

" खंड 3 का उपखंड (5), खंड का उपखंड (3) करें।

8 और केरल शिक्षा विधेयक के खंड 9 से 13, या कोई समर्थक

इसकी दृष्टि, संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) का उल्लंघन करती है।

किसी भी विवरण में या किसी भी हद तक शिक्षा?

विधेयक के खंड 3 (5) ने नए विद्यालयों को मान्यता दी

विधेयक के अन्य प्रावधानों और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के बारे में खंड 36 के अधीन आदेश। खंड 15 सरकार को अधिकृत करता है कि

स्कूलों की किसी भी श्रेणी का अधिग्रहण करें। खंड 8 (3) ने इसे अनिवार्य बना दिया

13 ने विद्यालयों के विनियमन और प्रबंधन के लिए प्रावधान किए, शिक्षकों को वेतन का भुगतान और उनके नियम और शर्तें

नियुक्ति। संदर्भ की सुनवाई करने वाली पीठ में 7 सदस्य थे - न्यायाधीशों। पीठ के छह सदस्यों ने दास सी. जे. के माध्यम से जवाब दिया

प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित शब्दों में:

" प्रश्न संख्या 2: ((i) हाँ, जहाँ तक आंग्ल-भारतीय शिक्षा का संबंध है।

कला के तहत अनुदान के हकदार राष्ट्रीय संस्थान। 337 कौन हैं

सुनिश्चित किया। ((ii) अन्य अल्पसंख्यकों के संबंध में जो अनुदान के हकदार नहीं हैं।

संविधान के किसी स्पष्ट प्रावधान के तहत अधिकार के रूप में,

लेकिन सहायता प्राप्त कर रहे हैं या ऐसी सहायता चाहते हैं और

एंग्लो-भारतीय शैक्षणिक संस्थान जहाँ तक वे हैं जो उन्हें देय है उससे अधिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं

कला. 337 , खंड 8 (3) और 9 से 13 तक अनुच्छेद का अपमान नहीं करते हैं। 30

(1) लेकिन खंड 3 (5) जहाँ तक वह ऐसा शैक्षिक बनाता है

(1) [1959] एससीआर 995।

खंड 14 और 15 के अधीन संस्थान कला का अपमान करते हैं। 30

(1) . ((iii) खंड 7 (उपखंडों को छोड़कर। (1) और (3) जो केवल सहायता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होता है), क्ल। 10 जहाँ तक वे लागू होते हैं

उक्त विधेयक के बाद स्थापित किए जाने वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों को लागू होता है कला का अपमान न करें। 30 (1) लेकिन सी. एल. 3 (5) इस प्रकार

जहाँ तक यह कॉम के बाद स्थापित नए स्कूलों को बनाता है

सी. एल. के अधीन विधेयक का उल्लेख। 20 कला का अपमान करता है।

30 (1) . ”

यह माना गया था कि:

" संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में कोई भेद नहीं था।

संविधान से पहले से मौजूद अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच

ट्यूशन या उसके बाद स्थापित और दोनों की रक्षा की। यह किया। यह आवश्यक नहीं है कि एक अल्पसंख्यक संस्थान को सीमित किया जाना चाहिए

उस समुदाय के सदस्य जिनसे वे संबंधित थे और

अल्पसंख्यक संस्थानों को स्वीकार करके ऐसा होना बंद नहीं किया जा सकता था

इसके गैर-सदस्य।

कला भी नहीं। 30 (1) किसी भी तरह से विषय को सीमित करें

एक अल्पसंख्यक संस्थान में पढ़ाया जाता है, और उनके महत्वपूर्ण शब्द अपनी पसंद ', स्पष्ट रूप से इंगित किया कि अधिकारों का दायरा यह है

तीन श्रेणियाँ जिनमें ऐसे संस्थान इस प्रकार हो सकते हैं वर्गीकृत किए गए थे (1) वे जिन्होंने न तो सहायता मांगी और न ही माफी मांगी।

राज्य से अनुदान, (2) सहायता मांगने वाले, और (3)

जो मान्यता चाहते थे लेकिन सहायता नहीं चाहते थे। द इम्पाग्ड

विधेयक का संबंध केवल दूसरे के संस्थानों से था और

तीसरी श्रेणियाँ "।

आगे आयोजित किया गया था:

" अल्पसंख्यकों का अपनी शिक्षा का प्रशासन करने का अधिकार कला के तहत संस्थान। 30 (1) , के साथ असंगत नहीं था

भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित सुरक्षा उपायों पर जोर देने का राज्य का अधिकार

उचित नियमों को लागू करके प्रशासन

सहायता के अनुदान के लिए पूर्ववर्ती। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं था कि राज्य विधानमंडल कला के तहत कानून बनाने की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। 245 और संविधान के 246,

अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करके मौलिक अधिकारों पर हावी हो जाता है, जिसके लिए उसके पास प्रत्यक्ष रूप से करने की कोई शक्ति नहीं थी, वह ऐसा नहीं कर सकता था

सीधे "।

अल्पसंख्यक समुदाय की राज्य मान्यता के सवाल का समाधान न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" हालांकि यह निस्संदेह सच था कि राज्य की मान्यता का कोई मौलिक मानसिक अधिकार नहीं हो सकता है, मान्यता से इनकार करना ऐसी शर्तों को छोड़कर जो वस्तुतः राज्य के समर्पण के बराबर है। संस्थान के प्रशासन का अधिकार, सार में, और

प्रभाव कला का उल्लंघन करता है। 30 (1) संविधान "।

न्यायाधीश एनकटरामा अय्यर ने अपनी अल्पमत राय में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को राज्य की मान्यता का अधिकार नहीं दिया गया है, और न ही इसका उचित अर्थ लगाया गया है कि क्या यह एस. टी. कर सकता है।

XAVIERS कॉलेज v. गुजरात (खन्ना, जे.)

229

इस तरह के निहितार्थ के लिए निहितार्थ, यदि उठाया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 45 के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत होगा। अनुच्छेद 30 (1) का मुख्य उद्देश्य ऐसे अल्पसंख्यक संस्थानों की रक्षा करना था जो विशुद्ध रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं और यह अभिनिर्धारित करना कि राज्य उन्हें मान्यता देने के लिए बाध्य है, न केवल अनुच्छेद 45 को पूरी तरह से निष्फल बनाने के समान होगा, बल्कि संविधान की मूल अवधारणा, अर्थात् इसके धर्मनिरपेक्ष चरित्र को भी रद्द करने के समान होगा।

रेव. सिद्धजभाई भाई और अन्य। वी. बॉम्बे राज्य और ए. एन. आर. (1) था।

अगला मामला जिसमें यह न्यायालय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के सवाल पर गया। उस मामले में याचिकाकर्ताओं ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया और वे यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से संबंधित थे। वे एक ऐसे समाज के सदस्य थे जो मुख्य रूप से ईसाई समुदाय के लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बनाए रखता था। सोसायटी 42 प्राथमिक विद्यालयों और शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालय का संचालन करती थी। महाविद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों को समाज द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शामिल किया गया था और जो इस तरह से शामिल नहीं थे, उन्हें यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया द्वारा संचालित अन्य ईसाई मिशन स्कूलों द्वारा नियुक्त किया गया था। प्रशिक्षण महाविद्यालय और प्राथमिक विद्यालयों के रखरखाव का खर्च आयरिश प्रेस्बिटेरियन मिशन से प्राप्त दान, विद्वानों से शुल्क और राज्य सरकार से अनुदान सहायता से पूरा किया जाता था। 28 मई, 1955 को बॉम्बे सरकार ने एक आदेश जारी किया कि

शैक्षणिक वर्ष 1955-56, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटें

गैर-सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा नामित शिक्षकों के लिए आरक्षण किया जाना चाहिए। के प्रधानाचार्य

इसके बाद प्रशिक्षण महाविद्यालय से शैक्षिक निरीक्षक नं.

शिक्षा विभाग की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रवेश देना

प्रत्येक कक्षा में कुल संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक निजी छात्र।

यह भी शैक्षिक निरीक्षक द्वारा उल्लेख किया गया था कि इनकार करने के लिए

यह स्वीकार करें कि सरकार द्वारा नामित शिक्षक अनियमित थे और सरकार के खिलाफ थे

आवास नीति। याचिकाकर्ताओं को चेतावनी दी गई थी कि

सरकारी आदेशों को ध्यान में रखते हुए अनुदान पर रोक लगा दी जाएगी।

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। संविधान ने इस आरोप पर कि उन्हें जारी किए गए निर्देश

जहाँ तक वे आदेश के तहत उसमें सीटों के आरक्षण से संबंधित हैं आरक्षण के संबंध में सरकार और उसके अनुसार दिए गए निर्देश

80 प्रतिशत सीटें और अनुदान-इन-सहायता को रोकने और पुनः प्राप्त करने का खतरा महाविद्यालय का गठन, अनुच्छेद के तहत मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन

30 (1) .

रेव फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट एंड ओआरएस। वी. बिहार राज्य और अन्य। (ए) था

अगला मामला जिसमें इस न्यायालय ने प्रदत्त सुरक्षा से निपटा अनुच्छेद 30 (1) द्वारा अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को

बंधन। यह मामला रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से संबंधित था।

रांची के जेसुइट्स द्वारा स्थापित और पटना विश्वविद्यालय से संबद्ध था

सिटी। कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, कैथोलिक को देना था।

(1) [1963] 3 एस. सी. आर. 837

(2) [1969] 2 एस. सी. आर. 73

युवाओं को नैतिक और उदार शिक्षा का एक पूर्ण पाठ्यक्रम प्रदान करके, एक संपूर्ण धार्मिक निर्देश प्रदान करके और संस्थान में एक कैथोलिक आत्मा को बनाए रखते हुए। हालाँकि, कॉलेज गैर-कैथोलिकों के लिए खुला था और सभी गैर-कैथोलिक छात्रों को नैतिक विज्ञान का एक पाठ्यक्रम प्राप्त था। बिहार विधानमंडल ने एक संशोधन अधिनियम द्वारा बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम में धारा 48-ए को 1 मार्च, 1962 से लागू किया। उक्त खंड राज्य सरकार से संबंधित नहीं होने वाले संबद्ध कॉलेजों के लिए एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। उस धारा के खंड 6 के अनुसार, विश्वविद्यालय के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, किसी संबद्ध कॉलेज के शिक्षकों की नियुक्तियां, बर्खास्तगी, निष्कासन, सेवा की समाप्ति या पद में कमी राज्य सरकार के लिए लालायित नहीं होगी, जो आयोग की सिफारिश पर कॉलेज के शासी निकाय द्वारा की जाएगी। उस धारा के खंड 11 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि कॉलेज के शिक्षक को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों में आयोग का निर्णय कॉलेज के शासी निकाय द्वारा किया जाएगा और ऐसे मामलों से संबंधित किसी भी स्मारक या याचिका का निपटारा नहीं किया जाएगा और न ही आयोग के निष्कर्ष के अनुरूप के अलावा कॉलेज के शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या कोई सजा दी जाएगी। द.

याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची की स्थापना ईसाई अल्पसंख्यकों द्वारा की गई थी और उन्हें इसे प्रशासित करने का अधिकार है। के अनुसार

याचिकाकर्ताओं को, धारा 48-ए, उन्हें अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार से वंचित करती है क्योंकि इसके प्रावधानों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ नियुक्तियों की आवश्यकता होती है,

सभी अनुशासनात्मक मामलों में सायन से परामर्श किया जाना था और एक शिक्षक पर लगाया गया कोई भी दंड आयोग के निष्कर्षों के अनुसार ही हो सकता था। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के बीच उत्पन्न मतभेदों को देखते हुए, धारा 48-ए की शुरुआत के बाद, विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय की संबद्धता को वापस ले लिया। जबकि पेटी यह लंबित था, धारा 48-बी को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम में शामिल किया गया था, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित संबद्ध कॉलेजों के शासी निकाय को नियुक्तियां, बर्खास्तगी, सेवा की समाप्ति या शिक्षकों के पद में कमी करने या अन्य अनुशासनात्मक उपाय करने का अधिकार होगा, जो केवल आयोग और विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की मंजूरी के बाद ही उप-अधिनियम के तहत होगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए, यह इस अदालत की एक संविधान पीठ द्वारा हिदायतुल्ला सी. जे. के माध्यम से कहा गया था।

कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया संरक्षण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के शब्दों से निकला है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 30 (1) की चौड़ाई में कटौती उन विचारों को शामिल करके नहीं की जा सकती है जिन पर अनुच्छेद 29 (1) आधारित था।

आर टी। रेव. बिशप एस. के. पात्रो और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य। (1) अगला मामला था जिसमें इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के आधार पर दावे पर विचार किया। यह मामला 1954 में भागलपुर में स्थापित एक स्कूल से संबंधित है। इस विद्यालय का प्रबंधन राष्ट्रीय विद्यालय द्वारा किया जा रहा था।

(1) [1970] 1 एस. सी. आर 172

एसटी. एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (खन्ना, जे.)

क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया। दो व्यक्तियों को स्कूल के अध्यक्ष और सचिव के रूप में चुना गया और उनके चुनाव को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के आदेश को सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव ने 22 मई, 1967 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया था। 21 जून, 1967 को क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर ने चर्च के सचिव को एक पत्र लिखा।

मिशनरी सोसाइटी स्कूल, भागलपुर ने 22 मई, 1967 के आदेश की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और उनसे उस आदेश के अनुसार स्कूल की एक प्रबंध समिति के गठन के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया। इसके बाद चार याचिकाकर्ताओं द्वारा पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें बिहार राज्य और उसके अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के स्कूल के मामलों के प्रशासन और प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप करने से रोकने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि स्कूल अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान नहीं था। इसके बाद उपरोक्त याचिकाकर्ता इस अदालत में अपील करने आए। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा भी इस न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थीं। इस न्यायालय ने माना कि विचाराधीन विद्यालय एक धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान था। उपरोक्त निष्कर्ष पर न्यायाधीश शाह (जैसा कि वे तब थे) के माध्यम से बोलते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया कि 22 मई, 1967 के आदेश के अनुसार एक प्रबंध समिति का गठन करने के लिए स्कूल के सचिव से कदम उठाने की आवश्यकता वाले शैक्षणिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेश अमान्य था।

मामले में अगले अनुच्छेद 30 (1) के संरक्षण का सवाल उठा।

केरल राज्य, आदि। बहुत रेव. माँ प्रांतीय। (1) यह मामला केरल विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969 से संबंधित है। उक्त अधिनियम केरल राज्य के दक्षिणी जिलों के लिए एक शिक्षण, आवासीय और संबद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने की दृष्टि से केरल विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के लिए पारित किया गया था। इसके कुछ प्रावधानों ने निजी कॉलेजों, विशेष रूप से राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित कॉलेजों को प्रभावित किया। उन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। अधिनियम की धारा 48 और 49 निजी कॉलेजों के लिए शासी निकाय से संबंधित है जो कॉर्पोरेट प्रबंधन के तहत नहीं हैं और कॉर्पोरेट प्रबंधन के तहत निजी कॉलेजों के लिए प्रबंधन परिषद से संबंधित हैं। किसी भी मामले में एक निजी कॉलेज की शैक्षिक एजेंसी को एक निजी कॉलेज के लिए एक शासी निकाय या एक कॉर्पोरेट प्रबंधन के तहत निजी कॉलेजों के लिए एक प्रबंधन परिषद की स्थापना करने की आवश्यकता थी। खंडों में दोनों निकायों की संरचना के लिए प्रावधान किया गया था ताकि निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल और मैनेजर, विश्वविद्यालय और सरकार के नामांकित व्यक्तियों के साथ-साथ शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सके। उप-धारा (2) में प्रावधान किया गया है कि नए निकाय

स्थायी उत्तराधिकार और एक आम मुहर वाले निगमित निकाय होंगे। उप-धारा (4) में प्रावधान किया गया है कि सदस्य चार साल तक पद धारण करेंगे। उप.

प्रत्येक खंड की धारा (5) ने नए शासी निकाय या प्रबंधन परिषद को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निजी कॉलेज या कॉलेजों का प्रशासन करने का कर्तव्य दिया। प्रत्येक की उप-धारा (6)

खंड ने निर्धारित किया कि नए निकायों की शक्तियाँ और कार्य,

उसके सदस्यों को हटाना और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया,

(1) [1971] 1. एस. सी. आर, 734.

विधियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने उन दो धाराओं के साथ-साथ धारा 53 की उप-धाराओं (1), (2), (3) और (9) को भी चुनौती दी, जो विश्वविद्यालय के सिंडिकेट को शासी परिषद के निर्णयों को वीटो करने की शक्ति और उनके कार्य से व्यथित किसी भी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। इसी तरह, याचिकाकर्ताओं ने धारा 56 को चुनौती दी, जो शिक्षकों के संबंध में अनुशासनात्मक मामलों में विश्वविद्यालय और सिंडिकेट को अंतिम शक्तियां प्रदान करती है, धारा 58, जो शिक्षकों के लिए अयोग्यता के रूप में विधान सभा की सदस्यता को हटा देती है और धारा 63 (1), जिसमें प्रावधान है कि जब भी सरकार संतुष्ट होती है कि किसी निजी कॉलेज के कामकाज में गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है, तो वह अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय को ऐसे निजी कॉलेज के मामलों का प्रबंधन करने के लिए अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त कर सकती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को अमान्य करार दिया। अपील पर यह न्यायालय हिदायतुलिया सी. जे. के माध्यम से बोल रहा है। यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करना सही था कि धारा 48 और 49 की उप-धाराएँ (2) और (4) अनुच्छेद 30 (1) के अधिकार से बाहर थीं। उन दोनों धाराओं में से प्रत्येक की उप-धारा (6) को भी अधिकार से बाहर माना गया था। उच्च न्यायालय, यह फर था यह घोषित करना भी सही था कि धारा 53 की उप-धारा (1), (2) और (9), धारा 56 की उप-धारा (2) और (4), अधिकार से बाहर थीं क्योंकि वे धारा 48 और 49 के भीतर आती थीं; वह धारा 58 (जहां तक वह अयोग्यता को हटा देती है जिससे संस्थापक सहमत नहीं हो सकते हैं), और धारा 63 अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में अनुच्छेद 30 (1) के अधिकार से बाहर थी।

अंतिम दो मामले जिनमें इस न्यायालय ने प्रभाव पर विचार किया

अल्पसंख्यक संस्थानों पर अनुच्छेद 30 डी. ए. वी. कॉलेज बठिंडा आदि थे। पंजाब राज्य और अन्य। (1) और डी. ए. वी. कॉलेज आदि। पंजाब राज्य और अन्य। (2) इन दोनों मामलों में निर्णय 5 मई, 1971 को सुनाया गया था। जे. जगमोहन रेड्डी ने इन दोनों मामलों में अदालत की ओर से बात की। डी. ए. वी. कॉलेज बठिंडा के मामले में याचिकाकर्ता डी. ए. वी. कॉलेज ट्रस्ट एंड सोसाइटी द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान थे। यह आर्य समाजियों का एक संगठन था। ये संस्थान पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध पंजाब राज्य के पुनर्गठन से पहले थे। पंजाबी विश्वविद्यालय की स्थापना 1961 में की गई थी। पंजाब के पुनर्गठन के बाद, पंजाब सरकार ने अधिनियम की धारा 5 के तहत उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया जिनमें पंजाबी विश्वविद्यालय अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और धारा के उद्देश्य के लिए तारीख को अधिसूचित किया। अधिसूचना का प्रभाव यह था कि याचिकाकर्ताओं को पंजाबी विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से जुड़ा हुआ माना जाता था और उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय के साथ किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं माना जाता था। इसके बाद 15 जून, 1970 के परिपत्र द्वारा विश्वविद्यालय ने घोषणा की कि शैक्षणिक वर्ष से विज्ञान समूहों के लिए भी पूर्व-विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा और परीक्षा का एकमात्र माध्यम पंजाबी होगा। 7 अक्टूबर, 1970 को एक संशोधन किया गया था जिसमें अंग्रेजी को परीक्षा राष्ट्र के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अनुमति दी गई थी। हालाँकि, यह उल्लेख किया गया था कि प्रारंभिक पंजाबी प्रश्नपत्रों में योग्यता प्राप्त करना अंग्रेजी माध्यम की पेशकश करने वाले छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। इसके बाद इस न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस आधार पर याचिकाएं दायर की गईं कि विश्वविद्यालय के पास कोई शक्ति नहीं थी

(2) [1971] 1

एस. सी. आर 638

(1) [1971] एस. सी. आर. 677

एसटी. एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (खन्ना, जे.)

:

पंजाबी को शिक्षा का एकमात्र माध्यम बनाना। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 2 जुलाई, 1970 और 7 अक्टूबर, 1970 के सर्क्यू लार्स द्वारा संशोधित 15 जून, 1970 का परिपत्र अमान्य था और विश्वविद्यालय में निहित शक्तियों से परे था। अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता एक धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा बनाए गए संस्थान थे और इस तरह सभी कॉलेजों में शिक्षा और परीक्षा के माध्यम के रूप में गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा के विशेष उपयोग का निर्देश याचिकाकर्ताओं के अधिकार का सीधे उल्लंघन करता है। यह देखा गया कि विश्वविद्यालय के पहले के निर्देश में दी गई छूट से बहुत कम फर्क पड़ा क्योंकि रियायत से छात्रों को हिंदी को माध्यम और देवनागरी को लिपि के रूप में लाभ नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था, जिसमें चुनने का अधिकार शामिल था

* बी.

सी.

शिक्षा का माध्यम भी। यह अनुच्छेद 30 (1) को अनुच्छेद 29 (1) के साथ पढ़ने का परिणाम होगा। कोई भी असुविधा या कठिनाइयाँ, प्रशासन की त्रयी या वित्तीय, गारंटीकृत अधिकारों के उल्लंघन को उचित नहीं ठहरा सकती हैं। दूसरा मामला, डी. ए. वी. कॉलेज बनाम। पंजाब राज्य (उपरोक्त) डी. ए. वी. कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजिंग सोसाइटी द्वारा प्रबंधित और प्रशासित विभिन्न कॉलेजों द्वारा दायर रिट याचिकाओं से उत्पन्न हुआ। ये

पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से पहले कॉलेज थे। गुरु नानक विश्वविद्यालय (अमृतसर) अधिनियम (1969 का अधिनियम 21) की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना के परिणामस्वरूप, वे कॉलेज, जो निर्दिष्ट क्षेत्रों में थे, पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं थे और जिन्हें गुरु नानक विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से संबद्ध और प्रवेश दिया जाना था। अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों के खंड 2 (1) (ए) द्वारा कॉलेजों के लिए आवश्यक था

ई.

नियमित रूप से गठित शासी निकाय जिसमें सीनेट द्वारा अनुमोदित 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होते हैं। यह भी प्रावधान किया गया था कि शासी निकाय में विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि और महाविद्यालय के प्राचार्य शामिल होंगे। खंड (1) (3) के तहत यदि इन आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था, तो संबद्धता वापस लेने के लिए उत्तरदायी थी। खंड 17 के तहत शुरू में नियुक्त कर्मचारियों को कुलपतियों द्वारा अनुमोदित किया जाना था और बाद के सभी परिवर्तनों को कुलपतियों की मंजूरी के लिए विश्वविद्यालय को सूचित किया जाना था। खंड 18. मांग

गैर-सरकारी कॉलेजों को गैर-सरकारी क्षेत्रों में शिक्षकों की सेवा और संचालन को नियंत्रित करने वाले अध्यादेश में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करने के लिए

विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाने वाले सरकारी कॉलेज। इस न्यायालय ने माना कि आर्य समाज पंजाब राज्य में हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यक का एक हिस्सा था और आर्य समाजियों की अपनी जी की एक अलग लिपि थी, जिसका नाम देवनागरी था। आर्य समाजियों को अनुच्छेद 29 (1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार का आह्वान करने का अधिकार दिया गया था क्योंकि वे नागरिकों का एक वर्ग थे जिनकी एक अलग लिपि थी; वे भी इसके हकदार थे -

अनुच्छेद 30 (1) का आह्वान करें क्योंकि वे एक धार्मिक अल्पसंख्यक थे। विधियों के अध्याय 5 के खंड 2 (1) (ए) और 17 को न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन करने के रूप में निरस्त कर दिया गया था क्योंकि वे धार्मिक अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार में हस्तक्षेप करते थे। एच खंड 18 को खंड 17 के समान दोष से पीड़ित नहीं माना गया था। मैंने अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का सार ऊपर दिया है। ऐसा करने के बाद, हमें अब 234 होना चाहिए।

[1975] 1

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन सिद्धांतों पर विचार करें जिन्हें उन अनुच्छेदों के अर्थ में अपनाया जाना चाहिए।

एक उदार, उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है

जहां तक अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों का संबंध है, उनके अधिकारों के संरक्षण के मामले में संविधान। हालाँकि इस संबंध में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम करने के लिए अतीत में प्रलोभन दिए गए हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के सतर्क वर्गों ने इस तरह के प्रयासों का विरोध किया है। परिणामस्वरूप विवाद उत्पन्न हुए हैं और यह निर्धारित करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आए हैं कि क्या विवादित उपाय अनुच्छेद 29 और 30 में सन्निहित संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। इस न्यायालय ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लगातार बरकरार रखा है

उन अनुच्छेदों में सन्निहित है और यह सुनिश्चित किया है कि अल्पसंख्यक अधिकारों का दायरा और दायरा संकुचित न हो। व्यापक दृष्टिकोण यह देखने का रहा है कि अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों के मामले में उनके अधिकारों को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है और उन अधिकारों से संबंधित संविधान के प्रावधानों की चौड़ाई और दायरा सीमित नहीं है। वह सिद्धांत जिसे समझा जा सकता है

इस न्यायालय के विभिन्न निर्णय यह हैं कि कैथोलिक दृष्टिकोण जिसके कारण अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का मसौदा तैयार किया गया, संकीर्ण न्यायिक व्याख्या द्वारा शून्य नहीं किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक हैं

मिट्टी के उतने बच्चे जितने बहुसंख्यक और दृष्टिकोण रहे हैं

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक वंचित हो सकें

अपनत्व की भावना, सुरक्षा की भावना, एक चेतना की

समानता और जागरूकता कि उनके धर्म का संरक्षण,

संस्कृति, भाषा और लिपि के साथ-साथ उनकी शिक्षा की सुरक्षा

संस्थान संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है। द.

समान उदार, उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ वजन करना चाहिए

न्यायालयों ने अनुच्छेद 29 और 30 को विचार-विमर्श के रूप में परिभाषित किया

उन लेखों का मसौदा तैयार करने और बनाने में संविधान निर्माताओं की भूमिकाएँ

वे मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं। ब्याज की रक्षा

जनसंख्या के वर्गों के बीच अल्पसंख्यकों की संख्या उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि

व्यक्तियों के बीच हितों का संरक्षण जो नीचे दिए गए हैं

वयस्कता की आयु या अन्यथा किसी प्रकार के संक्रमण से पीड़ित हैं

खेद है। संविधान और सभ्य राष्ट्रों द्वारा बनाए गए कानून, वहाँ

वास्तव में, इसे सभ्यता के स्तर का सूचकांक कहा जा सकता है और एक राष्ट्र की कैथोलिकता कि उनके अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित महसूस करते हैं और हैं

किसी भी भेदभाव या दमन के अधीन नहीं।

अब हम गारंटीकृत अधिकार के दायरे और दायरे से निपट सकते हैं।

अनुच्छेद 30 के खंड (1) द्वारा। खंड सभी नाबालिगों को अधिकार प्रदान करता है। संबंध, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, स्थापित करने और

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करें। अधिकार प्रदान करें

खंड द्वारा लाल पूर्ण शब्दों में है और प्रतिबंधों के अधीन नहीं है,

जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के मामले में है। द.

अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार नहीं है।

तथापि, के संबंध में उचित विनियम बनाने से रोकें

उन संस्थाओं को। नियम अनिवार्य रूप से बनाए जाने चाहिए

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में संस्थान का हित। वे.

इसे इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि इसे प्रदान करने के लिए एक प्रभावी वाहन बनाया जा सके शिक्षा. शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने का अधिकार स्पष्ट रूप से एसटी हो सकता है।

एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (खन्ना, जे.)

235

इसमें कुशासन का अधिकार शामिल नहीं है। किसी शैक्षणिक संस्थान के अस्वास्थ्यकर आवास को रोकने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं और साथ ही योग्य शिक्षकों के बिना किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना या निरंतरता को भी रोका जा सकता है। संस्थान की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए राज्य नियम निर्धारित कर सकता है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानकों का निर्धारण अल्पसंख्यकों के संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार के खिलाफ नहीं है। शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और इसी तरह की दक्षता के सच्चे हित में बनाए गए विनियम निस्संदेह लागू किए जा सकते हैं। इस तरह के नियम उस अधिकार के सार पर प्रतिबंध नहीं हैं जिसकी गारंटी दी गई है: वे शैक्षिक मामलों में संस्थान के

उचित कामकाज को सुनिश्चित करते हैं (शाह जे. की टिप्पणियाँ देखें। 850) . इसके अलावा, जैसा कि हिदायतुल्ला सी. जे. ने देखा। बहुत रेव. मदर प्रोविंशियल (ऊपर) के मामले में मानकों की चिंता

ए.

बी. सी निकाय राजनीतिक है और प्रगति के विचारों द्वारा निर्धारित किया जाता है

देश और उसके लोग। इसलिए, यदि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम स्थापित करते हैं, तो उनका पालन किया जाना चाहिए, हालांकि विशेष उप-क्षेत्रों के अधीन, जिन्हें संस्थान पढ़ाना चाहते हैं, और कुछ हद तक राज्य शिक्षकों के रोजगार की शर्तों और छात्रों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी विनियमित कर सकता है। इस तरह के नियम सीधे प्रबंधन पर लागू नहीं होते हैं, हालांकि वे अप्रत्यक्ष रूप से इसे प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी शिक्षा, शैक्षिक स्थिति और संबद्ध मामलों को विनियमित करने के राज्य के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थान

डी.

शैक्षणिक संस्थानों से अपेक्षित उत्कृष्टता के मानकों से नीचे गिरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, या मानव अधिकार की आड़ में, सामान्य पैटर्न का पालन करने से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जबकि प्रबंधन। उन्हें उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए, वे कदम रखने के लिए मजबूर हो सकते हैं

अन्य।

ई.

मेरी राय में, महीने की एक विशेष तिथि से पहले वेतन का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने की अनुमति है। विनियमों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि संस्थान के धन को शिक्षा के उद्देश्यों या संस्थान की बेहतरी के लिए खर्च किया जाना चाहिए, न कि बाहरी उद्देश्यों के लिए। विनियमों में संस्थानों के धन को प्रबंधन के प्रभारी लोगों की जेबों में जाने या किसी अन्य तरीके से उनके गबन को रोकने के प्रावधान भी हो सकते हैं। संस्थान के खातों के लेखापरीक्षा के प्रावधान अनुमेय विनियमन होंगे। इसी तरह, विनियमों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी और कर्मचारियों के सदस्यों के रूप में कार्यरत लोग राष्ट्रीय अंतर-राज्य के खिलाफ किसी भी गतिविधि के दोषी नहीं होने चाहिए। अल्पसंख्यकों को राष्ट्र का उतना ही हिस्सा होना चाहिए जितना कि बहुसंख्यक, और राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज को इसके अंतिम संचालन में उन सभी के हितों को प्रभावित करना चाहिए

जो इस विशाल भूमि को रोकते हैं, चाहे वे जनसंख्या के बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित हों। इसलिए, यह सुनिश्चित करना अल्पसंख्यकों के हित में है जितना कि बहुसंख्यक के हित में है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को दी गई सुरक्षा का उपयोग कुछ ऐसा करने के लिए किया जाए जो राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक हो। इसलिए, शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। उचित माना जाए।

एफ.

जी.

एक विनियमन जो एक के कुप्रशासन को रोकने के लिए बनाया गया है

शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद के खंड (1) का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

30. साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि सत्ता के तहत

नियम बनाना कुछ भी नहीं किया जाता है जो चरित्र से अलग होगा।

संस्थान का अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में या जो अल्पसंख्यकों के स्थापना और प्रशासन के अधिकारों को बाधित करना

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान। अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार

30 (1) इसका उद्देश्य वास्तविक और प्रभावी होना है न कि केवल पवित्र और

. अमूर्त भावना; यह वास्तविकता का एक वादा है न कि एक चिढ़ाने वाला भ्रम। इस तरह के अधिकार को किसी भी उपाय से कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

एक विनियमन के रूप में मास्करेडिंग। जैसा कि इस मामले में इस न्यायालय ने कहा है

रेव. सिद्धजभाई भाई (ऊपर) के नियम जो कानूनी रूप से हो सकते हैं

एक शर्त के रूप में विधायी या कार्यकारी कार्रवाई द्वारा लगाया गया

अनुदान या मान्यता प्राप्त करने का निर्देश अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपने चरित्र को बनाए रखते हुए संस्थान को प्रभावी बनाने के लिए दिया जाना चाहिए।

एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में। इस तरह के विनियमन को एक दोहरी परीक्षा को संतुष्ट करना चाहिए -

तर्कसंगतता की कसौटी, और यह कसौटी कि यह संस्थान के शैक्षिक चरित्र का नियामक है और संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय या इसका सहारा लेने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का एक प्रभावी वाहन बनाने के लिए अनुकूल है।

यह अमेरिकी संविधान के संदर्भ में कहा गया है और

कनाडाई अधिकार विधेयक कि धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षण ने अक्षमताओं को समाप्त कर दिया, इसने नए विशेषाधिकारों का निर्माण नहीं किया। इसने धार्मिक समानता दी, न कि नागरिक प्रतिरक्षा। इसका सार धार्मिक हठधर्मिता के अनुरूपता से स्वतंत्रता है, न कि धार्मिक हठधर्मिता के कारण कानून के अनुरूपता से स्वतंत्रता (वेस्ट वर्जीनिया स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाम में फ्रैंक फर्टर जे. की असहमत राय देखें। बार्नेटी 1) के साथ-साथ रॉबर्टसन और रोसेटानी रोसेटानी बनाम में कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के लिए बोलते हुए जे. रिची का निर्णय। . रानी (3) एक व्यापक प्रस्ताव के रूप में उपरोक्त में बहुत अधिक अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

डिक्टम और यह बड़ी संख्या में मामलों में एक व्यावहारिक पैमाना प्रदान कर सकता है। हालाँकि, उन मामलों में कठिनाई उत्पन्न होती है जो गोधूलि क्षेत्र में होते हैं। निःसन्देह, अक्षमताओं की रोकथाम के प्रावधान सकारात्मक विशेषाधिकार पैदा नहीं करते हैं, दोनों पहलुओं को कभी-कभी इतना मिश्रित किया जाता है कि खतरा यह है कि कोई व्यक्ति विशेषाधिकार से इनकार करते हुए उस प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है जो अक्षमता को रोकने के लिए बनाया गया है और इस प्रकार संविधान की गारंटी को शून्य कर देता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो भी स्थिति हो, जहां तक हमारे संविधान का संबंध है, इसमें ऐसे लेख शामिल हैं जो न केवल अल्पसंख्यकों की अक्षमताओं को रोकने के लिए बनाए गए हैं, बल्कि उनके लिए सकारात्मक अधिकार भी पैदा करते हैं। अनुच्छेद 30 (1) उस राज्य से संबंधित है।

गोरी।

यदि किसी शिक्षक की संबद्धता या मान्यता के लिए अनुरोध किया जाता है

राष्ट्रीय संस्थान, यह अनुरोध में निहित है कि शैक्षणिक संस्थान उन नियमों का पालन करेगा जो संबद्धता या मान्यता प्रदान करने वाले लेखक द्वारा बनाए गए हैं। उक्त प्राधिकारी हमेशा विनियम निर्धारित कर सकता है और इस बात पर जोर दे सकता है कि किसी शैक्षणिक संस्थान को

संबद्धता या मान्यता देने से पहले उनका पालन किया जाना चाहिए। प्राधिकरण को विनियम बनाने की शक्ति से वंचित करना

(2) [1963] एस. सी. आर. 651; (1964) डी. एल. आर. 2 डी 485।

(1) 319 यू. एस. 624 एसटी

एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (खन्ना, जे.)

237

ए.

संबंधित के परिणामस्वरूप संबद्धता या पुनर्निर्धारण की अवधारणा को लूट लिया जाएगा

जब तक यह एक निश्चित मानक के अनुरूप न हो। तथ्य यह है कि

संस्थान वास्तव में निर्धारित मानक का है

संबद्धता या मान्यता की अवधारणा। अतः इसकी अनुमति है -

विनियमों को विहित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी जो सुसंगत होने चाहिए -

इससे पहले कि कोई संस्थान संबद्धता की तलाश कर सके और उसे बनाए रख सके और

मान्यता। तब सवाल उठता है कि क्या कोई सीमा है

बी.

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए विनियमों का निर्धारण।

जहाँ तक इस पहलू का संबंध है, विनियमन को निर्धारित करने वाला प्राधिकरण राष्ट्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि संविधान ने एक निधि की गारंटी दी है

अल्पसंख्यकों को स्थापित करने के लिए मानसिक अधिकार और

प्रशासन

प्राधिकरण

उनके शैक्षणिक संस्थान। द्वारा बनाए गए नियम

संबंधित को उस अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः संतुलन है, दो उद्देश्यों के बीच रखा जाना, मानक सुनिश्चित करना

सी.

संस्थान की उत्कृष्टता और उसके अधिकार का संरक्षण

अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना। नियम जो दोनों उद्देश्यों को शामिल करते हैं और उनका मिलान करते हैं, वे हो सकते हैं -

उचित माना जाता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह विवादित नहीं किया गया है कि यदि

राज्य या अन्य वैधानिक प्राधिकरण इसके लिए उचित नियम बनाते हैं

डी.

शैक्षणिक संस्थान, वे नियम अधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक। हम सहमत हैं कि

इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा लिया गया रुख। यह गलत होगा।

यह मान लेना कि अनुच्छेद 30 के अनुसार एक अप्रतिबंधित अधिकार अनुपस्थिति को स्वीकार करता है नियमों का। संयुक्त राष्ट्र के बावजूद नियम निर्धारित किए जा सकते हैं

अधिकार की सीमित प्रकृति। अधिकार की अप्रतिबंधित प्रकृति

अधिकार के प्रयोग में स्वतंत्रता को दर्शाता है। शब्द भी।

ई.

" "स्वतंत्रता" और "स्वतंत्र" की कुछ सीमाएँ हैं। जेम्स वी. द.

राष्ट्रमंडल (!) प्रिवी काउंसिल ने इसके अर्थ से निपटा

ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 92 में "बिल्कुल मुक्त" शब्द हैं। कहा गया: " "मुक्त" अपने आप में अस्पष्ट और अनिश्चित है। इसे होना ही चाहिए।

" इसका रंग संदर्भ से लें। उदाहरण के लिए तुलना करें, इसका उपयोग

मुक्त भाषण, मुक्त प्रेम, मुक्त रात्रिभोज और मुक्त व्यापार। बोलने की आजादी

इसका मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है; इसका मतलब है कि भाषण सभी कानूनों से सुरक्षित है।

एफ.

मानहानि, ईशनिंदा, राजद्रोह आदि के विरुद्ध; इसका अर्थ है स्वतंत्र

कानून द्वारा शासित डोम। अमेरिका का पहला संशोधन

संविधान में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कांग्रेस कोई कानून नहीं बनाएगी।

धर्म की स्थापना का सम्मान करना या स्वतंत्र व्यायाम को प्रतिबंधित करना

वहाँ से। उस संशोधन से निपटने के लिए, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया

रेनॉल्ड्स बनाम के मामले में। संयुक्त राज्य अमेरिका () कि उस संशोधन ने किया

कांग्रेस को उन कार्यों को दंडित करने की शक्ति से वंचित नहीं करना जो थे

जी.

सामाजिक कर्तव्यों का उल्लंघन या अच्छी व्यवस्था का उल्लंघन। द कॉन उस मामले में अपीलार्थी की ओर से दिया गया उल्लेख कि

गैमी उनकी धार्मिक आस्था और कांग्रेस के अधिनियम का एक हिस्सा था।

बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने से उनके धर्म के स्वतंत्र अभ्यास का उल्लंघन हुआ

पेल्ड। कैंटवेल बनाम के मामले में। कनैकटिकट (3) रॉबर्ट्स जे. बोल रहे हैं अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम संशोधन के संबंध में टिप्पणी की

एच.

विचार:

(1) [1936] ए. सी. 578 .

(2) 98 यू. एस. 145 (1878)

(3) . 310 अमेरिका 296 (1940)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

. 2 38

[1975] 1 एस सी आर।

" इस प्रकार संशोधन में दो उपबंध शामिल हैं-मुक्त

विश्वास करना और कार्य करने की स्वतंत्रता। पहला निरपेक्ष है। लेकिन, चीजों की प्रकृति में, दूसरा नहीं हो सकता है। कोन.

नलिका संरक्षण के लिए विनियमन के अधीन रहती है

समाज। कार्य करने की स्वतंत्रता की उचित परिभाषा होनी चाहिए। उस सुरक्षा के प्रवर्तन को बनाए रखने के लिए "।

लाथम सी. जे. द्वारा भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था। एडिलेड के मामले में

कंपनी ऑफ़ जेहोवा 'ज़ विट्नेस इंक. (ऊपर) के साथ व्यवहार करते समय

ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 116 जब उन्होंने कहा कि

आम तौर पर समुदाय पर लागू होने वाले कानूनों का पालन करने का अधिकार है

स्वतंत्रता के साथ असंगत नहीं माना जाता है। अत: यह होगा कि

इसका पालन करें कि एक अधिकार की अप्रतिबंधित प्रकृति को रोकने नहीं है

अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित विनियम बनाना।

बहस के दौरान सवाल उठाया गया है कि क्या

अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थान

केवल वे संस्थान होने चाहिए जो एक के साथ स्थापित किए गए हैं अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण करना। रखने के लिए

दूसरे शब्दों में, सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 30 का खंड (1) यह अनुच्छेद 29 के खंड (1) के प्रावधानों के अधीन है। इस रेज़ में

पी. टी. आई. का विचार है कि अनुच्छेद 29 का खंड (1) और खंड (1)

अनुच्छेद 30 अलग-अलग मामलों से संबंधित है और इसकी अनुमति नहीं है -

अनुच्छेद के खंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार को सीमित या सीमित करें।

30 इसमें खंड (1) से आयातित किसी सीमा को पढ़कर अनुच्छेद 29. अनुच्छेद 29 (1) नागरिकों के किसी भी वर्ग को अधिकार प्रदान करता है।

संरक्षित करने के लिए अपनी खुद की एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति होना

खंड कि नागरिकों के वर्ग को अल्पसंख्यक होना चाहिए। के रूप में इसके विपरीत, अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नाबालिगों को है।

ऐसे संबंध जो धर्म या भाषा पर आधारित हों। सही कॉन

अनुच्छेद 29 (1) भाषा, लिपि या लिपि के संरक्षण के लिए है।

संस्कृति, जबकि अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत स्थापना के लिए है

शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन और प्रशासन अल्पसंख्यक। अगर यह संविधान निर्माताओं का इरादा होता कि

शैक्षणिक संस्थान जिन्हें स्थापित और प्रशासित किया जा सकता है अल्पसंख्यकों को केवल अपनी भाषा के संरक्षण के लिए होना चाहिए,

लिपि या संस्कृति, वे इसके लिए शब्दों का उपयोग करने में विफल नहीं होते अनुच्छेद 30 (1) में प्रभाव। उन शब्दों के अभाव में, यह मुश्किल है

इस विचार को स्वीकार करने के लिए कि में उल्लिखित शैक्षणिक संस्थान

अनुच्छेद 30 (1) केवल वे हैं जिनका उद्देश्य भाषा का संरक्षण करना है,

अल्पसंख्यकों की लिपि या संस्कृति। अनुच्छेद 30 का खंड (1) भी

"उनकी पसंद के" शब्दों पर दाग लगाता है। ये शब्द जो "शिक्षा" के योग्य हैं

राष्ट्रीय संस्थान विशाल विवेक और विकल्प दिखाते हैं जो

स्थापित करने के लिए। यदि एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्थापित किया जाता है अल्पसंख्यक अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए, अधिकार

ऐसी संस्था की स्थापना और प्रशासन दोनों अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं।

29 (1) साथ ही अनुच्छेद 30 (1) के तहत। हालाँकि, अल्पसंख्यक कर सकते हैं,

एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चुनें जो विशुद्ध रूप से एक

सामान्य धर्मनिरपेक्ष चरित्र और उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। ऐसी संस्था की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 30 (1) और एस. टी. द्वारा दी गई है।

एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (खन्ना, जे.)

239

ए.

ऐसी संस्था विशिष्ट भाषा, लिपि का संरक्षण नहीं करती है या

अल्पसंख्यकों की संस्कृति इसे अनुच्छेद के दायरे से बाहर नहीं ले जाएगी।

30 (1) .

उपरोक्त निष्कर्ष पर मैं दास की टिप्पणियों से मजबूत हुआ हूं।

सीजे। केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) और हिदायतुल्ला सी. जे. में। में रेव. फादर प्रोस्ट (ऊपर) का मामला। दास सी. जे. देखा गया:

बी.

" ऐसे अल्पसंख्यकों को दिया गया अधिकार यह स्थापित करना है कि

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान। करता है।

न कहें।

कि धर्म पर आधारित अल्पसंख्यकों को शिक्षा की स्थापना करनी चाहिए

अल्पसंख्यकों को शिक्षा स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए संस्थान केवल अपनी भाषा पढ़ाने के लिए। क्या बात?

लेख कहता है और इसका अर्थ है कि धार्मिक और भाषाई

सी एस

अल्पसंख्यकों को शिक्षा स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए

अपनी पसंद की संस्थाएं। कोई सीमा नहीं है

ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर।

इस तरह के अल्पसंख्यक आम तौर पर चाहेंगे कि उनके बच्चे

ठीक से और कुशलता से पाला जाना चाहिए और योग्य होना चाहिए उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए और दुनिया में बाहर जाने के लिए

इस तरह की बौद्धिक उपलब्धियों से पूरी तरह से सुसज्जित

डी.

उन्हें सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा में प्रवेश के लिए उपयुक्त बनाना। उनकी पसंद के संस्थानों में अनिवार्य रूप से संस्थान शामिल होंगे।

सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी प्रदान करने वाले देश "।

हिदायतुल्ला सी. जे. निम्नलिखित शब्दों में कुछ हद तक समान दृष्टिकोण व्यक्त किया:

" हमारी राय में, कला की चौड़ाई। 30 (1) काटा नहीं जा सकता है

ई.

इसमें किस कला पर विचार प्रस्तुत किया गया है। 29 (1) आधारित है। बाद वाला अनुच्छेद एक सामान्य संरक्षण है जो अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए दिया जाता है। पहला अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का विशेष

अधिकार है। यह विकल्प भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण की मांग करने वाले संस्थानों तक ही सीमित नहीं है और यदि अल्पसंख्यक समुदाय ने अपनी पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया है तो अन्य समुदायों के सदस्यों को भी स्वीकार करने का विकल्प नहीं लिया जाता है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो कला के अनुप्रयोग के लिए अप्रासंगिक है। 30 (1) क्योंकि ऐसी कोई सीमा व्यक्त नहीं की गई है और कोई भी निहित नहीं किया जा सकता है। दोनों लेख दो अलग-अलग अधिकार पैदा करते हैं, हालांकि यह है

एफ.

संभव है कि वे किसी मामले में मिल सकें।

उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि कोई नहीं है

जी.

संबद्धता या मान्यता का मौलिक अधिकार और संबद्धता या मान्यता प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को मान्यता या संबद्धता के लिए निर्धारित शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। जहाँ तक इस पहलू का संबंध है, मेरा विचार है कि राज्य के लिए यह अनुमत है कि वह उचित विनियम निर्धारित करे जैसे कि मैंने पहले संदर्भित किया है और इसे अल्पसंख्यक संस्थान की मान्यता या संबद्धता के अनुसार एक पूर्ववर्ती शर्त बनाए।

एच.

हालाँकि, मान्यता या संबद्धता के लिए ऐसी शर्तें निर्धारित करने की अनुमति नहीं है जो अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को बाधित करती हैं। संबद्धता 240

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर.

और मान्यता, निस्संदेह, अनुच्छेद 30 (1) में उल्लिखित नहीं है,

स्थिति वही बनी हुई है जो मुझे पहचानने या संबद्ध करने से इनकार करती है नोरी संस्थाएँ जब तक कि वे (अल्पसंख्यक) अधिकार का समर्पण नहीं करते हैं

उन संस्थानों को प्रशासित करने का प्रभाव होगा

अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार पूरी तरह से भ्रामक है और वास्तव में

अपने संस्थानों की मान्यता या संबद्धता के बदले में अल्पसंख्यक। एक कीमत जिसमें कम करना या समाप्त करना शामिल होगा

अनुच्छेद 30 (1) के तहत। एक शैक्षणिक संस्थान शायद ही ऐसा कर सकता है किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करना या किसी भी व्यावहारिक उपयोगिता का होना जब तक कि यह इससे संबद्ध न हो

एक विश्वविद्यालय या अन्यथा अन्य शैक्षणिक संस्थान की तरह मान्यता प्राप्त है

टियोन। अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार एक वास्तविक और सार्थक अधिकार है।

यह न तो एक अमूर्त अधिकार है और न ही इसे निर्वात में प्रयोग किया जाना है। अनुच्छेद 30 (1) का वास्तविक महत्व रखने का इरादा था और यह नहीं है

इसका इस तरह से अर्थ लगाने की अनुमति है जो इसे उससे लूट ले

दास सी. जे. के अवलोकन। केरल शिक्षा विधेयक का मामला (ऊपर) पृष्ठों पर 1067-68:

" मान्यता के बिना, इसलिए, शैक्षणिक संस्थान

अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित या स्थापित किए जाने वाले राज्य

मुद्राएँ अपनी पसंद के वास्तविक उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकती हैं और Art.30 (1) के तहत अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। द.

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार,

इसलिए, वास्तविक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है जो अपने समुदाय की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करेंगे और

विद्वान जो अपने शैक्षणिक संस्थानों का सहारा लेते हैं। वहाँ

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे मान्यता देने का मौलिक अधिकार है।

समर्पण के समान शर्तों को छोड़कर संस्थाएं शिक्षा के प्रशासन के उनके संवैधानिक अधिकार का

उनकी पसंद की राष्ट्रीय संस्थाएं सच्चाई में और प्रभावी रूप से हैं उन्हें Art.30 (1) के तहत उनके अधिकारों से वंचित करना। हम दोहराते हैं।

कि विधायी शक्ति मौलिक अधिकारों के अधीन है

और विधायिका अप्रत्यक्ष रूप से इसे हटा या कम नहीं कर सकती है।

मौलिक अधिकार जो वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सका और फिर भी वह परिणाम होगा यदि उक्त विधेयक में कोई

उल्लंघनकारी खंड कानून बन जाता है।

रेव. सिद्धजभाई भाई (उपरोक्त) के मामले में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था जिसमें यह कहा गया था:

" सरकार अनुदान देने के लिए भी परीक्षा आयोजित करती है

प्रशिक्षित प्राथमिक के रूप में सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र

मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक और विद्वान

केवल शिक्षक ही परीक्षा में उपस्थित होने के हकदार हैं। मणि

उत्सव के रूप में, सरकारी ट्रेन की अनुपस्थिति या मान्यता में

महाविद्यालय में प्रवेश की बहुत कम व्यावहारिक उपयोगिता होगी। द.

महाविद्यालय एक गैर-लाभकारी संस्थान है और इस पर निर्भर करता है

बैठक के लिए दान और सरकारी अनुदान पर मैरीली

उनके खर्च। इस तरह के अनुदान के बिना, यह अत्यधिक होगा संस्थान के लिए काम करना असंभव नहीं तो मुश्किल है।

- एसटी. एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (खन्ना, जे.)

241

सहायता या मान्यता के संबंध में जो ऊपर कहा गया है वह समान रूप से लागू होता है।

विश्वविद्यालय से किसी महाविद्यालय की संबद्धता के लिए क्योंकि लेकिन इस तरह के संबंध के लिए छात्र विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा जो कई व्यवसायों के लिए पासपोर्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है और भविष्य में लोक सेवा में कार्यरत है।

उत्तरदाताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि

जब तक कोई कानून या विनियमन अनुच्छेद 30 (1) के तहत अप्राप्त संबंध के अधिकार का पूरी तरह से विनाशकारी नहीं है, तब तक वह निरस्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह तर्क असमर्थनीय है और अनुच्छेद 13 के सामान्य युग के विपरीत है। उस अनुच्छेद के अनुसार, एक कानून अमान्य होगा, भले ही वह केवल भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार का हनन करे और उस अधिकार को पूरी तरह से छीन न ले। यह तर्क कि किसी कानून या विनियम को तब तक अनुचित नहीं माना जा सकता जब तक कि यह शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने के अल्पसंख्यक के अधिकार का पूरी तरह से विनाशकारी न हो, इस न्यायालय द्वारा रेव. सिद्धजभाई भाई (उपरोक्त) के मामले में स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। रे के मामले को संदर्भित करने के बाद। केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) इस न्यायालय ने रेव.

सिद्धजभाई भाई:

" हालाँकि, न्यायालय ने तर्क का कोई परीक्षण निर्धारित नहीं किया।

विनियमन की निष्पक्षता। न्यायालय ने यह निर्णय नहीं लिया कि

लोक या राष्ट्रीय हित एकमात्र उपाय या परीक्षा थी

1

तर्कसंगतता: यह भी तय नहीं किया कि एक विनियमन होगा केवल तभी अनुचित माना जाएगा जब यह पूरी तरह से विनाशकारी था

अल्पसंख्यक समुदाय का शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने का अधिकार।

कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है जिस पर तर्कसंगतता या अन्यथा

एक विनियमन का परीक्षण किया जा सकता है जिसे निर्धारित करने की मांग की गई थी

अदालत। इसलिए केरल शिक्षा विधेयक का मामला नहीं है।

1

अतिरिक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण

महान्यायवादी ने कहा कि सभी विनियामक उपाय जो नहीं हैं

संस्था के चरित्र का विनाशकारी या विनाशकारी

अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित, बशर्ते नियम में हों

राष्ट्रीय हित या सार्वजनिक हित मान्य हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मामले के पृष्ठ 1065 पर केरल शिक्षा विधेयक दास सीजे है। विधेयक के खंड 14 और 15 पर विचार करते हुए कहा गया कि उन खंडों के प्रावधान अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकारों के लिए पूरी तरह से विनाशकारी हो सकते हैं। इन टिप्पणियों का उद्देश्य उन खंडों के प्रभाव का वर्णन करना था। उन टिप्पणियों में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि यह न्यायालय उन खंडों को बरकरार रखता यदि उन खंडों ने अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार को संक्षिप्त या आंशिक रूप से नष्ट कर दिया होता और पूरी तरह से नष्ट नहीं किया होता।

यह सही है।

उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, यह कहा जा सकता है कि एक कानून जो एक शासी निकाय की अल्पसंख्यकों की पसंद में हस्तक्षेप करता है या

प्रबंधन परिषद अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन करेगी। आर. टी. के मामलों में इस न्यायालय द्वारा यह दृष्टिकोण लगातार लिया गया है। रेव. बिशप एस. के. पात्रो, मदर प्रोविंशियल और डी. ए. वी.

गुरु नानक विश्वविद्यालय (ऊपर) से संबद्ध महाविद्यालय।

धारा 33-ए, जो महाविद्यालय के प्रबंधन के लिए एक नए शासी निकाय और चयन समितियों के साथ-साथ उसके गठन का भी प्रावधान करती है, जहां तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का

संबंध है, अनुच्छेद 30 (1) के उल्लंघन के कारण इसे निरस्त करना होगा। इस धारा के प्रावधानों को पहले पुनः प्रस्तुत किया गया है और वे केरल विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 48 के समान हैं, जिनमें से उप-धारा (2), (4), (5) और (6) को इस न्यायालय द्वारा मातृ प्रांतीय (उपर्युक्त) के मामले में अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन करने वाला माना गया था। आरटी के मामले में। रेव. बिशप एस. के. पात्रो, इस न्यायालय ने शैक्षणिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को अमान्य घोषित कर दिया जिसमें चर्च मिशनरी सोसाइटी हायर सेकेंडरी स्कूल के सचिव को शैक्षणिक अधिकारियों के आदेश के अनुसार एक प्रबंध समिति का गठन करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता थी। धारा 33-ए भी क़ानून 2 (1) (ए) के समान है जिसे गुरु नानक विश्वविद्यालय (अमृतसर) अधिनियम के तहत बनाया गया था। क़ानून 2 (1) (ए) निम्नानुसार था:

" 2 (1) (क) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाला महाविद्यालय

विश्वविद्यालय के अधिकारी आवेदन पत्र भेजेंगे पंजीयक और सीनेट को संतुष्ट करेगा -

(क) कि महाविद्यालय का नियमित रूप से गठन किया जाएगा।

सीनेट द्वारा अनुमोदित प्रति पुत्र 20 से अधिक नहीं होने वाला शासी निकाय और अन्य लोगों के अलावा, विश्वविद्यालय के 2 प्रतिनिधि और

महाविद्यालय के प्राचार्य पदेन।

बशर्ते कि उक्त शर्त में लागू नहीं होगी

सरकार द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय का मामला जो कैसे होगा

कभी भी एक सलाहकार समिति हो जिसमें अन्य लोग शामिल हों

महाविद्यालय के प्राचार्य (पदेन) और दो प्रतिनिधि

विश्वविद्यालय के मूल निवासी।

उपरोक्त कानून को इस न्यायालय द्वारा दूसरे डी. ए. वी. कॉलेज मामले में निरस्त कर दिया गया था।

एक अन्य निष्कर्ष जो ऊपर चर्चा की गई है, वह यह है कि एक कानून जो अल्पसंख्यकों की पसंद में हस्तक्षेप करता है।

योग्य शिक्षक या शिक्षकों और संस्थान के कर्मचारियों के अन्य सदस्यों पर इसका अनुशासनात्मक नियंत्रण अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन करने के रूप में अमान्य है। बेशक, राज्य और उसके शैक्षिक प्राधिकरणों के लिए शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने की अनुमति है, लेकिन

एक बार जब अल्पसंख्यकों द्वारा अपेक्षित योग्यता रखने वाले शिक्षकों का उनके शैक्षणिक संस्थानों के लिए चयन कर लिया जाता है, तो राज्य को उन शिक्षकों के चयन पर वीटो करने का कोई अधिकार नहीं होगा। एक शैक्षणिक संस्थान के लिए शिक्षकों का चयन और नियुक्ति एक शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन के अधिकार के आवश्यक तत्वों में से एक है और अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन किए बिना चयन और नियुक्ति के ऐसे अधिकार से स्पष्ट रूप से वंचित नहीं किया जा सकता है। रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 48-ए पर विचार करते हुए कहा कि उक्त प्रावधान एसटी है।

XAVIERS कॉलेज v. गुजरात (खन्ना, जे.)

243

महाविद्यालय के शासी निकाय की स्वायत्तता को पूरी तरह से छीन लिया और वस्तुतः महाविद्यालय का नियंत्रण विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सौंप दिया। इसलिए उस मामले में याचिकाकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के संरक्षण का हकदार माना गया था। उस धारा के प्रावधानों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस धारा के अनुसार, विश्वविद्यालय की नियुक्तियों की मंजूरी, बर्खास्तगी, निष्कासन, सेवा की समाप्ति या राज्य सरकार से संबंधित नहीं होने वाले किसी संबद्ध कॉलेज के शिक्षकों के पद में कमी विश्वविद्यालय सेवा आयोग की सिफारिश पर कॉलेज के शासी निकाय द्वारा की जानी चाहिए। इस धारा में आगे यह प्रावधान किया गया कि उक्त आयोग से कॉलेज के शिक्षकों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों में कॉलेज के शासी निकाय द्वारा परामर्श किया जाएगा और आयोग के निष्कर्षों के अनुरूप होने के अलावा कॉलेज के शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई सजा नहीं की जाएगी। डी. ए. वी. कॉलेज, जो गुरु नानक विश्वविद्यालय से संबद्ध था, के मामले में, गुरु नानक विश्वविद्यालय (अमृतसर) अधिनियम के तहत बनाए गए कानून 17 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि शुरू में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और बाद के सभी परिवर्तनों की सूचना कुलपति की मंजूरी के लिए विश्वविद्यालय को दी जाएगी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कानून 17 याचिकाकर्ता कॉलेजों के

प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप करता है और इस प्रकार, अनुच्छेद 30 (1) को आहत करता है।

यद्यपि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के शिक्षकों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण शासी परिषद के पास होगा, लेकिन मेरी राय में, शिक्षकों की सेवा की उचित शर्तें सुनिश्चित करने और शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में एक निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। ऐसे प्रावधान जिनकी गणना शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए की जाती है, उनके परिणामस्वरूप कार्यकाल की सुरक्षा होगी और इस प्रकार अनिवार्य रूप से शिक्षकों के पदों के लिए सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित किया जाएगा। इस तरह के प्रावधान से शिक्षकों में हताशा के संभावित कारण भी समाप्त हो जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए बनाए गए विनियमों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के हित में माना जाना चाहिए और इस तरह वे अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन नहीं करेंगे।

विवादित अधिनियम की धारा 51 ए की उप-धाराओं (1) और (2) का खंड (ए) जो उचित अवसर देने का प्रावधान करता है।

किसी शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारी के सदस्य पर प्रस्तावित दंड के खिलाफ कारण बताने की योग्यता को परिणामस्वरूप वैध माना जाएगा। उन उप-धाराओं का खंड (बी) जो कुलपति और उनके द्वारा अधिकृत विश्वविद्यालय के अधिकारी को कर्मचारियों के किसी सदस्य को सजा देने में किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रबंध निकाय की कार्रवाई पर वीटो करने की शक्ति देता है, मेरी राय में, प्रबंध निकाय के अनुशासनात्मक नियंत्रण में हस्तक्षेप करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

244

शिक्षक। यह महत्वपूर्ण है कि धारा 51 क की दो उप-धाराओं में से प्रत्येक में खंड (ख) द्वारा कुलपति या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी को प्रदत्त अनुमोदन की शक्ति एक व्यापक शक्ति है। उस शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं और यह प्रावधान नहीं है कि बर्खास्तगी, निष्कासन, रैंक में कमी या सेवा की समाप्ति दुर्भावनापूर्ण या उत्पीड़न या इसी तरह के अन्य कारणों से होने पर ही अनुमोदन को रोका जाना चाहिए। किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन निकाय की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर वीटो करने के लिए कुलपति या अन्य लेखक अधिकारी को ऐसी व्यापक शक्ति प्रदान करने से उनके अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

किसी शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने के लिए प्रबंध निकाय। खंड

((ख) इसलिए धारा 51 क की दो उप-धाराओं में से प्रत्येक में -

जहाँ तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का संबंध है, उन्हें अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा।

अधिनियम की धारा 52 ए दोनों के बीच विवादों के संदर्भ से संबंधित है।

एक शासी निकाय और शिक्षण का कोई भी सदस्य, अन्य शैक्षणिक

और ऐसे सदस्य की सेवा की शर्तों से जुड़े किसी संबद्ध कॉलेज या मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्थान के गैर-शिक्षण कर्मचारी

मध्यस्थता मध्यस्थता के एक न्यायाधिकरण के लिए, जिसमें कॉलेज के शासी निकाय द्वारा नामित एक व्यक्ति या, जैसा भी मामला हो,

मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्थान, द्वारा नामित एक सदस्य

विवाद में शामिल कर्मचारियों का सदस्य और कुलपति द्वारा नियुक्त एक अंपायर। धारा 52 ए व्यापक रूप से शब्दबद्ध है, और

यह खड़ा है कि यह इसके दायरे में इससे जुड़े हर विवाद को शामिल करेगा

एक शैक्षिक संस्थान के कर्मचारी की सेवा की शर्तें

संस्था चाहे कितनी भी तुच्छ या महत्वहीन क्यों न हो, जो उत्पन्न हो सकती है। महाविद्यालय के शासी निकाय और कर्मचारी वर्ग के सदस्य के बीच।

इस धारा का प्रभाव यह होगा कि एक की प्रबंध समिति

शैक्षणिक संस्थान अपने कर्मचारियों द्वारा एक शृंखला में उलझा हुआ होगा

मध्यस्थता कार्यवाही। धारा 52 ए के प्रावधान

इस प्रकार एक के प्रभावी प्रशासन के चक्र में एक बोलने के रूप में कार्य करें

शैक्षणिक संस्थान। यह भी कहा जा सकता है कि प्रमुख मामलों के निपटारे के लिए मध्यस्थता की विधि का चयन करने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है

शिक्षा के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित विवाद संस्थाएं। यह वास्तव में एक इच्छा हो सकती है। जो आपत्तिजनक है,

ऊपर जो उल्लेख किया गया है, उसके अलावा, शक्ति देना है

अंपायर को नामित करने के लिए कुलपति को। आम तौर पर ऐसे में

विवादों में मध्यस्थ के बीच शायद ही कोई समझौता होगा

संस्थान के शासी निकाय और एक नामांकित व्यक्ति द्वारा नामित

कर्मचारियों के संबंधित सदस्य द्वारा स्थापित। इसका परिणाम यह होगा कि

शक्ति सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए नामित व्यक्ति में निहित होगी

शासी निकाय के बीच सभी विवादों का फैसला करने के लिए कुलपति

और बाद की शर्तों से जुड़े कर्मचारी का सदस्य सेवा करते हैं। इस प्रकार शासी निकाय शायद ही ऐसी स्थिति में होगा कि

कर्मचारी के किसी सदस्य के खिलाफ कोई भी प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।

यह शासी निकाय के अधिकार में प्रवेश का कारण बनना चाहिए

संस्थान का नाम दर्ज करें। इसलिए, धारा 52 ए को माना जाना चाहिए -

जहां तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का संबंध है, अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन है।

वे चिंतित हैं।

एसटी. एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (खन्ना, जे.)

245

ए.

ऊपर जो उल्लेख किया गया है उसे ध्यान में रखते हुए, धारा 40 और 41

जहां तक अल्पमत है, अधिनियम को भी निरस्त करना होगा।

महाविद्यालय अनुच्छेद 30 (1) के उल्लंघन के रूप में चिंतित हैं। इसका प्रभाव

धारा 40 और 41 का यह है कि यदि विश्वविद्यालय ऐसा निर्धारित करता है

और राज्य सरकार उप के तहत आवश्यक अधिसूचना जारी करती है

धारा 40 की धारा (2) में सभी निर्देश, शिक्षण और प्रशिक्षण विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

बी.

विश्वविद्यालय द्वारा और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाएगा

विविधता। परिणाम यह होगा कि में उल्लिखित मामलों को छोड़कर

धारा 41 की उप-धारा (4) का परंतुक कोई निर्देश नहीं, शिक्षण

और अध्ययन के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण, जो अब तक रहे हैं

संबद्ध कॉलेजों द्वारा संचालित किया जाएगा, इन द्वारा संचालित किया जाएगा

महाविद्यालय, क्योंकि वही विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाना होगा

विविधीकरण और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए

सी.

सिटी। संबद्ध महाविद्यालय भी उपरोक्त के परिणामस्वरूप बन जाएंगे

घटक महाविद्यालय। एक प्रावधान जो इसे अनिवार्य बनाता है कि

स्नातक पाठ्यक्रमों में शिक्षण केवल द्वारा संचालित किया जा सकता है

विश्वविद्यालय और केवल विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जा सकता है

अल्पसंख्यकों के स्थापना और प्रशासन के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है

उनके शैक्षणिक संस्थान। फलस्वरूप ऐसा प्रावधान होना चाहिए -

डी.

अनुच्छेद का उल्लंघन करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों का गठन किया गया

30 (1) . इसलिए, मैं धारा 40 को अल्पसंख्यक के रूप में समाप्त कर दूंगा।

शैक्षणिक संस्थान Art.30 (1) के उल्लंघन के रूप में चिंतित हैं। इसके अलावा, एक बार धारा 40 को असंवैधानिक माना जाता है।

शिक्षा संस्थानों का संबंध है, वही बुराई प्रभावित करेगी

धारा 41 क्योंकि धारा 41 केवल तभी काम कर सकती है जब धारा 40 बनी रहे। हमला और अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन नहीं माना जाता है। मैं करूँगा।

ई.

इसलिए, अल्पसंख्यकों के संबंध में धारा 40 और 41 को अमान्य ठहराएँ।

शैक्षणिक संस्थान।

प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि मामले में

केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) के इस न्यायालय ने खंड 11 को बरकरार रखा

और 12. खंड 11 ने सभी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए चयन करना अनिवार्य कर दिया

एफ.

द्वारा प्रत्येक जिले के लिए चुने गए उम्मीदवारों के एक पैनल से शिक्षक

लोक सेवा आयोग। की शर्तों से संबंधित खंड 12 सहायता प्राप्त शिक्षकों की सेवा। खंड 12 के उपखंड (4) के अनुसार,

सहायता प्राप्त विद्यालय के किसी भी शिक्षक को बर्खास्त, हटाया या हटाया नहीं जा सकता था।

पिछली मंजूरी के बिना प्रबंधक द्वारा पद पर या निलंबित किया गया

अधिकृत अधिकारी से। दास सी. जे. यह पाया गया कि उपरोक्त प्रावधान

प्रशासन के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण थे और प्रकट हुए

जी.

खतरनाक रूप से उस अधिकार का उल्लंघन करने के करीब। फिर भी, उन्होंने देखा कि

यह न्यायालय "जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है" उन नियमों पर विचार करने के लिए तैयार था

कि बाद के मामलों में इस न्यायालय ने इसी तरह के प्रावधानों को उल्लंघन माना अल्पसंख्यक संस्थानों के मामले में अनुच्छेद 30 (1) का उपबंध। राय.

केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया था

एक सलाहकार चरित्र और हालांकि बहुत अधिक वजन जोड़ा जाना चाहिए

एच.

इसके प्रेरक मूल्य के कारण, उक्त राय ओवरराइड नहीं कर सकती है

बाद में इस न्यायालय द्वारा विवादित मामलों में व्यक्त की गई राय।

यह बाद के विवादित मामलों में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून है सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर.

246

जिसका एक बाध्यकारी प्रभाव होगा। शब्द "जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है"

साथ ही पूर्ववर्ती वाक्य इंगित करता है कि द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण

इस संबंध में केरल शिक्षा विधेयक में यह न्यायालय संकोच कर रहा था

और अस्थायी और मामले में अंतिम दृष्टिकोण नहीं। यह बताया गया है

इसे एस्टेट शुल्क (1) स्पेंस सी. जे. के पुनः शुल्क में शामिल किया गया है। संदर्भित किया जाता है

ओंटारियो के महान्यायवादी बनाम के मामले में किया गया वचन। वकील

कनाडा के लिए जनरल (2) की सलाहकार राय। अदालत करेगी

कानून अधिकारियों की राय से अधिक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है।

मामले के इस पहलू पर विस्तार करें क्योंकि मेरी राय है कि

ऊपर निर्दिष्ट बाद के मामलों में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार

री केरल एजुकेशन में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों को लागू करके

यह विधेयक सही है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने की आवश्यकता है।

उत्तरदाताओं की ओर से संदर्भ दिया गया है

डॉ. राधाकृष्णन आयोग की प्रशंसा 1948-49 में की गई

जिसमें घटक कॉलेजों के लिए वरीयता दिखाई गई थी। जहाँ तक इस

पहलू का संबंध है, मैं देख सकता हूं कि यदि कोई वैधानिक प्रावधान है

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन पाया गया, तथ्य

कि यह एक की सिफारिश के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है विशेषज्ञ निकाय न्यायालय को उस पक्ष को खारिज करने से नहीं रोकेगा

दृष्टि। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि मातृ प्रांत के मामले में

सिया! (ऊपर) शिक्षा की रिपोर्ट पर निर्भरता रखी गई थी।

आयोग। इस न्यायालय ने उस संदर्भ में टिप्पणी की कि वह तथ्य साथ ही यह तथ्य कि प्रावधान हितकर थे, इसमें खड़ा नहीं हो सकता था

संवैधानिक गारंटी का चेहरा। उक्त री का संदर्भ

इसलिए बंदरगाह को आवश्यक नहीं माना जाता था। मैं आगे बढ़ सकता हूँ।

उल्लेख करें कि डॉ. राधाकृष्णन कॉम की रिपोर्ट के बाद

मिशन, तीन अन्य निकायों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनमें से एक

1965 में कोठारी समिति द्वारा बंदरगाह दिए गए थे। दूसरा था डॉ. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की रिपोर्ट

1966 में। तीसरा डोंगरकेरी आयोग की उप-रिपोर्ट थी। 1972 में स्थापित। एफ़ी के रूपांतरण का कोई संदर्भ नहीं था

इन तीनों रिपोर्टों में से किसी एक में महाविद्यालयों को घटक महाविद्यालयों में विभाजित किया गया।

किसी भी रिपोर्ट में ऐसा कोई अवलोकन नहीं किया गया कि प्रो

अनुच्छेद 30 (1) के दर्शन और उस पर रखी गई संरचना

किसी भी तरह से शिक्षा के मानकों को ऊपर उठाने के रास्ते में खड़ा था या

शैक्षणिक संस्थानों की उत्कृष्टता में सुधार करना। यह भी हो सकता है

सी. पी. टी. और विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में भिन्न हो सकता है। की अवधारणा घटक महाविद्यालय जो के विवादित प्रावधानों में देखे गए हैं

अधिनियम की धारा 40 और 41 में विचार किया गया है कि

निर्धारित पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर पर शिक्षण केवल विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। अल्पसंख्यक कोल

इस तरह के कानून पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने के हकदार नहीं होंगे

अपने स्वयं के शिक्षकों के माध्यम से अध्ययन करें। धारा 40 और 41, वहाँ

इसके अलावा, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन है।

इस तरह के मामले में, शायद किसी को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वीकृत मानदंडों को भी ध्यान में रखना होगा। अब तक जो जहाँ तक स्नातकोत्तर शिक्षण का संबंध है, सामान्य स्वरूप प्रचलित है और अब तक यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा निम्न स्तर की है।

विश्वविद्यालय से अलग। इसके विपरीत, अंडर के लिए मोड

(2)

[1912] ए. सी. 571

(1) [1944] एफ. सी. आर. 317.

247

एसटी. एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (खन्ना, जे.)

स्नातक शिक्षण यह रहा है कि यह व्यक्तिगत कर्नल द्वारा प्रदान किया जाता है

ए.

पैर। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित बहुत बड़ी संख्या में महाविद्यालय,

स्थापित किए गए हैं और प्रदान करने के उद्देश्य से अस्तित्व में हैं

स्नातक शिक्षा। विवादित प्रावधानों की गणना की जाती है

वर्तमान प्रणाली को समाप्त करने के लिए और इस प्रक्रिया में वे बाधा डालते हैं

समस्या के लिए एक सही दृष्टिकोण यह मानने के लिए कि क्योंकि प्रदान करना विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर शिक्षण को स्वीकार कर लिया गया है

बी.

आपत्ति के बिना, वही नियम अंडर के लिए भी अच्छा होना चाहिए

स्नातक शिक्षण और उसी की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इस तरह

विस्तार की प्रक्रिया, मेरी राय में, बहुत मददगार नहीं है। अगर ऐसा है तो

द्वारा शिक्षा प्रदान करने को रोकने के लिए राज्य के लिए अनुज्ञेय

स्नातक स्तर पर महाविद्यालय क्योंकि इस तरह का एक पाठ्यक्रम है स्नातकोत्तर स्तर पर होने के कारण, ऐसा करने का कोई कारण नहीं होगा

सी.

इस सिद्धांत को स्कूली शिक्षा तक आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। प्रो. विस्तार का उपकर इस प्रकार द्वारा गारंटीकृत अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है

अनुच्छेद 30 (1)।

उत्तरदाताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि हम

विवादित खंडों को समाप्त नहीं करना चाहिए, लेकिन तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि

उन धाराओं के अनुसरण में कानून या अध्यादेश बनाए जाते हैं। में।

डी.

इस संबंध में मेरा विचार है कि चूंकि विवादित अनुभाग प्रदान करते हैं

मौलिक का उल्लंघन करने वाले कानूनों या विनियमों को तैयार करने की शक्ति

अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार, अधिनियम के प्रावधान प्रदान करते हैं

अल्पसंख्यकों के स्थापना और प्रशासन के अधिकार का संक्षिप्तकरण उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान बड़े पैमाने पर लिखे गए हैं

विवादित प्रावधान। तथ्य यह है कि कोई क़ानून या अध्यादेश नहीं हैं

ई.

विवादित प्रावधानों के अनुसरण में तैयार किया गया था जिसके परिणामस्वरूप संवैधानिक रूप से निर्धारित करने में शायद ही बहुत अधिक महत्व हो

विवादित प्रावधानों की वैधता। इसलिए यह नहीं होगा कि अधिकार का उल्लंघन करते हुए क़ानून बनाए जाने तक प्रतीक्षा करने का सही तरीका

अनुच्छेद 30 (1) के अधीन। इसके तहत कोई नियम या क़ानून या अध्यादेश नहीं बनाए गए हैं।

अधिनियम के प्रावधान संवैधानिक दुर्बलता को दूर कर सकते हैं उन प्रावधानों को। यह, जैसा कि मामले में न्यायिक समिति द्वारा देखा गया है

एफ.

ओटावा बनाम के लिए रोमन कैथोलिक अलग स्कूलों के न्यासी। ओटावा

निगम और अन्य। , (1) शक्ति का निर्माण, न कि उसका प्रयोग जो आपत्ति के अधीन है और आपत्ति को हटाया नहीं जाएगा

भले ही प्रदत्त शक्तियों का कभी भी प्रयोग नहीं किया गया था। सिमी री-केरल शिक्षा विधेयक के मामले में यह विचार व्यक्त किया गया था

(ऊपर) जिसमें दास सी. जे. खंड 3 (5) के साथ व्यवहार करते हुए

खंड 20 में कहा गया है:

जी.

" यह सच है कि सी. एल. 36 (2) ((c) सरकार को सशक्त बनाता है

प्रिय को मान्यता प्रदान करने के लिए नियम बनाना

वेटे स्कूल और हमें अपनी राय को तब तक निलंबित करने के लिए कहा जाता है जब तक कि

उक्त विधेयक लागू होता है और वास्तव में नियम बनाए जाते हैं। लेकिन सी. एल. के तहत कोई नियम नहीं बनाया जाएगा। 36 (2) (ग) रद्द कर सकते हैं

सी. एल की संवैधानिक दुर्बलता। 3 (5) सीएल के साथ पढ़ें। 20

एच.

जिसकी गणना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए की जाती है

(1) [1917] ए. सी. 76

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर.

248

मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में अल्पसंख्यक समुदाय

उक्त विधेयक के प्रारंभ होने के बाद स्थापित किया गया। ”

उत्तरदाताओं की ओर से अध्याय वी. आई. ए. के प्रावधान का भी संदर्भ दिया गया है जिसमें धारा 38 बी से 38 ई शामिल है जिसे संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ये प्रावधान स्वायत्त महाविद्यालयों, स्वायत्त संस्थानों और स्वायत्त विश्वविद्यालय विभागों से संबंधित हैं। धारा 38 बी के अनुसार, विश्वविद्यालय के अधिकारी एक संबद्ध कॉलेज, एक विश्वविद्यालय कॉलेज, एक मान्यता प्राप्त संस्थान या एक विश्वविद्यालय विभाग को छात्रों के प्रवेश के मामले में स्वायत्तता प्राप्त करने, अध्ययन के पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने, निर्देश और प्रशिक्षण प्रदान करने, परीक्षाओं के आयोजन और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक नियम बनाने की शक्तियों की अनुमति दे सकते हैं, यदि विश्वविद्यालय के अधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसे कॉलेज, संस्थान या विभाग में शिक्षा का स्तर इतना विकसित है कि कॉलेज, संस्थान या विभाग को स्वायत्तता प्राप्त करने की अनुमति देना शिक्षा के हित में होगा। यह आग्रह किया जाता है कि संबद्ध कॉलेजों को घटक कॉलेजों में बदलने का प्रावधान एक ऐसी योजना का हिस्सा है जो एक तरफ स्वायत्त कॉलेजों और दूसरी तरफ घटक कॉलेजों के दायरे में आता है। इस परिस्थिति का, मेरी राय में, शायद ही कोई महत्व है। यदि अल्पसंख्यकों के संबद्ध कॉलेजों का घटक कॉलेजों में रूपांतरण अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन करता है, तो यह तथ्य कि ऐसा

रूपांतरण एक ऐसी योजना के अनुसरण में है जो एक व्यक्तिगत कॉलेज को स्वायत्तता प्रदान करने की अनुमति देती है, ऐसा नहीं होगा।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, मेरा मानना है कि गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 की धारा 33ए, धारा 40, धारा 41 और धारा 52ए इस प्रकार है - गुजरात विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा संशोधित अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन करता है और इस प्रकार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में शून्य हैं। जहां तक अधिनियम की धारा 51ए का संबंध है, मैं उस धारा की उप-धारा (1) और (2) के खंड (ए) की वैधता को बरकरार रखता हूं। उन दोनों उपखंडों में से प्रत्येक का खंड (बी) अनुच्छेद का उल्लंघन करता है।

30 (1) और जहाँ तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का संबंध है, यह शून्य है।

मैथ्यू, जे. (अपनी ओर से और चंद्रचूड़, जे.) हम विद्वान मुख्य न्यायाधीश के निष्कर्षों के साथ सम्मानपूर्वक सहमत हैं, लेकिन हम अपने कारणों को अलग से बताने का प्रस्ताव करते हैं। रिट याचिका संख्या 232/1973 में विचार के लिए पहला सवाल यह है कि क्या संविधान का अनुच्छेद 30 (1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए केवल शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है, या, क्या उस अनुच्छेद के तहत गारंटी का दायरा इतना व्यापक है कि वे किसी अन्य भाषा की स्थापना और प्रशासन करने में सक्षम हो सकें।

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान।

अनुच्छेद 30 (1) में कहा गया है:

" सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, शिक्षा की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

अपनी पसंद की संस्थाएं "। एसटी.

जेवियर कॉलेज वी. गुजरात (मैथ्यू, जे.)

249

प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 29 (1) जो प्रदान करता है कि

" भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसी के संरक्षण का अधिकार होगा, अनुच्छेद 30 (1) के दायरे को निर्धारित करना चाहिए। उनका कहना है कि जब अनुच्छेद 30 (1) धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की बात करता है, तो इसका मतलब केवल अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थान हो सकते हैं, या, अधिक से अधिक, अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थान हो सकते हैं, न कि उपरोक्त उद्देश्यों से अलग सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थान।

इन री: केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (1) दास, सी. जे.

6 से 1 के बहुमत के लिए अनुच्छेद 143 (1) के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ में कहा गया है कि अनुच्छेद 30 (1) के सही अर्थ और उसके उपयोग को समझने की कुंजी, लेख में "उनकी अपनी पसंद के शब्द" हैं और यह कि लेख इसे उन अल्पसंख्यकों की पसंद पर छोड़ देता है।

ऐसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना जो दोनों उद्देश्यों को पूरा करेंगे, अर्थात्, उनके धर्म, भाषा या संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य और उनके लिए एक संपूर्ण, अच्छी सामान्य शिक्षा देने का उद्देश्य।

बच्चे।

अनुच्छेद 29 (1) और 30 (1) के अंतर-संबंध की जांच की गई थी

हिदायतुल्ला, सी. जे. की अध्यक्षता में इस न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ।

रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट और अन्य बनाम। बिहार राज्य और अन्य (2)। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि चौड़ाई

अनुच्छेद 30 (1) को इसमें विचार प्रस्तुत करके कम नहीं किया जा सकता है।

किस अनुच्छेद 29 (1) पर आधारित है; कि जबकि बाद वाला अनुच्छेद एक

सामान्य सुरक्षा जो अल्पसंख्यकों को उनके लैन के संरक्षण के लिए दी जाती है

अनुमान, लिपि या संस्कृति, पूर्व अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार है

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें और यह कि यह विकल्प भाषा, लिपि या लिपि के संरक्षण की मांग करने वाले संस्थानों तक सीमित नहीं है।

संस्कृति। उन्होंने आगे कहा कि इस विकल्प को दूर नहीं किया जाता है यदि

अल्पसंख्यक समुदाय ने एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की है इसकी पसंद, अन्य समुदायों के सदस्यों को भी स्वीकार करती है, और, कि

दो अनुच्छेद दो अलग-अलग अधिकार पैदा करते हैं, हालांकि यह संभव है कि

वे किसी मामले में मिल सकते हैं।

रेव. सिद्धजभाई भाई और अन्य बनाम। बम्बई राज्य (3)

न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 30 (1) कानून बनाने तक सीमित है। केवल धार्मिक और भाषाई भाषा, लिपि या संस्कृति की सेवा करें।

अल्पसंख्यक।

आर. टी. में इस न्यायालय द्वारा इस प्रश्न की फिर से जांच की गई थी। रेव.

बिशप एस. के. पात्रो और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (4) जहाँ,

शाह, जे., अनुमोदन के साथ उद्धृत पाँच न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए

रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट की पुस्तक में हिदायतुल्ला, सी. जे. की टिप्पणियाँ

मामला (2) और अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 29 (1) और 30 (1) अलग-अलग अधिकार प्रदान करते हैं,

हालांकि किसी दिए गए मामले में, ये अधिकार ओवरलैप हो सकते हैं।

(1) [1959] एस. सी. आर. 995-1053।

(2) [1969] 2 एस. सी. आर. 73

(3) [1963] 3 एस. सी. आर. 837

(4) [1970] एस सी आर 172.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

250

डी. ए. वी. महाविद्यालय आदि में v. पंजाब राज्य और अन्य। (1), रेड्डी, जे.

न्यायालय की ओर से बोलते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 29 (1) अनुच्छेद 30 (1) से अधिक व्यापक है, जिसमें अल्पसंख्यकों सहित नागरिकों का कोई भी वर्ग अनुच्छेद 29 (1) के तहत गारंटीकृत अधिकारों का आह्वान कर सकता है, अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत अधिकार केवल धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने आगे कहा कि इन दोनों अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ने से यह भ्रम पैदा होगा कि एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, जो अधिकार, हालांकि, मुख्य रूप से राज्य की नियामक शक्ति के अधीन है और इसके मानकों की उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाता है और हालांकि ऐसा है, ये दोनों लेख आपस में जुड़े नहीं हैं और न ही वे उन्हें हमेशा एक साथ पढ़ने की अनुमति देते हैं। उन्होंने रेव. फादर डब्ल्यू. प्रूफ्ट के मामले में हिदायतुल्ला, सी. जे. की टिप्पणियों को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया (2)

इस प्रभाव से कि अनुच्छेद 30 (1) की चौड़ाई में कटौती नहीं की जा सकती है

इसमें विचार प्रस्तुत करना कि अनुच्छेद 29 (1) किस पर आधारित है, और

कि, अनुच्छेद 30 (1) में "उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान" अभिव्यक्ति भाषा के संरक्षण की मांग करने वाले संस्थानों तक सीमित नहीं है,

लिपि या संस्कृति।

रामास्वामी, सी. जे. ने दीपेंद्र नाथ बनाम में कहा। बिहार राज्य (3)

कि अनुच्छेद 30 (1) में महत्वपूर्ण वाक्यांश "उनकी पसंद का" है, कि

अतः अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त चयन की स्वतंत्रता का दायरा इस प्रकार है -

विशेष समुदाय की पसंद के रूप में व्यापक हो सकता है और कि

यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए खुला है। अपने धर्म, भाषा या संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से, और

लेख के रूप में उनके बच्चे संस्थान के इन दोनों वर्गों पर लागू होते हैं टयूशन।

अनुच्छेद 29 (1) में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को

भारत का क्षेत्र, अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार।

यह किसी भी अल्पसंख्यक, धार्मिक या अन्य की बात नहीं करता है। जबकि

अनुच्छेद 29 (1) न केवल अल्पसंख्यक को निम्नानुसार अधिकार प्रदान करता है -

भारत के क्षेत्र में निवासी जो इसके क्षेत्र में अल्पसंख्यक नहीं हो सकता है। तकनीकी दृष्टि से, अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार का लाभार्थी एक है

अल्पसंख्यक, या तो धार्मिक या भाषाई। यह एक अंतर है अनुच्छेद 29 (1) और अनुच्छेद 30 (1)।

ध्यान देने योग्य दूसरा अंतर यह है कि जबकि अनुच्छेद 29 (1)

तीन विषयों के संबंध में प्रदान करता है। , भाषा, लिपि या संस्कृति,

एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति रखने वाले नागरिक, उसी के संरक्षण के लिए एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करें। लेकिन,

अनुच्छेद 30 (1) के तहत धार्मिक या भाषाई अधिकार

अल्पसंख्यक केवल एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार नहीं है

(2) [1969] 2 एस. सी. आर. 73

(1) [197] सप. 2 एस. सी. आर. 688

(3) ए. आई. आर. 1962 पटना, 101.

एसटी. जेवियर कॉलेज वी. गुजरात (मैथ्यू, जे.)

251

अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का उद्देश्य, लेकिन अपनी पसंद की कोई भी शैक्षिक संस्था। जबकि अनुच्छेद 29 शिक्षा से संबंधित नहीं है, अनुच्छेद 30 केवल शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन से संबंधित है। यह हो सकता है कि किसी दिए गए मामले में, दोनों लेख ओवरलैप हो सकते हैं। जब कोई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा के संरक्षण के लिए

किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करता है, तो भाषाई अल्पसंख्यक दोनों अनुच्छेदों के संरक्षण का आह्वान कर सकते हैं। जब अनुच्छेद 30 (1) कहता है कि एक भाषाई अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वह किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन कर सकता है। यदि कोई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा के संरक्षण के लिए केवल एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकता है, तो अनुच्छेद 30 (1) में उनकी पसंद की अभिव्यक्ति व्यावहारिक रूप से इसके अर्थ से वंचित हो जाती है।

इन दोनों लेखों पर एक और नज़र डालने से यह पता चलता है कि

अनुच्छेद 29 (1) अनुच्छेद 30 (1) की चौड़ाई को सीमित नहीं कर सकता है। इस देश में धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जिनकी कोई अलग भाषा, लिपि नहीं है। या संस्कृति, जैसा कि अनुच्छेद 29 (1) में परिकल्पित है। इन धार्मिक अल्पसंख्यक संबंधों के कारण, अनुच्छेद 29 (1) किसी भी अधिकार की गारंटी नहीं देता है। फिर भी, अनुच्छेद 30 (1) उन्हें अपने क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।

चयन करें। उस लेख में यह नहीं कहा गया है कि केवल एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति वाले धार्मिक अल्पसंख्यक ही अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। फिर वे कौन से शैक्षणिक संस्थान हैं जिन्हें वे अनुच्छेद के तहत स्थापित करने और प्रशासित करने के हकदार हैं? अनुमान के अनुसार, इन धार्मिक अल्पसंख्यकों की कोई अलग भाषा, लिपि या संस्कृति नहीं है। इसलिए, जिन शैक्षणिक संस्थानों को वे स्थापित करने और प्रशासित करने के हकदार हैं, वे अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए नहीं हो सकते हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 30 (1) के तहत किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को गारंटीकृत अधिकार उसकी पसंद के किसी भी शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने का अधिकार है।

सवाल यह है कि क्या ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में शामिल हो सकते हैं

सैन्य अकादमी या पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस रिट याचिका के तथ्यों के संदर्भ में, क्योंकि, यहाँ, हम केवल सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं जैसा कि सामान्य रूप से समझा जाता है।

की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

गुजरात राज्य ने कहा कि यद्यपि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन उनके पास उनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों के लिए मान्यता या संबद्धता प्राप्त करने का कोई अधिकार, मूल या अन्यथा नहीं है, जब तक कि वे उचित प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन नहीं करते

हैं और जो बहुमत द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थानों पर समान रूप से लागू होते हैं। तर्क यह था कि अनुच्छेद 30 (1) मान्यता या संबद्धता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, कि मान्यता या संबंध एक विशेषाधिकार है जिसे रोककर दिया जा सकता है जैसा कि विधायिका उचित समझे।

हम सोचते हैं कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा उठाया गया मुद्दा

इसका न केवल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर. के क्षेत्र में दूरगामी संवैधानिक महत्व है।

252

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने का अधिकार लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी और इसके न्यायिक आधार की जांच के योग्य है। और, हम यह भी सोचते हैं कि इस प्रश्न को कानूनी तर्क की सख्त सीमाओं के भीतर रखा जाना चाहिए, जिसे आम लोग अक्सर तकनीकी रूप से दुर्भावनापूर्ण मान सकते हैं। न्यायाधीशों के रूप में, हम हैं। न तो यहूदी और न ही गैर-यहूदी, न ही कैथोलिक और न ही अज्ञेयवादी और हम अपनी निजी राय लिखने में उचित नहीं होंगे, चाहे हम उन्हें कितना भी गहराई से संजो कर रखें। और निर्णय के समर्थन में जो कहा जाता है, वह हमें मुद्दों के तहत राजनीतिक या धार्मिक संघर्ष से यथासंभव तर्कसंगत रूप से अलग करेगा। हम संविधान के प्रति समान निष्ठा रखते हैं और इसका समर्थन करने के लिए न्यायिक दायित्व से समान रूप से बाध्य हैं। (1)

विचार की स्पष्टता के हित में एक के साथ शुरुआत करना आवश्यक है

डेमो क्रेटिक राजनीति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के वास्तविक कारण की समझ।

" अल्पसंख्यकों का संरक्षण गैर-प्रमुख समूहों का संरक्षण है,

जो, सामान्य रूप से माजो के साथ व्यवहार की समानता की कामना करते हुए

ऋति, संरक्षण के लिए अंतर उपचार के एक उपाय की इच्छा बुनियादी विशेषताएं जो उनके पास हैं और जो उन्हें अलग करती हैं

ऐसे समूहों से संबंधित व्यक्ति और समान सुरक्षा चाहते हैं। यह इस प्रकार है कि ऐसे समूहों या व्यक्तियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है।

ऐसे समूहों से संबंधित होना उचित है जब इसका उपयोग ब्याज में किया जाता है।

उनकी संतुष्टि और समग्र रूप से समुदाय के कल्याण के लिए। (2)

" अल्पसंख्यकों की समस्या वास्तव में संस्थाओं की समस्या नहीं है।

समानता का अभाव क्योंकि अगर शाब्दिक रूप से लिया जाए, तो ऐसी समानता होगी

मतलब अल्पसंख्यकों और माजो दोनों के साथ पूर्ण समान व्यवहार रियायतें। इसके परिणामस्वरूप केवल कानून में समानता होगी लेकिन वास्तव में असमानता होगी।

इस भेद को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट है कि "समानता"

कानून किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है; जबकि वास्तव में समानता

एक प्राप्त करने के लिए विभेदक उपचार की आवश्यकता शामिल हो सकती है

परिणाम जो विभिन्न स्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करता है (3) "

यह विरोधाभासी लग सकता है लेकिन फिर भी यह सच है कि अल्पसंख्यक

उन्हें न केवल तब संरक्षित किया जा सकता है जब उनके पास समानता हो, बल्कि निश्चित रूप से भी परिस्थितियाँ, विभेदक उपचार।

डेढ़ दशक से भी पहले मुख्य न्यायाधीश दास ने इस कोर्ट का नेतृत्व किया था

यह मानते हुए कि मान्यता के बिना, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करते हैं

अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा दिया गया या स्थापित किया जाना पूरा नहीं हो सकता है

उनकी पसंद के वास्तविक उद्देश्य और अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार

प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सही टी. सी.

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का अर्थ है स्थापित करने का अधिकार वास्तविक संस्थान जो प्रभावी रूप से अपनी कंपनियों की जरूरतों को पूरा करेंगे

(1) वेस्ट वर्जीनिया स्टेट बोर्ड ऑफ जस्टिस में जस्टिस फ्रैंकफर्टर की टिप्पणियाँ देखें।

शिक्षा वी. बर्नेट, 319 यू. एस. 624।

(2) उप-आयोग द्वारा मानवाधिकारों पर कॉम मिशन को अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिश-उर्मिला हक्सर द्वारा "अल्पसंख्यक संरक्षण और मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक" के पृष्ठ 27 पर उद्धृत की गई है।
(3) अल्बानिया में अल्पसंख्यक स्कूलों पर सलाहकार राय 6 अप्रैल, 1935

न्यायालय श्रृंखला ए/बी सं. 64 पी के प्रकाशन। 19 .

एसटी. जेवियर कॉलेज वी. गुजरात (मैथ्यू, जे.)

253

समुदाय और वे विद्वान जो अपने शैक्षणिक संस्थानों का सहारा लेते हैं और यह कि यद्यपि राज्य द्वारा मौलिक अधिकार जैसी कोई चीज नहीं है) मान्यता, फिर भी शैक्षणिक संस्थानों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन के उनके संवैधानिक अधिकार के समर्पण के समान शर्तों को छोड़कर मान्यता से इनकार करना वास्तव में और प्रभावी रूप से उन्हें अनुच्छेद 30 (1) के तहत उनके अधिकारों से वंचित करना है। केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (ऊपर)।] .

कारण कि संविधान निर्माताओं को देने के लिए दर्द हो रहा था

धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार माता-पिता को देना है। समुदायों को अपने धर्म के अनुकूल वातावरण वाले संस्थानों में अपने बच्चों को शिक्षित करने का अवसर मिलता है। किसी की अपनी इच्छा जो भी हो, वे जो सोचते हैं कि मनुष्य उसके द्वारा नहीं जीता है।

केवल रोटी से ही नहीं, बल्कि भगवान से आने वाले शब्द से भी धर्म की समस्या के संबंध में और उसके हिस्से के रूप में उदासीन नहीं रह सकते हैं। शिक्षा.

वास्तव में कई धार्मिक अल्पसंख्यकों के अनुसार,

राज्य में स्कूलों और कॉलेजों की एक ऐसी प्रणाली है जो सी. सी. एम. नहीं है।

उनके लिए पूरी तरह से संतोषजनक है, क्योंकि धर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया है

और नैतिकता। पाठ्यक्रम से धर्म को पूरी तरह से हटा दिया गया है।

धर्म के खिलाफ दबाव। चूँकि वे समझते हैं कि शिक्षा

धर्मनिरपेक्ष शाखाओं में धर्म और शिक्षा सही या उचित नहीं हो सकती है। सफलतापूर्वक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वे मजबूर होते हैं

सामान्य शिक्षा के लिए स्कूलों और कॉलेजों की अपनी प्रणाली बनाए रखें धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ।

" शिक्षा के कारणों की जांच करना महत्वपूर्ण है।

धार्मिक समूहों द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय संस्थान। साफ तौर पर,

उनकी स्थापना एक गहरे के कारण नहीं आती है

यह विश्वास कि ऐसे संस्थान तथ्यों तक पहुँचने में सक्षम होंगे

साहित्य, भूगोल या गणित राज्य से बेहतर

धार्मिक शिक्षा देना और एक धार्मिक वातावरण विकसित करना और साहित्य, भूगोल और भूगोल के अध्ययन के लिए भी दृष्टिकोण

गणित। दूसरे शब्दों में, एक धार्मिक निकाय स्थापित करता है

और एक संपूर्ण वातावरण बनाने के लिए स्कूलों को बेहतर तरीके से बनाए रखता है

जो इसके विशेष प्रचार के लिए अनुकूल होगा।

धार्मिक मूल्य "। (1)

शायद, गणित जैसे विषयों को धर्मनिरपेक्ष बनाना संभव है।

भौतिकी या रसायन विज्ञान, लेकिन जैसा कि न्यायमूर्ति जैक्सन ने कहा:

" पवित्र संगीत के बिना संगीत, वास्तुकला माइनस

देखें। फिर भी इन भेषों में धर्म की प्रेरक अपील यह अक्सर स्पष्ट उपदेश की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। यहाँ तक कि

' विज्ञान 'जीव विज्ञान के रूप में विकास और विकास के बीच का मुद्दा उठाता है इस ग्रह पर हमारी उपस्थिति की व्याख्या के रूप में सृष्टि।

1 डोनाल्ड यूजीन स्मिथ द्वारा लिखित "भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में" देखें, p.361।

लेकिन सीएनई कैसे सिखा सकता है, संतुष्टि के साथ या न्याय के साथ भी।

सभी धर्मों के लिए, जैसे कि सुधार की कहानी,

इन्क्विजिशन एक से अधिक समझ में आता है। यह भी है यह उम्मीद करने के लिए कि मनुष्य जिन विषयों के बारे में पढ़ाएंगे

अलगाव वे दूरस्थ उप के बारे में शिक्षण के लिए बुला सकते हैं कन्फ्यूशियस या मोहमेट जैसे विमान। (1)

राज्य इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि बच्चे धार्मिक हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय को राज्य द्वारा संचालित शिक्षा में शिक्षित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय संस्थान या इमाजो द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में

रिति। जहाँ तक धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात है, शिक्षा में राज्य की रुचि

चिंतित हैं, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर निर्भरता द्वारा पर्याप्त रूप से सेवा की जाएगी

अल्पसंख्यक विद्यालयों में वैकल्पिक धार्मिक प्रशिक्षण के साथ कैटिचिन और कॉलेज, अगर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा वहाँ के अनुसार आयोजित की जाती है

निर्धारित पाठ्यक्रम और मानक। अनुच्छेद 28 (3) का तात्पर्य है कि एक शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक

सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता है।

धर्मनिरपेक्षता प्रदान करने के लिए धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा दृढ़ता से बताती है कि सूचित राय का एक विस्तृत खंड

यह पाया है कि ये कॉलेज धर्मनिरपेक्षता प्रदान करने के लिए एक स्वीकार्य जे. सी. बी. करते हैं

शिक्षा. माना जा सकता है कि राज्य के पास विनियमन और नियंत्रण करने की शक्ति है

अपने बच्चों की शिक्षा, लेकिन यह एक सामान्य कानून द्वारा मजबूर नहीं कर सकता है

पब्लिक स्कूल या सी. सी. एल. ई. जी. में लिंग उपस्थिति, में उपस्थिति को रोकता है धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विद्यालय या महाविद्यालय, जब

माता-पिता धार्मिक शिक्षा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जो प्रदान नहीं किया गया है

सरकारी स्कूलों में। माता-पिता को यह तय करने का अधिकार है कि किसके लिए उनके बच्चों को स्कूल या कॉलेज शिक्षा के लिए भेजा जाना चाहिए।

हम यह देखने में विफल हैं कि एक शिक्षा संस्थान की संबद्धता कैसे प्रदान करती है

छात्रों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के अलावा धार्मिक शिक्षा

अनुच्छेद 28 (3) में परिकल्पित रूप से धर्मनिरपेक्ष चरित्र का अपमान होगा। राज्य से। हमारे संविधान ने एक कठोर दीवार नहीं खड़ी की है

चर्च और राज्य के बीच संबंध। हमें गंभीर संदेह है कि क्या पूर्व

" दबाव "धर्मनिरपेक्ष राज्य" के रूप में यह चर्च के एक निश्चित पैटर्न को दर्शाता है और

राज्य संबंध को औचित्य के साथ भारत में लागू किया जा सकता है। यह केवल में है

एक योग्य भावना कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जा सकता है। वहाँ संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो किसी को समझाने में संकोच करते हैं

हमारे राज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित करें। डॉ. राधाकृष्णन ने कहा है:

" भारतीय राज्य की धार्मिक निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए

धर्मनिरपेक्षता या नास्तिकवाद के साथ भ्रमित। यहाँ की तरह धर्मनिरपेक्षता

भारत से। यह विश्वासियों की संगति का निर्माण करने की कोशिश करता है, न कि व्यक्तिगत गुणों को समूह मन के अधीन करना लेकिन

उन्हें एक-दूसरे के साथ सामंजस्य में लाना। यह गतिशील

फेलोशिप एकता में विविधता के सिद्धांत पर आधारित है

जिसमें अकेले रचनात्मकता का गुण है (2)। धर्मनिरपेक्षता यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि धर्महीनता या नास्तिकता या यहाँ तक कि इस पर जोर दिया जाए।

(1) मैककॉलम बनाम बोर्ड ओ एजुकेशन में जस्टिस जैक्सन की राय देखें,

: 333 , अमेरिका। 303 .

(2) विश्वास की पुनर्प्राप्ति पी।

202 एसटी. जेवियर कॉलेज वी. गुजरात (मैथ्यू, जे.)

255

भौतिक सुख-सुविधाएं। यह घोषणा करता है कि यह यूनी पर जोर देता है

आध्यात्मिक मूल्यों की बहुमुखी प्रतिभा जो एक द्वारा प्राप्त की जा सकती है

विभिन्न प्रकार के तरीके '(1)'।

संक्षेप में, वर्तमान संविधान के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ केवल

" जीने और जीने देने का एक रवैया जो जीने और जीने में मदद करने के दृष्टिकोण में विकसित हो रहा है। (2)

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अभिधारणा किसी भी शक्ति को बाहर करता है।

राज्य अपने बच्चों को मजबूर करके उनका मानकीकरण और सामाजिककरण करे

केवल सार्वजनिक विद्यालयों में भाग लेने के लिए। एक बच्चा केवल राज्य का एक प्राणी नहीं है। जो उनका पालन-पोषण करते हैं और उनके भाग्य को निर्देशित करते हैं, उन्हें अधिकार है

उसे पहचानने और आदी के लिए तैयार करने के उच्च कर्तव्य के साथ

राष्ट्रीय दायित्व। (*)

शिक्षा में माता-पिता का अधिकार एक प्रदर्शन का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।

क्रेटिक प्रणाली। यह लोकतांत्रिक के बीच अंतर का स्पर्श है। सांस्कृतिक अधिनायकवाद की शिक्षा और अखंड प्रणाली। जब

अपनी अपार शक्ति के साथ आधुनिक राज्य के मिशन की शुरुआत

अपने बच्चों को शिक्षित करने की पूरी प्रवृत्ति राज्य के एकाधिकार की ओर है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन नए के विस्फोटक विस्तारवाद को सीमित करने के लिए केवल कानूनी बाधा

शैक्षिक लेवियाथन। के बीच विचारों की बड़ी विविधता मौजूद है इस देश के लोग बच्चों को प्रशिक्षित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में

समाज में उनका स्थान। इन मतभेदों के कारण और

शिक्षा की एकल लौह कास्ट प्रणाली की अनुमति देने में अनिच्छा

कई उपभेदों से भरे एक राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया गया, संविधान

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्रदान किया है।

आज शिक्षा राज्य और स्थानीय स्तर का एक महत्वपूर्ण कार्य है

सरकारें। अनिवार्य विद्यालय उपस्थिति कानून और स्थापना

शिक्षा के लिए खर्च दोनों आई. एम. की मान्यता को प्रदर्शित करते हैं।

हमारे लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का विस्तार। यह आवश्यक है कि हमारी सबसे बुनियादी सार्वजनिक जिम्मेदारियों का प्रदर्शन। यह वह है जो

अच्छी नागरिकता की नींव। आज यह एक प्रमुख उपकरण है

बच्चे को सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागृत करना, उसे बाद के पेशेवर के लिए तैयार करना

पेशेवर प्रशिक्षण और उसे अपने परिवेश के साथ सामान्य रूप से तालमेल बिठाने में मदद करना।

[ब्राउन वी. देखें। शिक्षा बोर्ड (1)]।

अगर शिक्षा में लोकतंत्र का कोई प्रतीक है तो वह जनता नहीं है

सी. एफ. पर संबद्ध कॉलेजों सहित कई प्रकार के स्कूल और कॉलेज परिणामी आनुपातिक रूप से समान के साथ न्यायिक समानता का मतदान

राज्य प्रोत्साहन और समर्थन का उपाय। और, न्यायिक समानता यह मानता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को एक गारंटीकृत अधिकार होना चाहिए

अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन जहां वह कर सकता है

धार्मिक वातावरण में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करना।

(1) डॉ. राधाकृष्णन का डॉ. एस. आबिद हुसैन के लिए प्रस्तावना, राष्ट्रीय भारत की संस्कृति, पी। vii.

(2) होरास एम. कैलन, धर्मनिरपेक्षता ईश्वर की इच्छा है, पीपी। 11 , 12 और 13.

(3) पियर्स वी. देखें। सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ होली नेम्स, 268 यू. एस. 510 , 535 .

(4) 349 यू. एस. यू. एस. सी.

धर्मनिरपेक्ष शिक्षा में राज्य की रुचि को मोटे तौर पर इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:

यह सुनिश्चित करने में रुचि है कि इसकी सीमाओं के भीतर बच्चे एक

कौशल में योग्यता का न्यूनतम स्तर, साथ ही न्यूनतम राशि

और ज्ञान, एक व्यक्ति दोनों में एक गंभीर नुकसान में होगा लोकतांत्रिक स्वशासन में भाग लेना और जीविकोपार्जन करना।

माता-पिता के संतुष्ट करने के संवैधानिक अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। राज्य-अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्हें भेजने का दायित्व

अपने स्वयं के धार्मिक द्वारा स्थापित और प्रशासित स्कूल या कॉलेज अल्पसंख्यक तब तक जब तक ये स्कूल और कॉलेज मानकों को पूरा करते हैं

धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए स्थापित।

धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के सामुदायिक स्वरूप की अवधारणा की आवश्यकता है -

वास्तविकता की पृथ्वी पर नीचे लाया जाए और इसकी अस्पष्टता से वंचित किया जाए रहस्यवाद। इस अवधारणा का कृत्रिम शासन से कोई लेना-देना नहीं है।

मेंट-सभी मतभेदों को समतल करने को बढ़ावा दिया। पब्लिक स्कूल नहीं है

एक मंदिर जिसमें सभी बच्चों को धर्मनिरपेक्ष एकता में बपतिस्मा दिया जाना है

लोकतांत्रिक विश्वास, जबकि जो इसके बिना खड़े हैं वे मंद रूप से विधर्मी हैं।

" इसलिए लोकतांत्रिक देशों में शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता

के ढांचे के भीतर विभिन्न मूल्यों के साथ विभिन्न प्रकार का

संविधान को अनावश्यक रूप से सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यह शुरुआत है

विचार की स्वतंत्रता के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ। नियंत्रण

ऊपर सुझाए गए महाविद्यालय ऐसे होने चाहिए जो अंततः सुरक्षित हों।

अपनी मर्जी से कॉलेजों द्वारा इन उच्च सिद्धांतों का समर्थन और नहीं

एकता को बढ़ावा देने का सरकार का जो भी आध्यात्मिक मिशन हो, वह न्याय, सम्मान को बढ़ावा देने के अपने प्राथमिक कर्तव्य से सशर्त है। अधिकारों की गारंटी और मतभेदों की समानता सुनिश्चित करना।

संविधान के निर्माता इस बात से अनजान थे कि

उन्होंने जो प्रणाली बनाई है, गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की अधिकांश विधायी या सरकारी कटौती को विधायी निर्णय का समर्थन प्राप्त होगा कि सार्वजनिक हित को इसके संवैधानिक संरक्षण के बजाय इसकी कटौती से पूरा किया जाएगा। शिक्षा के सामान्य स्वरूप के रूप में अल्पसंख्यकों के लोकप्रिय इच्छा के अधिकार के संवैधानिक संरक्षण का कोई समर्पण नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इस न्यायालय ने समय-समय पर ऐसी स्थितियों में विधायी निर्णय की न्यायिक जांच के महत्व पर जोर दिया है जहां असतत और द्वीपीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्वाग्रह है: उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से अधिकारों में कटौती करने की प्रवृत्ति हो सकती है। यह कि अल्पसंख्यक राजनीतिक प्रक्रिया में संरक्षण प्राप्त करने में असमर्थ हो सकते हैं और इसलिए, न्यायालय विशेष आग्रह के साथ उनके हित को उचित रूप से मान सकता है, स्टेसिन, जे. ने संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम को अपने प्रसिद्ध फुट-नोट में सुझाव दिया था। कैरोलीन प्रोड।, कं. (2)

वर्षों से, इस न्यायालय ने माना है कि मान्यता के बिना या

संबद्धता, अनुच्छेद 30 (1) के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का कोई वास्तविक या सार्थक प्रयोग नहीं हो सकता है। , केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (1) (1067-68 पर); रेव.

(1) विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श अधिनियम पर समिति की रिपोर्ट, अध्याय देखें।

वी: महाविद्यालय और छात्र कल्याण, पृष्ठ 28।

(2) 304 , यू. एस. 144

एसटी. XAVIERS कॉलेज बनाम गुजरात (मैथ्यू, जे.)

257

सिद्धजभाई भाई और अन्य बनाम। बॉम्बे राज्य (2) और डी. ए. वी.

महाविद्यालय, आदि। Str: ई पंजाब और अन्य (3)।

आइए अब हम इस तर्क की वैधता की जांच करते हैं कि:

मान्यता का कोई मौलिक या अन्यथा अधिकार नहीं है।

या संबद्धता, सरकार पुरानी मान्यता दे सकती है या

किसी भी कारण से संबद्धता या इसके लिए कोई शर्त लागू करना

समान, और परिणामस्वरूप, यह इसे रोक सकता है या रद्द भी कर सकता है

हालाँकि ऐसा करने का कारण अल्पसंख्यक समुदाय हो सकता है

प्रशासन के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों को आत्मसमर्पण करने के लिए फ्यूसल

संस्था। इस तर्क को शब्दांशात्मक शब्दों में व्यक्त किया गया है:

अनुच्छेद 30 (1) किसी को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता है।

मान्यता या मान्यता प्राप्त करने के लिए धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक राज्य विधानमंडल का कोई कर्तव्य या दायित्व नहीं है कि वह

संबद्धता के लिए सुविधाओं के साथ एक विश्वविद्यालय स्थापित करें या स्थापित करें शैक्षिक संस्थान। उन लोगों को छोड़ दें जो स्थापित हैं और

ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जो केवल विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं शहर और जो संबद्धता के लिए कोई सुविधा प्रदान नहीं करते हैं;

यदि विधायिका आपके साथ विश्वविद्यालय स्थापित करने में सक्षम है

संबद्धता या मान्यता के लिए कोई सुविधा प्रदान करना और

इस प्रकार संबद्धता को रोक दिया जाता है, यह इसे सीमित रूप में प्रदान कर सकता है

चूंकि निरपेक्षता को रोकने की अधिक शक्ति। इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी

सैली में इसे प्रतिबंध के साथ देने की कम शक्ति शामिल है राज्य और शर्तें और इसलिए, विधायिका के पास शक्ति है

स्थापित संबद्ध महाविद्यालयों पर शर्तें लागू करना और

धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित जो

उनके घटक महाविद्यालय बनने के परिणामस्वरूप, और, एक कोरोल के रूप में

इस तर्क के लिए, यह सबमी है। टेड, कि प्राप्तकर्ता

लाभ या सुविधा, अर्थात्, धार्मिक या भाषाई

अल्पसंख्यक, अपने मौलिक अधिकार से वंचित नहीं है क्योंकि यह

केवल अस्वीकार करके अपने मौलिक अधिकार को बनाए रख सकता है

पसंदीदा लाभ या सुविधा।

हम सोचते हैं कि खतरनाक परिणाम होंगे यदि तर्क

तर्क सभी मामलों में स्वीकार किया जाता है। संख्या में तेजी से वृद्धि सरकारी नियामक और कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ-साथ

विस्तार के परिणामस्वरूप सरकारी अनुबंधों का गुणन

लाभों या विशेषाधिकारों की कुल संख्या में बहुत वृद्धि हुई है

जो सरकार द्वारा प्रदान किया जा सकता है, इस प्रकार सरकार

संविधान के समर्पण के लिए सौदेबाजी करने के अनगिनत नए अवसर

राष्ट्रीय अधिकार। राज्य की खर्च करने की शक्ति में वृद्धि के साथ-ए

आधुनिक कल्याणकारी राज्य का आवश्यक सहयोग। पर्स की शक्ति के माध्यम से नियंत्रण की अस्थिरता तेजी से बढ़ी है। (1)

(1) (1959) आई. एस. सी. आर. 9);

(3) [1971] सुपर, एसः सी. एक्स. 688,709

(2) [1963] 3 एस. सी. आर. 837,856

(4] चार्ल्स ए रीख, 73 वर्षीय लॉ जोमी अल 733 द्वारा "द न्यू प्रॉपर्टी" देखें।

हालाँकि अदालतों ने माना है कि अनुच्छेद 14 जनता पर लागू होता है

राज्य के अन्य अधिनियमों की तरह ही लाभ और सार्वजनिक रोजगार,

वे संवैधानिक औचित्य की मांग करने में कम जल्दी करते हैं जब एक लाभ होता है

मान्यता, संबद्धता या सहायता जैसे उपयुक्त या विशेषाधिकार इस तरह से सशर्त हैं कि,

इसे प्राप्त करने के लिए, किसी को अपनी बुनियादी स्वतंत्रताओं के कुछ हिस्से का समर्पण करना होगा।

कहानी जस्टिस होम्स के फैसले से शुरू होती है।

मैकऑलिफ बनाम। न्यू बेडफोर्ड (1) जहाँ उन्होंने याचिका भेजी

एक पुलिसकर्मी जिसे उल्लंघन करने के लिए अपनी सेवा से छुट्टी दे दी गई थी

नियम जिसने उनकी राजनीतिक गतिविधियों को यह कहकर प्रतिबंधित कर दिया कि "

याचिकाकर्ता को राजनीति पर बात करने का संवैधानिक अधिकार हो सकता है: लेकिन उसने

पुलिसकर्मी होने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। नौकर नहीं आ सकता है स्पष्ट रूप से वह उन शर्तों पर नौकरी करता है जो उसे दी जाती हैं।

यह धारणा कि "याचिकाकर्ता को होने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है

एक पुलिसकर्मी हालांकि उसे राजनीति पर बात करने का संवैधानिक अधिकार है

व्यापक दृष्टिकोण का विशिष्ट अनुप्रयोग कि किसी के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है सरकारी उदारता या विशेषाधिकार का अधिकार और काफी हद तक समान है

यहाँ तर्क है कि एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक एक प्रशासन

शैक्षणिक संस्थान को मान्यता या संबद्धता का कोई अधिकार नहीं है, हालांकि

श्री न्यायमूर्ति होम्स के विकास में एक मोहक प्रभाव पड़ा है कानून की इस शाखा का।

डेविस वी. मैसाचुसेट्स (2) एनेलेंट को दोषी ठहराया गया था

बोस्टन कॉमन पर भाषण देने का। एक शहर का उल्लंघन

अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी सार्वजनिक संबोधन को प्रतिबंधित करने वाला अध्यादेश

महापौर की अनुमति के बिना सार्वजनिक मैदानों पर। द कन्वी

मैसाचुसेट्स के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी न्यायमूर्ति होम्स की राय, जिसमें उन्होंने कहा: —

" यह तर्क कि अध्यादेश असंवैधानिक था।

इसमें उसी तरह की भ्रांति शामिल है जिससे निपटा गया था

मैकऑलिफ बनाम। न्यू बेडफोर्ड। (1) यह मानता है कि आदेश

नैन्स को आम तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ निर्देशित किया जाता है।

वास्तव में यह बोस्टन के तरीकों की ओर निर्देशित है।

सामान्य का उपयोग किया जा सकता है।

उन्होंने जारी रखा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च द्वारा उद्धृत भाषा में

फैसले की पुष्टि करते हुए न्यायालयः

" विधायिका के लिए पूरी तरह से या सशर्त रूप से निषेध करने के लिए

राजमार्ग या सार्वजनिक पार्क में सार्वजनिक रूप से बोलना अब कोई काम नहीं है।

जनता के किसी सदस्य के अधिकारों का उल्लंघन

एक निजी घर के मालिक के लिए अपने घर में इसे मना करने के लिए।

जब कोई स्वामित्व अधिकार हस्तक्षेप नहीं करता है, तो विधायिका समाप्त हो जाती है

सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश करने का जनता का अधिकार

सार्वजनिक उपयोग के प्रति समर्पण को समाप्त करना। तो यह ले सकता है सार्वजनिक उपयोग को कुछ उद्देश्यों तक सीमित करने का कम कदम।

तब सुप्रीम कोर्ट ने कहाः

(1) 155 मास, 216।

(2) 167 अमेरिका 43.

आई एस. टी. XAVIERS कॉलेज v. गुजरात (मैथ्यू, जे.)

259

" उपयोग के सभी अधिकार को पूरी तरह से बाहर करने का अधिकार, आवश्यकताएँ

इस तरह के उपयोग का लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि अधिक से अधिक शक्ति इसमें सबसे कम (48 पर) शामिल है।

जब उन्होंने 1902 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी सीट ली,

न्यायमूर्ति होम्स ने अभी भी सशर्त विशेषाधिकारों के बारे में उन विचारों का पालन किया जो उन्होंने मैकऑलिफ बनाम में व्यक्त किए थे। न्यू बेडफोर्ड (ऊपर) और

डेविस बनाम। मैसाचुसेट्स। (ऊपर) पुलमैन कंपनी में अदालत के लिए लिखना।

वी. एडम्स (1) ने इस तर्क का संक्षेप में निपटारा किया कि

स्थानीय व्यवसाय इतना भारी था कि अंतर-राज्य संचालन पर बोझ पड़ता था पुलमैन कंपनी ने कहा:

" कंपनी कर लगाए जाने की शिकायत नहीं कर सकती है

एक स्थानीय व्यवसाय करने का विशेषाधिकार जो फिर से करने के लिए स्वतंत्र है झपकी लें "।

और, जब 1910 में, न्यायालय का बहुमत इसके विपरीत हो गया

वेस्टर्न यूनियन कं. वी. में स्थिति कैनसस, (*) उन्होंने असहमति जताते हुए कहा

" यहाँ तक कि कानून में भी पूरे में आम तौर पर इसके भाग शामिल होते हैं।

यदि राज्य निषेध कर सकता है, तो यह विशेषाधिकार के साथ निषेध कर सकता है

एक निश्चित तरीके से निषेध से बचने के लिए "।

एक बहुत ही संवेदनशील आलोचक ने लिखा है: (3)

" उनके (होम्स के) तर्क का सार व्यक्त किया गया था

उक्ति: ' यहाँ तक कि कानून में भी आम तौर पर

इसके हिस्सों को जोड़ता है '। इस प्रकार उनका तात्पर्य है कि कुल की शक्ति

बहिष्करण एक 'संपूर्ण' है, जिसमें से किसी को भी लागू करने की शक्ति है

स्वीकार किए गए इन लोगों पर जो कुछ भी-तो-कभी भी एक 'हिस्सा' है, वह बोझ डालता है।

उन्होंने आगे कहा:

" तार्किक रूप से एक ऐसी चीज जिसे पूरी तरह से बाहर रखा जा सकता है, वह नहीं है

एक ऐसी चीज़ के समान जो एक के बोझ के अधीन हो सकती है

अलग तरह का, भले ही इस तरह के बोझ को माना जाएगा

पूर्ण बहिष्कार के बोझ से कम भारी।

'पूर्ण बहिष्करण की शक्ति' एक ऐसा शब्द है जो अनिवार्य नहीं है। सापेक्ष बहिष्करण 'या' अधिरोपित करने की शक्ति 'के साथ

कोई भी बोझ जो भी हो "।

जब न्यायमूर्ति होम्स बाहर थे-ऊपर निर्दिष्ट मामले में मतदान किया और

उन्होंने वेस्टर्न यूनियन टेल में एक सर्वसम्मत अदालत के लिए कहा। को. वी. फोस्टर (1), जिसने अंतर-राज्य कॉम के साथ हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया

इसलिए:

" यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य को अपनी सत्ता से बिजली मिलती है।

सड़कों पर बिजली जो टेलीग्राफ के लिए आवश्यक है

(2) 216 अमेरिका 1.

(3) थॉमस रीड पॉवेल को देखिए: 16 कोलंबिया लॉ रेव. 99,110-111 पर। (4) 247 यू. एस. 105

पार करने के लिए। लेकिन अगर हम यह मान लें कि वादी त्रुटि में हैं

उनके वर्तमान पात्रों को सड़कों से बाहर रखा जा सकता था, परिणाम सामने नहीं आएगा। आम तौर पर विधिसम्मत कार्य

गैरकानूनी कार्य पूरा करने के लिए किया जाने पर यह गैरकानूनी हो सकता है

अंत, और एक संवैधानिक शक्ति का उपयोग किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता है

एक असंवैधानिक परिणाम प्राप्त करने की शर्त "(114 पर)। .

(जोर दिया गया)

रूढ़िवादी अमेरिकी सिद्धांत यह था कि एक विदेशी का अधिकार

किसी राज्य की सीमाओं के भीतर व्यवसाय करने के लिए निगम निर्भर करता है

पूरी तरह से राज्य की अनुमति पर। ऐसा लगता है कि यह एक साधन प्रदान करता है

वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए। अगर राज्यों के पास इनकार करने की शक्ति थी

कारण के साथ या बिना कारण विदेशी निगमों में प्रवेश,

निश्चित रूप से वे प्रवेश के बदले में जो चाहें कर सकते हैं। सी.

यदि ऐसा है, तो प्रवेश से पहले संघीय अदालतों का सहारा नहीं लेने का वादा,

या ऐसे रिसॉर्ट के मामले में निष्कासन का दायित्व, जिसकी कीमत के रूप में आवश्यकता होती है

प्रवेश का, एक वैध और प्रभावी साधन प्रतीत होगा

वांछित लक्षय प्राप्त करना। बीमा कंपनी के मामले में v. मोर्स (1)

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एक क़ानून को अमान्य कर दिया जिसकी आवश्यकता थी

एक शर्त के रूप में संघीय अदालतों के मुकदमों को नहीं हटाने के लिए एक समझौता।

प्रवेश के लिए पूर्ववर्ती। यह निर्णय जमीन पर आधारित था,

पहले के दो मामलों में व्यक्त किए गए आदेश द्वारा समर्थित है कि

समझौते का एक अभ्यास में हस्तक्षेप करने का प्रयास था

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान और कानूनों से प्राप्त अधिकार। जबकि "असंवैधानिक स्थिति" शब्द। क्या वे विशेष रूप से नहीं थे

राय में नियोजित, मामला स्पष्ट रूप से फाउंटेनहेड प्रतीत होता है

उस सिद्धांत का जो अब उस नाम से जाता है (2)।

"असंवैधानिक स्थिति" के सिद्धांत का अर्थ है कोई भी शर्त

विशेषाधिकार प्राप्तकर्ता को कुछ संवैधानिक त्याग करने की आवश्यकता होती है सही है। यह सिद्धांत इस बात को स्वीकार करता है कि याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं है

एक पुलिसकर्मी होने के लिए 'लेकिन यह उस अधिकार पर जोर देता है जो उसके पास है

" राजनीति पर बात करने के लिए। इस सिद्धांत की प्रमुख आवश्यकता यह है कि स्थिति की शिकायत करने वाले व्यक्ति को यह प्रदर्शित करना होगा कि यह एक नहीं है

यह विशेष अर्थ में उचित है कि यह संविधान के एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा संरक्षित अधिकार के प्रयोग को छीन लेता है या कम कर देता है (विलियम डब्ल्यू. वान अल्स्टीन को देखें): द डिमाइज ऑफ द राइट-प्रिविलेज डिस्टिंक्शन इन कांस्टीटचूशन लॉ)। (3)

फ्रॉस्ट एंड फ्रॉस्ट ट्रकिंग कंपनी v. रेल मार्ग। कॉम. (1) सूर्य

संयुक्त राज्य अमेरिका का रेमे कोर्ट कैलिफोर्निया के एक क़ानून की वैधता के सवाल से चिंतित था, जिसमें राज्य के सार्वजनिक राजमार्गों पर अपने व्यवसाय पर ध्यान देने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में सार्वजनिक सहमति और आवश्यकता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, चाहे वह सामान्य हो या निजी। अधिनियम की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा आवेदक पर कर्तव्यों को ग्रहण करने का दायित्व अधिरोपित करने के रूप में की गई थी और

(1) 20 दीवार। 445 , 447 (यू. एस. 1874)

(2) 77 विश्वविद्यालय के मौरिस एच. मेरिल की "असंवैधानिक शर्तें" देखें।

पेन्सिलवेनिया लॉ रेव., 879,880।

(3) 81 हार्व। विधि रेव., 1439।

(4) 271

यू. एस. 583

एसटी. XAVIERS कॉलेज v. गुजरात (मैथ्यू, जे.)

261

प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में एक सामान्य वाहक की देनदारियाँ इसने क़ानून को, इतना अर्थ लगाया, असंवैधानिक, मुख्य रूप से इस आधार पर माना कि एक निजी वाहक पर उसकी इच्छा के खिलाफ एक सामान्य वाहक की स्थिति को मजबूर करना कानून

की उचित प्रक्रिया के बिना प्रो पर्टी से वंचित करने के बराबर है। इस सुझाव के अनुसार, राज्य अपने राजमार्गों के उपयोग को वाहक के रूप में पूरी तरह से अस्वीकार कर सकता है, वह सार्वजनिक उपयोगिता का दर्जा ग्रहण करने पर अपनी अनुमति को सशर्त बना सकता है, न्यायालय ने जवाब दिया कि ऐसा करने के लिए शक्ति का उपयोग करना होगा। एक वर्जित परिणाम तक पहुँचने से इनकार करना, और इसलिए स्वयं असंवैधानिक होगा। श्री न्यायमूर्ति सदरलैंड ने बहुमत के लिए बोलते हुए कहा:

" इस प्रस्ताव को चुनौती देना आवश्यक नहीं है कि,

एक सामान्य नियम, राज्य, जिसे विशेषाधिकार के रूप में अस्वीकार करने की शक्ति है

कुल मिलाकर, इसे ऐसी शर्तों पर प्रदान कर सकता है जो इसे उचित लगे अधिरोपित करें; लेकिन उस संबंध में राज्य की शक्ति एक नहीं है

सीमित, और सीमाओं में से एक यह है कि यह लागू नहीं हो सकता है

ऐसी स्थितियाँ जिनके लिए संवैधानिक त्याग की आवश्यकता होती है।

अधिकार। यदि राज्य एक संविधान के आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर सकता है

राष्ट्रीय अधिकार अपने पक्ष की शर्त के रूप में, यह उसी तरह से हो सकता है।

सभी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करें। यह अकल्पनीय है कि गारंटी

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अंतर्निहित इस प्रकार हो सकता है

अस्तित्व से बाहर हेरफेर किया जाए "। (पी पर। 593)।

यह निर्णय स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि, हालांकि राज्य के पास अपने नियंत्रण में विशेषाधिकार हो सकते हैं जिन्हें वह रोक सकता है, लेकिन वह उन विशेषाधिकारों के अनुदान का उपयोग उन कार्यों के लिए एक वैध सहमति प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकता है, जो यदि आमंत्रण में अनुदान प्राप्तकर्ता पर लगाया जाता है, तो यह उसकी संवैधानिक शक्ति से परे होगा।

श्री न्यायमूर्ति सदरलैंड का तर्क था कि इसमें शामिल था

इस तरह के मामलों में, एक भी शक्ति नहीं, बल्कि दो अलग-अलग शक्तियां और इनमें से एक, उचित मामलों में सार्वजनिक राजमार्गों के उपयोग को प्रतिबंधित करने की शक्ति, राज्य के पास है; और दूसरा, एक निजी वाहक को उसकी इच्छा के खिलाफ एक सामान्य वाहक के कर्तव्यों और बोझ को ग्रहण करने के लिए मजबूर करने की शक्ति, राज्य के पास नहीं है। उनके अनुसार, यह

स्पष्ट है कि बाद वाले को अलग से और मूल रूप से लागू करने का कोई भी प्रयास संविधान के सर्वोच्च प्राधिकरण के समक्ष आना चाहिए। फिर सवाल यह है कि क्या यह उस सशर्त रूप में खड़ा हो सकता है जिसमें इसे बनाया गया है? द.

विद्वान न्यायाधीश-ने कहा कि यदि ऐसा किया जा सकता है, तो संवैधानिक गारंटी, जो सीधे हमले से इतनी सावधानी से सुरक्षित हैं, अप्रत्यक्ष रूप से विनाश के लिए खुली हैं, लेकिन कम प्रभावी नहीं हैं, आत्मसमर्पण की आवश्यकता की प्रक्रिया, जो, हालांकि स्वैच्छिक रूप में, वास्तव में मजबूरी के किसी भी तत्व का अभाव है। वास्तव में, वाहक को चट्टान और बवंडर के बीच एक विकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है-एक विशेषाधिकार को छोड़ने का विकल्प जो हो सकता है। उसकी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण या एक आवश्यकता के अधीन जो

एक असहनीय बोझ हो सकता है।

यह काफी हद तक वैसा ही है जैसा दास, सी. जे. ने इन रे में कहा था: केरल के लोग

शिक्षा विधेयक (!) :

" वास्तव में कोई भी शैक्षणिक संस्थान ऐसा नहीं हो सकता है

राज्य से सहायता के बिना किया गया और यदि वे नहीं करेंगे

इसे तब तक प्राप्त करें जब तक कि वे अपने अधिकारों का समर्पण नहीं करते, वे com द्वारा करेंगे

(1) [1959] एस. सी. आर. 99

.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर.

262

वित्तीय आवश्यकताओं की स्पंदन, उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार।

इस स्थिति में समर्पण की शर्त उतनी ही प्रभावी है।

अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार के प्रयोग के लिए एक निवारक

प्रतिबंध होगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धार्मिक

अल्पसंख्यक स्वेच्छा से अपने अधिकार को माफ नहीं करते हैं-इसे मजबूर किया गया है इसमें शामिल विशेषाधिकार के बुनियादी महत्व के कारण, अर्थात्,

संबद्धता।

यह संदेहपूर्ण है कि क्या अनुच्छेद 30 (1) के तहत मौलिक अधिकार है।

किसी स्वैच्छिक कार्य द्वारा विनिमय या समर्पण किया जा सकता है या यह कि त्याग किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि मौलिक अधिकार निहित है

एक इकाई के रूप में व्यक्तियों की बहुलता या यदि हम ऐसा कहते हैं, तो एक समुदाय में

अनिवार्य रूप से उतार-चढ़ाव वाले व्यक्ति। ए के वर्तमान सदस्य कर सकते हैं

अल्पसंख्यक समुदाय वस्तु-विनिमय करता है या अनुच्छेद के तहत अधिकार को छोड़ देता है

ताकि इसके भावी सदस्यों को एक इकाई के रूप में बांधा जा सके? मौलिक अधिकार जीवित पीढ़ी के लिए है। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्थान की संबद्धता के स्वैच्छिक कार्य द्वारा समुदाय के पूर्व सदस्य उस समुदाय के भावी सदस्यों के अधिकार को आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं। समुदाय के भावी सदस्य उत्तराधिकार या विरासत द्वारा अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं।

हालाँकि, निगम क्षेत्र में असंवैधानिक स्थिति के समाप्त होने के परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रों में समान तर्क का उपयोग समाप्त नहीं हुआ। अन्य गतिविधियों के संबंध में संवैधानिक अधिकारों के समर्पण की आवश्यकता वाले कानूनों का सामना करने वाली अदालतों ने निगमों के राज्य नियंत्रण से संबंधित मामलों से वाक्यांश और तर्क उधार लिए हैं और उन्हें कई और विविध विषयों से जुड़े समकालीन निर्णयों में स्थानांतरित कर दिया है। (1)

" कांग्रेस बेहतर जीवन के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं को रोक सकती है "श्री जूस्टिस फ्रैंकफर्टर ने डाउड्स मामले (2) में लिखा" लेकिन अगर वह उन्हें प्रदान करती है। यह उन्हें स्पष्ट रूप से मनमाने तरीके से उपलब्ध नहीं करा सकता है या सुविधाओं के उद्देश्य से असंबंधित स्वतंत्रताओं का सटीक समर्पण नहीं कर सकता है।

प्रोफेसर हेल ने कहा कि कोई राज्य किसी शर्त को जोड़कर ऐसा नहीं कर सकता है

किसी विशेषाधिकार के लिए, संघीय प्रणाली के कामकाज में अनुचित हस्तक्षेप लाना; और यह भी कि इस तरह से संवैधानिक अधिकारों के समर्पण की आवश्यकता नहीं हो सकती है, जब तक कि 'समर्पण' उस उद्देश्य को पूरा नहीं करता है जिसके लिए आम तौर पर बिना शर्तों के शक्ति का

प्रयोग किया जा सकता है। ( ) बाद की सीमा, यह ध्यान दिया जाएगा, अनिवार्य रूप से वही है जो न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने डाउड्स मामले (2) में आवाज उठाई थी कि कांग्रेस 'सुविधाओं के उद्देश्य से असंबंधित स्वतंत्रताओं का सटीक आत्मसमर्पण' नहीं कर सकती है।

कंडी लागू करने की शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता

इस क्षेत्र में विशेषाधिकार या लाभ के अनुदान में शामिल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शर्त की प्रासंगिकता है।

(1) 28 इंडियन लॉ जर्नल, नोट्सः सशर्त विशेषाधिकार सिद्धांत के विस्तार के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों के अधिकार के लिए न्यायिक अधिग्रहण ", 520,525।

2) अमेरिकी संचार संगठन। वी. डौड्स। 339 यू. एस. 382,417) "असंवैधानिक शर्तें और संवैधानिक अधिकार", 35 कोलंबिया देखें।

लॉ रेव., 321 357।

एसटी. जेवियर कॉलेज वी. गुजरात (मैथ्यू, जे.)

203

एक शर्त को इस आधार पर अमान्य किया जा सकता है कि

प्रभावी रूप से किसी अधिकार के प्रयोग के कारण लाभ या विशेषाधिकार दंडनीय है।

इसका अभ्यास (स्टाइनबर्ग बनाम देखें। संयुक्त राज्य) (1)। शेरबर्ट वी।

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक राज्य को निषेध करने के लिए आवेदन किया गया सातवें दिन के एडवेंटिस्ट के इनकार करने के लिए बेरोजगारी लाभ जारी रखें

शनिवार एम्प। दिन के सब्त के दिन होने के कारण उसका विश्वास। अदालत ने कहाः

" न ही दक्षिण कैरोलिना न्यायालय का निर्माण हो सकता है

कानून को जमीनी स्तर पर संवैधानिक दुर्बलता से बचाया जाए कि बेरोजगारी क्षतिपूर्ति लाभ अपीलार्थी के नहीं हैं

' सही 'लेकिन केवल एक' विशेषाधिकार '। दिन में बहुत देर हो चुकी है

संदेह है कि धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकती है एक पर शर्तों के इनकार या रखने से उल्लंघन किया गया

लाभ या विशेषाधिकार। अमेरिकन कम्युनिकेशंस एसो वी।

डाउड्स (ऊपर) वीमन बनाम। अनडिग्रेफ, (3) हैनेगन बनाम।

एस्क्वायर, इंक (4) "।

एक राज्य ने कर छूट के रूप में सब्सिडी देने से इनकार कर दिया

चर्च समूहों के दिग्गज जिन्होंने वफादारी की शपथ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कि

असंवैधानिक ठहराया गया था क्योंकि यह एक के रूप में सब्सिडी का उपयोग निहित था

गैर-आपराधिक भाषण पर अंकुश लगाने का अर्थ है (स्पीज़र v देखें। रान्डेल (ओ)। में।

उस मामले में अदालत ने कहा:

" उन दावेदारों को छूट देने से इनकार करना जो कुछ कार्यों में संलग्न हैं।

भाषण के रूप इस तरह के भाषण के लिए उन्हें दंडित करने के लिए प्रभावी हैं।

इसका निवारक प्रभाव वैसा ही है जैसे राज्य ठीक था। उनके भाषण के लिए। अपीलार्थी स्पष्ट रूप से गलत हैं

उनका तर्क है कि, क्योंकि कर छूट एक 'विशेषाधिकार' है

या 'इनाम', इसका इनकार भाषण का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यह सामग्री

कैलिफोर्निया न्यायालयों के समक्ष यह प्रबल नहीं था, जो पुनर्विचार करते हैं। विशेषाधिकार प्रदान करने पर लगाई गई शर्तों को समाप्त कर दिया।

या उपदान 'उचित' होना चाहिए।

" तो यहाँ, इसमें शामिल होने के लिए कर छूट से इनकार

कुछ भाषण अनिवार्य रूप से मजबूर करने का प्रभाव होगा

दावेदार निर्धारित भाषण से बचना। ... .

एक शर्त को एक अन्य आधार पर अमान्य किया जा सकता है: रोक लगाएँ

जो लोग अपने अधिकारों को बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें किसी विशेषाधिकार या लाभ के आनंद में भाग लेने से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला एक अनुचित वर्गीकरण प्रतीत होगा। शर्तों को लागू करने की भेदभावपूर्ण प्रकृति का उल्लेख श्री न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने अमेरिकन कम्युनिकेशंस एसोसिएशन बनाम में अपनी कॉन करिंग राय में किया है। डाउड्स (ऊपर)। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि राज्य नहीं है

कानून के समक्ष समानता से इनकार करना क्योंकि शर्त का बोझ

(1) 163 एफ. सप. 590. 592 .

(2) 374 यू. एस. 398,404-405।

(3) 344 यूएस 183,191,192।

(4) 327 यू. एस. 146,155,156,

(5) 357 यू. एस. 513,518-9।

यह उन सभी प्राप्तकर्ताओं पर लागू होता है, जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करते हैं और मान्यता या संबद्धता चाहते हैं, चाहे वे धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक हों या नहीं। तर्क यह है कि एक लाभ-बोझ पैकेज अर्थात। , सभी शर्तों के साथ संबंध का विशेषाधिकार बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है; कि राज्य या विश्वविद्यालय किसी भी व्यक्ति या संस्था से विशेषाधिकार नहीं रोकता है, बल्कि यह कि व्यक्ति या संस्था स्वयं निर्णय लेती है कि उसे स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। हमारी राय है कि, वास्तव में, सभी बी को एक ही पैकेज की पेशकश नहीं की जा रही है क्योंकि शर्त केवल उन लोगों की गतिविधियों पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध के रूप में कार्य करती है जिनके पास है

अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत प्रकृति के मौलिक अधिकार, अर्थात्, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, और जो इसका प्रयोग करना चाहते हैं

विशेषाधिकार की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में अधिकार को माफ करने की आवश्यकता है। संवैधानिक अधिकार और फिर भी भेदभाव की बात करना विरोधाभासी है। उस अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा करें।

इनमें से किसी भी आधार पर किसी शर्त के अमान्य होने से बचने के लिए, यह

यह दिखाना आवश्यक प्रतीत होगा कि लाभ या विशेषाधिकार प्रदान करने से प्राप्तकर्ता को ऐसी स्थिति में रखा जाता है जो विश्वविद्यालय के राज्य को अपने अधिकारों को विनियमित करने में वैध रुचि देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दो वैध हित हैं जो इस तरह के विनियमन को उचित ठहरा सकते हैं। पहला यह सुनिश्चित करने में रुचि है कि दिए गए या दी गई लाभ या सुविधा, अर्थात् मान्यता या संबद्धता को इच्छित उद्देश्यों के लिए बनाए रखा जाए, ताकि लाभ की प्रभावशीलता की रक्षा की जा सके।

सुविधा स्वयं। दूसरा, उन लोगों के खिलाफ सामाजिक हितों की रक्षा की जानी चाहिए जिनकी लाभ या सुविधा के कब्जे से नुकसान पहुंचाने की क्षमता बढ़ जाती है (1)।

. शक्ति के पारंपरिक आधारों की एक परीक्षा E

सरकार पर शर्तें थोपना। लाभ या विशेषाधिकारों से पता चलेगा कि शर्तों को लागू करने की शक्ति रोकने की अधिक से अधिक शक्ति का कम हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके बजाय शक्ति का एक अलग प्रयोग है जिसे अपना औचित्य खोजना चाहिए, और यह कि मान्यता या संबद्धता को पूरी तरह से रोकने की शक्ति अपने साथ ऐसी शर्तों को लागू करने की सीमित शक्ति नहीं रखती है जो मौलिक अधिकारों के प्रयोग को रोकने का प्रभाव डालती हैं। विशेषाधिकारों का आनंद लेने की सामान्य इच्छा जैसे संबद्धता या मान्यता जिसके बिना अल्पसंख्यकों द्वारा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित शैक्षणिक संस्थान उस उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे जिसके लिए वे स्थापित किए गए थे, उन्हें गारंटीकृत अधिकार के दमन का साधन नहीं बनाया जा सकता है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन फिर भी उल्लंघन है क्योंकि इसे पूरा किया गया है।

कंडीशनिंग के माध्यम से। एक विशेषाधिकार। यदि कोई विधायिका किसी सार्वजनिक लाभ या विशेषाधिकार के साथ एक परिशिष्ट संलग्न करती है, जो किसी भी तर्कसंगत तरीके से लाभों की योजना के उद्देश्यों का समर्थन नहीं करता है, लेकिन मौलिक अधिकार के उन्मूलन को रोकता है, तो प्रतिबंध को लाभ या विशेषाधिकार से जोड़े जाने से कोई भी संवैधानिक ताकत नहीं मिल सकती है, लेकिन इसे इस तरह मापा जाना चाहिए जैसे कि यह पूरी तरह से अलग अधिनियम था।

इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या कोई शर्त लागू करने वाला विनियमन उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए मान्यता या संबद्धता दी जाती है, एच यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कौन सा विनियमन उपयुक्त प्रमाण है।

(1) टिप्पणियाँ देखें-" असंवैधानिक शर्तें "। 74 हार्व। विधि रेव. 1595.

धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित और कोई मान्यता या सहायता प्राप्त नहीं करने वाले शैक्षणिक संस्थान के संबंध में न्याय व्यवस्था लागू कर सकती है। ऐसी संस्था, निश्चित रूप से, देश के भौगोलिक कानूनों जैसे कराधान कानून, स्वच्छता से संबंधित कानून, संपत्ति के हस्तांतरण या दस्तावेजों के पंजीकरण आदि के अधीन होगी, क्योंकि वे न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को प्रभावित करने वाले कानून हैं, बल्कि अन्य सभी व्यक्तियों और संस्थानों को भी प्रभावित करते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि इन सामान्य कानूनों द्वारा, राज्य किसी भी तरह से अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत अधिकार को छीन या कम कर देता है। क्योंकि। ए. आर. अनुच्छेद 30 (1) को पूर्ण शब्दों में जोड़ा गया है, यह इस बात का पालन नहीं करता है कि गारंटीकृत अधिकार नियामक कानूनों के अधीन नहीं है जो इसे कम करने के बराबर नहीं होगा। यह कहना पूरी तरह से गलत धारणा है कि क्योंकि अधिकार पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए अधिकार के प्रयोग को विनियमित नहीं किया जा सकता है या उस अधिकार का प्रत्येक विनियमन निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप होगा: सही है।

न्यायमूर्ति होम्स ने हडसन कंट्री वाटर कंपनी बनाम में कहा। मैकार्टर (1):

" सभी अधिकार स्वयं को उनके लिए निरपेक्ष घोषित करते हैं।

तार्किक चरम। फिर भी वास्तव में सभी पड़ोसियों द्वारा सीमित हैं

नीति के सिद्धांतों का पोषण जो उनके अलावा अन्य हैं

जिस पर विशेष अधिकार का वित्तपोषण किया जाता है, और जो बन जाता है एक निश्चित बिंदु होने पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत

पहुँच गया "

कोई भी अधिकार, चाहे वह कितना भी निरपेक्ष क्यों न हो, विनियमन से मुक्त नहीं हो सकता है। द प्रिवी परिषद ने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल बनाम में कहा। बैंक ऑफ न्यू साउथ

वेल्स (2) कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का विनियमन कॉम है

उनकी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अनुकूल; वह एस। 92 ऑस्ट्रेलियाई कॉम राष्ट्रमंडल अधिनियम का उल्लंघन केवल तभी होता है जब कोई अधिनियम सीधे वाणिज्य को प्रतिबंधित करता है।

और कुछ अप्रत्यक्ष या परिणामी बनाने से तुरंत अलग

बाधा जिसे उचित रूप से दूरस्थ माना जा सकता है। इसी तरह,

तथ्य यह है कि व्यापार और वाणिज्य बिल्कुल हैं। संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत मुक्त उनके विनियमन के साथ संगत है जो प्रतिबंध (3) के बराबर नहीं होगा।

'एब्रिज' शब्द का प्रयोग कई देशों में मुश्किल नहीं हो सकता है।

महत्वपूर्ण वे हैं जहाँ कोई कानून अधिकार का प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं है। लेकिन एक अन्य उद्देश्य और उस पर प्रभाव को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है

अधिकार गौण या अप्रत्यक्ष होता है। ऐसे उपाय जो दूसरों की ओर निर्देशित हों।

कार्यकलापों के रूप लेकिन जिनमें गौण या अप्रत्यक्ष या आनुषंगिक हैं

मजदूरी, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और स्वच्छता बनाए रखने के उपाय और अन्य सामान्य अनुप्रयोग के कानून। परिकल्पना द्वारा, कानून, अपने आप में लिया जाता है, है

एक वैध, जिसका उद्देश्य सीधे किसी अन्य गतिविधि के नियंत्रण पर है।

प्रश्न स्वीकृत क्षेत्र पर इसके द्वितीयक प्रभाव के बारे में है

शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन। यह विशेष रूप से एक समस्या है।

(2) [1950] ए. सी. 235,310।

(1) 209 अमेरिका 349,355,357 (3) द ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड,

वी. राजस्थान

राज्य और

अन्य [1963] 1 एस. सी. आर. 491।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी.

आर.

266

यह निर्धारित करने के लिए कि जारी किए गए विनियमन का प्रभाव कब पड़ता है जो अनुच्छेद 13 (2) के अर्थ के भीतर संवैधानिक अधिकार को संक्षिप्त करता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक मामले में, न्यायालय को अनुच्छेद 13 (2) (1) में 'सेतु' शब्द को परिभाषित करने और विषय-वस्तु देने की आवश्यकता है। पूछा और जवाब दिया जाने वाला सवाल यह है कि क्या विशेष रूप से मेरा

यह सुनिश्चित है कि यह विनियामक है या क्या यह अनुमेय विनियमन के क्षेत्र को पार करता है और प्रतिबंधों या संक्षिप्तता के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है। बी इसलिए, भले ही किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित कोई शैक्षणिक संस्थान मान्यता, संबद्धता या सहायता नहीं चाहता है, लेकिन इसकी गतिविधि को विभिन्न तरीकों से विनियमित किया जा सकता है बशर्ते कि नियम गारंटीकृत अधिकार को छीन या कम न करें। नियमित कर उपायों, आर्थिक विनियमों, सामाजिक कल्याण कानून, मजदूरी और घंटे कानून और इसी तरह के उपायों का अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जहां बोझ वही है जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लगे अन्य लोगों द्वारा वहन किया जाता है, तो अधिकार पर समान प्रभाव पड़ता है।

यदि किसी धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित कोई शैक्षणिक संस्थान कोई मान्यता, संबद्धता या सहायता नहीं चाहता है, तो राज्य को पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम या शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है।

हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करना असंभव पाते हैं जिसकी राज्य को आवश्यकता है।

शिक्षा यह तय करने के लिए मानदंड है कि क्या किसी शैक्षणिक संस्थान पर लगाया गया विनियमन अनुच्छेद के तहत अधिकार को छीनता है या कम करता है।

30 (1) . यदि कोई विधायिका कोई भी विनियमन लागू कर सकती है जो उसके विचार में राज्य या समाज के हित में है, तो अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। यह विरोधाभासी लगता है कि एक अधिकार जिसे संविधान निर्माता निरपेक्ष बनाना चाहते थे, उसे नियमों के अधीन किया जा सकता है जो केवल राज्य की आवश्यकता के अस्पष्ट और लोचदार परीक्षण को संतुष्ट करने की आवश्यकता है। संविधान के भाग III में इस अधिकार को अन्य मौलिक अधिकारों के विपरीत पूर्ण रूप से निगमित करने का उद्देश्य इसे बहुमत की पहुंच से वापस लेना था। आज के अधिकार को राज्य की आवश्यकता की प्रोटियन अवधारणा द्वारा निर्धारित विनियमनों के अधीन करना, जैसा कि बहुमत द्वारा कल्पना की गई थी, उसी उद्देश्य को नष्ट करना होगा जिसके लिए अधिकार दिया गया था।

फिर कौन से अतिरिक्त नियम हैं जो वैध रूप से हो सकते हैं

धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित एक शैक्षणिक संस्थान पर लागू किया जाता है जो सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करता है और मान्यता या संबद्धता चाहता है?

मान्यता या संबद्धता उत्कृष्टता के आधार पर दी जाती है।

किसी शैक्षणिक संस्थान का, अर्थात्, कि वह विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित शैक्षिक मानक तक पहुँच गया है। मान्यता या संबद्धता किसी शैक्षणिक संस्थान में छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से मांगी जाती है। उस उद्देश्य के लिए, छात्रों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षा के स्तर को प्राप्त कर सकें। मान्यता या संबद्धता

यह सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय में रुचि पैदा करता है कि शैक्षणिक संस्थान

(1) आम तौर पर बेनेट कोलमैन एंड कंपनी आदि में हम में से एक (मैथ्यू, जे.) का निर्णय देखें। आदि वी। भारत संघ और अन्य (1972) 2 एस. सी. सी. 788.

एसटी. XAVIERS कॉलेज v. गुजरात (मैथ्यू, जे.)

267

उद्देश्य और किसी भी विनियमन के लिए बनाए रखा जाता है जो उस उद्देश्य को आगे बढ़ाना या आगे बढ़ाना उचित होगा और कोई शिक्षा नहीं होगी।

किसी धार्मिक या भाषाई द्वारा स्थापित और प्रशासित राष्ट्रीय संस्था। अल्पसंख्यक उन लोगों को प्रस्तुत किए बिना मान्यता या संबद्धता का दावा कर सकते हैं

नियम। यह मान्यता या संबद्धता की कीमत है; लेकिन यह करता है

इसका मतलब यह नहीं है कि इसे समर्पण के लिए निर्धारित एक विनियमन के अधीन होना चाहिए संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार या स्वतंत्रता, जो असंबंधित है

मान्यता या संबद्धता के उद्देश्य के लिए। दूसरे शब्दों में, मान्यता

या संबद्धता एक ऐसी सुविधा है जिसे विश्वविद्यालय किसी शैक्षणिक संस्थान को प्रदान करता है।

संस्थान, वहाँ के छात्रों को बैठने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विषयों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा।

और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री प्राप्त करने के लिए, और इसलिए, यह

यह अभिनिर्धारित करने के लिए तर्कपूर्ण है कि कोई भी विनियमन जो प्रावधान से असंबंधित है

मुद्रा थोपी जा सकती है। यदि, मान्यता या संबद्धता के अलावा, एक शिक्षा

यह सुनिश्चित करने के लिए विनियम कि सहायता का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसे यह दिया जाता है, वह अनुज्ञेय होगा। दिल की बात यह है कि

धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं विधायिका या विश्वविद्यालय द्वारा विनियमों से पूर्ण प्रतिरक्षा का दावा कर सकते हैं

संस्करण यदि यह संबद्धता या मान्यता चाहता है; लेकिन प्रति का चरित्र अनुपयुक्त विनियमों को उनके उद्देश्य पर निर्भर होना चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं,

विनियम अनुमत होंगे यदि वे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं मान्यता या संबद्धता के उद्देश्य को सुरक्षित करना या बढ़ावा देना। वहाँ

सीमा रेखा वाले मामले होंगे जहाँ यह तय करना मुश्किल है कि क्या एक नियम है

सिद्धांत के प्रश्न को प्रभावित नहीं करता है। हर मामले में, जब एक विनियमन की तर्कसंगतता से पहले विचार के लिए आता है

अदालत, पूछा और जवाब दिया जाने वाला सवाल यह है कि क्या विनियमन है। गणना को कम करने के लिए किया जाता है या प्रभावी रूप से रीको के उद्देश्य को कम करेगा

मान्यता या संबद्धता, अर्थात्, अल्पसंख्यक समुदाय और इसका सहारा लेने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए एक वाहन के रूप में संस्थान की उत्कृष्टता। यह सवाल कि क्या कोई विनियमन जनता के सामान्य हित में है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, अगर यह आगे नहीं बढ़ता है।

सामान्य धर्मनिरपेक्ष सी. डी. यू. सी. के लिए एक वाहन के रूप में संस्थान की उत्कृष्टता

पूर्व परिकल्पना के रूप में, केवल अनुमेय नियम वे हैं जो

सुविधा के उद्देश्य की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना, अर्थात् उनके शैक्षिक मानकों के संबंध में शैक्षणिक संस्थानों की उपस्थिति। यही कारण है कि इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि यह सवाल कि क्या किसी विशेष विनियमन की गणना आम जनहित को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, इसका कोई परिणाम नहीं है यदि यह अल्पसंख्यक समुदाय और उन व्यक्तियों के हितों के लिए अनुकूल नहीं है जो इसका सहारा लेते हैं।

सिद्धजभाई बनाम। बॉम्बे राज्य (!) , अदालत ने कहा कि कोई जीन नहीं है

आरएल सिद्धांत जिस पर किसी विनियमन की तर्कसंगतता या अन्यथा परीक्षण किया जा सकता है, अदालत द्वारा पुनः निर्धारित करने की मांग की गई थीः केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (2) और इसलिए, मामला इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि सभी नियामक उपाय जो विनाशकारी नहीं हैं।

यदि विनियम राष्ट्रीय या सार्वजनिक हित में हैं तो लघु निकाय द्वारा स्थापित संस्थान के चरित्र को निरस्त किया जा सकता है। अदालत ने आगे कहा कि मौलिक स्वतंत्रताओं के विपरीत

(1) [1963.3 एस. सी. आर. 837,856-857।

(2)

[1959] एससीआर 995।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर.

268

अनुच्छेद 19 के अनुसार, अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन नहीं है और यह कि अधिकार का उद्देश्य स्पष्ट होना है और इसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के हित में परिकल्पित तथाकथित नियामक उपायों द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिए।

शासन, लेकिन जनता या पूरे राष्ट्र का। न्यायालय का विचार था कि अनुदान या मान्यता प्राप्त करने की शर्त के रूप में विधायी रूप से लागू किए जाने वाले विनियमों या विशेष कार्रवाई को एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपने चरित्र को प्रभावी बनाए रखते हुए संस्थान को बनाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए और यह कि इस तरह के विनियमन को तर्कसंगतता की दोहरी कसौटी को पूरा करना चाहिए, अर्थात् यह कि यह संस्थान के शैक्षिक चरित्र का नियामक है और इसे अल्पसंख्यक समुदाय या अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का एक प्रभावी वाहन बनाने के लिए अनुकूल है जो अनुदान या मान्यता प्राप्त करने की शर्त के रूप में लागू किया जा सकता है।

यह। केरल राज्य में बनाम। मदर प्रोविंशियल (1) अदालत ने कहा-हम एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान के संबंध में सोचते हैं जो मान्यता या सहायता चाहता है।

कि शिक्षा के मानक प्रबंधन का हिस्सा नहीं हैं

इस प्रकार कि शिक्षा के मानक राजनीतिक निकाय से संबंधित हैं और देश की प्रगति और इसके महत्व पर विचार करके निर्धारित किए जाते हैं।

लोग और इसलिए, यदि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम स्थापित करते हैं, तो उनका पालन किया जाना चाहिए, हालांकि, विशेष विषयों के लिए जो संस्थान पढ़ाना चाहते हैं, और कुछ हद तक S.ate कर सकते हैं। शिक्षकों के रोजगार और उपचार की स्थितियों को भी विनियमित करता है। एच.

और छात्रों की स्वच्छता और यह कि ये नियम सीधे तौर पर लागू नहीं होते हैं

प्रबंधन पर इस तरह से, हालांकि वे अप्रत्यक्ष रूप से इसे प्रभावित कर सकते हैं। द. न्यायालय ने आगे कहा कि शिक्षा को विनियमित करने का राज्य का अधिकार,

शैक्षिक मानक और संबद्ध एम. ए. इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थानों को मानकों से नीचे आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, या

प्रबंधन के अनन्य अधिकार की आड़ में, पालन करने से इनकार करना

सामान्य स्वरूप और जबकि प्रबंधन को छोड़ दिया जाना चाहिए उन्हें दूसरों के साथ कदम रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है। क्या बात?

श्री मोहन कुमारमंगा लाम के तर्क के जवाब में अदालत ने कहा कि केरल विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था।

नीचे की कल्पना सामान्य शिक्षा के हित में की गई थी इस संदर्भ में ध्यान दें:

" श्री मोहन कुमारमंगलम ने हमारे ध्यान में लाया

शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के अंश

जिसके बारे में आयोग ने सुझाव दिए थे

विश्वविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

और महाविद्यालय और शिक्षण के मानक। उन्होंने शिक्षा आयोग की स्थिति पर रिपोर्ट का भी उल्लेख किया

शिक्षक, शिक्षण विधियों और मानकों में सुधार के लिए सुझाव। उन्होंने तर्क दिया कि केरल ने क्या किया है।

विश्वविद्यालय अधिनियम इन सुझावों को अध्यायों में लागू करता है।

VIII और IX और विशेष रूप से विवादित खंड। हम.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम के प्रावधानों को प्रामाणिक बनाया गया था

ईमानदारी से और शिक्षा के हित में लेकिन दुर्भाग्य से वे

इन संस्थानों के प्रशासन को प्रभावित करते हैं और लूटते हैं

उस अधिकार के संस्थापकों को जो संविधान चाहता है

(1) [1971] 1 एस. सी. आर. 734

(

एसटी. जेवियर कॉलेज वी. गुजरात (मैथ्यू, जे.)

269

ए.

उनका बनो। प्रावधान, भले ही हितकारी हों, इसमें टिक नहीं सकते हैं।

संवैधानिक गारंटी का चेहरा। इसलिए हम नहीं करते, दोनों रिपोर्टों को संदर्भित करना आवश्यक समझते हैं।

उपरोक्त चर्चा के आलोक में आइए हम इसकी वैधता की जांच करें

►

गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 के विवादित प्रावधान

क्रमिक रूप से संशोधित।

बी.

धारा 33 ए (1) (ए) प्रदान करती है:

" 33 ए (1) प्रत्येक महाविद्यालय (सरकारी महाविद्यालय के अलावा)।

सरकार द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय)। कॉम से पहले संबद्ध। नासूर

गुजरात विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 (इसके बाद)

इस धारा में जिसे "ऐसा प्रारंभ" कहा गया है) -

(क) एक शासी निकाय के प्रबंधन के अधीन होगा।

सी.

महाविद्यालय के मित्र, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि कुलपति द्वारा नामित, और तीन प्रतिनिधि

महाविद्यालय के शिक्षकों के मूल निवासी और कम से कम एक

गैर-शिक्षण के सदस्यों का प्रतिनिधि दल कॉलेज के कर्मचारी और छात्र, जिन्हें फिर से चुना जाएगा

प्रभावी रूप से ऐसे शिक्षकों में से, के सदस्य

गैर-शिक्षण कर्मचारी और छात्र; और

(ख) प्राचार्य और सदस्यों की भर्ती के लिए

एक कॉलेज के शिक्षण कर्मचारी वहाँ एक चयन कॉम है

महाविद्यालय की समिति जिसमें शामिल होंगे -

(1) प्रधानाचार्य की भर्ती के मामले में,

ई.

द्वारा नामित विश्वविद्यालय की प्रस्तुति

कुलपति, और

(2) उसके किसी सदस्य की भर्ती के मामले में

महाविद्यालय के शिक्षण कर्मचारी, एक प्रतिनिधि

कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय

और प्रस्थान करने वालों के प्रमुख: यदि कोई चिंता है

एफ.

ऐसे सदस्य द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय के साथ।

हम समझते हैं कि उप-धारा (1) (ए) और (1) (बी) के प्रावधान

एस. 33 धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रशासन के अधिकार को कम करना

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान। आवश्यकता यह है कि

महाविद्यालय में एक शासी निकाय होना चाहिए जिसमें व्यक्ति शामिल हों।

उन लोगों के अलावा जो समाज के शासी निकाय के सदस्य हैं

जी.

जीसस कॉलेज का प्रबंधन छीन लेगा

सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा गठित शासी निकाय और इसे एक

अलग शरीर। शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन का अधिकार

एक धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित इसमें निहित है। यह शासन में है

सोसाइटी ऑफ जीसस का निकाय कि वह धार्मिक अल्पसंख्यक है जो

स्थापित कॉलेज ने प्रशासन का अधिकार निहित किया है

संस्थान और केवल उस निकाय को ही इसे प्रशासित करने का अधिकार है।

एच.

आवश्यकता है कि महाविद्यालय में एक शासी निकाय होना चाहिए

शासी निकाय का गठन करने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों को शामिल करना

सोसाइटी ऑफ जीसस का प्रभाव अपने सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर. के उस निकाय को विभाजित करने का है।

270

शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन का अनन्य अधिकार। यह है कि

विधायिका की राय में प्राचार्य को संबद्ध करना वांछनीय है

एस में संदर्भित महाविद्यालय या अन्य व्यक्तियों के। 33 ए (1) (ए) में

महाविद्यालय का प्रबंधन एक प्रासंगिक विचार नहीं है। द.

सवाल यह है कि क्या प्रावधान का विनिवेश का प्रभाव है

अपने अनन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा गठित शासी निकाय

संस्थान के प्रशासन का अधिकार। प्रीवेन की आड़ में। िग

कुप्रशासन, महाविद्यालय के शासी निकाय का अधिकार

संस्था के प्रशासन के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा गठित

दूर नहीं किया जा सकता। प्रावधान का प्रभाव यह है कि धार्मिक

अल्पसंख्यक वस्तुतः उस संस्था को प्रशासित करने का अपना अधिकार खो देता है जो उसके पास है।

स्थापित "। प्रशासन का अर्थ है 'मामलों का प्रबंधन'

संस्था। यह प्रबंधन नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए ताकि

संस्थापक या उनके नामांकित व्यक्ति अपने अनुसार संस्थान को ढाल सकते हैं।

सामान्य रूप से समुदाय और विशेष रूप से संस्था सबसे अच्छा परोसा जाता है। इस प्रबंधन का कोई भी हिस्सा नहीं लिया जा सकता है और

गारंटी पर अतिक्रमण के बिना किसी अन्य निकाय में निहित

सही (1) "। केरल विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969 की धारा 48 और 49,

जो उस मामले में क्रमशः विचार के लिए आया था

निजी कॉलेजों के लिए शासी निकाय जो कॉर्पोरेट प्रबंधन के तहत नहीं है

कॉर्पोरेट के तहत निजी कॉलेजों के लिए प्रबंधन और प्रबंधन परिषद

प्रबंधन। इन धाराओं के प्रावधानों के तहत, शैक्षिक

एजेंसी या कॉर्पोरेट प्रबंधन को एक शासी निकाय स्थापित करना था।

क्रमशः निकाय या एक प्रबंध परिषद। जिन अनुभागों के लिए प्रावधान किया गया है

दोनों निकायों की संरचना। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुभागों ने

शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन के अधिकार को कम करने का प्रभाव वहाँ विचाराधीन धार्मिक अल्पसंख्यक। दिए गए आधारों में से एक

उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने के फैसले में हड़ताल

खंडों के नीचे यह है कि इन निकायों का एक अलग कानूनी व्यक्तित्व था शैक्षिक अभिकरण या द्वारा स्थापित शासी निकायों से

निगमित प्रबंधन और वे जवाबदेह नहीं थे

शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन के मामले में संस्थापक।

न्यायालय ने कहा कि एक कानून जो संरचना में हस्तक्षेप करता है

द्वारा गठित शासी निकाय या प्रबंध परिषद

धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकार का संक्षिप्तकरण है

स्थापित शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने के लिए धार्मिक अल्पसंख्यक

इसके द्वारा (डब्ल्यू. प्रोस्ट बनाम भी देखें। बिहार (2) और रेव. बिशप एस. के. पार्टो

· वी. बिहार (3)।

यह कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों पर है कि स्वर

और एक शैक्षणिक संस्थान का स्वभाव निर्भर करता है। उन पर

इसकी प्रतिष्ठा, अनुशासन के रखरखाव और इसकी दक्षता पर निर्भर करता है।

अध्यापन में। प्रधानाचार्य चुनने और उसके बाद प्रबंधन द्वारा नियुक्त शिक्षकों द्वारा शिक्षण का संचालन करने का अधिकार

उनके दृष्टिकोण और दर्शन का समग्र मूल्यांकन शायद है

शिक्षा का प्रशासन करने के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू

संस्था। हम कोई कारण नहीं समझ सकते हैं कि कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए

(1) केरल बनाम देखें। मदर प्रोविंशियल, [1971] 1 एस. सी. आर. 734 740 पर।

(3) [197] 1 एस सी आर 172.

(2) [1969] 2 एस. सी. आर. 73 77-78 पर।

एसटी. जेवियर कॉलेज वी. गुजरात (मैथ्यू, जे.)

271

प्रधानाचार्य की भर्ती या आग्रह के लिए चयन समिति

विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के अलावा विभाग के प्रमुख

सदस्यों की भर्ती के लिए चयन समिति में होना

शिक्षण कर्मचारी। जब तक चुने गए व्यक्तियों के पास योग्यताएँ हैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित, विकल्प प्रबंधन पर छोड़ दिया जाना चाहिए

मन में। यह अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार का हिस्सा है

उनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करना।

धारा 40 (1) में प्रावधान है कि न्यायालय (सीनेट) निर्धारित कर सकता है

कि अध्ययन के पाठ्यक्रमों में सभी निर्देश, शिक्षण और प्रशिक्षण

जिसके संबंध में विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम है,

विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर विश्वविद्यालय और विद्यालय द्वारा संचालित किया जाए

विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाएगा और न्यायालय

अपने निर्णय के बारे में राज्य सरकार को सूचित करें। उप-धारा (2)

एस. 40 कहते हैं कि उप-धारा के तहत संचार की प्राप्ति पर

(1) , सरकार, ऐसी जाँच करने के बाद जो वह सोचती है

ठीक है, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा की जाती है कि प्रावधान।

एस. 41 ऐसी तारीख को लागू होगा जो निर्दिष्ट की जाए।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह धारा वस्तुतः

धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रशासन के अधिकार का बहुत सार प्रश्न में कॉलेज।

इस प्रश्न का निर्णय लेने के लिए अन्य में से कुछ को पढ़ना आवश्यक है।

प्रावधान।

धारा 2 (2) एक 'कॉलेज' को एक डिग्री कॉलेज या एक अंतर महाविद्यालय के रूप में परिभाषित करता है।

मध्यस्थता महाविद्यालय। धारा 2 (2 ए) में कहा गया है कि एक 'घटक महाविद्यालय'

इसका अर्थ है एक विश्वविद्यालय कॉलेज या एक संबद्ध कॉलेज को घटक बनाया गया है

एस के तहत। 41. एक डिग्री कॉलेज 'को एस द्वारा परिभाषित किया गया है। 2 (3) के रूप में

एक संबद्ध महाविद्यालय जो अपने छात्रों को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है

विश्वविद्यालय की किसी भी डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली परीक्षा। अनुभाग

2 (13) प्रदान करता है:

" विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अर्थ है नियुक्त शिक्षक।

विश्वविद्यालय द्वारा अपनी ओर से निर्देश प्रदान करने के लिए।

धारा 2 (15ए) में कहा गया है कि "विश्वविद्यालय महाविद्यालय" का अर्थ है महाविद्यालय।

जिसे विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्थापित या बनाए रख सकता है या महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया और इसके द्वारा इसका रखरखाव किया गया।

एस के सादे शब्दों पर। 40 यह स्पष्ट है कि शासी निकाय

जो महाविद्यालय के प्रशासन के अपने अधिकार से संबंधित है, अर्थात् अध्ययन के पाठ्यक्रमों में शिक्षण, प्रशिक्षण और निर्देश,

जिनमें से विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम है। द.

शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करने का अल्पसंख्यक समुदाय का मौलिक अधिकार

इसकी पसंद में आचरण करने का प्राथमिक अधिकार शामिल है।

शिक्षण। संस्थानों में अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण और निर्देश

1

इस प्रकार अल्पसंख्यकों द्वारा नियुक्त शिक्षकों द्वारा स्थापित। अगर यह जरूरी है। प्रशासन के अधिकार के घटक को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर. से छीन लिया गया है।

अल्पसंख्यक और विश्वविद्यालय में निहित, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत शैक्षणिक संस्थान को प्रशासित करने का उसका अधिकार छीन लिया गया है।

धारा 39 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर का संचालन करेगा।

निर्देश दिए। इसका मतलब है कि शिक्षण, प्रशिक्षण और निर्देश

आईआर

विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। एस में आने वाला शब्द आचरण। 40 इसका अर्थ बी से अलग नहीं हो सकता है जो इसका एस में है। 39 . यदि एस में। 39 इसका मतलब यह है कि विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षा में अनन्य शिक्षण और प्रशिक्षण एजेंसी है, यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि इन मामलों को विश्वविद्यालय द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद पढ़ाने, प्रशिक्षित करने या निर्देश देने के अधिकार का कोई भी अवशेष अल्पसंख्यकों पर छोड़ दिया जाएगा। कॉलेज में शिक्षण और प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा उनके लिए और उनकी ओर से किया जाएगा।

विश्वविद्यालय। 'यूनिव के शिक्षक' शब्द की परिभाषा। 'सी' को एस में दिया गया है। 2 (13) यह इंगित करेगा कि वे विश्वविद्यालय द्वारा उसकी ओर से निर्देश प्रदान करने के लिए नियुक्त शिक्षक हैं।

यदि यह धारा अनुच्छेद 30 (1) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो हमें नहीं लगता कि

एस. 41 जिस पर कानून की वर्तमान योजना निर्भर है

एस. 40 जीवित रह सकते हैं और इसलिए किसी भी विचार को व्यक्त करना अनावश्यक है

इसके प्रावधानों की संवैधानिकता पर।

एस की उप-धारा (1) और (2)। 51 ए पढ़िए:

" 51 ए (1) शिक्षण का कोई सदस्य नहीं, अन्य शैक्षणिक और गैर

किसी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित कॉलेज के शिक्षण कर्मचारी

संस्थान को बर्खास्त या हटा दिया जाएगा या रैंक में कम किया जाएगा सिवाय इसके कि

एक जांच के बाद जिसमें उन्हें उनके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया है

उसे उचित अवसर दिया जाता है या उसके संबंध में सुना जाता है

उन आरोपों और 'जब तक

(क) उसे माक का उचित अवसर दिया गया है।

प्रस्तावित ऐसी किसी दंडात्मकता पर प्रतिनिधित्व

उस पर थोपा जाए, और

(ख) उस पर लगाए जाने वाले दंड को मंजूरी दी जाती है

कुलपति या विश्वविद्यालय का कोई अन्य अधिकारी

इस संबंध में कुलपति द्वारा प्राधिकृत।

(2) ऐसे सदस्य की सेवा की समाप्ति की कोई राशि नहीं

उप-धारा (1) के तहत आने वाली उसकी बर्खास्तगी या निष्कासन तब तक वैध होगा जब तक कि

((क) उसे प्रदर्शन का उचित अवसर दिया गया है।

प्रस्तावित समाप्ति के विरुद्ध कार्य करना,

और

(ख) ऐसी समाप्ति को कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

या उप द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी इस संबंध में कुलाधिपति:

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी किसी पर लागू नहीं होगा

बेटा जिसे केवल अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं के लिए यह तर्क दिया गया था कि धारा (1) (बी)। 51 ए.

एस. टी. की सामान्य शक्ति कुलपति को सौंपने का प्रभाव पड़ता है।

XAVIERS कॉलेज v. गुजरात (मैथ्यू,

जे.)

273

एक शिक्षक को बर्खास्त करने के प्रबंधन के अधिकार पर वीटो। सटीक कुलपतिक या कुलपतिक अधिकारीक शक्तिक दायरा

इस उप-खंड में उनके द्वारा अधिकृत विश्वविद्यालय स्पष्ट नहीं है। अगर अनुमोदन का उद्देश्य यह देखना है कि उप-धारा के प्रावधान

51 ए (1) (ए) का अनुपालन किया जाता है, संभवतः इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

उपराष्ट्रपति के मनोनीत व्यक्ति में भी अनुमोदन की शक्ति दर्ज करना

कुलाधिपति। लेकिन बिना किसी दिशानिर्देश के एक अप्रचलित शक्ति

रोक अनुमोदन के अधिकार का सीधा संक्षिप्तकरण होगा

किसी शिक्षक को बर्खास्त या हटाने या कोई अन्य जुर्माना लगाने के लिए प्रबंधन

जाँच करने के बाद।

प्रबंधन और एक शिक्षक के बीच संबंध यह है कि

एक नियोक्ता और कर्मचारी की और यह किसी की समझ को पारित करता है कि क्यों

प्रबंधन एक शिक्षक की सेवाओं को समाप्त नहीं कर सकता है रोजगार अनुबंध का आधार। बेशक, यह खुला है

राज्य अपनी नियामक शक्ति का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करे कि इससे पहले

एक शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी जाती है, उसे एक अवसर दिया जाना चाहिए

उसके बचाव में सुने जाने की धुन। लेकिन इसे समाप्त करने के लिए आवश्यक है जाँच के बाद एक शिक्षक की सेवाएँ लेते हुए,

प्रबंधन को किसी बाहरी एजेंसी की मंजूरी होनी चाहिए जैसे कि

कुलपतिया एबा बिथांनि मुं सायख 'जानायआ बेनि सुंद' जागोन।

शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन का अधिकार। कोई दिशानिर्देश नहीं हैं

विधानमंडल द्वारा कुलपति को इसके प्रयोग के लिए प्रदान किया गया

उसकी शक्ति। तथ्य यह है कि शक्ति वाइस द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती है

विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी के कुलाधिपति का अर्थ है कि कोई भी छोटा अधिकारी जिसे शक्ति सौंपी गई है वह वीटो की सामान्य शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

उप-धारा (1) (बी) और (2) (बी) के तहत कोई बाध्यता नहीं है।

कि कुलपति या उनके मनोनीत व्यक्ति को कोई कारण देना चाहिए

अस्वीकृति। जैसा कि हमने कहा कि बिना किसी दिशानिर्देश के एक कंबल शक्ति प्रबंधन की कार्रवाई को अस्वीकार करना निश्चित रूप से होगा

प्रबंधन को बर्खास्त करने या समाप्त करने का अधिकार

पूछताछ के बाद एक शिक्षक की सेवाएँ। जबकि हम प्रो को बनाए रखते हैं

एस के उपखंड (1) (ए) और (2) (ए) के दर्शन। 51 हम सोचते हैं कि एस के उपखंड (1) (बी) और (2) (बी)। 51 ए का उल्लंघन होता है

यहाँ विचाराधीन धार्मिक अल्पसंख्यक के अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार।

अंदर। पुनः: केरल शिक्षा विधेयक, 1957, इस न्यायालय में कोई संदेह नहीं है,

खारिज करने या समाप्त करने के लिए बाद में अनुमोदन की आवश्यकता एक शिक्षक की सेवाएँ अनुच्छेद 30 (1) के उल्लंघन के रूप में खराब होंगी।

डी. ए. वी. कॉलेज बनाम पंजाब राज्य, आक्षेप का खंड 17

कार्यकाल के लिए बाद में अनुमोदन की आवश्यकता से संबंधित कानून

शिक्षा के प्रशासन के अधिकार के संक्षिप्तकरण के रूप में दृष्टि वहाँ अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित संस्था।

धारा 52 ए में कहा गया है कि शासी निकाय के बीच कोई भी विवाद

और शिक्षण का कोई भी सदस्य, अन्य शैक्षणिक और गैर-शिक्षण किसी संबद्ध महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्थान के कर्मचारी,

जो ऐसे सदस्य की सेवा की शर्तों से जुड़ा है,

शासी निकाय या सदस्य के अनुरोध पर एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाएगा जिसमें

एक

-131 सुप. सी. 1. /75 274

इस प्रावधान का कोई उद्देश्य नहीं है और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह संस्थान के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगा। किसी सदस्य द्वारा उठाया गया कोई भी और हर छोटा विवाद यदि ऐसा लगता है कि यह सेवा शर्तों को छू रहा है तो शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारियों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए। मध्यस्थता, शिक्षा प्रदान करना नहीं, शैक्षिक संस्थानों का व्यवसाय बन जाएगा। यह खंड हमारी राय में इसके अनुप्रयोग में बुरा है

अल्पसंख्यक। परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि एस के प्रावधान। 33 ए, एस। 40 , एस के उपखंड (1) (बी) और (2) (बी)। 51 ए और एस। 52 ए संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन है और इसलिए, वे धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं हो सकते हैं।

बी. ई. जी., जे. हमारे द्वारा उत्तर दिए जाने वाले दो प्रश्न हैं:

(1) क्या संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का प्रभाव

हमारे समक्ष अधिनियम के किसी भी प्रावधान पर, या इसके विपरीत, चाहे अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर अधिनियम के किसी भी प्रावधान का प्रभाव। 30 (1) क्या इन प्रावधानों को अमान्य करने के लिए ऐसा है?

(2) क्या अनुच्छेद 30 द्वारा गारंटीकृत अधिकार किसी भी तरह से अनुच्छेद 29 द्वारा सीमित हैं?

दूसरे प्रश्न पर, मेरे प्रभु मुख्य न्यायाधीश की ओर से जो कुछ गिर गया है, उसमें मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इस विचार के साथ

कि यद्यपि, जहां तक अल्पसंख्यकों के कुछ अधिकारों का संबंध है, अनुच्छेद 29 और 30 एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं, फिर भी संविधान का अनुच्छेद 29 किसी भी तरह से शिक्षा के प्रकार या चरित्र पर कोई सीमा नहीं लगाता है जिसे अल्पसंख्यक प्रदान करने का विकल्प चुन सकते हैं।

अपने संस्थान के माध्यम से अपने स्वयं के सदस्यों के बच्चों या अन्य लोगों के लिए जो अपने बच्चों को इसके स्कूलों में भेजने का विकल्प चुन सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इसे सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। हालांकि, मैं यह बताना चाहूंगा कि चूंकि अधिकार और कर्तव्य समान रूप से निहित हैं, इसलिए यह अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों के इस व्यापक अधिकार की सीमा से मिलता है। 30 (1) उन लोगों को भी सामान्य या गैर-सांप्रदायिक प्रतिभूति शिक्षा प्रदान करने के लिए जो अपनी संस्कृति का पालन नहीं कर सकते हैं या अपनी मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, कि जब कोई अल्पसंख्यक संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा के इस व्यापक शैक्षिक क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लेता है, तो इस स्वतंत्र विकल्प के कारण, कम से कम जब भी वह विकल्प वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, तो देश में ऐसी शिक्षा के सामान्य पैटर्न की जरूरतों का पालन करने का विकल्प चुना जा सकता है। अपनी शिक्षा को एक धर्मनिरपेक्ष अभिविन्यास या चरित्र देने के उद्देश्य से शिक्षा प्रदान करने के लिए इसके विकल्प में अनिवार्य रूप से "धर्मनिरपेक्ष" शिक्षा एसटी के बारे में राज्य द्वारा की गई पसंद की अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए इसकी सहमति आवश्यक है।

जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है या हमारे संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को बढ़ाता है, और इसे देने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि इस तरह का चुनाव करना अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हिस्सा है, तो यह उसके दायित्वों का भी हिस्सा होना चाहिए, जो आवश्यक रूप से पसंद से पालन करते हैं, सामान्य पैटर्न का पालन करने के लिए। इस तरह के विकल्प का तार्किक आधार यह है कि विशेष अल्पसंख्यक संस्थान, जो इस तरह की सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने का विकल्प चुनते हैं, स्वतंत्रता की उस उच्च श्रेणी को पसंद करते हैं, जहां कवि रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार, "संकीर्ण घरेलू दीवारें" जो राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच बाधाओं का निर्माण करती हैं, गिरती और गिरती हैं। यह द्वारा किए गए विकल्प को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है

राज्य जिस तरह की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा चाहता है या जिस तरह से चाहता है

जिसे दिया जाना चाहिए। लेकिन, उस स्थिति में, क्या उसे राज्य द्वारा मान्यता के लाभों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए? राज्य बाध्य है

अल्पसंख्यक संस्थान की पसंद की अनुमति और सुरक्षा के लिए जो कुछ भी हो

यह हो सकता है। लेकिन, क्या इसे एक अलग उपचार देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? जो इस तरह का विकल्प चुनने वाले अन्य संस्थानों को दिया गया है?

पहले और अधिक जटिल प्रश्न की ओर मुड़ते हुए, मुझे लगता है कि यह है

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तर्क का जवाब देना मुश्किल है,

गुजरात राज्य की ओर से उपस्थित होते हुए, कि, जहाँ एक अल्पसंख्यक

संस्थान ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसके तहत संबद्धता का विकल्प चुना है

एक कानून की शर्तों के रूप में, यह माना जाना चाहिए कि इसे छोड़ने के लिए चुना गया है

संबद्धता के परिणामस्वरूप होने वाले लाभों के लिए मूल्य, कुछ का अभ्यास

ऐसे अधिकार जो एक अन्य संदर्भ में अनुचित प्रतीत हो सकते हैं इसके मौलिक अधिकारों की जोड़ी।

यह सच है कि, यदि किसी अधिनियम का उद्देश्य किसी अल्पसंख्यक को मजबूर करना है

संस्थान, यहां तक कि अप्रत्यक्ष रूप से भी, अपने मौलिक अभ्यास को छोड़ देता है अधिकार, जिन प्रावधानों का यह प्रभाव है वे शून्य या निष्क्रिय होंगे

अल्पसंख्यक संस्थान के खिलाफ। संबद्धता की कीमत एक नहीं हो सकती है अल्पसंख्यक को स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार का पूर्ण परित्याग

कला द्वारा प्रदत्त संस्थान। 30 (1) संविधान से। यह पहलू

उनके आवश्यक परिणाम या प्रभाव। मैं यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि वह दृष्टिकोण जो इस न्यायालय ने जब भी इस तरह के प्रश्न किए हैं

कानून के प्रावधानों के प्रभाव पर इसके समक्ष उत्पन्न हुए हैं, हालांकि

सैद्धांतिक और तार्किक रूप से शायद हमेशा प्रो पर काफी सुसंगत नहीं होता है।

पद स्वीकार किए जाते हैं, परिणाम को संतुलन पर छोड़ने का गुण होता है

विशेष प्रावधान पर किए जाने वाले परस्पर विरोधी विचारों का

प्रत्येक मामले में शामिल तर्क और तथ्य।

जब हम या तो समग्र रूप से अधिनियम या विवादित पक्ष की जांच करते हैं

हमारे सामने अधिनियम के दर्शन, हम किसी भी का कोई उल्लेख नहीं पाते हैं ऐसी चीज जो किसी अल्पसंख्यक या उसके शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ निर्देशित हो

टिक्स। गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 के विवादित प्रावधान

(इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) हैं: धारा 20 (खंड XXXIX)

गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 में शामिल किया गया, जैसा कि

गुजरात विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972; धारा 33ए में जोड़ा गया गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949, गुजरात विश्वविद्यालय सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर. द्वारा संशोधित।

276

सिटी (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1973 का गुजरात अधिनियम संख्या 6); गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम 1949 की धारा 40 और 41,

गुजरात विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 (गुजरात अधिनियम सं. 6)

1973) ; गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम में धारा 51ए और 52ए अंत:स्थापित की गई।

1949 , गुजरात विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधित, 1972 , (1973 का गुजरात अधिनियम सं. 6)। यदि हम इस तर्क को स्वीकार करते हैं कि जिन संशोधनों पर हमला किया गया है, उन्हें लागू करने से पहले राज्य का कानून

याचिकाकर्ता को इस तथ्य से अवगत माना जाना चाहिए कि याचिका

हमारे सामने अल्पसंख्यक संस्थान अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज है।

अल्पसंख्यक संस्थान ने संबद्धता के लिए आवेदन करके अपनी पसंद का प्रयोग किया अधिनियम के प्रावधानों के तहत, इससे पहले कोई संशोधन नहीं किया गया था।

दूसरी ओर, यह तर्क दिया जा सकता है कि, जहां एक वैधानिक अधिकार है यदि किसी भी पक्ष द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है, तो यह माना जाना चाहिए कि उसने इसे इस शर्त के अधीन चुना है कि विधानमंडल किसी भी समय अपने कार्यकाल को बदल सकता है। लेकिन, क्या यह माना जा सकता है कि उसने भविष्य के किसी भी और हर संशोधन को स्वीकार करने का विकल्प चुना है? शायद यह आरोपित के सिद्धांत को ले जाएगा

ज्ञान और सहमति यह कहने के लिए बहुत दूर है कि एक अल्पसंख्यक संस्थान चुनता है

एक वैधानिक अधिकार के लिए एक रिक्त पर हस्ताक्षर किए हुए माना जाना चाहिए

किसी भी और किसी भी संभावित संशोधन के लिए सहमति देने के लिए चेक

भविष्य में उसके द्वारा अपनी पसंद की कीमत के रूप में जो भी भुगतान किया जाए। जो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए किसी की सहमति नहीं मानी जा सकती थी।

एक सशर्त ताकि इसे संस्थान द्वारा हटाया जा सके जब भी इसे हटाने की कीमत चुकाने के लिए तैयार किया जाता है

कुछ ऐसे लाभों को छोड़ना जो इसके मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं हैं। इस तरह के सशर्त प्रतिबंध को केवल एक अनुमेय नियामक प्रतिबंध के रूप में माना जा सकता है।

पहला प्रावधान जिसका अहमदाबाद पर बाध्यकारी प्रभाव पड़ता है

सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसायटी सेक है। 5 (1) अधिनियम के बारे में जो कहता है:

" 5 (1) : इसके भीतर कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है।

विश्वविद्यालय क्षेत्र राज्य की मंजूरी के साथ बचेगा।

सरकार कानून द्वारा स्थापित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय के साथ किसी भी तरह से संबद्ध हो या उसके किसी भी विशेषाधिकार में प्रवेश ले।

चूंकि सेंट जेवियर्स कॉलेज स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर स्थित है, इसलिए इसे कानून द्वारा स्थापित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने से रोक दिया गया है। यह, मेरी राय में, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता के लिए एक मूल्य के रूप में संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रभाव होगा क्योंकि इसे सरकार की मंजूरी के बिना किसी अन्य विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध करने की अनुमति नहीं है। याचिकाकर्ता ने नहीं किया है,

हालाँकि, याचिका द्वारा मांगी गई राहतों में, यह घोषणा करने के लिए कहा गया कि धारा 5 अमान्य है। लेकिन, सेक का बाध्यकारी प्रभाव। 5 याचिकाकर्ता की ओर से श्री नानावती द्वारा दी गई दलीलों में से एक थी। राज्य की ओर से बहस करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने व्यावहारिक रूप से स्वीकार किया था कि सेक। 5 याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम अमान्य होगा। हालाँकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर हम इसे राज्य सरकार पर एक दायित्व थोपने के रूप में व्याख्या कर सकते हैं तो इसे बचा लिया जाएगा। प्रत्येक एसटी में इसकी मंजूरी देना।

जेवियर कॉलेज वी. गुजरात (बेग। जे.)

277

मामला जहाँ एक अल्पसंख्यक संस्थान दूसरे के साथ संबद्धता के लिए आवेदन करता है

विश्वविद्यालय। चूंकि अधिनियम की धारा 5 का बाध्यकारी प्रभाव पड़ता है

याचिका दायर करने वाले कॉलेज को इससे बाहर रहने के विकल्प से इनकार करके

कानून पूरी तरह से, यह, मेरी राय में, इसके खिलाफ निष्क्रिय होगा।

हालाँकि, धारा 41 (1) और भी अधिक सीधे तौर पर याचिका पर काम करती है।

टियॉनिंग कॉलेज, जिसे "के विशेषाधिकारों में प्रवेश दिया गया था

विश्वविद्यालय "संबद्धता द्वारा धारा 5 (3) के तहत। यह प्रावधान होगा

इसे स्वचालित रूप से एक घटक इकाई बनाने का सम्मोहक प्रभाव है

विश्वविद्यालय का, और इसलिए, इसके खिलाफ निष्क्रिय माना जाना चाहिए

याचिका दायर करने वाला कॉलेज क्योंकि यह कला द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है। 30 (1) संविधान से। सेक के प्रावधान। 40

और धारा के शेष प्रावधान। 41 अधिनियम के सभी भाग हैं

वही बाध्यकारी योजना या तंत्र जो कला द्वारा प्रभावित है। 30 (1) .

यदि हम मानते हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि हमें प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए

कला. 30 (1) संविधान में कहा गया है कि "शब्द घटक होंगे।

विश्वविद्यालय का महाविद्यालय ", सेक में उपयोग किया जाता है। 41 (1) अधिनियम का केवल अर्थ है

कि, जहाँ तक याचिका दायर करने वाले कॉलेज का संबंध है, यह विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज बन सकता है, इसके तहत एक अधिसूचना के बाद भी

सेक. 40 (2) अधिनियम का, कानून, समग्र रूप से पढ़ा जाता है, इससे पहले रखता है

कॉलेज को निम्नलिखित चार विकल्पों के लिए याचिका दायर करना:

(1) विश्वविद्यालय की एक घटक इकाई बनना।

(2) नई शर्तों पर एक संबद्ध कॉलेज के रूप में जारी रखना

धारा 20 में निहित संशोधित प्रावधानों में मृत्यु हो गई,

33 अधिनियम के ए, 51 ए और 52 ए।

(3) संबद्धता वापस लेने के परिणाम का सामना करने के लिए

इसकी संबद्धता, या, दूसरे शब्दों में, क़ानून के बाहर कदम रखना कुल मिलाकर।

(4) सेक के तहत एक "स्वायत्त" कॉलेज का दर्जा प्राप्त करना।

38 अधिनियम का बी जिसके लिए याचिका दायर करने वाले कॉलेज के पास है

तैयार लागू किया।

इस प्रकार विकल्पों की सीमा व्यापक है। एक अल्पसंख्यक को अपनी पसंद का कोई भी विकल्प चुनने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। उसे यह जानने के लिए प्रत्येक विकल्प की कीमत चुकानी पड़ती है कि इसमें क्या शामिल है।

यदि कानून के प्रावधानों का संयुक्त प्रभाव यह है कि चार परिवर्तन

"संबद्धता" को लागू करने के अपने प्रारंभिक विकल्प के कारण कॉलेज के लिए देशी पाठ्यक्रम खुले हैं, जो कि कड़ाई से कहने पर, केवल एक वैधानिक है और एक मौलिक अधिकार नहीं है, कला के तहत इसके अधिकार हो सकते हैं। 30 (1) संविधान का उल्लंघन तब तक कहा जाना चाहिए जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि स्वायत्तता के लिए उसका आवेदन अस्वीकार

किया गया है या अस्वीकार किया जाना तय है? महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का एक घटक हिस्सा बनने के लिए मजबूर करना कानून के बल पर इसकी अलग पहचान को छीनने के बराबर है। लेकिन, अगर कॉलेज ने वास्तव में संगठन और उत्कृष्ट बाड़ के ऐसे मानकों को प्राप्त किया है जैसा कि वह दावा करता है, तो इसे एक स्वायत्त दर्जा मिल सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर.

अधिनियम की धारा 38 बी के तहत इसके सभी लाभों और स्वतंत्रताओं के साथ

व्यावहारिक रूप से पूछने के लिए। क्या इन परिस्थितियों में ऐसा कहा जा सकता है? कि महाविद्यालय की पहचान का नुकसान एक आवश्यक परिणाम है

हमारे सामने क़ानून के प्रावधान? पहचान के साथ कोई अन्य क़ानून नहीं

किसी भी मामले में समान प्रावधानों और प्रभाव की व्याख्या की गई थी जो

अब तक इस अदालत में आया है।

यदि याचिका दायर करने वाला कॉलेज, जिसने एक की स्थिति के लिए आवेदन किया है

अधिनियम की धारा 38 बी के तहत स्वायत्त महाविद्यालय 1972 , संशोधित प्रावधान द्वारा बचने का एक मार्ग प्रदान किया गया है

स्वयं मानते हैं, प्रभाव पर विचार करना काफी अनावश्यक लगता है

सेक. 20 , सेक. 33 ए और सेक। 51 अधिनियम का ए और 52 ए।

जो 1972 के अधिनियम द्वारा मौलिक आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कला द्वारा संरक्षित अधिकार। 30. धारा 20 में कोई कार्य निर्धारित नहीं है।

एक वाहन के संबंध में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद का गठन अध्याय के प्रावधानों द्वारा शासित नामांकित महाविद्यालय। अधिनियम का वी. आई. ए.

धारा 33 ए केवल उस "कॉलेज" पर भी लागू होती है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है।

सेक. के अधीन स्थायी समितियाँ। 38 सरकार के बजाय अधिनियम का सी अधिनियम की धारा 33 ए में उल्लिखित निकाय। फिर से, सेक। 51 ए.

और 52 ए केवल एक संबद्ध कॉलेज या मान्यता प्राप्त या अनुमोदित पर लागू होता है।

संस्थान "ताकि एक स्वायत्त महाविद्यालय, प्रो के तहत काम कर रहा हो

चैप के दर्शन। वी. आई. ए., उनके दायरे से बाहर है। केवल प्रावधान

जो अपने वर्तमान रूप में, याचिका दायर करने वाले कॉलेज के खिलाफ एक बाध्यकारी प्रभाव डाल सकता है। 5 और फिर धारा 40 और 41 वह अधिनियम जो स्वचालित रूप से संबद्ध कॉलेजों को संघ में परिवर्तित कर देगा

विश्वविद्यालय के स्थायी महाविद्यालय, एक के अंतर्वेशन के बिना

विकल्प, और इसलिए, याचिका दायर करने वाले कॉलेज को एक स्वायत्त कॉलेज बनने के अवसर से वंचित करने के लिए कहा जा सकता है। वास्तव में, सेक। 41 अधिनियम का, जैसा कि यह खड़ा है, अधिकारों को नकारने का प्रभाव हो सकता है

सेक द्वारा प्रदान किया गया। 38 अधिनियम का बी, यांत्रिक रूप से और

कानून के संचालन से, संबद्ध कॉलेजों को घटक कॉलेजों में विभाजित किया जाता है ताकि उसके बाद स्वायत्तता का कोई सवाल ही न उठे।

इसलिए, यदि हम अधिनियम की धारा 5,40 और 41 के संचालन को, जितना हम कर सकते हैं, अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा अन्य संस्थानों तक सीमित करते हैं, जिनके द्वारा संरक्षित

कला. 30 (1) क्योंकि वे याचिका दायर करने वाले कॉलेज को अपनी पहचान खोने के लिए मजबूर करेंगे, यह तत्काल आवश्यक नहीं हो सकता है

निधि पर किसी अन्य प्रावधान के प्रभाव पर विचार करने के लिए याचिकाकर्ता महाविद्यालय के मानसिक अधिकार। यह केवल तभी है जब याचिका दायर की जाए,

कॉलेज एक स्वायत्त कॉलेज बनने के अपने प्रयास में विफल रहता है कि धारा 20,33 ए, 51 ए और 52 ए के प्रभाव का प्रश्न उठ सकता है।

अधिनियम की धारा 5,40 और 41 ही एकमात्र ऐसी धाराएँ हैं जो इसके स्वायत्त संस्थान बनने के रास्ते में बाधा बन सकती हैं।

इसलिए, हमारे सामने मामले में इस पर विचार करना अनावश्यक लगता है

वर्तमान में याचिका दायर करने वाले महाविद्यालय के अधिकारों पर अधिनियम की धारा 5,40 और 41 के अलावा अन्य प्रावधानों का प्रभाव। इन प्रश्नों को यहाँ अपरिपक्व माना जा सकता है।

तथापि, यह मानते हुए कि हमें याचिका दायर करने के मौलिक अधिकारों पर धारा 20,33 ए, 51 ए, 52 ए के प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

कॉलेज के रूप में, कम से कम जब तक इसे एक स्वायत्त दर्जा नहीं मिल जाता है, तब तक उनके द्वारा शासित किया जाता है और यदि वे वैध हैं, तो एसटी के बारे में सवाल उठते हैं।

XAVIERS कॉलेज v. गुजरात (बेग. जे.)

279

अनुच्छेद द्वारा याचिका दायर करने वाले कॉलेज को प्रदान किए गए अधिकारों पर अनुमेय विनियमन या प्रतिबंध का स्रोत या आधार और सीमा। 30 (1) संविधान से। एक अल्पसंख्यक संस्थान की ओर से पेश होने वाले प्रत्येक विद्वान वकील ने स्वीकार किया है कि, कला के तहत अधिकारों की शर्तों की "निरपेक्षता" के बावजूद। 30 (1) व्यक्त किया जा सकता है, राज्य में उनके अभ्यास को विनियमित करने की शक्ति है। इस न्यायालय ने बार-बार कला के तहत अधिकारों के विनियमन की वैधता को भी मान्यता दी है। 30 विनियमित करने की ऐसी शक्ति के वास्तविक आधार को स्पष्ट रूप से बताए बिना विभिन्न आधारों पर। मैं यह सोचने का साहस करता हूं कि क्या हम कला में निहित मौलिक अधिकारों पर विनियमन या प्रतिबंध की शक्ति का सटीक आधार या स्रोत तैयार करने में सक्षम हैं। 30 (1) संविधान में हम कम अनिश्चितता और अधिक सटीकता और निश्चितता के साथ यह निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि राज्य किस हद तक अनुच्छेद द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों को विनियमित या संशोधित कर सकता है। 30 (1) संविधान से।

बहुत शर्तों के लिए राज्य द्वारा प्रावधान और विनियमन

जो अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें मंत्री बनाने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जाहिर है, अपरिहार्य और गैर-जरूरी है।

अस्वीकार करने योग्य। इस प्रकार, जब तक कि राज्य एक के भीतर अराजकता को दंडित नहीं कर सकता

इसके न्यासियों द्वारा धन की संस्था या दुरुपयोग या दुरुपयोग को रोकना।

एक प्रबंध निकाय द्वारा शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों पर अपनी शक्तियों का

किसी शैक्षणिक संस्थान का, चाहे वह संस्थान अल्पसंख्यक हो या

एक बहुसंख्यक संस्था, न ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति न ही संस्थान का उचित और प्रभावी प्रशासन होगा

संभव है। दूसरे शब्दों में, कुछ शक्ति का अस्तित्व

इस्टा के अधिकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्तें या पूर्व-आवश्यकताएं

एक स्वस्थ स्थिति में एक संस्था को स्वयं को प्रसन्न करना और प्रशासित करना अंतर्निहित है संगठित समाज का अस्तित्व जिसका प्रतिनिधित्व राज्य करता है।

संगठित समाज की स्थितियों को बनाए रखने के लिए बनाए गए कानून

और सभ्य अस्तित्व, ताकि मौलिक सहित सभी के अधिकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखा जा सकता है और लागू किया जा सकता है

केवल निहितार्थ पर। कला के विशिष्ट प्रावधान। 245 254 पढ़ने के लिए

संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन विधायी सूचियों के साथ

यह राज्य विधानमंडलों को कई विधायी शक्तियां प्रदान करता है और

विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए संसद अल्पसंख्यक संस्थान। कला में कोई संदेह नहीं है। 30 (1) , अन्य बुनियादी बातों की तरह

संवैधानिक अधिकार, सामान्य विधायी के दायरे को सीमित करने के लिए है

शक्ति। लेकिन, राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि यह केवल एक " कानून जो भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या कम करता है

संविधान, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल हैं, जो

"शून्य" है और वह भी केवल "उल्लंघन की सीमा तक"। इस प्रकार,

एक के अभ्यास पर केवल एक आकस्मिक विनियमन या प्रतिबंध

मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने और वास्तव में इसे और अधिक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से

मौलिक अधिकार को हटाना या छीनना या प्राप्त करना उस प्रभाव को। जब इस तरह के कानून का विश्लेषण किया जाएगा, तो यह पाया जाएगा कि इसका उद्देश्य कुछ लोगों को लक्षित करना है।

एक अल्पसंख्यक के मौलिक के संक्षिप्त होने से काफी अलग बात है

कला के तहत अधिकार। 30 (1) संविधान से। यह वास्तव में नहीं लेगा

मौलिक अधिकारों को दूर करना या उन्हें कम करना, भले ही यह उनके अधिकारों को विनियमित करता हो।

व्यायाम करें। यदि, दूसरी ओर, एक कानून अनिवार्य रूप से बाध्यकारी है मौलिक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1975] 1 एस. सी. आर. को पर्याप्त रूप से संक्षिप्त करने या हटाने का प्रभाव।

- 280

यह ऐसा नहीं कहता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उस प्रभाव को उत्पन्न करता है। उद्देश्यों के लिए कला को लागू करना। 13 (2) संविधान के बारे में हमें देखना होगा

उन्हें। इस तरह मैं रे में बहुमत के दृष्टिकोण को समझता हूं। केरल एडु राशन विधेयक, 1957। (11)

कला द्वारा गारंटीकृत अधिकार का सार। 30 (1) कमियों में से

अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा उनकी पसंद का एक स्वतंत्र अभ्यास है शिक्षा के साथ-साथ उनके प्रशासन का स्वरूप

शैक्षणिक संस्थान। इन दोनों को एक साथ लेते हुए यह निर्धारित किया जाता है कि

एक शैक्षणिक संस्थान का प्रकार या चरित्र जो एक अल्पसंख्यक के पास है चुनने का अधिकार। जहाँ इन प्रतिमानों को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है

स्वयं एक अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा, भले ही उद्देश्य हो सकता है

उनकी स्वीकृति से अपने लिए कुछ लाभ सुरक्षित करें, पुनः

इन प्रतिरूपों का निरीक्षण करने की आवश्यकता वास्तविक उल्लंघन नहीं होगी।

कला द्वारा संरक्षित अधिकार। 30 (1) . वास्तव में, स्वीकृति हो सकती है

जिसे चुनने के अधिकार के दावे के रूप में अधिक उचित रूप से देखा जाए

कला द्वारा संरक्षित अधिकार के "मूल" के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 30 (1) .

एक ऐसे मामले में जिसमें अल्पसङ्ख्यक द्वारा स्वेच्छा से पैटर्न स्वीकार किया जाता है

प्रदत्त लाभों का लाभ उठाने की दृष्टि से संस्था

एक कानून द्वारा, मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से जोर नहीं दे सकता है

प्रशासन के अधिकार का मुक्त प्रयोग। यहाँ, आकस्मिक

संस्थान के प्रबंधन के अधिकार पर बंधन, जो केवल एक हिस्सा है

मौलिक अधिकार, के एक अभ्यास के परिणाम होंगे

अधिकार का सार या सार जो, जैसा कि मैं इसे देखता हूं, स्वतंत्रता है

चयन करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कला द्वारा संरक्षित अधिकार। 30 (1) निर्धारित किए जाते हैं

व्यक्त प्रतिबंधों के प्रकार के बिना "निरपेक्ष" शब्दों में पाया गया

संस्थान के पास वैधानिक प्रतिबंध से बचने का विकल्प खुला है। कुल मिलाकर, यदि यह इसके साथ, एक वैधानिक के लाभों को छोड़ देता है

ठीक है, मैं यह देखने में विफल हूं कि कला के तहत अधिकार की निरपेक्षता कैसे है। 30 (1) संविधान को हटा दिया जाता है या संक्षिप्त कर दिया जाता है। बस इतना ही होता है

कि कानून इसके प्रदान करने के लिए सामान्य ब्याज में एक कीमत तय करता है

लाभ होता है। इसे मुक्त करने के लिए संबंधित अल्पसंख्यक संस्थान खुला है। किसी भी वैधानिक नियंत्रण या बंधनों से स्वयं को यदि उनसे स्वतंत्रता है

इसे कला के तहत अपने मौलिक अधिकारों के पूर्ण प्रयोग के लिए आवश्यक माना जाता है। 30 (1) संविधान से। इस अनुच्छेद का उद्देश्य अपने द्वारा संरक्षित कुछ अधिकारों के हनन के खिलाफ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की ढाल के रूप में काम करना था और इसे मौलिक घोषित किया गया था।

कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, उनके द्वारा इसे अनुचित या भेदभावपूर्ण हथियार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है

अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए उपचार ताकि लाभ प्राप्त किए जा सकें लेकिन वैधानिक अधिकारों के दायित्वों को अस्वीकार किया जा सके। यह केवल तभी होता है जब क़ानून की शर्तें

अनिवार्य रूप से एक अल्पसंख्यक संस्थान को कला के तहत अपने मौलिक अधिकारों के मूल को छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं। 30 (1) कि यह कला के अर्थ के भीतर एक मौलिक अधिकार को छीनने या संक्षिप्त करने के बराबर हो सकता है। 13 (2) संविधान से। तभी यह सिद्धांत लागू हो सकता है कि जो सीधे नहीं किया जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष तरीकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। के प्रति मेरा दृष्टिकोण बताते हुए

(1) [1959] एस सी आर 995।

ए.

कला की व्याख्या। 30 (1) संविधान के बारे में, मैं अब आगे बढ़ता हूँ

विवादित प्रावधानों पर इस अनुच्छेद के प्रभाव पर विचार करें।

मुझे ऐसा लगता है कि सेक। 20 अधिनियम, जो संबंधित है

गुजरात विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की शक्तियाँ,

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कला के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकारों को छूता है।

30 (1) संविधान का केवल इसलिए कि कार्यकारी परिषद

बी.

ऐसे निर्णय लें जिनका प्रभाव पड़ सकता है। वास्तव में, अगर कला। 30 (1)

कार्यकारी परिषद की शक्तियों पर भी एक बंधन के रूप में कार्य करता है,

परिषद धारा के तहत ऐसे निर्णय लेने के लिए शक्तिहीन है। 20 में से

ऐसा अधिनियम जो मौलिक अधिकारों को छीनता है या उनका हनन करता है ताकि उन्हें निरस्त किया जा सके

कला द्वारा। 13. किसी भी मामले में, यह केवल तभी होता है जब विशिष्ट निर्णय और कार्य किए जाते हैं

कहा जाता है कि इस प्रभाव को न्यायालयों के समक्ष लाया जाता है कि उनका अधिकार

€ सी, सेक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कथित प्रयोग में। 20 में से

अधिनियम, निर्धारित किया जा सकता है क्योंकि धारा स्वयं एक सामान्य देता है

शक्ति विशेष रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों के खिलाफ निर्देशित नहीं है।

सेक. 33 अधिनियम के ए में एक सामान्य पैटर्न के पालन की आवश्यकता है

एक संबद्ध के शासी निकाय के गठन के संबंध में

कॉलेज चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक संस्थान यह। कुलपतियों के प्रतिनिधियों की मात्र उपस्थिति

डी.

लॉर, शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सदस्य, और

महाविद्यालय के छात्र प्रशासकों के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे

टेर। मेरी राय में, इस तरह के "छिड़काव" से मदद मिलने की अधिक संभावना है

उस प्रशासन को अधिक प्रभावी और सभी के लिए स्वीकार्य बनाना।

इससे प्रभावित होते हैं। एक अल्पसंख्यक संस्थान के पास अभी भी अपना माजो हो सकता है।

शासी निकाय पर दया। और, हम यहाँ चिंतित नहीं हैं।

इस तरह के प्रावधान के ज्ञान या हमारे लिए स्वीकार्यता के साथ। हम.

ई.

केवल यह तय करना है, मुझे लगता है, यह पदार्थ को कैसे प्रभावित करता है

कला द्वारा प्रदत्त अधिकार। 30 (1) संविधान से।

अधिनियम की धारा 51 ए मुझे उन सभी कॉलेजों के कर्मचारियों की बर्खास्तगी, निष्कासन, रैंक में कमी और सेवाओं की समाप्ति के लिए सामान्य शर्तें निर्धारित करती प्रतीत होती है जिन पर यह लागू होती है। एफ पुनः, हमें यहाँ ज्ञान या अज्ञानता पर विचार नहीं करना है।

ऐसे प्रावधान या धारा के किसी भाग की वैधता। 51 अधिनियम का ए इस आधार पर कि यह कला द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अलावा किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। 30 (1) संविधान से। यदि, जैसा कि मैंने ऊपर संकेत दिया है, किसी संस्थान के प्रशासन या प्रबंधन के अधिकार में अधिक मात्रा में हस्तक्षेप को किसी कानून द्वारा शासित संस्थान के लिए अल्पसंख्यक के विकल्प के प्रयोग के तार्किक परिणाम के रूप में अनुमत माना जा सकता है, जिसके सभी लाभ और नुकसान हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि धारा के प्रावधान। 51 ए अनुच्छेद द्वारा संरक्षित अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकारों के सार पर अनुचित अतिक्रमण का गठन नहीं करता है। 30 (1) संविधान जिसमें चयन की स्वतंत्रता शामिल है। इसी तरह के कारणों से, मुझे नहीं लगता कि सेक। 52 अधिनियम का ए अनुच्छेद के तहत विशेष अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन है। 30 (1) संविधान का

जी.

एच.

जब संस्था एक सांविधिक अधिकार का विकल्प चुनती है जो आवश्यक रूप से सांविधिक प्रतिबंधों को कम करता है। बेशक, अगर इन प्रावधानों को सभी संबद्ध कॉलेजों के खिलाफ किसी भी आधार पर अमान्य माना जा सकता है, [1975] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

282

चाहे वे किसी राज्य में अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रशासित हों,

उन्हें उन आधारों पर याचिका दायर करने वाले कॉलेज के खिलाफ भी अमान्य माना जा सकता है। लेकिन, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, हम यहां ऐसे आधारों या प्रश्नों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हैं।

रे में। केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (ऊपर), यह न्यायालय

इस तर्क को खारिज कर दिया कि अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने संस्थानों के प्रबंधन में सभी नियंत्रणों से मुक्त होने का पूर्ण अधिकार है। अधिकांश विद्वान न्यायाधीशों ने निर्णय लिया (पी। 1062):

" प्रशासन के अधिकार में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हो सकता है

कुशासन का अधिकार। अल्पसंख्यक निश्चित रूप से नहीं पूछ सकते हैं। द्वारा संचालित किसी शैक्षणिक संस्थान के लिए सहायता या मान्यता के लिए

उन्हें अस्वस्थ परिवेश में, बिना किसी सक्षम के

योग्यता की कोई भी झलक रखने वाले शिक्षक, और

जो शिक्षण के उचित मानक को भी बनाए नहीं रखता है

या जो कल्याण के विनाशकारी मामलों को सिखाता है

विद्वानों। यह तर्क के लिए खड़ा है, तो संवैधानिक

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने का अधिकार आवश्यक रूप से राज्य के दावे के खिलाफ विद्रोह नहीं करता है

इस बात पर जोर देना कि सहायता प्रदान करने के लिए राज्य निर्धारित कर सकता है

इन की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए उचित नियम

सहायता करने के लिए शीर्षक। विद्वान अटॉर्नी-जनरल ने स्वीकार किया

कि उचित नियम निश्चित रूप से लागू किए जा सकते हैं

द्वारा

सहायता के लिए या यहाँ तक कि मान्यता के लिए एक शर्त के रूप में राज्य "।

वहाँ शिक्षा का कार्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया था (पृष्ठ पर)

1019) :

" हमारी सबसे प्यारी वस्तुओं में से एक। संविधान

इस प्रकार यह अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा। कुछ भी नहीं।

लोगों में विचार और अभिव्यक्ति को उत्तेजित और उत्तेजित करता है

शिक्षा से अधिक। यह शिक्षा ही है जो हमें स्पष्ट करती है

विश्वास और विश्वास और हमारी पूजा की भावना को मजबूत करने में मदद करता है।

धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अच्छे कार्यों पर विचार कर सकता है या

पूजा के सर्वोत्तम रूप के रूप में अपने नैतिक दायित्वों और कर्तव्यों का गठन। पूजा के योग्य क्या है, इस बारे में लोगों की राय भिन्न हो सकती है। लेकिन, मतभेद के लिए बहुत कम जगह है जब यह कहा जाता है कि राज्य जिस भावना को बढ़ावा देने के लिए बाध्य है, वह हमारे संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित आदर्शों की खोज और पूजा है।

कला की व्याख्या करना। 30 संविधान के बारे में दास, सी. जे. ने कहा (ibid -

पी पर। 1053) :

" सही अर्थ को समझने की कुंजी

और विचाराधीन अनुच्छेद के निहितार्थ हैं

अपनी पसंद के शब्द '। ऐसा कहा जाता है कि प्रमुख शब्द पसंद है और उस लेख की सामग्री उतनी ही व्यापक है

विशेष अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद के रूप में हो सकता है इसे बनाएँ। कला द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दायरा। 30 (1)

इसलिए, एसटी के विचार पर निर्धारित किया जाना है।

जेवियर कॉलेज वी. गुजरात (बेग। जे.)

283

शैक्षणिक संस्थान के दृष्टिकोण से मामला

ए.

स्वयं को "।

उन्होंने यह भी कहा (आईबीआईडी एट पी। 1052):

" कला का वास्तविक महत्व। 29 (2) और कला। 30 (1) हमें ऐसा लगता है कि वे स्पष्ट रूप से एक अल्पसंख्यक संस्थान पर विचार कर रहे हैं

इसमें बाहरी लोगों के छिड़काव के साथ प्रवेश किया गया। के द्वारा

बी.

किसी गैर-सदस्य को इसमें शामिल करने से अल्पसंख्यक संस्थान अपना चरित्र नहीं छोड़ता है और अल्पसंख्यक संस्थान बनना बंद कर देता है।

यह "।

मेरे विचार से केरल शिक्षा विधेयक में बहुमत की राय है।

मामला (ऊपर) केवल कुछ सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करता है। यह असंवैधानिक और अमान्य होने से अधिक कुछ भी घोषित नहीं करता है जिसका एक सम्मोहक प्रभाव है ताकि व्यावहारिक रूप से कोई विकल्प न रह जाए।

सी.

प्रस्तुत करने को छोड़कर अल्पसंख्यक संस्थान

इससे पहले

ए

खोलें।

भुगतान की जाने वाली कीमत के रूप में नियम

वैधानिक

को इसका

अस्तित्व

जैसे-जैसे

शैक्षणिक

संस्थान।

अ.

यह उस मामले से नहीं निपटता था जिसमें एक अल्पसंख्यक संस्थान

कानून की शर्तों के तहत, उसके द्वारा प्राप्त दक्षता और उत्कृष्टता की स्थिति के आधार पर, कम या ज्यादा स्वायत्तता चुनने का विकल्प था, जैसा कि हमारे सामने कानून में स्थिति है। वहाँ व्यक्त किए गए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों का विचार था कि राज्य द्वारा मान्यता अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं थी। 30 (1) संविधान की, और यह भी कि राज्य द्वारा ऐसी मान्यता के लिए इसके लिए कीमत का भुगतान करना पड़ सकता है। बहुमत और अल्पसंख्यकों के विचार केवल यथोचित रूप से भिन्न थे।

डी.

ई.

सहायता और मान्यता के लिए एक मूल्य के रूप में वैधानिक मजबूरी की अनुमेय राशि। यदि भुगतान की जाने वाली कीमत किसी मौलिक अधिकार के प्रयोग पर एक बंधन है, तो मौलिक अधिकार का सार या मूल विकल्प का प्रयोग है, जो उचित है या नहीं। स्वाभाविक रूप से, एक साथ विचार किए गए सभी प्रावधानों के कुल प्रभाव पर निर्भर होना चाहिए न कि बाकी प्रावधानों से अलग देखे जाने वाले विशेष प्रावधानों पर। और, मुझे यह सोचने का साहस करना चाहिए कि हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम इस तरह के प्रश्न पर विधायी निर्णय के लिए अपनी राय को हल्के में नहीं ले सकते हैं।

एफ.

मुझे बहुत सम्मान के साथ ऐसा लगता है कि, रेव. सिद्धराजभाई भाई और अन्य में। वी. बॉम्बे राज्य और ए. एन. आर. , (1) यह न्यायालय कुछ हद तक री में बहुमत के दृष्टिकोण से परे चला गया। केरल शिक्षा विधेयक मामला (ऊपर)

यह इंगित करने के बाद कि कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है जिस पर तर्कसंगतता है

जी.

या अन्यथा किसी विनियमन का परीक्षण किया जा सकता है जिसे उस मामले में न्यायालय द्वारा निर्धारित करने की मांग की गई थी। वहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी विनियमन को अनुच्छेद के तहत "केवल तभी अनुचित माना जाए जब वह पूरी तरह से अधिकार का विनाशकारी हो"। 30 (1) . यहाँ, वास्तव में जिस प्रश्न पर विचार किया गया वह यह था कि क्या मान्यता वापस लेने की धमकियाँ हैं।

और कॉलेज को दिए गए अनुदान का उपयोग अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को सरकार के नामांकित व्यक्तियों को प्रवेश देने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा सकता है। उसमें। द.

एच.

इस तरह के दंडात्मक तरीकों का उपयोग असंवैधानिक माना गया था। एक परीक्षण

(1) [1963] 3 एस. सी. आर. 837

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[19

75] 1 एस सी आर।

284

एक नियामक उपाय की वैधता का प्रस्ताव इस प्रकार किया गया था:

(पी पर। 857):

" इस तरह के विनियमन को एक दोहरी परीक्षा को संतुष्ट करना चाहिए -

तर्कसंगतता, और यह परीक्षण कि यह शिक्षा का नियामक है

संस्थान का राष्ट्रीय चरित्र और इसके लिए अनुकूल है

संस्थान को शिक्षा का एक प्रभावी साधन बनाना

अल्पसंख्यक समुदाय या अन्य व्यक्ति जो इसका सहारा लेते हैं।

हालाँकि, यह देखने के बाद इंगित किया गया था कि मौलिक

सीएल के तहत स्वतंत्रता। (1) कला की। 30 निरपेक्ष शब्दों में व्यक्त किया जाता है

(पी पर। 850):

" हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यह खुला नहीं है

इस अधिकार के प्रयोग पर विनियम लागू करने के लिए राज्य।

स्थापना और प्रशासन करने की मौलिक स्वतंत्रता है।

शैक्षणिक संस्थानः यह स्थापित करने और विज्ञापन करने का अधिकार है मंत्री वास्तव में शैक्षणिक संस्थान, संस्थान क्या हैं

राज्य, जो शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं

नागरिक, या उसके अनुभाग। सही में बनाया गया विनियमन शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य, सानी की दक्षता के हित

संस्कार, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और इस तरह के अन्य मुद्दे निस्संदेह हो सकते हैं।

थोपा जाता है। इस तरह के नियम प्रतिबंध नहीं हैं

अधिकार का सार जिसकी गारंटी दी गई हैः वे सुरक्षित करते हैं शैक्षणिक मामलों में संस्थान का उचित कार्य "।

इस प्रकार, यहाँ भी हानि के बीच एक अंतर किया गया था मौलिक अधिकार का सार और एक आकस्मिक अतिक्रमण

आवश्यक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन के अधिकार पर

अच्छी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य और कल्याण की स्थिति

किसी संस्थान में शिक्षा प्रदान करने से जुड़ा हुआ।

रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट एंड ओआरएस में। वी. बिहार राज्य और अन्य।, (1)

रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज का सामान्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार,

कला की आवश्यकताओं द्वारा सीमित नहीं। 29 (1) संविधान का कला की व्यापकता को देखते हुए इसे मान्यता दी गई थी। 30 (1) . इसमें कोई शक नहीं।

यहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रबंधकीय कार्यों के अधीन होने के लिए एक प्रावधान

एक वैधानिक की देखरेख के लिए कॉलेज के शासी निकाय का

विश्वविद्यालय सेवा आयोग असंवैधानिक था। हालांकि, यह

किसी प्रावधान के संदर्भ में निर्णय नहीं था, जैसे कि धारा। 38 बी का

हमारे समक्ष अधिनियम, जो याचिका दायर करने वाले कॉलेज को अधिकार प्रदान करता है

"सामान्य पर्यवेक्षण" से परे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण से काफी स्वतंत्र और मुक्त हो जाना। उस निर्णय का प्रभाव

सायन को, मेरी राय में, उस स्थिति तक सीमित होना चाहिए जो इस न्यायालय के समक्ष क़ानून की शर्तों पर विचार करने से उत्पन्न हुई है। उस अवसर पर व्याख्या।

आर टी में। रेव. बिशप एस. के. पात्रो और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य।, (2)

शिक्षा सचिव द्वारा सरकार को पारित एक आदेश। बिहार के,

एक तरफ रखते हुए, चर्च के अध्यक्ष और सचिव के चुनाव

मिशनरी सोसाइटी हायर सेकेंडरी स्कूल और संस्थान का निर्देशन सहमति से एक प्रबंध समिति के गठन के लिए कदम उठाने का प्रावधान

इसे भेजे गए आदेशों की शर्तों को चुनौती दी गई थी। कानूनी

(1) [1969] 2 एस. सी. आर. 73

(2)

[1970] 1 एस. सी. आर. 172, एसटी.

XAVIERS कॉलेज v. गुजरात (बेग. जे.)।

285

इस तरह के आदेश के लिए मंजूरी स्पष्ट नहीं थी। इसके बाद यह

ए.

इस न्यायालय द्वारा तय किए गए गंभीर मामले, पक्ष निर्धारित करें। सवाल के अलावा कि यह अनुच्छेद के तहत अधिकार के दायरे में एक मामला था। 30 (1) में से

संविधान, यह मुझे हल करने में सहायक नहीं लगता है

हमारे सामने मामले की कठिनाइयाँ।

केरल आदि राज्य में v. बहुत रेव. माँ प्रांतीय, आदि (1)

बी.

इस न्यायालय के पास कला के दायरे पर फिर से विचार करने का अवसर था। 30 (1) से

संविधान और केरल के प्रावधानों पर इसका प्रभाव

1969 का विश्वविद्यालय अधिनियम 9। यह बताया गया था कि कला। 30 (1) है।

सुरक्षा के दो अलग-अलग क्षेत्र प्रत्येक से समय के बिंदु पर अलग किए गए हैं।

अन्य: स्थापना के प्रारंभिक अधिकार से संबंधित पहला, और

दूसरा संस्थान के प्रशासन के अधिकार को अपनाना जो

स्थापित किया गया है। प्रशासन को प्रबंधन के बराबर माना जाता था।

एस.

संस्थान के मामलों के बारे में और यह देखा गया (पृष्ठ 740 पर):

" यह प्रबंध नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए ताकि

संस्थापक या उनके नामांकित व्यक्ति संस्थान को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं।

उचित सोचें, और उनके विचारों के अनुसार कि कैसे सामान्य रूप से समुदाय और संस्था में

विशेष रूप से सबसे अच्छा परोसा जाएगा। इस प्रबंधन का कोई हिस्सा नहीं

डी.

ले जाया जा सकता है और एक के बिना दूसरे शरीर में निहित किया जा सकता है

:

गारंटीकृत अधिकार पर अतिक्रमण "

इसके तुरंत बाद, हालांकि, एक पैराग्राफ का पालन किया गया, जिसके साथ

बहुत सम्मान, मुझे किसी के साथ पूरी तरह से सुलह करने में कुछ कठिनाई होती है

" संस्थान के प्रबंधन की पूर्ण स्वतंत्रता

नियंत्रण:

" हालाँकि, इसमें एक अपवाद है और यह है कि

ई.

शिक्षा के मानक प्रबंधन का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि

इस तरह। ये मानक राजनीतिक निकाय से संबंधित हैं और डीआईसी हैं। देश की प्रगति पर विचार

और उनके लोग। इसलिए, यदि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम स्थापित करते हैं

परीक्षणों का पालन किया जाना चाहिए, हालांकि इसके अधीन

विशेष विषय जिन्हें संस्थान पढ़ाना चाहते हैं, और कुछ हद तक राज्य शर्तों को भी विनियमित कर सकता है।

एफ.

शिक्षकों के रोजगार और स्कूल के स्वास्थ्य और स्वच्छता

डेंट। इस तरह के नियम सीधे प्रबंधन पर लागू नहीं होते हैं।

हालांकि वे अप्रत्यक्ष रूप से इसे प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी

शिक्षा, शैक्षणिक स्तर को विनियमित करने का राज्य का अधिकार दुर्भावनापूर्ण और संबद्ध मामलों से इनकार नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यक

संस्थानों को मानकों से नीचे आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

शैक्षणिक संस्थानों से अपेक्षित उत्कृष्टता, या

जी.

प्रबंधन के अनन्य अधिकार की आड़ में, पालन करने से इनकार करना

सामान्य पैटर्न। जबकि प्रबंधन को छोड़ दिया जाना चाहिए

उन्हें दूसरों के साथ कदम रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

जाहिर है, इसका मतलब यह था कि संस्थान के अनन्य प्रबंधन का अधिकार निर्धारित करने के अधिकार से अलग है

शिक्षा का स्वरूप और उसके मानक। यह समझा सकता है कि शिक्षा के "मानकों" को "प्रबंधन का हिस्सा नहीं" के रूप में क्यों कहा गया था। इसका मतलब था कि प्रबंधन का अधिकार, में प्रदान किया गया है

एच.

(1) [1971] 1 एस. सी. आर.-734

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1

975] 1 एस सी आर।

286

निरपेक्ष शर्तों, के साथ बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, हालांकि वस्तु उस प्रबंधन का निर्धारण एक सामान्य पैटर्न द्वारा किया जा सकता है

राज्य द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम और मानक निर्धारित कर सकता है

शिक्षा से। अपने लिए बोलते हुए, मुझे अलग होना बहुत मुश्किल लगता है

यह निर्धारित करने के अधिकार से शिक्षण के उद्देश्य और मानक कि कौन पढ़ाना चाहिए और उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके अलावा, यदि

"शिक्षा के मानक" प्रबंधन का हिस्सा नहीं हैं, यह मुश्किल है।

यह देखने के लिए कि वे कैसे स्वतंत्रता के सिद्धांत के अपवाद हैं

नियंत्रण से प्रबंधन। फिर से, अगर सीधे तौर पर जिसका उद्देश्य है वह है

इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव से अलग किया जाए, कार्यकाल की सुरक्षा

शिक्षकों और प्रावधानों का उद्देश्य निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करना है

उनके लिए किसी संस्थान के प्रबंधन द्वारा भी सलाह नहीं दी जाएगी

इसका उद्देश्य सीधे इसके प्रबंधन में हस्तक्षेप करना है। वे और अधिक कर सकते हैं।

उचित रूप से सुधार और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए के रूप में देखा जाए संस्थान में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या, और इसलिए, बढ़ाने के लिए

शिक्षा का सामान्य मानक। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए पर्याप्त है

इस मामले को इस आधार पर अलग करें कि प्रावधानों को अंतर किया जाए

हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए अलग हैं, हालांकि, अपने लिए बोलते हुए, मैं बाध्य महसूस करता हूं

बड़े सम्मान के साथ कहना कि मैं हर प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं

वहाँ सही बताया गया। उस मामले में, के प्रावधान

1969 का केरल विश्वविद्यालय अधिनियम 9, जिसे अपरिहार्य माना जाता था

उनका ऑपरेशन। जैसा कि मैं पहले ही देख चुका हूँ, हमारे सामने मामले में, सेक. 38 अधिनियम का बी हमारे सामने याचिका दायर करने वाले कॉलेज को एक प्रदान करता है

प्रोवी की मजबूरी से बचने का व्यावहारिक रूप से एक निश्चित तरीका अधिनियम की धारा 5,40 और 41 के अलावा अन्य यदि दावे किए जाते हैं -

उसकी ओर से सही हैं।

डी. ए. वी. कॉलेज, बठिंडा आदि में v. पंजाब राज्य और अन्य।, (1)

इस न्यायालय ने पंजाब सरकार की अधिसूचना के प्रभाव पर विचार किया। और पंजाबी विश्वविद्यालय की धारा 4 (2) और 5 की संवैधानिकता

1961 का सिटी एक्ट 35, जिसका परिणाम यह हुआ कि याचिका दायर करने वाला कर्नल

पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम 1947 के तहत गठित विश्वविद्यालय से संबद्ध होना बंद हो गया और अधिनियम के तहत एक अन्य विश्वविद्यालय, पंजाबी विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के लिए मजबूर हो गया।

1961 का। परिणाम यह हुआ कि यदि यह अनिवार्य संबद्धता थी

वैध, पंजाबी विश्वविद्यालय की एक अधिसूचना, जिसमें घोषणा की गई है कि पंजाबी "पूर्व के लिए निर्देशों और परीक्षाओं का एकमात्र माध्यम होगा।

विश्वविद्यालय यहाँ तक कि वर्ष 1970-71 "से विज्ञान समूह के लिए भी लागू हो गया। जाहिरा तौर पर, इन प्रावधानों से बचने का कोई उचित साधन नहीं था ताकि प्रभावित संस्था को मजबूर किया जा सके

अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए इसके चरित्र और शिक्षा के माध्यम को बदलें। ऐसी स्थिति में, इसके अधिकार समर्थक

दोनों को कला द्वारा लिखा गया। 29 (1) और 30 (1) को उल्लंघनकारी प्रावधानों द्वारा उल्लंघन किया गया था।

डी. ए. वी. महाविद्यालय आदि में v. पंजाब राज्य और अन्य। (2) वैधता

1969 के गुरु नानक विश्वविद्यालय (अमृतसर) अधिनियम 21 की कुछ धाराओं और इसके तहत बनाए गए विश्वविद्यालय के कुछ कानूनों को इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 29 (1) और 30 (1) के साथ-साथ कला द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के आलोक में दरकिनार कर दिया गया था। 19 (1) ((ग) संविधान का।

(2) [1971] सप. एस. सी. आर 688

(1) [1971] सप. एस. सी. आर 677

एसटी. XAVIERS कॉलेज v. गुजरात (बेग. जे.)

287

ए.

गुरु नानक विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4 और 5 पर हमले

साथ ही इसे चैप के तहत उपयोग करें। विश्वविद्यालय के कानूनों का वी विफल रहा

लेकिन खंड (1) (2) और 17 के साथ संघर्ष के लिए निरस्त कर दिया गया था

शर्तों के रूप में उनके प्रावधानों के अनुपालन के लिए मजबूर करना था संबद्धता "। यह वहाँ आयोजित किया गया था (पी। 709):

बी.

" तथापि, हमारे विचार में खंड 18 से ग्रस्त नहीं है -

खंड 17 के समान ही, क्योंकि वह प्रावधान जहां तक अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होता है, विश्वविद्यालय को शिक्षकों की सेवा और आचरण को नियंत्रित करने वाले विनियमों द्वारा निर्धारित करने का अधिकार देता है, जो उनकी दक्षता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों के व्यापक हित में अधिनियमित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यह सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में एक अध्यादेश जारी कर सकता है या इसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित कर सकता है।

सी.

ऐसे संस्थानों द्वारा या तो आम तौर पर या विशेष विषयों में शिक्षकों को नियुक्त किया जाना। सभी गैर-सरकारी कर्नल दलों में शिक्षकों की सेवा और आचरण की स्थितियों में एकरूपता सौहार्द बनाएगी और निराशा से बचेगी। बेशक, जबकि निर्दिष्ट मामलों के संबंध में अध्यादेश बनाने की शक्ति असाधारण है, अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार, यदि कोई हो, के उल्लंघन की प्रकृति अध्यादेश के वास्तविक उद्देश्य और महत्व पर निर्भर करेगी और जिस तरह से यह शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके बारे में अब भविष्यवाणी करना संभव नहीं है।

डी.

याचिका दायर करने वाले कॉलेज की ओर से यह आग्रह किया गया था कि यदि उसे विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता या मान्यता का लाभ केवल एक अधिनियम की शर्तों के तहत मिल सकता है, जिसके लिए उसे निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक है -

ई.

प्रतिमान या योजना जिसके तहत संस्था के प्रबंधन से संबंधित पर्याप्त शक्तियों को आत्मसमर्पण करना पड़ता है, यह वास्तव में

इसे अपने मौलिक अधिकार के प्रयोग को छोड़ने के लिए मजबूर करना

कला द्वारा गारंटीकृत। 30 (1) संविधान के अनुसार

प्रबंधन कारण, मान्यता के बिना, गारंटी भ्रामक होगी। यह कम माना जाता है कि जो स्थिति सामने आती है, वह यह है कि व्यावहारिक रूप से कॉलेज के पास संबद्धता या मान्यता की शर्तों के अनुपालन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जिसके बिना इसके छात्र डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते थे। यह प्रस्तुत किया जाता है

कि गैर-अनुपालन का परिणाम यह होगा कि इसके द्वारा शिक्षा उन लोगों की मदद नहीं करेगी जिन्हें यह प्रदान की जाती है।

एफ.

ई.

जीवन में आगे बढ़ने के लिए और इस प्रकार इसका बहुत कम व्यावहारिक मूल्य होगा। यह

जी का अर्थ है, तर्क चलता है कि अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ भेदभाव किया जाएगा और कानून के समक्ष समानता से वंचित किया जाएगा।

30 (1) संविधान का उद्देश्य इसे प्रदान करना है।

इसका उत्तर यह दिया गया है कि इस तरह के तर्क केवल आगे बढ़ाए जा सकते हैं।

यह आग्रह करने के लिए कि अल्पसंख्यक कॉलेजों के लिए कुछ वैकल्पिक प्रावधान होना चाहिए, जो संबद्धता और मान्यता के लिए बहुसंख्यक प्रबंधित कॉलेजों के समान वैधानिक नियंत्रणों की कीमत का भुगतान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे प्रावधान जो अल्पसंख्यक के साथ-साथ बहुसंख्यक के लिए भी समान रूप से लागू होते हैं

एच.

अन्य में

इस आधार पर प्रबंधित कॉलेजों को अमान्य नहीं किया जा सकता था।

एक छोटा सा

शब्दों में, यह वह कला हो सकती है। 30 (1) संविधान [1975] 1 एस. सी. आर. को सक्षम बनाता है।

यह तर्क देना उचित होगा कि कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त करने के लिए,

राज्य को कुछ वैधानिक प्रावधान करना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय ट्यूशन मान्यता प्राप्त कर सकते हैं या द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री के लिए पढ़ा सकते हैं

राज्य अपने किसी भी हिस्से का त्याग किए बिना प्रबंधन के अधिकार प्रदान करता है।

याचिका दायर करने के लिए ऐसा वैकल्पिक प्रावधान करने के लिए राज्य हमारे सामने अल्पसंख्यक संस्थान बनाए गए हैं।

वास्तव में जो दावा किया जाता है वह यह है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को मिलना चाहिए

प्रबंधित बहुमत के लिए निर्धारित शर्तों के अलावा अन्य शर्तों पर संबद्धता

संस्थान जब हमारे सामने क़ानून में संबद्धता के लिए कोई प्रावधान नहीं है

अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए ऐसी किसी भी विशेष वैकल्पिक शर्तों पर। दा इम।

संबद्ध महाविद्यालयों पर लागू प्रस्तावित प्रावधान, चाहे वे बहुसंख्यक हों

या अल्पसंख्यक प्रबंधित, धारा 5,40 और 41 के अलावा जो सेपा हैं

रैबल, अधिनियम की धारा 20,33 ए, 51 ए और 52 ए में निहित हैं। अगर हम मानते हैं कि संबद्धता एक अल्पसंख्यक संस्थान के लिए खुली है

कुछ अन्य शब्द जो वैधानिक प्रावधानों में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, वे होंगे - यह मुझे लगता है, वास्तव में कानून से कम नहीं है जो है

वास्तव में हमारा कार्य नहीं है। इसके अलावा, हमारे सामने मामले में, दावों पर

इसलिए, में पाए जाने वाले संबद्धता के परिणामों से बच जाएगा विवादित अनुभाग।

यह सच है कि अधिनियम की धारा 38 बी कुछ शर्तें लगाती है

जो, यदि याचिका दायर करने वाले कॉलेज की ओर से किए गए दावे हैं सही है, कॉलेज को संतुष्ट करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जो भी हो,

जब तक स्वायत्त दर्जे के लिए उसका आवेदन खारिज नहीं किया जाता, तब तक वह उचित रूप से शिकायत नहीं कर सकता था कि अधिनियम की धारा 5,40 और 41 के अलावा अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उपयोग उसके खिलाफ किया जाएगा। इस कारण से भी, कम से कम इस स्तर

पर, धारा 20 और 33 ए और 51 ए के प्रभाव के बारे में घोषणा करना मुझे अनावश्यक लगता है।

और 52 क अनुच्छेद द्वारा संरक्षित याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों पर। 30 (1) संविधान से।

धारा 38 ख, जिसके लिए मैं काफी महत्व देता हूँ

इस मामले के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

" 38 बी. (1) कोई भी संबद्ध कॉलेज या विश्वविद्यालय कॉलेज या

कोई मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय विभाग,

पंजीयक को संबोधित एक पत्र द्वारा, निष्पादक को आवेदन करें

परिषद कॉलेज, संस्थान या, मामले के रूप में अनुमति देने के लिए

विज्ञापन के मामलों में स्वायत्तता का आनंद लेने के लिए विभाग हो सकता है छात्रों का मिशन, अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्धारित करना, आई. एम

बिदाई के निर्देश और प्रशिक्षण, परीक्षाओं का आयोजन और

उद्देश्य के लिए आवश्यक नियम बनाने की शक्तियाँ (यहाँ

"निर्दिष्ट मामलों" के रूप में संदर्भित)।

(2) या तो एक पत्र या आवेदन की प्राप्ति पर

उप-धारा (1) या जहां यह कार्यकारी वकील को दिखाई देता है कि किसी भी संबद्ध कॉलेज में शिक्षा के मानक

या विश्वविद्यालय कॉलेज या मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय

विभाग इतने विकसित हैं कि यह एसटी के हित में होगा।

महाविद्यालय, संस्थान या विभाग को अनुमति देने के लिए शिक्षा

निर्दिष्ट मामलों में स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर,

कार्यकारी परिषद,

(ए) खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से कि क्या स्टेन

ऐसे महाविद्यालय, संस्थान या विभाग में शिक्षा की कमी

इतना विकसित है कि यह शिक्षा के हित में होगा

कॉलेज, संस्थान या विभाग को ऑटो का आनंद लेने की अनुमति देना निर्दिष्ट मामलों में नाम

(i) ए द्वारा की जाने वाली स्थानीय जांच का निर्देश देना। सक्षम

कार्यकारी परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्ति

इस ओर से, और

((ii) ऐसी आगे की जांच करें जो उसे प्रतीत हो।

आवश्यक;

(ख) इन प्रश्नों पर अकादमिक परिषद से परामर्श करने के बाद

क्या महाविद्यालय, संस्थान या विभाग को ऐसा करना चाहिए

निर्दिष्ट मामलों में स्वायत्तता प्राप्त करने की अनुमति दी जाए और

खंड (ए) के तहत जांच के परिणाम को दर्ज करते हुए उस प्रश्न पर राय; और

(ग) उस प्रश्न पर न्यायालय को एक रिपोर्ट दें जिसमें शामिल हैं -

ऐसी रिपोर्ट में पूछताछ का परिणाम, की राय

शैक्षणिक परिषद और उसके द्वारा अभिलिखित राय।

(3) उप-धारा (2) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर,

न्यायालय, ऐसी आगे की जाँच के बाद, यदि कोई हो, जो दिखाई दे। ताकि आवश्यक हो कि वह प्रश्न पर अपनी राय दर्ज करे

क्या कॉलेज, संस्थान या विभाग होना चाहिए

निर्दिष्ट मामलों में स्वायत्तता की अनुमति दी गई।

(4) पंजीयक इसके बाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

ऐसे महाविद्यालय, संस्थान को ऐसी स्वायत्तता प्रदान करना या

शैक्षणिक विभाग और सभी कार्यवाहियां, यदि कोई हों,

परिषद, कार्यकारी परिषद और उससे संबंधित न्यायालय 10 , राज्य सरकार को।

(5) प्रस्तावों और कार्यवाही की प्राप्ति पर

उप-धारा (4), राज्य सरकार, ऐसी जांच के बाद

जैसा कि आवश्यक प्रतीत हो, प्रोप को मंजूरी दे सकता है

प्रस्तावों को अस्वीकार करें या अस्वीकार करें।

(6) जहाँ राज्य सरकार प्रस्तावों को मंजूरी देती है।

यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक आदेश द्वारा प्रदान करेगा

प्रो में निर्दिष्ट कॉलेज, संस्थान या विभाग पर

पद, छात्रों के प्रवेश को विनियमित करने की शक्ति

महाविद्यालय, संस्थान या, जैसा भी मामला हो, विभाग, महाविद्यालय, संस्थान या संस्थान में अध्ययन का पाठ्यक्रम निर्धारित करना।

विभाग, निर्देश, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना

अध्ययन के क्रम में प्रवेश, परीक्षाओं का आयोजन और

समझौते के बाद इस उद्देश्य के लिए आवश्यक नियम बनाने की शक्तियाँ कार्यपालक परिषद और ऐसी अन्य शक्तियों को कम करना जो हो सके

प्रस्तावों में निर्दिष्ट किया गया है।

upCI/75 290।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1975] आई एस. सी. आर.

(7) एक कॉलेज, मान्यता प्राप्त संस्थान या। विश्वविद्यालय डी-'

उप-धारा (6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाला विभाजन एक स्वायत्त महाविद्यालय कहल जाए, जो स्वायत्त मान्यता प्राप्त हो।

संस्थान या, जैसा भी मामला हो, स्वायत्त विश्वविद्यालय विभाग।

(8) एक स्वायत्त महाविद्यालय के मामले में, स्वायत्त

मान्यता प्राप्त संस्थान या स्वायत्त विश्वविद्यालय विभाग,

विश्वविद्यालय सामान्य पर्यवेक्षण करना जारी रखेगा। ऐसे महाविद्यालय, संस्थान या विभाग के बारे में और

महाविद्यालय, संस्थान या विश्वविद्यालय के छात्रों पर डिग्री

किसी भी डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करना: विश्वविद्यालय "।

एक मिनो के मौलिक अधिकारों पर एक अधिनियम का प्रभाव

शिक्षा संस्थान, जैसा कि मैंने पहले ही ऊपर इंगित करने की कोशिश की है,

यह वास्तविक प्रावधानों की समग्रता पर निर्भर करता है, और वास्तव में, इस पर भी

किसी विशेष संस्थान से संबंधित वास्तविक तथ्य। क्या यह संभव है?

हम इन सभी कारकों को ध्यान में रखे बिना कुल प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए

साइडरेशन? मैं बड़े सम्मान के साथ यह सोचने का साहस करता हूं कि हम ऐसा नहीं कर सकते।

प्रत्येक प्रावधान के प्रभाव को अमूर्त या पृथक रूप में निर्धारित करें।

अन्य प्रावधानों और विशेष याचिका से संबंधित तथ्यों से

कॉलेज ने हमारे सामने रखा।

यह वह कला हो सकती है। 30 (1) संविधान का एक स्वाभाविक परिणाम है

अल्पसंख्यकों द्वारा महसूस की जाने वाली असुरक्षा की भावना को

एक गारंटी द्वारा दूर किया जा सकता है जिसे "चिढ़ाने" तक कम नहीं किया जा सकता है

भ्रम "। लेकिन, क्या यह विकल्प को देखने के लिए एक भ्रम से ज्यादा कुछ है?

एक अल्पसंख्यक के रूप में यह अपने शैक्षणिक संस्थान के साथ क्या करता है

पूरे संगठित समाज के प्रति असावधानी और उदासीनता का मामला

राज्य किसका प्रतिनिधित्व करता है?

स्वतंत्रता की अनुपस्थिति के रूप में उन्नीसवीं शताब्दी का "उदार" दृष्टिकोण

बाधा ", जो काफी हद तक नकारात्मक थी, को जे. एस. मिल ने आवाज दी थी।

उनका "स्वतंत्रता पर निबंध"। (1) परिचय में, विद्वान लेखक (

अपने निबंध का उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित करें (देखें-" महान पुस्तकें

वेस्टर्न वर्ल्ड ", पृष्ठ 271 पर जे. एस. मिल):

" इस निबंध का उद्देश्य एक बहुत ही सरल पर जोर देना है।

सिद्धांत, के रूप में पूरी तरह से लेनदेन को नियंत्रित करने का अधिकार है

मजबूरी के रास्ते में व्यक्ति के साथ समाज और नियंत्रण, क्या उपयोग किए जाने वाले साधन रूप में भौतिक बल हैं

कानूनी दंड, या जनमत की नैतिक जबरदस्ती।

वह सिद्धांत यह है कि एकमात्र लक्षय जिसके लिए मानव जाति है

हस्तक्षेप करने में, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वारंट किया गया

उनकी संख्या में से किसी पर भी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता, आत्म-सुरक्षा है।

कि एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए शक्ति सही हो सकती है

सभ्य समुदाय के किसी भी सदस्य के खिलाफ प्रयोग किया गया उसकी इच्छा दूसरों को नुकसान पहुँचाने से रोकने की है। उसका अपना भला भी

भौतिक या नैतिक, एक पर्याप्त वारंट नहीं है। वह नहीं कर सकता। उचित रूप से करने या सहन करने के लिए मजबूर किया जाए क्योंकि यह होगा

.....(1) अमेरिकन स्टेट पेपर्स-फेडरलिस्ट-जे. एस. मिल, पी। 267 @ 271 और 305।

एसटी. जेवियर कॉलेज वी. गुजरात (बेग, जे.)

291

उसके लिए ऐसा करना बेहतर है, क्योंकि यह उसे खुश कर देगा, क्योंकि, दूसरों की राय में, ऐसा करना बुद्धिमानी होगी।

सही भी। ये विरोध करने के अच्छे कारण हैं। उसे, या उसके साथ तर्क करना, या उसे राजी करना, या विनती करना

उसे, लेकिन उसे मजबूर करने या किसी के साथ उससे मिलने के लिए नहीं बुराई अगर वह अन्यथा करता है। इसे उचित ठहराने के लिए, आचरण:

.

जिनसे उसे रोकना वांछित है, उसकी गणना की जानी चाहिए

किसी और के लिए बुराई उत्पन्न करें। आचरण का एकमात्र भाग

-

जिसके लिए वह समाज के लिए उत्तरदायी है, वह है जो

दूसरों की चिंता करते हैं। उस भाग में जो केवल उससे संबंधित है स्वयं, उसकी स्वतंत्रता, सही, निरपेक्ष है। अपने ऊपर,

अपने शरीर और मन पर, व्यक्ति संप्रभु है "।

कला है। 30 संविधान का उद्देश्य इस तरह के दर्शन को प्रतिबिंबित करना है

"मैन वर्सेज" में हर्बर्ट स्पेंसर के रूप में। राज्य ", जैसा कि अल्पसंख्यक समूहों को राज्य के खिलाफ खड़ा माना जाता है, या, क्या इसका अंतर्निहित दर्शन अधिक उदार नहीं है जो हमारे पूरे संविधान को सक्रिय करता है और प्रस्तावना में कहा गया है, जो मुख्य न्यायाधीश दास के

अनुसार, केरल शिक्षा विधेयक मामले (उपरोक्त) में; शिक्षा के उद्देश्य को भी शामिल करता है? इंडिका; व्यक्ति के अच्छे को अलग करने की अलग संस्कृति, या, एक विस्तार से, एक अल्पसंख्यक समूह का गठन करने वाले समूह की भलाई

समाज, इस प्रकार स्वयं जे. एस. मिल द्वारा व्यक्त किया गया था (पी. 305):

" कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अलग-थलग नहीं है; यह असंभव है।

एक व्यक्ति के लिए कुछ भी गंभीरता से करना। या अपने लिए स्थायी रूप से हानिकारक, कम से कम उसके निकट पड़ोस तक पहुंचे बिना, और अक्सर उनसे बहुत दूर। यदि वह अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो वह उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे समर्थन प्राप्त करते हैं, और आम तौर पर समुदाय के सामान्य संसाधनों को कम या ज्यादा मात्रा में कम कर देता है। यदि वह अपनी शारीरिक या मानसिक क्षमताओं को खराब कर देता है, तो वह न केवल उन सभी पर बुराई लाता है जो अपनी खुशी के किसी भी हिस्से के लिए उस पर निर्भर थे, बल्कि अपने साथी को दी जाने वाली सेवाओं के लिए खुद को अयोग्य घोषित कर देता है। प्राणी आम तौर पर; शायद उनके स्नेह या परोपकार पर बोझ बन जाता है; और यदि ऐसा आचरण बहुत बार होता है, तो शायद ही कोई अपराध जो किया जाता है वह अच्छे के सामान्य योग से अधिक कम करेगा। अंत में, अगर कोई व्यक्ति अपनी बुराइयों या मूर्खताओं से ऐसा करता है। दूसरों को कोई सीधा नुकसान नहीं पहुँचाता है, फिर भी वह अपने उदाहरण से हानिकारक है (यह कहा जा सकता है) और उन्हें उन लोगों के लिए खुद को धोखा देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए जिन्हें उनके आचरण को देखकर या जानते हुए भ्रष्ट या गुमराह किया जा सकता है।

भले ही कला। 30 (1) संविधान के निरपेक्ष प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है

और अल्पसंख्यक संस्थानों पर प्रबंधन के निरंकुश अधिकार, स्वास्थ्य और कानून और व्यवस्था के हित में केवल बिल्कुल न्यूनतम और नकारात्मक नियंत्रणों के उप-अधिनियम, इसे बाहर करने के लिए नहीं किया जा सकता था

विनियमन और नियंत्रण की अधिक डिग्री जब एक अल्पसंख्यक संस्थान सामान्य धर्मनिरपेक्ष और गैर-सांप्रदायिक के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करता है शिक्षा, बड़े पैमाने पर ऐसे शिक्षकों को नियुक्त करती है जो संबंधित पार्टी अल्पसंख्यक के सदस्य नहीं हैं, और जब यह अपनी आय [1975] का बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

292

उन लोगों द्वारा भुगतान किए गए शुल्क से जो विचाराधीन विशेष अल्पसंख्यक के सदस्य नहीं हैं। इस तरह के अधिक नियंत्रण को उन लोगों के हितों को सुरक्षित करने की आवश्यकता से उचित ठहराया जा सकता है जो अल्पसंख्यक संस्थान के प्रबंधन से प्रभावित हैं और जो इसे प्रदान करते हैं लेकिन प्रबंधन में अल्पसंख्यक के सदस्य नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, उचित रूप से अनुमेय नियंत्रण की मात्रा स्थिति से स्थिति में भिन्न होनी चाहिए। ऊपर दिए गए कारणों से, मुझे लगता है कि अधिनियम की धारा 5,40 और 41 बी, अनुच्छेद द्वारा संरक्षित याचिका दायर करने वाले अल्पसंख्यक प्रबंधित महाविद्यालय के अधिकारों पर प्रत्यक्ष और अनुचित रूप से अतिक्रमण करती है। 30 (1) संविधान का, लेकिन अन्य प्रावधानों का वह प्रभाव नहीं है। हमारे समक्ष विचाराधीन स्थिति पर, अधिनियम से प्रभावित अल्पसंख्यक संस्थान, अपनी ओर से किए गए दावों पर, धारा 5,40 और 41 का सहारा लेकर अधिनियम की धारा 5,40 और 41 के अलावा अन्य विवादित प्रावधानों से बचने का एक साधन है। 38 अधिनियम का बी।

नतीजतन, मेरा मानना है कि अधिनियम की धारा 5,40 और 41 हैं -

उन कॉलेजों के अलावा अन्य कॉलेजों में उनके संचालन में प्रतिबंधित, जो कला द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के रूप में समर्थित हैं। 30 (1) कैन स्टेटचूशन का। इसलिए, याचिका दायर करने वाले कॉलेज के खिलाफ इन प्रावधानों को लागू नहीं करने के लिए विरोधी पक्षों को उचित निर्देश जारी करने चाहिए। लेकिन, मेरी राय है कि अधिनियम के शेष प्रावधानों के संबंध में ऐसी किसी घोषणा या निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

द्विवेदी, जे. चूंकि मैं आंशिक रूप से सहमत हूं और आंशिक रूप से डिग्री के साथ

बहुलता-राय, मेरे लिए एक अलग निर्णय लिखना आवश्यक हो गया है। कलाओं के बीच विरोधाभास। 25 और संविधान के 26 और 30 (1)

व्यापक अर्थों में, सभी मौलिक अधिकारों का पता 'स्वतंत्रता' के एकल केंद्रीय विचार से लगाया जा सकता है। 'लिबर्टी' के अपने विभिन्न चरण हैं। कला द्वारा संरक्षित अधिकार। 25 और 26 उन चरणों में से एक है: कला द्वारा संरक्षित अधिकार। 30 (1) एक और चरण बनाएँ। अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। 30 (1) शिक्षा की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अधिक सटीक होने के लिए, कला। 30 (1) शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह सच है।

कि कोई शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा भी प्रदान कर सकता है और इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता के प्रयोग के साधन के रूप में काम कर सकता है। लेकिन कला। 30 (1) एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को एक स्वतंत्र अधिकार के स्तर तक बढ़ाता है। यह एक साधन के अपने आप में एक अंत बनने का मामला है।

फिर से, कला के तहत अधिकारों के लाभार्थी। 25 और 26, और 30 (1) अलग हैं। अनुच्छेद 25 किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 26 किसी समूह की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

कुछ विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में व्यक्तियों का। व्यक्ति और समूह अल्पसंख्यक समुदाय के साथ-साथ मजोरिती समुदाय से भी संबंधित हो सकते हैं। इसके विपरीत, कला। 30 (1) अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करता है। इसका बहुसंख्यक समुदाय से कोई लेना-देना नहीं है। इस प्रकार, हालांकि कला। 30 (1) एक समूह की रक्षा करता है-कला की तरह। 26 , एसटी है।

एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (द्विवेदी, जे.)

293

यह कला से मौलिक रूप से अलग है। 26 क्योंकि यह केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है

समुदाय।

जबकि कला। 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता, कला से संबंधित हैं।

30 (1) एक शिक्षा की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का विस्तार

राष्ट्रीय संस्था न केवल एक धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए बल्कि एक भाषा के लिए भी टिक अल्पसंख्यक जो नास्तिक भी हो सकते हैं। तो कला का दायरा। 30 (1) ,

अधिकार की सामग्री और इसके लाभार्थियों दोनों के संबंध में

बी.

ठीक है, कला की तुलना में व्यापक है, 25 और 26।

अनुच्छेद 25 (2) धर्मनिरपेक्ष गतिविधि सहित कुछ गतिविधियों को धार्मिक प्रथाओं से अलग करता है और उन्हें कानूनी विनियमन या प्रतिबंधों के अधीन बनाता है। लेकिन कला। 30 (1) एक धर्मनिरपेक्ष के अधिकार को सुरक्षित करता है

धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक के लिए गतिविधि। ऐसा अल्पसंख्यक हो सकता है सेकुलर जनरल प्रदान करने के लिए संस्थानों की स्थापना और प्रशासन

सी.

शिक्षा. धर्मनिरपेक्ष सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को अलग नहीं किया जा सकता है।

कला के तहत अधिकारों के पूरे जाल से। 30 (1) , और कला के तहत अधिकार। 30 (1) केवल धार्मिक या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

भाषाई शिक्षा।

कला के बीच विरोधाभास। 29 (1) और कला। 30 (1)

डी.

कला के तहत अधिकार की सामग्री। 29 (1) कला के तहत अधिकार की सामग्री से अलग है। 30 (1) . अनुच्छेद 29 (1) नागरिकों के एक वर्ग को अलग लिपि, भाषा या संस्कृति रखने का अधिकार देता है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 30 (1) एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक के स्थापना और प्रशासन के अधिकार की गारंटी देता है।

ई.

शैक्षणिक संस्थान। अनुच्छेद 29 (1) ब्याज को सुरक्षा प्रदान करता है: अनुच्छेद 30 (1) किसी गतिविधि को सुरक्षा प्रदान करता है। (सीमांत की तुलना करें

कला पर ध्यान दें। 29 (1) .

यह सच है कि एक शैक्षणिक संस्थान लिपि, भाषा और संस्कृति के संरक्षण के साधन के रूप में काम कर सकता है, लेकिन यह कला का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। 30 (1) . एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक, कला के तहत अपने एफ अधिकार का प्रयोग करते हुए। 30 (1) , एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है जिसका अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से कोई सरोकार न हो। अल्पसंख्यक समुदाय अपने सदस्यों को राष्ट्र की सेवा करने के योग्य बनाने और उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक रूप से अपने जीवन को समृद्ध करने में सक्षम

बनाने के उद्देश्य से धर्मनिरपेक्ष सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित कर सकता है।

सीली।

जी.

अनुच्छेद 30 (1), स्पष्ट या निहित शब्दों में, अल्पसंख्यकों के किसी विशेष राज्य के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के अधिकार को सीमित नहीं करता है।

प्रकार। एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का अधिकार निहित रूप से दो प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों को किसी विशेष प्रकार के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने या न करने का अधिकार है। यह नकारात्मक विकल्प है। अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के शैक्षणिक एच संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। यह सकारात्मक विकल्प है।

चुनाव हर स्वतंत्रता में निहित है। कला के तहत संघों और संघों के गठन का अधिकार। 19 (1) (ग) हर प्रकार के ए. एस. ओ. [1975] 1 एस. सी. आर. तक विस्तारित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

294

संघ और संगठन। इसी तरह, के संबंध में एक नागरिक की पसंद

कला के तहत संपत्ति। 19 (1) (च) या कला के तहत व्यवसाय और पेशा।

19 (1) (छ) किसी विशिष्ट प्रकार की संपत्ति या व्यवसाय तक सीमित नहीं है।

या पेशा। एक नागरिक किसी भी प्रकार का अधिग्रहण, धारण और बिक्री कर सकता है।

प्रो

किसी भी व्यवसाय या पेशे को संभालना या चलाना। बेशक, ये मुफ़्त हैं डोम कला के तहत राज्य विनियमन के अधीन हैं। 19 (3) , (5) और (6)।

लेकिन विकल्प के बिना स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो मुझे लगता है कि

'अपनी पसंद के' शब्द केवल पेटेंट बनाते हैं जो कला में छिपी हुई है। 30 (1) .

' उन शब्दों का उद्देश्य पहले से ही पसंद के क्षेत्र को बढ़ाना नहीं है।

कला द्वारा प्रदत्त अधिकार में निहित। 30 (1) .

न्यायालय ने पहले ही यह अभिनिर्धारित किया है कि शिक्षा की स्थापना का अधिकार

कला के तहत राष्ट्रीय संस्थान। 30 (1) उद्देश्यों तक सीमित नहीं है

अनुच्छेद 29 (1) में विनिर्दिष्ट। [बॉम्बे राज्य बनाम देखें। बॉम्बे एडु

कैशन सोसायटी; (1) रे में। केरल शिक्षा विधेयक; (2) रेव. फादर डब्ल्यू.

प्रोस्ट और अन्य वी। बिहार राज्य (3) और डी. ए. वी. कॉलेज बनाम राज्य

पंजाब (4)।

संबद्धता का अधिकार

इस मुद्दे पर हमारे सामने तीन अलग-अलग तर्क रखे गए हैं:

(1) कला में अधिकार अनिवार्य रूप से निहित है। 30 (1) . तदनुसार,

संबद्धता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। (2) यह न तो पूर्व है

प्रेस द्वारा और न ही कला द्वारा निहित रूप से प्रदान किया गया। 30 (1) . तदनुसार यह एक नहीं है मौलिक अधिकार। इसके विपरीत, संबद्धता एक वैधानिक अवधारणा है।

और निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर प्राप्त किया जा सकता है

इसके लिए एक कानून द्वारा। (3) हालांकि यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह है

अनिवार्य रूप से कला में निहित। 30 (1) जिसके लिए संबद्धता से इनकार नहीं किया जा सकता है

किसी अल्पसंख्यक संस्था द्वारा हमें अपना अधिकार पूरी तरह या आंशिक रूप से देने से इनकार कला के तहत। 30 (1) .

स्पष्ट रूप से, संबद्धता के अधिकार का कोई स्पष्ट अनुदान नहीं है

कला. 30 (1) . मेरे विचार में, यह आवश्यक रूप से कला में निहित नहीं है। 30 (1) . मेरे कारण ये हैं: (1) संदर्भ इसके पक्ष में नहीं है

निहितार्थ का दावा किया। संविधान निर्माताओं ने लिया है

चयन के संबंध में शंकाओं को उनकी पसंद के शब्दों से दूर करने का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने गारंटी देने के लिए भी विशेष ध्यान रखा है

में भेदभाव के खिलाफ एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को

राज्य से सहायता का मामला इस आधार पर कि यह प्रबंधन के अधीन है

धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक। [कला देखें। 30 (2)] . यदि वे किसी मौलिक अधिकार के दर्जे के लिए संबद्धता के अधिकार को ऊपर उठाने का इरादा रखते, तो वे आसानी से कला में स्पष्ट शब्दों में अपना इरादा व्यक्त कर सकते थे। 30. यह स्पष्ट है कि एक अल्पसंख्यक संस्थान जो केवल धार्मिक शिक्षा या अपने स्वयं के धर्मशास्त्र को पढ़ाता है, उसे न तो संबद्धता की आवश्यकता होगी और न ही इसकी आवश्यकता होगी। यह संबद्धता की मांग नहीं करेगा क्योंकि संबद्धता कम से कम कुछ हद तक इसकी स्वतंत्रता को कम करने के लिए बाध्य है। फिर से जब हमारा राज्य चरित्र में धर्मनिरपेक्ष है, तो धार्मिक शिक्षा प्रदान करने या केवल एक विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक के धर्मशास्त्र को पढ़ाने वाली संस्था की संबद्धता धर्म के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के अनुरूप नहीं हो सकती है।

राज्य। कला के रूप में। 30 (1) ऐसी संस्था को संबद्धता का अधिकार प्रदान नहीं करता है, यह प्रदान करने वाले संस्थान को वह अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है

(2) [1959] एस. सी. आर. 995,1047,1052-53।

(1) [1955] 1 एस. सी. आर. 568,578,582।

(4) [1971] सप. एससीआर 688,695।

(3) [1969] 2 180 पर एस. सी. आर. 73।

एसटी. एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (द्विवेदी, जे.)

295

धर्मनिरपेक्ष सामान्य शिक्षा। कला के तहत अधिकार की सामग्री। 30 (1)

ए.

दोनों प्रकार के संस्थानों के लिए समान होना चाहिए। [केरल शिक्षा देखें।

पी. पी. पर यह विधेयक (ऊपर)। 1076-1077 जे. वेकटाराम अय्यर के अनुसार]।

रोमेश थैपर बनाम। मद्रास राज्य (1) इस न्यायालय ने कहा:

" [टी] इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि विचारों की स्वतंत्रता; और

अभिव्यक्ति में विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता शामिल है; और

कि स्वतंत्रता परिसंचरण की स्वतंत्रता से सुनिश्चित होती है।

बी.

प्रसार की स्वतंत्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी प्रचार की स्वतंत्रता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिना प्रसार के प्रसार होगा

कम मूल्य "।

यह आग्रह किया जाता है कि जिस तरह 'प्रचार की स्वतंत्रता' को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित माना जाता है, उसी तरह संबद्धता के अधिकार का उपयोग शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के अधिकार में किया जाना चाहिए। तर्क सी प्रशंसनीय लेकिन भ्रामक है। स्वतंत्रता के बीच एक अंतर है

विचार और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पूर्व देता है

एक आदमी को जो कुछ भी वह पसंद करता है उसे सोचने की स्वतंत्रता; बाद वाला उसे एक या अधिक व्यक्तियों के साथ संवाद करने की स्वतंत्रता देता है जो वह सोचता है। क्रमिक रूप से, बाद वाला आवश्यक रूप से विचारों के प्रचार या प्रसार की स्वतंत्रता को दर्शाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि संबद्धता का अधिकार उस अर्थ में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के अधिकार में निहित हो। डी इतिहास से पता चलता है कि राज्य की मान्यता या संबद्धता के बिना शैक्षणिक संस्थान पूरे जोश और उत्कृष्टता के साथ अस्तित्व में रहे हैं। यूरोप में गैर-संबद्ध अकादमियों ने विज्ञान और मानविकी के विकास में बहुत योगदान दिया है। पूर्व-स्वतंत्र भारत में अच्छी प्रतिष्ठा के कई असंबद्ध और गैर-मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान थे। हमारे दिवंगत

प्रधानमंत्रियों में से एक उन संस्थानों में से एक की उपज थे। निजी क्षेत्र के रोजगार ई का विशाल क्षेत्र गैर-संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों से आने वाले छात्रों के लिए खुला होगा, यदि वे अन्यथा योग्य हैं। मान्यता प्राप्त गरिमा और डिप्लोमा के आधार पर राज्य सेवाओं में भर्ती की केवल दुर्घटना कला में संबद्धता के अधिकार को पढ़ने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होना चाहिए। 30 (1) . राज्य किसी भी समय इस आसान और यांत्रिक उपयुक्तता परीक्षण को छोड़ सकता है और सभी के लिए, चाहे उसके पास स्वामित्व हो या न हो, छोटी परीक्षाओं द्वारा चयन कर सकता है।

एफ.

एक मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा। हालाँकि, किसी संबद्ध विश्वविद्यालय की संबद्धता के मामले में किसी अल्पसंख्यक संस्थान को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इसका प्रबंधन अल्पसंख्यक द्वारा किया जाता है, चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो या मनमाने या तर्कहीन आधार पर। इस तरह का इनकार कला का उल्लंघन होगा। 14 और 15 (1) और अदालतों द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। फिर से, कला। 13 (2) राज्य को कला के तहत अधिकार को छीनने या कम करने से प्रतिबंधित करता है। 30 (1) .

जी.

चूँकि राज्य कला के तहत प्रदत्त अधिकार को सीधे छीन या कम नहीं कर सकता है। 30 (1) , राज्य ऐसी शर्तों के अधीन संबद्धता अनुदान देकर अप्रत्यक्ष रूप से उस अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकता है जो

इसमें निषिद्ध परिणाम शामिल होगा। [रे में देखें। केरल शिक्षा विधेयक

(ऊपर) pp-1063-1964] पर।

संबद्ध विश्वविद्यालय

श्री पालखीवाला ने अपने उत्तर में प्रस्तुत किया है कि कला।

एच.

30 (1) प्रत्येक राज्य के लिए कम से कम एक संबद्ध विश्वविद्यालय होना अनिवार्य है।

(1) [1950] एस. सी. आर. 594 597 पर।

मैं इस निवेदन को स्वीकार करने में पूरी तरह से असमर्थ हूं। कला के रूप में। 30 (1) नहीं करता है

संबद्धता का अधिकार प्रदान करने के लिए, राज्य बाध्य नहीं है

एक संबद्ध विश्वविद्यालय। यह एक राज्य के लिए केवल एक शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए खुला है।

विश्वविद्यालय।

कला की भ्रामक निरपेक्षता। 30 (1) .

याचिकाकर्ताओं का समर्थन करने वाले कुछ वकीलों ने, मुझे लगता है, गलत किया है

कला की मौखिक निरपेक्षता पर अधिक जोर दिया। 30 (1) . के अनुसार

श्री तारकुंडे, जबकि कला। 19 (1) (छ) बहुमत को अधिकार देता है

शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए समुदाय

लोक हित में उचित प्रतिबंध, कला। 30 (1) समान देता है

पूर्ण रूप से धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का अधिकार। के अनुसार उसके लिए, कला। 30 (1) एक उच्च अधिकार प्रदान करने के लिए समझा जाना चाहिए

कला द्वारा बहुमत पर प्रदान किए गए एक से अल्पसंख्यक। 19 (1) (जी)।

श्री पालखीवाला के अनुसार, कला के तहत अधिकार। 30 (1) सम्मानित किया जाता है पूर्ण भाषा में और न तो लिया जा सकता है और न ही संक्षिप्त किया जा सकता है

कला के निषेधाज्ञा के कारण राज्य। 13 (2) .

यह सच है कि कला। 30 (1) विशाल और अयोग्य में व्यक्त किया जाता है

भाषा। कला भी ऐसी ही है। 14 : " राज्य किसी भी व्यक्ति से इनकार नहीं करेगा।

कानून के समक्ष समानता या कानून के भीतर कानूनों का समान संरक्षण

भारत का क्षेत्र "। हालाँकि, इस न्यायालय ने इस सीमा को पढ़ा है

कला की सामान्य और अप्रतिबंधित भाषा में वर्गीकरण। 14 .

" [टी] वह कला की सामान्य भाषा है। 14 ..... हो चुका है

राज्य के विनियमन की मान्यता से बहुत योग्य

विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग तरीके से काम करने वाले कानून बनाने की शक्ति

अपने विषयों के शासन में व्यक्तियों का, परिणाम के साथ

कि नागरिक अधिकारों की समानता और समानता का सिद्धांत

कानूनों के संरक्षण को केवल एक सुरक्षा के रूप में प्रभाव दिया जाता है।

राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ "। (पश्चिम बंगाल राज्य बनाम।

अनवर अली सरकार (1) प्रति पाटनाली शास्त्री सी. जे.)।

" अनुच्छेद 14 एक निषेध लागू करके एक अधिकार प्रदान करता है जो,

कम से कम निरपेक्ष तो है. लेकिन. कला। 14 वास्तव में निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि

सायंस। अनुच्छेद 14, जैसा कि अदालतों द्वारा व्याख्या की गई है, कुछ ऐसे मामलों में लागू होगा इस प्रकार के शब्द: राज्य किसी भी व्यक्ति को समानता से वंचित नहीं करेगा -

कानून या कानून के समान संरक्षण के लिए बशर्ते कि कुछ भी नहीं

इसमें निहित राज्य को इसके आधार पर कानून बनाने से रोकेगा - या एक बोधगम्य भिन्नता पर आधारित वर्गीकरण को शामिल करना।

द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना

कानून "। (एच. एम. सीरवई द्वारा भारत का संवैधानिक कानून, 1967 एडन। पी।

188) . पतंजलि शास्त्री सी. जे. के अनुसार, बनाने की आवश्यकता

विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष कानूनों ने न्यायालय को पढ़ने के लिए बाध्य किया

कला की व्यापक भाषा। 14. (चरणजीत लाल बनाम। भारत संघ (2)

और काथी रानींग रावत बनाम। सौराष्ट्र राज्य। (3)

कला की तरह। 30 (1) , संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का प्रथम संशोधन है

पूर्ण शब्दों में भी व्यक्त किया गया: " कांग्रेस कोई कानून नहीं बनाएगी

(2) [1950] एस. सी. आर. 869 890

(1) [1952] एस. सी. आर. 284,295

(3) [1952] एस. सी. आर. 435,442

एसटी. एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (द्विवेदी, जे.)

297

ए.

धर्म की स्थापना का सम्मान करना, या स्वतंत्र आचरण को प्रतिबंधित करना

इसका हवाला; या बोलने की स्वतंत्रता, या प्रेस की स्वतंत्रता को कम करना; या

लोगों का शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और सरकार को याचिका दायर करने का अधिकार

शिकायतों के निवारण के लिए "। हालांकि यह आयोजित किया गया है

यू. एस. ए. सुप्रीम कोर्ट कि स्वतंत्रता आई संशोधन में मान्यता प्राप्त है

मन निरपेक्ष नहीं है और विनियमन के अधीन है। स्वतंत्रता

धर्म) दो अवधारणाओं को शामिल करता है, विश्वास करने की स्वतंत्रता और करने की स्वतंत्रता।

बी.

अभिनय करें। पहला निरपेक्ष है, लेकिन चीजों की प्रकृति में, दूसरा कर सकता है

नहीं "। (कैंटवेल वी। कनेक्टिकट)। (1) बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में,

न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने कहा है:

" (टी) संविधान में पहले दस संशोधन, जिन्हें आर्थिक रूप से "बिल ऑफ राइट्स" के रूप में जाना जाता है, को लागू करने का इरादा नहीं था।

सरकार के किसी भी नए सिद्धांत, लेकिन बस करने के लिए

सी.

इसमें कुछ गारंटी और उन्मुक्ति शामिल हैं जो हमें अपने अंग्रेजी पूर्वजों से विरासत में मिली थीं और जो प्राचीन काल से मामले की आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाले कुछ अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवादों के अधीन थीं। इन सिद्धांतों को मौलिक कानून में शामिल करने में उन अपवादों की अवहेलना करने का कोई इरादा नहीं था, जिन्हें मान्यता दी जाती रही जैसे कि उन्हें औपचारिक रूप से व्यक्त किया गया था। (2)

डी.

कला की तरह। 30 (1) , ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 92 को भी पूर्ण शब्दों में व्यक्त किया गया है: " राज्यों के बीच सीमा शुल्क, व्यापार, वाणिज्य और संभोग के समान कर्तव्यों को लागू करने पर, चाहे वह आंतरिक परिवहन या समुद्री नौवहन के माध्यम से हो, पूरी तरह से मुक्त होगा। (जोर दिया गया) फिर भी, यह माना गया है कि यह 'पूर्ण' स्वतंत्रता विनियमन के अधीन है। "बिल्कुल मुक्त" शब्दों ने धारा 92 के संबंध में सबसे बड़ी समस्याओं को जन्म दिया है। यह जल्दी तय किया गया था कि वे आर्थिक बोझ तक ही सीमित नहीं थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता की प्रकृति में व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर सभी कानूनी प्रतिबंधों का उन्मूलन शामिल नहीं है, लेकिन अनुमत हस्तक्षेप की सटीक सीमा तैयार करना आसान नहीं है। सभी मामलों में लागू होने वाले सामान्य नियम को बताने में कठिनाई एक अनिवार्य रूप से व्यावहारिक विषय को सामान्य अमूर्त शब्दों तक कम करने की असंभवता से उत्पन्न होती है। व्यापार, वाणिज्य और संभोग की सटीक प्रकृति, ठीक वैसी ही जो यह आम लोगों के लिए समझती है।

ई.

एफ.

सेक की मुद्रा। 92 , अधिक नहीं, और कम नहीं और निर्धारित स्वतंत्रता की गुणवत्ता ऐसे प्रश्न हैं जिनका अलग-अलग उत्तर दिया गया है और जिनके परिणाम अलग-अलग हैं। (3)

प्रिवी काउंसिल ने हाल ही में माना है कि व्यापार का विनियमन,

जी.

राज्य के बीच व्यापार और संभोग इसकी पूर्ण स्वतंत्रता के अनुरूप है। (ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल और अन्य बनाम। बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स और अन्य)। (1) विनियमन की सीमा के बारे में,

प्रिवी काउंसिल ने कहा:

(1) 310 यू. एस. 296 पीपी पर। 303-304 .

(2) 95 लॉ एडन। 1137 पी पर। 1160 .

एच.

2 एन. डी. ई. एन. पी। 339) . (4) [1950] ए. सी. 235

[19 75] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

298

" [टी] उत्तराधिकारी लॉर्डशिप्स इसे निर्धारित करने का इरादा नहीं रखते हैं कि

किसी भी परिस्थिति में प्रतियोगिता का बहिष्कार नहीं किया जा सकता था ताकि

किसी राज्य या राष्ट्रमंडल एजेंसी में एकाधिकार बनाएँ

या किसी अन्य निकाय में उचित ठहराया जाए। हर मामले का न्याय किया जाना चाहिए

अपने स्वयं के तथ्यों और समय और परिधि की अपनी सेटिंग में रुख, और यह हो सकता है कि कुछ आर्थिक गतिविधियों के संबंध में

सामाजिक विकास के कुछ स्तर पर यह हो सकता है

राज्य के एकाधिकार की दृष्टि से उस निषेध को बनाए रखा

विनियमन का एकमात्र व्यावहारिक और उचित तरीका था

और इस प्रकार अंतर-राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक संबंध

निषिद्ध और इस प्रकार एकाधिकार पूरी तरह से बना रहा

मुफ़्त "। (1)

यह सर्वेक्षण एब्सो के तर्क को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

वीणा या निकट-किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का पूर्ण अधिकार।

कला के शब्द। 30 (1) . पूर्ण शब्द पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि शब्दों की व्यापकता को संदर्भ और क़ानून या संविधान की योजना, जैसा भी मामला हो, द्वारा कम किया गया हो सकता है। इस प्रकार कला में 'गिरफ्तारी' शब्द की व्यापकता को सीमित करते हुए। 22 (1)

और संविधान के (2), जे. दास ने कहा:

" यदि, तथापि, दो निर्माण संभव हैं तो

अदालत को वह अपनाना चाहिए जो सुचारू और कठोरता सुनिश्चित करेगा।

संविधान का काम करना और दूसरे से बचना

जो बेतुकेपन की ओर ले जाएगा या व्यावहारिक असंगतता को जन्म देगा

मौजूदा कानून के अच्छी तरह से स्थापित प्रावधान करना या बनाना

नासमझ "। (पंजाब राज्य बनाम। अजैब सिंह) (2)

संविधान के भाग III के संदर्भ और योजना पर एक नज़र

यह दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं का मन नहीं था

किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का पूर्ण अधिकार। सहयोगी कला। 29 (2) थोपा जाता है

कला में अधिकार पर एक प्रतिबंध। 30 (1) . कोई धार्मिक या भाषाई नहीं

अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त करता है, वह किसी भी निधि में प्रवेश से इनकार करेगा।

केवल धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर संस्था का नागरिक,

भाषा या उनमें से कोई भी। एक छात्र को शिक्षा में प्रवेश देने का अधिकार

राष्ट्रीय संस्था स्वीकार्य रूप से इसे प्रशासित करने के अधिकार में शामिल है। इस अधिकार को कला द्वारा आंशिक रूप से कम किया गया है। 29 (2) .

प्रवेश के अधिकार को कला द्वारा और कम कर दिया गया है। 15 (4) जो

कला को एक अपवाद प्रदान करता है। 29 (2) . अनुच्छेद 15 (4) राज्य को किसी भी सामाजिक और सामाजिक विकास के लिए कोई विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति के लिए

और शिक्षा में प्रवेश के मामले में अनुसूचित जनजातियाँ

राज्य द्वारा अनुरक्षित या राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं।

अनुच्छेद 28 (3) अनुच्छेद में अधिकार पर तीसरा प्रतिबंध लगाता है। 30 (1) .

इसमें प्रावधान है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा।

राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या प्राप्त करने के लिए भाग लेना आवश्यक होगा।

में

ऐसी संस्था में दी जाने वाली कोई धार्मिक शिक्षा या

(2) [1953]

एस. सी. आर. 254,264

(1) [1950] ए. सी. 235,311।

एसटी. एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (द्विवेदी, जे.)

किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए जो ऐसी संस्था में या उससे जुड़े किसी परिसर में आयोजित की जा सकती है जब तक कि ऐसा व्यक्ति या, यदि ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, उसके अभिभावक ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। जाहिर है, कला। 28 (3) एक धार्मिक अल्पसंख्यक की स्थापना को प्रतिबंधित करता है और

एक शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करना जो सहायता प्राप्त करता है या फिर से शुरू किया जाता है

राज्य द्वारा किसी भी नागरिक को संस्थान में पढ़ने के लिए मजबूर करने से

उसकी इच्छा के विरुद्ध या अपने अभिभावक की इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का धार्मिक अल्पसंख्यक का अधिकार संस्थान को प्रशासित करने के अधिकार का हिस्सा है। और

फिर भी कला। 28 (3) यह उस अधिकार को कुछ हद तक कम करता है।

संक्षेप में, कला। 29 (2) , 15 (4) और 28 (3) निश्चित एक्सप्रेस रखें

कला में अधिकार पर सीमाएँ। 30 (1) . इस अधिकार पर कुछ निहित सीमाएँ भी हैं। अधिकार को उनके अधीन पढ़ा जाना चाहिए निहित सीमाएँ।

संविधान का भाग III व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है,

समूहों और कुछ अल्पसंख्यक समूहों पर। उन अधिकारों का गठन एक

हमारे संविधान में स्वतंत्रता की एकल अविभाज्य संतुलन प्रणाली। द. प्रणाली का तात्पर्य विभिन्न अधिकारों के बीच व्यवस्था और सद्भाव से है।

प्रत्येक मामले की आवश्यकताओं के अनुसार हमारी स्वतंत्रता का प्रचार करना। जाहिर है, संविधान निर्माताओं द्वारा अधिकारों का कभी भी एक दूसरे के साथ टकराव का इरादा नहीं रखा जा सकता था। उदाहरण के लिए, एक नागरिक दूसरे पर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

अधिकार के इस तरह के प्रयोग के लिए व्यक्ति की अनुमति के बिना संपत्ति, कला के तहत उसे प्रदत्त संपत्ति रखने के अधिकार का उल्लंघन करेगी। 19 (1) (जी)। यद्यपि एक धार्मिक संप्रदाय का अधिकार कला. 26 अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना स्पष्ट रूप से कला के अधीन नहीं किया गया है। 25 (2) (ख) जो हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को खोलने वाले कानून की रक्षा करता है, इस न्यायालय ने

हिंदुओं के बहिष्कृत वर्ग के लिए सार्वजनिक मंदिरों को खोलने वाले कानून की वैधता को माना। न्यायालय की ओर से बोलते हुए, जे. वेंकटरामा अय्यर ने कहा:

" तब परिणाम यह होता है कि दो समान प्रावधान हैं।

अधिकार, उनमें से कोई भी दूसरे के अधीन नहीं है। द.

सवाल यह है कि उनके बीच स्पष्ट संघर्ष कैसे होगा?

हल किया। निर्माण का नियम अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब एक अधिनियम में दो प्रावधान हैं जो नहीं हो सकते हैं

एक-दूसरे के साथ सुलह, उन्हें इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए

कि, यदि संभव हो, तो दोनों को प्रभाव दिया जा सकता है। यही बात है।

सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम के रूप में जाना जाता है। आवेदन करना यह नियम, यदि अपीलार्थियों के तर्क को स्वीकार किया जाना है,

फिर कला। 25 (2) (ख) इसमें पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगा।

हालाँकि, जैसा कि कहा गया है, संप्रदाय के मंदिरों के लिए आवेदन

ऊपर, उस अनुच्छेद की भाषा में वे शामिल हैं। जिस पर

तब कला को पूरा प्रभाव दिया जा सकता है। 26 ((ख) सभी मामलों में धर्म, केवल इस विषय के अधीन है कि के एक पहलू के संबंध में

उन्हें, पूजा के लिए एक मंदिर में प्रवेश, घोषित अधिकार

कला के तहत। 25 (2) (ख) प्रबल होगा। जबकि, पिछले मामले में, कला. 25 (2) (ख) पूरी तरह से संचालन से बाहर कर दिया जाएगा, में

उत्तरार्द्ध, उस प्रावधान और दोनों को प्रभाव दिया जा सकता है "

[1

975] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

300

कला. 25 (बी)। हमें तदनुसार उस कला को बनाए रखना चाहिए। 26 (ख)

अनुच्छेद 25 (2) (बी) के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। (श्री वेंकट

रमण देवरू और अन्य बनाम मैसूर राज्य। (1)

तदनुसार कला में अधिकार। 30 (1) मेरे विचार से ऐसा नहीं हो सकता।

किसी नागरिक के कानूनी या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार

प्रबंधन किसी शिक्षक या गैर-शिक्षक सदस्य को दंडित नहीं कर सकता है।

अपनी स्वतंत्रता के वैध प्रयोग के लिए शिक्षण कर्मचारी या छात्र

भाषण और अभिव्यक्ति या संघ या संघ बनाने का।

संविधान निर्माताओं ने लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है

एक लोकतांत्रिक गणराज्य में हमारा देश। लोकतांत्रिक गणराज्य होगा

अगर इसके सदस्य आपस में लगातार युद्ध में थे तो यह लंबे समय तक नहीं चल सकता था।

उनके अलग अधिकारों के उत्थान के लिए। यह जल्द ही अंदर चला जाएगा

एक या दूसरे प्रकार का निरपेक्षता। यूरोपीय इतिहास दर्शाता है

कि जब भी एक समूह ने दूसरे को स्वतंत्रता से वंचित करने का प्रयास किया है

समूह, इसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। मूर्तिपूजकों ने ईसाइयों को प्रताड़ित किया और हार गए

अपनी स्वतंत्रता। ईसाइयों ने, बदले में, धार्मिक स्वतंत्रता से इनकार किया मूर्तिपूजकों को और अपनी स्वतंत्रता या तो एक निरपेक्ष को सौंप दी

सम्राट या एक अचूक पोप के लिए। कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों ने इनकार किया

एक दूसरे के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और निरंकुशता को मजबूत किया

राजतंत्र।

पूर्ण अधिकार केवल चंद्रमा में ही संभव हैं। यह असंभव है कि

एक सभ्य समुदाय का सदस्य जिसे पूर्ण अधिकार हों। कुछ

प्रत्येक सदस्य द्वारा उचित आनंद के लिए अधिकारों का विनियमन आवश्यक है।

अपने स्वयं के अधिकारों के समाज से।

इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि कला के तहत अधिकार है। 30 (1) यह भी उप है

विभिन्न सामाजिक हितों के संरक्षण के लिए विनियमन के लिए अधिनियम जैसे

स्वास्थ्य, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और इसी तरह के लिए

लोगों की भलाई सर्वोच्च कानून है। आज शिक्षा, विशेष रूप से

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हमारे विकास के लिए एक पूर्व-खाली सामाजिक हित है

लोपिंग। राष्ट्र "। अब यह स्पष्ट है कि धन का वास्तविक स्रोत नहीं है।

कच्चे माल, श्रम बल या मशीनों में अधिक समय तक, लेकिन होने में

वैज्ञानिक, शिक्षित, तकनीकी मानव-शक्ति आधार। शिक्षा है।

नए युग की वास्तविक संपत्ति बनें। (2) परिसर पर हमला

और देश की तत्काल समस्याओं को दो के माध्यम से बनाना होगा।

कृषि के आधुनिकीकरण और तीव्र औद्योगीकरण के माध्यम से। इसके लिए विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।

सी. डी. यू. सी. ए. के एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम के माध्यम से मानव संसाधन

यह "।

यह बाद वाला कार्यक्रम है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

दो। जबकि भौतिक संसाधनों का विकास एक साधन है

मानव संसाधन का अंत अपने आप में एक अंत है, और

इसके बिना,

भौतिक संसाधनों का पर्याप्त विकास भी है

नहीं।

संभव है।

ब्ले "। (3) स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष सामान्य शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान

और प्रौद्योगिकी, विकास और लाभ में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए हमारे राष्ट्र की गरिमा। तदनुसार हमारा राज्य उतना ही होना चाहिए

(1) [1958] 2 एस. सी. आर. 895,918

(2) जे. डी. बर्नाल, साइंस इन हिस्ट्री, पेलिकन बुक, वॉल्यूम। आई एफ। 117 .

(3) कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, पैराल। 12 .

एसटी. एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (द्विवेदी, जे.)

301

अल्पसंख्यकों के छात्रों की सही और सामाजिक रूप से आवश्यक शिक्षा में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों से अधिक रुचि रखते हैं। छात्र केवल अल्पसंख्यकों से संबंधित नहीं हैं; वे भी हैं

राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष जीन प्रदान करने का अति-मुखर तर्क

मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक वातावरण में इस शिक्षा की अनदेखी की जा रही है।

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहलू। धर्मनिरपेक्ष सामान्य शिक्षा होनी चाहिए

राष्ट्र की पहली चिंता। यह वैध रूप से माना जा सकता है कि संविधान शिक्षण निर्माता इस प्राथमिकता के प्रति सचेत थे कि शिक्षा को क्या मिलना चाहिए

हमारे गणराज्य के कार्यक्रम में। (कलाएँ देखें। 41, 45 और 46)। कैसे?

क्या वे तब एक पूर्ण या निकट-पूर्ण अधिकार प्रदान करने का इरादा रख सकते हैं

धर्मनिरपेक्ष सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शैक्षणिक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के लिए एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक?

यह याद रखना अच्छा है कि यह संविधान है जिसके हम पूर्व हैं।

प्रहार करते हैं। एक क़ानून से निपटने के लिए एक विशिष्ट साजिश है

संविधान अच्छी सरकार के लिए एक सामान्य साजिश है और हमारे विकासशील गणराज्य के सभी लोगों की खुशी। इसे बनाया जाता है।

वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए भी। सभी महान जैविक ग्रंथों की तरह,

उन्होंने कहा, "मैं आपका स्वागत करता हूँ।

यह व्यापक और अनुकूल भाषा में लिखा गया है।

(वेद के शब्द विशाल हैं-एम. बी। , शांति परव, XIX, 1)। राज्य की निष्क्रियता को दर्शाने के बजाय, कला की सामान्य भाषा। 30 (1) मेरे विचार से, कला में अधिकारों को समायोजित करने में विधायिका और न्यायालयों को उचित लचीलापन देने के लिए बनाया गया है। 30 (1) प्रत्येक मामले की आवश्यकताओं के लिए।

जे. बोस ने कहा है: " ((संविधान के शब्दों की) वास्तविक सामग्री को केवल एक हाथ में शब्दों और दूसरे में शब्दकोश को लेकर एकत्र नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के प्रावधान गणितीय सूत्र नहीं हैं जिनका सार केवल रूप में है। वे मौलिक रूप से अलग-अलग विचारों वाले लोगों के लिए लिखी गई सरकार की एक रूपरेखा का गठन करते हैं और भविष्य के लिए उतना ही लिखा जाता है जितना कि वर्तमान के लिए। वे केवल एक पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ नहीं हैं, बल्कि एक प्रगतिशील लोगों के जीवन को व्यवस्थित करने के साधन हैं। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। अनवर अली सरकार (सुप्रा) पी। 359] . विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा: " (संविधान के शब्द) केवल नीरस, जीवनहीन शब्द नहीं हैं जो किसी ममीकृत पांडुलिपि की तरह स्थिर और छिपे हुए हैं, बल्कि एक महान राष्ट्र को जीवन देने और उसके अस्तित्व को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जीवित लपटें हैं, जो गतिशील अग्नि की जीभ हैं, जो भविष्य को ढालने के साथ-साथ वर्तमान का मार्गदर्शन करने में भी सक्षम हैं। मेरी राय में, संविधान को समय-समय पर बदलती दुनिया की बदलती स्थितियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लोचदार छोड़ दिया जाना चाहिए, जिसमें बदलते जोर और अलग-अलग ज़रूरतें हैं। (पी पर सुप्रा। 363)

विनियामक शक्ति का विस्तार

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के अनुसार राज्य की नियामक शक्ति का विस्तार अलग-अलग होगा। शैक्षणिक संस्थानों को कई तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है: (1) शिक्षा की प्रकृति के अनुसार जो अल्पसंख्यकों द्वारा दी जा रही है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई शिक्षा या धर्मनिरपेक्ष सामान्य शिक्षा या मिश्रित हो सकती है; (2) राज्य द्वारा सहायता और मान्यता के अनुदान के अनुसार।

कुछ

संस्थान [1975] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

302

देशों को सहायता मिल सकती है; दूसरों को नहीं मिल सकती है। इसी तरह, कुछ संस्थान मान्यता प्राप्त कर सकते हैं; अन्य नहीं भी कर सकते हैं। हो सकता है -

कुछ

अन्य जो सहायता और मान्यता दोनों प्राप्त कर सकते हैं; कुछ अन्य हो सकते हैं

न तो सहायता प्राप्त करें और न ही मान्यता, (3) के मानक के अनुसार

धर्मनिरपेक्ष सामान्य शिक्षा जो संस्थानों में दी जा रही है

प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर। (4) शिक्षा की प्रकृति के अनुसार

कैशन जैसे कि सैन्य अकादमी, समुद्री इंजीनियरिंग, जिसमें

राज्य विभिन्न कारणों से बहुत रुचि रखता है।

विनियामक शक्ति की सीमा वर्ग से वर्ग में भिन्न हो सकती है

एक वर्ग के भीतर भी। उदाहरण के लिए, सहायता और सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान

आयोग उन लोगों की तुलना में अधिक विनियमन के अधीन हो सकता है जो प्राप्त करते हैं

न ही। इसी तरह, धर्मनिरपेक्ष सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान

उन लोगों की तुलना में अधिक विनियमन के अधीन होना जो विश्वास प्रदान कर रहे हैं केवल धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई शिक्षा।

एक शैक्षणिक संस्थान में निम्नलिखित शामिल होंगे: (1) प्रबंधक:

संस्थान का निकाय, (2) शिक्षण कर्मचारी, (3) गैर-शिक्षण कर्मचारी, (4)

छात्र और (5) विभिन्न प्रकार की संपत्ति। यहाँ फिर से, की सीमा

नियामक शक्ति एक घटक से दूसरे घटक में भिन्न हो सकती है। के लिए उदाहरण के लिए, शिक्षण कर्मचारी और संपत्ति अधिक डी के अधीन हो सकती है।

प्रबंध निकाय की संरचना की तुलना में विनियमन। साफ तौर पर, नहीं। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को इलाज के लिए अलग किया जा सकता है

बहुसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को दिए गए किराए में से एक। ए.

इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार को पूरा करने वाला विनियमन कला के लिए अशोभनीय होगा। 30 (1) .

इन प्रारंभिक टिप्पणियों के अधीन, अब यह आवश्यक है कि

इस बात पर विचार करें कि एक विनियमन द्वारा प्रदत्त अधिकार पर कितना प्रभाव पड़ सकता है

यह तय करने के लिए क्या परीक्षण है कि क्या एक मिनो पर एक विनियमन लगाया गया है शिक्षा संस्थान प्रदत्त अधिकार को छीन लेता है या कम कर देता है

कला द्वारा। 30 (1) ? यह पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि एक वैध विनियमन का परीक्षण इसकी आवश्यकता है। कोई भी विनियमन जो समाज के हितों (जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं) या व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक से परे नहीं जाता है।

समाज के सदस्य संवैधानिक होने चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह का विनियमन कला द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन लेता है या कम कर देता है। 30 (1) .

आई।

यह निर्धारित करने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि क्या है

आवश्यक है। प्रश्न की जांच विवादित प्रावधानों और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में की जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि विवादित कानून को विनियमित अधिकार और सामाजिक हित या संरक्षित व्यक्तिगत अधिकार के बीच एक उचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। न्यायालय को विनियमित अधिकार के मूल्य और संरक्षित सामाजिक हित या व्यक्तिगत अधिकार के मूल्य को संतुलित करना चाहिए। इन प्रतिस्पर्धाओं को संतुलित करते हुए

हितों के लिए, न्यायालय को विधायी निर्णय को उचित महत्व देना चाहिए। न्यायालय की तरह, विधानमंडल ने भी संविधान को बनाए रखने की शपथ ली है। यह लोगों की स्वतंत्रता और कल्याण का उतना ही रक्षक है जितना कि न्यायालय। यह एस. टी. के बारे में न्यायालय की तुलना में अधिक सूचित है।

एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (द्विवेदी, जे.)

303

सरकार की तात्कालिक आवश्यकताएँ और निगम की आवश्यकताएँ

बहुत से लोग। (पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देखें। अनवर अली सरकार (ऊपर)

पी। 303 प्रति दास जे.)

मुझे इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि एक विनियमन, क्रम में

संवैधानिक होने के लिए, हमेशा सुधार के लिए गणना की जानी चाहिए

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की उत्कृष्टता। यह स्वीकार किया जाता है

याचिकाकर्ताओं का समर्थन करने वाले वकील द्वारा कि राज्य निर्धारित कर सकता है

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम जो

और पाठ्यक्रम की गणना आवश्यक रूप से उत्कृष्टता में सुधार के लिए नहीं की जा सकती है किसी विशेष अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की बाड़। खुद के लिए छोड़ दिया, ए

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान उच्च मानक का विकल्प चुन सकते हैं

राज्य द्वारा अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित निर्देश से अधिक या

पाठ्यक्रम। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य पाठ्यक्रम निर्धारित करता है और

पाठ्यक्रम शिक्षा की उत्कृष्टता की दृष्टि से जितना

शिक्षा का एक समान मानक होने की दृष्टि से। ए.

एक समान मानक शायद विभिन्न क्षमताओं के कारण आवश्यक है

विभिन्न विकसित और अविकसित वर्गों से आने वाले छात्र समाज और विभिन्न विकसित और अविकसित भौगोलिक क्षेत्रों से

देश के क्षेत्र।

लेकिन यह हम पर दबाव डाला जाता है कि एक पाठ्यक्रम निर्धारित करना और

राष्ट्रीय संस्था। विद्वान न्यायाधीशों के प्रति गहन सम्मान के साथ जिन्होंने मातृ प्रांतीय मामले का फैसला किया (1)। मुझे यह मुश्किल लगता है

इस तर्क को स्वीकार करें। याचिकाकर्ताओं का समर्थन करने वाले वकील के पास मुख्य है

कि राज्य इसके लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं कर सका

धार्मिक, सांस्कृतिक या भाषाई शिक्षा जो प्रदान की जा रही है

एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त शैक्षिक

संस्था। जाहिरा तौर पर इसका कारण यह है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम एक

एक शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा।

जहाँ तक कैथोलिक शैक्षणिक संस्थानों का संबंध है। कैथो

लिक्स का मानना है कि शिक्षा चर्च से संबंधित है,

कैथोलिक हठधर्मिता इस आधार को स्पष्ट रूप से नकारती है कि धर्मनिरपेक्ष जनरल

शिक्षा को धार्मिक शिक्षा से अलग किया जा सकता है। 1930 में

चक्रीय 'क्रिश्चियन एजुकेशियन ऑफ यूथ' पोप पायस XI ने सराहना की है:

" चर्च द्वारा अनुमोदित एकमात्र स्कूल एक (जहाँ) कैथो है। लिक धर्म पूरे वातावरण (और जहाँ) सभी शिक्षण में व्याप्त है।

और विद्यालय और उसके शिक्षकों का पूरा संगठन, पाठ्यक्रम और हर शाखा में पाठ्यपुस्तकों को ईसाई आत्मा द्वारा विनियमित किया जाता है।

(फेफर, चर्च, स्टेट एंड फ्रीडम, 1953 एडन. पी. 294)।

न ही नियामक शक्ति को ऐसी अवधारणाओं से बाधित किया जाना चाहिए।

क्योंकि "अधिकार के वास्तविक और प्रभावी प्रयोग" को छुआ नहीं जाना चाहिए विनियमन या वह विनियमन "प्रत्यक्ष रूप से और तुरंत" नहीं होना चाहिए

कला द्वारा प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन करना। 30 (1) . वास्तविक क्या है और

अधिकार का प्रभावी प्रयोग इस बात पर निर्भर करेगा कि विवादित व्यक्ति कितनी दूर है। समय, स्थान और परिस्थितियों के संदर्भ में विनियमन आवश्यक है।

किसी भी प्रतिस्पर्धी संगठन के किसी भी प्रतिस्पर्धी सामाजिक हित की रक्षा के लिए

किसी व्यक्ति का न्यायिक या कानूनी अधिकार।

(1) [1971] 1 एस. सी. आर. 734

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1

975] 1 एससीआर

304

रे में बहुमत की राय: केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर)

उस निर्माण का समर्थन करता है जिसे मैं कला पर रखना चाहता हूं। 30 (1)

बहुमत के लिए बोलते हुए, जे. दास ने कहा:

" इस प्रकार हम एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं।

लचीलापन स्पष्ट रूप से समाधान के लिए कठिन है। वहाँ एक पर है कला के तहत अल्पसंख्यक अधिकारों को सौंपें। 30 (1) स्थापित करना और

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करना और

शिक्षा को बढ़ावा देना सरकार का कर्तव्य है दूसरी ओर, अनुच्छेद के तहत राज्य का दायित्व। 45 को

" निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा शुरू करने का प्रयास करना। हम. इन दोनों परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा

और यदि संभव हो तो दोनों को लागू करना और

दोनों के बीच एक संश्लेषण "। (जोर जोड़ा गया) (ऊपर

पृष्ठ 1062)।

उस सी. एल. एस. को पकड़ना। 9 , 11 (2) और 12 (4) अनुमेय विनियम थे,

विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा:

" तथापि, खंड 9,11 (2) और 12 (4) पर आपत्ति है -

अनुमेय सीमा से बहुत आगे जाना। कहा जाता है कि

शुल्क आदि के संग्रह को अपने हाथ में लेकर और इसके तहत

शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना सरकार वास्तव में स्कूल को जब्त कर रही है, किसी के लिए नहीं।

स्कूल प्राधिकरण की देखभाल करेंगे। इसी तरह सीएल। 11 ले जाता है।

प्रबंधनक एकटा स्पष्ट वस्तु, कारण प्रबंधक नहि कऽ सकैत अछि। पैनल से बाहर किसी भी शिक्षक को नियुक्त करें

लोक सेवा आयोग, जो इसके अलावा

हो सकता है कि इस तरह के कर्तव्यों को निभाने की इसकी शक्ति का सवाल न हो उन शिक्षकों का चयन करने के लिए बिल्कुल भी योग्य होना जो स्वीकार्य होंगे

धार्मिक संप्रदाय और विशेष रूप से उप-वर्ग। (2) उस में से

खंड आपत्तिजनक है क्योंकि यह शैक्षणिक संस्थानों पर बल देता है।

अनुसूचित जातियों के धार्मिक अल्पसंख्यकों के शिक्षकों को शिक्षा

जिन्हें अपने धर्म के किरायेदारों का कोई ज्ञान नहीं हो सकता है

और अन्यथा शैक्षिक रूप से कमजोर हो सकता है। निराशा की शक्ति

साल, हटाने, रैंक में कमी या निलंबन एक सूचकांक है,

प्रबंधन का अधिकार और जिसे खंड द्वारा छीन लिया जाता है

12 (4) . इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सही दिशा में गंभीर बाधाएं हैं।

प्रशासन और खतरनाक रूप से उस अधिकार का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं।

लेकिन यह देखते हुए कि वे प्रावधान सभी पर लागू होते हैं

शैक्षणिक संस्थान और सी. एल. एस. के विवादित भाग। 9 , 11 और 12 को सुरक्षा और सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है

खराब वेतन पाने वाले शिक्षक जो सेवा प्रदान करने में लगे हुए हैं

राष्ट्र और पिछड़े वर्गों की रक्षा के लिए हम तैयार हैं,

जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, इन खंडों 9,11 (2) और

12 (4) अनुमेय विनियमों के रूप में जो राज्य लागू कर सकता है

अल्पसंख्यकों को सहायता देने की शर्त के रूप में

शैक्षणिक संस्थान "। (पी पर सुप्रा। 1064)

इस समय मैं शुद्धता या समावेश से चिंतित नहीं हूं।

उस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता जो सी. एल. एस. 9 , 11 (2) , 12 (4) संवैधानिक हैं। आई.

न्यायनिर्णयन की तकनीक को सामने लाने के लिए इस परिच्छेद को उद्धृत किया है एक कानून की संवैधानिकता जिसने खुद को सराहा है

न्यायालय के बहुमत के अनुसार, उस तकनीक के लिए न्यायालय को संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है।

एक्सएविअर्स कॉलेज वी. गुजरात (द्विवेदी, जे.)

कला द्वारा प्रदत्त अधिकार। 30 (1) और सामाजिक और व्यक्तिगत हितों की रक्षा करना आवश्यक है।

रेव. सिद्धजभाई भाई और अन्य बनाम। बम्बई राज्य (1)

शाह जे ने कहा:

" दक्षता के वास्तविक हित में बनाए गए विनियम

शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य स्वच्छता, नैतिकता, जनता

आदेश और इसी तरह के आदेश निस्संदेह लगाए जा सकते हैं। इस तरह के नियम

लेशन अधिकार के सार पर प्रतिबंध नहीं हैं

जिसकी गारंटी है; वे उचित कार्यप्रणाली को सुरक्षित करते हैं शिक्षा के मामलों में संस्था "। (जोर दिया गया)।

इस परिच्छेद से यह भी पता चलता है कि न्यायालय ने इस दृष्टिकोण का पालन किया है

दास सी. जे. द्वारा केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) में लिया गया

कि राज्य के पास कुछ सुरक्षा के लिए विनियम बनाने की शक्ति है

सामाजिक हित।

इस मामले में निर्णय मुझे विरोधाभासी नहीं लगता है

मेरे द्वारा सुझाए गए निर्माण, क्योंकि न्यायालय का विचार था कि निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों का अपने छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार

सरकारी आदेश द्वारा अपनी पसंद को "गंभीर रूप से प्रतिबंधित" किया गया था। में।

दूसरे शब्दों में, विवादित आदेश आवश्यकता से कहीं अधिक था मामले की परिस्थितियों में।

केरल राज्य में v. बहुत रेव. माँ प्रांतीय (2)।

हिदायतुल्ला सी. जे. ने सर्वसम्मत न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा: " " 'प्रशासन' का अर्थ है संस्थान के 'मामलों का प्रबंधन'।

यह प्रबंधन नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए ताकि संस्थापक या उनके

नामांकित व्यक्ति संस्थान को वैसा ही ढाल सकते हैं जैसा वे उचित समझते हैं, और उसके अनुसार सामान्य रूप से समुदाय के हितों के बारे में उनके विचारों के साथ और

विशेष रूप से संस्थान को सबसे अच्छी सेवा दी जाएगी। इस प्रबंधन का कोई हिस्सा नहीं

मन को दूर ले जाया जा सकता है और किसी अन्य निकाय में निहित किया जा सकता है।

गारंटीकृत अधिकार पर अतिक्रमण "। महान प्रतिक्रिया के साथ, मैं इसे पाता हूँ

इतनी दूर जाना मुश्किल है। उदाहरण के लिए किसी भी नागरिक के अधिकार को लें, एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को स्थापित करने और प्रशासित करने के लिए

सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक सैन्य अकादमी

जिन छात्रों ने इसमें प्रवेश लिया। श्री नानावती, पेटी के वकील

टियोनर्स, ने स्वीकार किया कि इस अधिकार को प्रतिबंधित और विनियमित किया जा सकता है

राज्य की सुरक्षा का हित। राज्य एक विनियमन बना सकता है

हथियारों और गोला-बारूद के प्रभावी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए

अपनी पसंद और विश्वास के अधिकारियों द्वारा अकादमी की लालसा

डेंस। मेरा मानना है कि राज्य निर्धारित करने की अवधि तक जा सकता है

कि हथियार और गोला-बारूद सरकार के पास रखे जाने चाहिए। शस्त्रागार और राज्य के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए

शस्त्रागार। कला के तहत अधिकार। 30 (1) एक परिसर का हिस्सा है और

विविध सामाजिक हितों का अंतर-आश्रित समूह। ऐसा नहीं हो सकता

अधिकार और उन सामाजिक हितों का स्थायी रूप से निश्चित समायोजन।

उन्हें समय-समय पर समायोजन और पुनः समायोजन की आवश्यकता होगी और

अलग-अलग परिस्थितियों में।

(1) [1963] 3 एस. सी. आर. 837 पी. 850 .

(2) [1971] 1 एस. सी. आर. 734 पी. 740 .

[1975] 1 एस सी आर।

306

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. ए. वी. कॉलेज बनाम पंजाब राज्य के मामले में, (1) इस न्यायालय ने फैसला सुनाया।

नीचे सी. एल. 17 उन कानूनों में से जो प्रदान करते हैं कि कर्मचारी शुरू में

नियुक्त को कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और यह कि सभी बाद के परिवर्तनों को विश्वविद्यालय को भेजा जाना चाहिए

कुलाधिपति की मंजूरी। हालांकि, रेड्डी जे., यूनानी के लिए बोल रहे हैं।

मूस कोर्ट ने टिप्पणी की:

1

" हमारे विचार में प्रो के लिए कोई संभावित औचित्य नहीं है।

खंड में निहित दर्शन। . 17 मूर्ति के अध्याय V का

जो प्रबंधन के अधिकारों में निश्चित रूप से हस्तक्षेप करते हैं।

याचिकाकर्ता महाविद्यालय। ये प्रावधान नहीं कर सकते हैं।

इसलिए संबद्धता की शर्तों के रूप में बनाया जाए, गैर-कॉम

जिसके लाभ में असंबद्धता शामिल होगी और इसके परिणामस्वरूप

उन्हें अपमानजनक कला के रूप में खारिज करना होगा। 30 (1) . "

न्यायालय को संतुष्ट कर सकता था कि विषय बनाना आवश्यक था उप के अनुमोदन के लिए शिक्षकों की नियुक्ति आदि की शक्ति

कुलाधिपति। ऐसा लगता है कि रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट में कुछ भी नहीं है और

अन्य बनाम। बिहार राज्य (2) और डी. ए. वी. कॉलेज, भटिंडा बनाम।

पंजाब राज्य (3) जो निर्माण के खिलाफ विद्रोह करेगा

कला. 30 (1) मेरे द्वारा सुझाए गए

विभिन्न उच्च अधिकारियों के निर्णयों में कोई नया सिद्धांत नहीं बताया गया है।

एल्डो मेरिया पैट्रोनी बनाम में न्यायालय। वी. ई. सी. केशवन, (4) दीपेंद्र नाथ

सरकार बनाम। बिहार राज्य, (3) मुस्लिम अंजुमन-ए-तालीम, धार

भंगा बनाम। बिहार विश्वविद्यालय, (*) वर्की बनाम केरल राज्य, (1)

केरल राज्य बनाम। विद्यालयों का निगमित प्रबंधन

चानानचेरी के आर्चडीओसीज, (*) और स्कूल शिक्षा निदेशक,

तमिलनाडु बनाम। रेव. फादर जी. इरोगियास्वामी। (ओ) ये सभी निर्णय,

इस न्यायालय के किसी न किसी निर्णय का पालन करें जैसा कि उन्हें करना चाहिए था

किया। तदनुसार उन्हें किसी भी विस्तार से संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नानावती ने भी स्थायी न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है। वार्षिक में निर्दिष्ट मामला संख्या 182 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायसार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून मामलों की रिपोर्ट का डाइजेस्ट (वर्ष 1935-37) लॉटरपैक्ट द्वारा। स्थिति से संबंधित घोषणा का अनुच्छेद 4 अल्बानिया में अल्पसंख्यकों ने प्रावधान किया कि "सभी अल्बानियाई नागरिक करेंगे कानून के समक्ष समान होना चाहिए और समान नागरिक और राजनीतिक लाभ उठाना चाहिए।

नस्ल, भाषा या धर्म के भेद के बिना अधिकार। अनुच्छेद 5 घोषणा इस प्रकार थी: " अल्बेनियाई नागरिक जो संबंधित हैं नस्लीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कानून में और वास्तव में अन्य अल्बानियाई नागरिकों के रूप में सुरक्षा। में। विशेष रूप से उन्हें बनाए रखने, प्रबंधित करने और रखने का समान अधिकार होगा।

अपने खर्च पर या भविष्य में धर्मार्थ, धार्मिक और सामाजिक संस्थानों, स्कूलों और अन्य शैक्षणिक प्रतिष्ठानों की स्थापना करने के लिए उन्हें अपनी भाषा का उपयोग करने और उसमें स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का प्रयोग करने का अधिकार है। 1933 में अल्बानिया राष्ट्रीय सभा ने अल्बानियाई संविधान में इस प्रकार संशोधन किया: शिक्षा और प्रशिक्षण

अल्बेनियाई विषय राज्य के लिए आरक्षित हैं और इन्हें राज्य के स्कूलों में दिया जाएगा। सभी अल्बेनियाई नागरिकों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है और इसे निःशुल्क दिया जाएगा। वर्तमान में संचालित सभी श्रेणियों के निजी स्कूल बंद रहेंगे। इस संशोधन के बाद संभवतः यूनानी मूल के अल्बानियाई अल्पसंख्यकों ने अपने अधिकारों के उल्लंघन के बारे में लीग ऑफ नेशंस से शिकायत की।

कला द्वारा गारंटीकृत। 5 घोषणा की। मामला चला गया विचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय। द माजो

न्यायालय की राय (तीन असहमति के साथ) यह थी कि न्यायिक संशोधन ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जिसकी गारंटी दी गई थी कला. 5 घोषणा की। यह समझना मुश्किल है कि बहुमत की राय कैसे गिर जाएगी।द्वारा गारंटीकृत अधिकार की प्रकृति और दायरे पर कोई उपयोगी प्रकाश कला. 30 (1) . जाहिर है, कला का संदर्भ। 30 (1) , दोनों के रूप में काल्पनिक पाठ के साथ-साथ, अल्बेनियाई के संदर्भ के साथ कोई तुलना नहीं है। संवैधानिक संशोधन और घोषणा का अनुच्छेद 5।

अब विभिन्न विवादित प्रावधानों की जांच करना आवश्यक है। कला के निर्माण के आलोक में। 30 (1) इसमें पहले सुझाव दिया गया था निर्णय। धारा 33ए (1) (ए) मैं बहुलता के इस दृष्टिकोण से सहमत हूं कि यह कला के लिए अप्रिय है। 30 (1) ,और मेरे पास जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील श्री नानावती ने हमले को छोड़ दिया।

इस प्रावधान के खिलाफ। राज्य और गुजरात विश्वविद्यालय के लिए वकील सिटी ने तदनुसार कोई जवाब नहीं दिया। श्री नानावती ने प्रो पर हमला नहीं कियाउनके जवाब में भी दृष्टि। इसलिए मुझे इस पर कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। प्रावधान। धारा 40 धारा 39 (1) में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर, सभी पद स्नातक शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा संचालित किया जाएगा

विश्वविद्यालय या ऐसे संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थानों द्वारा और ऐसे में कानून द्वारा निर्धारित विषय। याचिकाकर्ता नहीं करते हैं इस प्रावधान को चुनौती दें। लेकिन वे सवाल पूछना चाहते हैं। 40 जो कि स के समान। 39 (1) . धारा 40 (1) में प्रावधान है कि न्यायालय अध्ययन के पाठ्यक्रमों में सभी निर्देश, शिक्षण और प्रशिक्षण जिसके संबंध में विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम ह श्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर शैलों का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाए और न्यायालय अपने निर्णय के बारे में राज्य सरकार को सूचित करेगा। धारा 40 (2) में प्रावधान है कि संचार की प्राप्ति पर

राज्य सरकार ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे,आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना घोषित करती है कि एस के प्रावधान। 41 अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से लागू होगा।

कैशन। यह पहले ही माना जा चुका है कि संबद्धता का अधिकार Art.30 (1) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है। तदनुसार मुझे विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक कक्षाओं में शिक्षण को संभालने में कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती है।

विविधता। हम उप-विषयों से संबंधित नहीं हैं। (2) . उप-धारा (2) में कहा गया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान, की सहमति के अलावा, नहीं करेगा विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की मंजूरी किसी अन्य के किसी भी विशेषाधिकार के साथ संबद्ध हो या अनुमति ले विश्वविद्यालय। मुझे नहीं लगता कि किसी भी वैध आपत्ति को उप-धाराओं में ले जाया जा सकता है। (1) . केवल इसलिए कि एक संबद्ध कॉलेज को विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज बनाया गया है, जरूरी नहीं कि यह कला को आहत करेगा। 30 (1) . 'घटक महाविद्यालय' अभिव्यक्ति की परिभाषा अपने आप में निर्दोष है। । आखिरकार, किसी ने कहा है: " नाम में क्या है! एक घटक महाविद्यालय की अवधारणा तरल है। यह एक अल्पसंख्यक कॉलेज के प्रशासन पर प्रयोग किए जाने वाले बाहरी नियंत्रण की डिग्री है, न कि इसके वैधानिक नाम, जो Art.30 (1) के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहयोगी महाविद्यालय (जो संबद्ध महाविद्यालयों के समान हैं) शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में विश्वविद्यालय की आलोचना के अधीन हैं। लेकिन मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद, जो उस विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज है, इस तरह के नियंत्रण के अधीन नहीं है। जबकि सहायक महाविद्यालयों में शिक्षकों का चयन करने वाली चयन समिति में कुछ विश्वविद्यालय प्राधिकरण शामिल होते हैं, घटक महाविद्यालयों में शिक्षकों का चयन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है और शिक्षकों के चयन में विश्वविद्यालय की कोई आवाज नहीं होती है। (इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैलेंडर 1968 देखें)। उप-धारा (3) पर भी आपत्ति नहीं की जा सकती। यह एक संबद्ध कॉलेज को राज्य और गुजरात विश्वविद्यालय की अनुमति से किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध होने की अनुमति देता है जो एक घटक कॉलेज नहीं बनना चाहता है।

तथापि, याचिकाकर्ता की ओर से गंभीर आपत्ति को उप-धारा (4) के खंड (ii) से खंड (vi) तक ले जाया गया है। उपखंड (4) को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग के अनुसार

घटक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के संबंध उस संबंध में बनाए जाने वाले कानूनों द्वारा शासित होंगे। दूसरे भाग में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी कोई भी क़ानून विशेष रूप से सी. एल. एस. में निर्दिष्ट घटक कानूनों के संबंध में विश्वविद्यालय की शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है। ((ii) उप-धारा (4) से (vi) तक।

जाहिर है, उप-धारा (4) का पहला भाग क़ानून बनाने की सामान्य शक्ति प्रदान करता है। इसके दूसरे भाग में कुछ शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है। जिन पर कानून बनाए जाने चाहिए। उप के दो भाग

धारा (4) नियम बनाने के लिए आधुनिक कानूनों में प्रावधानों के सामान्य स्वरूप का पालन करती है। उप-धारा (4) का दूसरा भाग केवल पहले भाग द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता का उदाहरण है। जबकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने आग्रह किया है कि खंड (ii) से (vi) स्पष्ट रूप से Art.30 (1) के तहत अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आग्रह किया है कि उन खंडों की व्यापक भाषा इतनी ST हो सकती है।

ए.उन्हें संवैधानिक बनाने के लिए पढ़ें। मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। सैरी इस विवाद में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि

कला का प्रतीक। 30 (1) . फिर भी, याचिकाकर्ताओं को कुछ भी हासिल नहीं होगा इस प्रकार, पहली के खिलाफ कोई वैध आपत्ति नहीं की जा सकती है। उप-धारा (4) का भाग। तब यह बात आती है कि जब तक कानून न हों वास्तव में किया जाता है, संवैधानिक हमला समय से पहले होता है।

बी. धारा 51 (ए)धारा 51 (ए) में दो उप-धाराएँ हैं। पहला उप-खंडयह प्रावधान करता है कि किसी संस्थान के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का कोई सदस्य नहीं संबद्ध कॉलेज को बर्खास्त या हटा दिया जाएगा या रैंक में कम किया जाएगा। एक जांच के बाद, जिसमें उन्हें आरोपों के बारे में सूचित किया गया है

सी. उसके खिलाफ और सुनवाई का एक उचित अवसर दिया गया उन आरोपों का सम्मान करें। जब तक उसे उचित अवसर नहीं दिया जाता प्रस्तावित जुर्माने के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने की योग्यता, वह कर सकता है दंडित नहीं किया जाता। उप-धारा (1) का यह भाग अनुच्छेद 311 के समान है।

(2) संविधान का, और कोई वैध आपत्ति नहीं ली जा सकती है यह। उप-खंड (1) में शक्ति पर एक और सवार भी शामिल है प्रशासन अपने कर्मचारियों को निकाल देगा। इस सवार के अनुसार, दंड प्रबंधन द्वारा लागू किया गया आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे मंजूरी नहीं मिल जाती।कुलपति या विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस संबंध में कुलपति ने आपत्ति जताई।

उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि किसी भी सदस्य की सेवाएँ शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को तब तक समाप्त कर दिया जाएगा जब तक कि उन्हें प्रस्तावित के खिलाफ कारण

दिखाने का उचित अवसर दिया गया समाप्ति। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रावधान एक पर लागू नहीं होगा

वह व्यक्ति जिसे अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। उप-एस की तरह। (1) , यह शक्ति भी कुलपति के अनुमोदन के अधीन की जाती है या कुलपति द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय का कोई अन्य अधिकारी। उप-धाराओं के पहले भाग पर कोई वैध आपत्ति नहीं ली जा सकती है। (1) और (2)। लेकिन प्रावधान पर गंभीर आपत्ति ली जाती है कुलपति या विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी का अनुमोदन एफ.

इस संबंध में कुलपति द्वारा प्राधिकृत। यह सच है कि किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने का अधिकार नियोक्ता का है सेवा अनुबंध के तहत। यह भी सच है कि गोली चलाने का अधिकार है

Art.30 (1) के तहत संरक्षित एक प्रबंधन अधिकार। लेकिन यह अधिकार हो सकता है इसमें कर्मचारी के अधिकार को छीनने या कम करने का अधिकार शामिल नहीं है। संगठन बनाने, अपने पेशे और अन्य कार्यों को जारी रखने का न्यायिक अधिकार संवैधानिक और कानूनी अधिकार। एस का उद्देश्य। 51 ए जाँचने के लिए है

कुलाधिपति के बाद, कुलाधिपति अगला सर्वोच्च अधिकारी होता है। विश्वविद्यालय। यह माना जाना चाहिए कि देने या रोकने में अनुमोदन से वह तर्क और न्याय के अनुसार कार्य करेगा। जब मामला अनुमोदन के लिए कुलपति के समक्ष जाता है,

एच. प्रबंधन और शिक्षक या गैर के सदस्य दोनों शिक्षण कर्मचारियों को उनकी बात सुननी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक है। मूढ़ता से निहित, क्योंकि उनमें से किसी को भी सुने बिना यह मुश्किल होगा

उसे यह तय करना चाहिए कि उसे शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई को मंजूरी देनी चाहिए या रोकनी चाहिए। इसके बाद यह भी होगा कि स्वीकृति या अस्वीकृति देते समय, कुलपति को कारण दर्ज करना चाहिए, क्योंकि अपनी शक्ति का प्रयोग अदालतों के नियंत्रण के अधीन है। कानून उनके आदेश को अंतिम नहीं बनाता है, और अदालतें निश्चित रूप से उनके आदेश को रद्द कर देंगी यदि यह मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या अवैध है।

यदि प्रबंध निकाय दुर्भावनापूर्ण तरीके से या एक के रूप में गोली चलाने के अधिकार का प्रयोग करता है

पीड़ित होने के पैमाने पर, कुलपति के लिए अनुमोदन को रोकना उचित होगा। कुलपति अनुमोदन को भी रोक सकता है जहां निष्पक्ष सुनवाई नहीं की गई है या जहां पूछताछ के रिकॉर्ड में उस अपराध को स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है जिसके लिए शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी के सदस्य को दंडित किया गया है। दूसरी ओर, यदि कुलपति को लगता है कि सजा

उचित सुनवाई के बाद दी गई है और सबूत द्वारा समर्थित है, और इसे दुर्भावनापूर्ण या उत्पीड़न के उपाय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो वह अनुमोदन को रोक नहीं सकता है।

यह भी आग्रह किया जाता है कि अनुमोदन देने की शक्ति प्रदान नहीं की जाए

विशेष रूप से कुलपति पर। इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य अधिकारी को नामित करना उनके लिए खुला है। अधिनियम की धारा 8 विश्वविद्यालय के अधिकारियों की गणना करती है। वे इस प्रकार हैं: (1) कुलाधिपति; (2) कुलपति; (3) उप-कुलपति; (4) संकायों के डीन; (5) कुलसचिव; (6) विश्वविद्यालय

लाइब्रेरियन; और (7) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें कानूनों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जा सकता है। पहले छह अधिकारी विश्वविद्यालय के सभी महत्वपूर्ण और जिम्मेदार अधिकारी हैं। उन पर उचित तरीके से अनुमोदन की शक्ति का प्रयोग करने के लिए भरोसा किया जा सकता है।

तरीके से। यह हमें नहीं बताया गया है कि क्या क़ानूनों ने बनाया है विश्वविद्यालय का कोई अन्य अधिकारी। इसलिए हम अंतिम खंड से सहमत नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुलपति द्वारा अनुमोदन की शक्ति शिक्षण सेवा की सुरक्षा के हित में आवश्यक है और गैर-शिक्षण कर्मचारी। सेवा की सुरक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। कुशलता और कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन। यह सुधार करने के लिए गणना की जाती है दीर्घावधि में संस्था। शिक्षण के सदस्य और गैर शिक्षण कर्मचारी आम तौर पर निवारण के लिए अदालतों में जाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं।

धारा 51 ए उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उन्हें एक सस्ता और अधिक त्वरित उपचार प्रदान करती है। आक्षेपित प्रावधान एस के समान है। 33 , औद्योगिक विवाद अधिनियम जिसे इस न्यायालय ने माना है। वैध है।

यह कहा जा सकता है कि मामले का यह पहलू जो मेरे पास है एस के संबंध में। 51 ए को न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया था पहले के मामले। चूंकि अनुमोदन की शक्ति जाँच करने तक ही सीमित है कर्मचारियों को बर्खास्त करने के अधिकार का दुरुपयोग, मेरी राय है कि यह नहीं है

अपराध Art.30 (1)।

धारा 52 क।

इसमें दो उपखंड हैं। उप-सेक। (1) यह प्रदान करता है कि कोई भी शासी निकाय और शिक्षण और एसटी के किसी भी सदस्य के बीच बातचीत करें।

एक संबद्ध कॉलेज का गैर-शिक्षण कर्मचारी जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ऐसे सदस्य की सेवा की शर्तें, सरकार के अनुरोध पर निकाय या संबंधित सदस्य को किसी न्यायाधिकरण को भेजा जाए शासी द्वारा नामित एक मध्यस्थ से युक्त मध्यस्थता निकाय और दूसरा शिक्षण और गैर-शिक्षण के सदस्य द्वारा कुलपति द्वारा नियुक्त कर्मचारी और एक अंपायर। उप-खंड

(2) वास्तव में यह प्रावधान है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधान उप-धारा (1) के तहत मध्यस्थता पर लागू होगा। याचिकाकर्ताओं का समर्थन करने वाले वकील ने आग्रह किया है कि यह राशि के मामलों के प्रबंधन में बाहरी हस्तक्षेप के लिए महाविद्यालय। इस प्रावधान का उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना भी है।

प्रबंध निकाय द्वारा प्रशासन और एक सस्ता और प्रदान करने के लिए छोटे शिक्षण और गैर-शिक्षण के लिए त्वरित उपचार टाफ। यह सेवा की सुरक्षा के हित में आवश्यक है। मैं एक हूँ। कला के आधार पर इसके प्रति किसी भी वैध आपत्ति का पता लगाने में सक्षम।· 30 (1) .

पीबीआर.

2 - एल 177 सुपर सी. आई./75